राष्ट्रीय संस्करण

हरियाणा की पैरा एथलीट दीपा मलिक को भी मिलेगा खेल रत्न >> 14

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 69

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, रविवार, 18 अगस्त 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

सरोकार

दिल्ली में सुरक्षित सफर की साथी महिला कैब

नई दिल्ली : दिल्ली में एक महिला के द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई मोबाइल एप आधारित ऐसी कैब सेवा, जिसमें सभी चालक महिलाएं हैं। दो साल के अल्प समय में दो कारों से बढ़कर यह काफिला 17 कैब पार्टनरों तक पहुंच गया है और एनसीआर से बाहर निकलकर दूसरे शहरों में पहुंचने को तैयार है। (पेज-11)

रविवार विशेष

द्वापर का वैभव देख दंग रह जाएगी पूरी दुनिया

द्वारकापुरी : पौराणिक द्वारका नगरी के एक हिस्से बेट द्वारका (प्राचीन द्वारका का हिस्सा जो समुद्र में बने टापू पर है) तक दर्शनार्थियों को आसानी से पहुंचाने के लिए समुद्र पर केबल ब्रिज बनेगा। समुद्र के गर्भ में छिपे द्वारका जगत मंदिर को सीसीटीवी से भी देखने की व्यवस्था होगी। (पेज-11)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 4

कांग्रेस में गांधी परिवार के बाहर के नेता का नेतृत्व कठिन : अधीर

कोलकाता : लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि गांधी परिवार से बाहर के किसी नेता का पार्टी का नेतृत्व करना मुश्किल है। उन्होंने कहा, सोनिया गांधी पार्टी की कमान नहीं संभालना चाहती थीं, लेकिन राहुल के इस्तीफे से संगठन को संकट में देखकर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर लगा यूएपीए

पटना : बिहार पुलिस ने घर से एके 47 और ग्रेनेड बरामदगी के मामले में बाहुबली विधायक अनंत सिंह के खिलाफ यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) की धारा 13 के तहत केस दर्ज किया है। विधायक के घर का केयरटेकर पकड़ा जा चुका है। शीघ्र ही अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

श्रीलंका में महिंद्रा ने लगाई पहली असेंबलिंग यूनिट

कोलंबो : देश की अग्रणी ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने वैश्विक स्तर पर कदम बढ़ाते हुए श्रीलंका में शनिवार को पहला ऑटोमोटिव असेंबलिंग संयंत्र शुरू किया है। यह संयंत्र श्रीलंका की आइडियल मोटर्स के साथ संयुक्त उपक्रम के तहत खोला गया है। महिंद्रा का कहना है कि स्थानीय स्तर पर सोर्सिंग के साथ श्रीलंका में यह पहली बड़ी कार असेंबलिंग यूनिट है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

अमेरिका ने पाक की 31.30 अरब रुपये की मदद रोकी

वाशिंगटन : अमेरिका ने पाक को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में करीब 44 करोड़ डॉलर (भारतीय मुद्रा में करीब 31.30 अरब रुपये) की कटौती कर दी है। अब अमेरिका से उसे कुल 4.1 अरब डॉलर (करीब 2.92 खरब रुपये) की ही मदद मिल रही है। 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के मुताबिक, यह आर्थिक मदद पाकिस्तान इनहेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट (पीपा) 2010 के तहत दी जाती थी।

एम्स में भीषण आग, इमरजेंसी सेवाएं बंद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- एक्स-रे मशीन में धमाके से आग लगने की आशंका, करोड़ों का नुकसान
- टीचिंग ब्लॉक से सटी इमारत से 55 मरीज दूसरी जगह शिफ्ट किए गए

दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में शनिवार शाम करीब साढ़े चार बजे अचानक आग लग गई। टीचिंग ब्लॉक की दूसरी मंजिल से शुरू हुई आग कुछ ही देर में पहली, तीसरी, चौथी और पांचवीं मंजिल तक पहुंच गई। डॉक्टरों व अन्य स्टाफ समेत करीब 50 लोगों ने बाहर भागकर जान बचाई। इमरजेंसी लैब वाली इमारत में धुआं फैलने के कारण वहां भर्ती 55 मरीजों को स्थानांतरित किया गया। इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। देर रात तक 40 दमकल गाड़ियां आग बुझाने में लगी थीं। एक कर्मचारी के मुताबिक एक्स-रे मशीन में धमाके से आग लगी और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग में फैल गई। करोड़ों के नुकसान का अनुमान है।

एम्स परिसर में मुख्य अस्पताल के बराबर में टीचिंग ब्लॉक की पांच मंजिला इमारत है। इस इमारत में लैब मेडिसिन और इमरजेंसी लैब डिपार्टमेंट के साथ ही कई प्रोफेसरों के ऑफिस बने हुए हैं। सैंपल कलेक्ट करने के लिए डीप-फ्रीजर भी रखे हुए हैं। यहीं एक्स-रे भी होता है। शाम करीब साढ़े चार बजे दूसरी मंजिल पर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में आग लग गई। कुछ ही देर में आग बढ़ती चली गई। एम्स के सुरक्षाकर्मियों ने फायर फाइटिंग उपकरणों से काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग और तेज हो गई। करीब पौने पांच बजे कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। कुछ ही देर में दमकल गाड़ियां पहुंच गईं और कर्मचारी आग बुझाने में जुट गए। आग का विकराल रूप देख दिल्ली से सभी फायर स्टेशनों से दमकल गाड़ियां मौके पर बुला ली गईं।

टीचिंग ब्लॉक के बराबर वाली बिल्डिंग में चल रहा था ऑपरेशन

जिस टीचिंग ब्लॉक में आग लगी उसके बराबर वाली बिल्डिंग में इमरजेंसी लैब है, जिसमें हड्डियों की बीमारियों से पीड़ित के मरीजों का ऑपरेशन होता है। आग लगने के वक्त भी लैब में एक मरीज का ऑपरेशन चल रहा था। धुआं बिल्डिंग में भरने लगा तो उक्त मरीज का जल्द ऑपरेशन पूरा किया गया। उसके समेत अन्य सात-आठ ऐसे मरीज जिनका एक-दो दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ था, उन्हें समेत 55 मरीजों को दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया। ज्यादातर मरीजों को ओपीडी काउंटर की टिन शेड के नीचे शिफ्ट किया गया। इस दौरान कई ऐसे मरीज भी देखे गए जिनको खून चढ़ रहा था।

रेजिडेंट डॉक्टरों व नर्सों ने भी लोगों ने बचाया : टीचिंग ब्लॉक में आग लगने के बाद अफरातफरी और चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। इस दौरान रेडिजेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदस्यों और नर्सों ने लोगों की मदद की और उन्हें आग से निकाला। इन्हें इस भवन के सभी रास्ते व सुरक्षित आवागमन का तरीका पता था।

...तो ढह जाती पूरी बिल्डिंग : जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसके ग्राउंड फ्लोर पर 11 हजार किलोवाट का विद्युत सब स्टेशन है। वहां कई ट्रांसफामर्स रखे हैं। आग वहां तक पहुंच जाती तो भयंकर विस्फोट हो सकता था, क्योंकि ट्रांसफार्मर में अत्यधिक ज्वलनशील तेल होता है। इतने बड़े ट्रांसफार्मर के फटने से पूरी बिल्डिंग ढह जाती।

अस्पताल में आग पर काबू पाने में लाचार दिखा प्रशासन पेज>>2

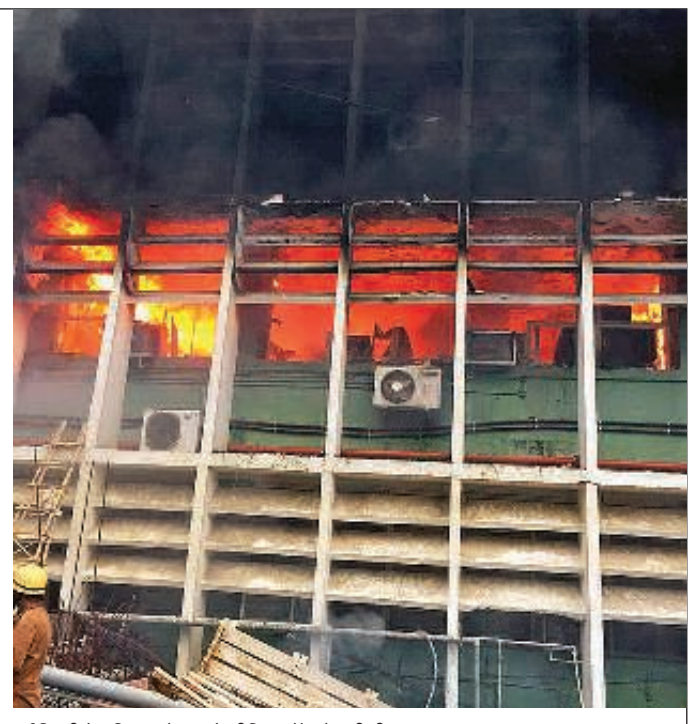

नई दिल्ली में शनिवार को एम्स के टीचिंग ब्लॉक में लगी भीषण आग। जागरण

भारत का जवाब, ढेर किए पाकिस्तान के दो अधिकारी और पांच सैनिक

कार्रवाई ▶ पाक की तीन चौकियां भी हुईं तबाह, राजौरी में तैनात लांस नायक हुआ शहीद

शनिवार सुबह सीमा पार से राजौरी और पुंछ में मोर्टार से की गई गोलाबारी

जागरण संवाददाता, राजौरी

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटने के बाद विश्व में अलग-थलग पड़ी पाकिस्तानी सरकार और उसकी सेना बौखला गई है। शनिवार सुबह पाक सेना ने जम्मू संभाग के राजौरी जिले की नौशहरा तहसील के कलाल और पुंछ के मनकोट सेक्टर में भारी गोलाबारी की। नौशहरा में भारतीय सेना के एक लांस नायक शहीद हो गए। इसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाक सेना की तीन चौकियां तबाह कर दीं। इस कार्रवाई में पाक सेना के दो अफसरों और पांच सैनिकों के मारे जाने की सूचना है। देर शाम तक नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी जारी रही।

रिहायशी क्षेत्रों पर भी दागे मोर्टार : जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह पाक सेना ने एकाएक नौशहरा सेक्टर में गोलाबारी शुरू कर दी। पाक सेना ने सैन्य चौकियों को निशाना बनाने के साथ-साथ रिहायशी क्षेत्रों पर भी मोर्टार दागना शुरू कर दिया। इस दौरान सीमा पर तैनात भारतीय सेना के लांस नायक संदीप थापा गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पर वहां मौजूद अन्य जवानों ने घायल लांस नायक को पास के सैन्य अस्पताल पहुंचाया। जहां उपचार के दौरान वह शहीद हो गए। 35 वर्षीय संदीप थापा मूलरूप से उत्तराखंड के सहसपुर के राजवाला गांव के मूल निवासी थे।

भारतीय सेना ने की जोरदार जवाबी कार्रवाई : इसके बाद भारतीय सेना ने जोरदार जवाबी कार्रवाई शुरू की। इसमें पाकिस्तानी सेना की तीन चौकियां पूरी तरह से नष्ट हो गई, जबकि छह से सात जवानों के मारे जाने की सूचना है। बताया जा रहा है कि इनमें दो अधिकारी हैं। वहीं, पुंछ के मनकोट सेक्टर में भी पाकिस्तानी सेना भारी गोलाबारी को जारी रखे हुए है। इस सेक्टर में भी पाक सेना को भारतीय सेना द्वारा मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। दोनों ओर से हो रही गोलाबारी के चलते सीमा पर भारी तनाव है।

स्वतंत्रता दिवस पर भी की थी गोलाबारी: 15 अगस्त को भी पाक सेना ने पुंछ की कृष्णा घाटी सेक्टर में भारी गोलाबारी की थी। इसके बाद भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में चार पाकिस्तानी फौजी ढेर हो गए थे, जबकि कई बंकर भी तबाह हुए थे। सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान सेना आतंकियों को भारतीय क्षेत्र में दाखिल करवाने के लिए ही बार-बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रही है।

कश्मीर में टेलीफोन, जम्मू में मोबाइल और 2जी इंटरनेट बहाल पेज>>5

राजौरी में शनिवार को भारतीय सेना ने सरहद पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के जवाब में उसकी सैन्य चौकी को तबाह कर दिया। एएनआइ

शहीद लांस नायक संदीप थापा (फाइल)

बैंकों की ओर से भी मिल रहे मंदी के संकेत

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

अर्थव्यवस्था के कई सारे क्षेत्र से जो मंदी के संकेत मिल रहे हैं वे आने वाले दिनों में और बिगड़ेंगे, ऐसी आशंका हाल के दिनों में कुछ प्रमुख आर्थिक थिंक टैंक ने जताई है, लेकिन शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की तरफ से जारी बैंकिंग कर्ज के आंकड़ों से यह आशंका सच होती लग रही है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में उद्योग जगत को मिलने वाले कर्ज में 2.6 फीसद की गिरावट हुई है। 18 में से 16 उद्योग ऐसे हैं, जिनमें कर्ज की रफ्तार कम हुई है। साफ है कि उद्योग जगत कारोबार बढ़ाने के लिए नया कर्ज नहीं ले रहा है। ऐसे में औद्योगिक सुस्ती गहराने के आसार हैं।

आरबीआइ का डाटा बताता है कि जैसे-जैसे रेपो रेट में कटौती की गई और कर्ज को सस्ता बनाने का रास्ता खोला गया, उद्योग की तरफ से कर्ज की मांग भी कम होती गई। इस वर्ष फरवरी से जून के बीच आरबीआइ ने बाजार में कर्ज सुलभ कराने के लिए रेपो रेट में 75 आधार अंकों (0.75 फीसद) की कटौती की है। वैसे, बैंकों की तरफ से कर्ज की दरों में 30 आधार अंकों का फायदा ही ग्राहकों को दिया गया है। इसके बावजूद पर्सनल लोन में सिर्फ 1.5 फीसद की वृद्धि हुई है। कंज्यूमर गुड्स उद्योग के लिए कर्ज में 8.3 फीसद, ऑटो लोन में 0.9 की गिरावट हुई है जबकि हाउसिंग लोन में 2.3 फीसद का इजाफा हुआ है। सूक्ष्म व लघु उद्योगों को दिए जाने वाले कर्ज में 2.5, मझोले उद्योगों में 1.2 और बड़े उद्योगों को 2.6 फीसद की गिरावट हुई है। रत्न व आभूषण, विनिर्माण, चमड़ा, कागज, टैक्सटाइल जैसे तमाम उद्योगों ने कर्ज लेना कम कर दिया है। ये उद्योग ना सिर्फ निर्यात के लिहाज से बेहद अहम हैं बल्कि सबसे ज्यादा रोजगार सृजन भी करते हैं।

मौजूदा आर्थिक हालात में नए निवेश लाना है बड़ी चुनौती पेज>>12

आरबीआइ का डाटा

- पहली तिमाही में बैंकिंग कर्ज में 1.5 फीसद की गिरावट
- उद्योग क्षेत्रों को मिलने वाले कर्ज में 2.6 फीसद की गिरावट

सीएमआइई का डाटा

- जीडीपी के मुकाबले निजी क्षेत्र का पूंजीगत खर्च 35 फीसद से घटकर 0.5 फीसद पर आया

एमबीबीएस के बाद ओडिशा छोड़ा तो देना होगा दो करोड़

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर

सरकार का निर्णय

- सूबे में चिकित्सकों की कमी के मद्देनजर स्वास्थ्य बांड नीति में बदलाव
- विशेष पदों पर तैनात चिकित्सकों की सेवानिवृत्त आयु में दो वर्ष की वृद्धि

ओडिशा के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए नवीन पटनायक सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार की ओर से सूबे के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई करने वालों छात्र-छात्राओं के लिए बनी स्वास्थ्य बांड नीति में परिवर्तन किया गया है। इसके तहत राज्य में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी अगर ओडिशा से बाहर जाना चाहेंगे तो उन्हें डेढ़ से दो करोड़ रुपये का बांड भरना होगा। पहले 36 लाख रुपये जमा करने का प्रावधान था। साथ ही सरकार ने राज्य में विशेष पदों पर तैनात डॉक्टरों की सेवानिवृत्त आयु को भी 68 की जगह 70 साल कर दिया है।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास ने बताया कि अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी को देखते हुए मेडिकल की पढ़ाई के बाद विद्यार्थियों को राज्य में ही नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। ओडिशा के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने के बाद जो छात्र-छात्राएं पीजी करने के लिए राज्य के बाहर जाना चाहेंगे उन्हे सरकार के पास डेढ़ करोड़ रुपये का बांड जमा कराना होगा। जो विद्यार्थी सुपर स्पेशलिटी कोर्स करने के लिए जाएंगे उन्हे 2 करोड़ रुपये देकर जाना होगा।

दास ने कहा, पहले 36 लाख रुपये जमा करके जाना होता था। इसलिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस करने के बाद बहुत सारे विद्यार्थी बाहर चले जाते थे। इससे राज्य में डॉक्टरों का निरंतर अभाव बना रहताा है। उन्होंने कहा, राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में इसी साल के नामांकन के बाद इस नई नीति को लागू किया जाएगा।

अलवर में फिर उन्मादी हिंसा का शिकार हुआ एक युवक

जागरण संवाददाता, जयपुर : उन्मादी हिंसा (मॉब लिंचिंग) के लिए पूरे देश में बदनाम अलवर जिले में एक और मामला सामने आया है। जिले के किशनगढ़बास थाना क्षेत्र के मुसखेड़ा गांव में शुक्रवार देर रात एक युवक को चोर समझ ग्रामीणों ने पकड़ लिया और फिर लोहे के एंगल से बांध दिया और जमकर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस युवक को थाने ले आयी और पूछताछ के बाद उसे घर भेज दिया।

किशनगढ़बास के थानाध्यक्ष मोहन सिंह गुर्जर ने बताया कि मुसखेड़ा गांव में ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया युवक मुबारिक खान है। उसने पूछताछ में बताया कि वह गांव में अपने रिश्तेदार के यहां गया था, लेकिन ग्रामीणों ने चोर समझकर उसे पकड़ लिया और फिर मारपीट की। इस मामले में पीड़ित और ग्रामीणों की ओर से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। ऐसा लग रहा है कि पहलू खान और हरीश जाटव के मामलों से जूझ रही पुलिस इस मामले को तूल नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने युवक को उसके घर भेज दिया।

आइएलएंडएफएस मामले में पहला आरोपपत्र दाखिल, 570 करोड़ की संपत्तियां हुईं कुर्क

- दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और ब्रसेल्स स्थित कई अचल संपत्तियों को भी कुर्क करने के प्राथमिक आदेश जारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : आइएलएंडएफएस के ऋण भुगतान में चूक के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपना पहला आरोपपत्र दायर कर दिया है। जांच एजेंसी पहले ही इस मामले में 570 करोड़ की संपत्तियां कुक कर चुकी है। अफसरों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में ईडी इस मामले में और आरोपपत्र दायर कर सकती है।

अधिकारियों ने बताया कि मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत मुंबई में विशेष कोर्ट के समक्ष शुक्रवार को आरोपपत्र दायर किया गया। ईडी कई संपत्तियों, बैंक खातों तथा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और ब्रसेल्स स्थित कई अचल संपत्तियों को भी कुर्क करने के प्राथमिक आदेश जारी कर चुकी है। ये अचल संपत्तियां वाणिज्यिक और आवासीय हैं तथा आइएलएंडएफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के निदेशकों रवि पार्थसारथी, रमेश बावा, हरि शंकरन, अरुण साहा और रामचंद करुणाकरन के पास हैं। बता दें कि एजेंसी साहा और करुणाकरन को जून में ही गिरफ्तार कर चुकी है।

अधिकारियों ने कहा कि एयरसेल के संस्थापक सी. शिवशंकरन द्वारा अपने परिजनों तथा समूह की कंपनियों के नाम पर परोक्ष तौर पर रखी गई कुछ संपत्तियों को भी कुर्क किया गया है। कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य करीब 570 करोड़ रुपये है। बता दें कि ईडी ने इस मामले में मनी लांड्रिंग कानून के तहत इस वर्ष फरवरी में मामला दर्ज किया था। उनके खिलाफ यह मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दायर प्राथमिकी के आधार पर दायर किया गया था।

ईडी ने कोर्ट में दायर अपने आरोपपत्र में कहा कि आइएलएंडएफएस का वरिष्ठ प्रबंधक एवं अधिकारी कमीशनखोरी -जैसे गैरकानूनी कृत्य में लिप्त था तथा कंपनी की लागत पर उसने निजी फायदा कमाया। एजेंसी ने कहा, 'आपस में तथा विभिन्न निजी निकायों के प्रमोटरों के साथ आपराधिक साठगांठ के जरिये वे स्थापित नियमों के उल्लंघन में लिप्त थे तथा पहले से कर्ज में फंसी कंपनियों को उन्होंने और बड़े कर्ज दिए। ये कर्ज ऐसी कंपनियों को भी दिए गए जो पहले ही उसकी सहायक कंपनी आइएफआइएन से लिए कर्ज के भुगतान में चूक कर चुकी थीं।'

जांच एजेंसी ने कहा, 'उन्होंने यही आपराधिक तरीका अपनाते हुए शिवशंकरन के साथ साजिश की। शिवा ग्रुप की कंपनियों को कथित तौर पर गलत तरीके से दिए गए कर्जों में से अभी 494 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हो सकी है।' ईडी ने कहा कि वित्त वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान आइएफआइएन का प्रदर्शन नकारात्मक रहा, लेकिन इसके बाद भी प्रबंधन के वरिष्ठ लोगों को कंपनी के कार्य प्रदर्शन पर आधारित भुगतान, डेप्यूटेशन खर्च और कमीशन में भारी वृद्धि की गई।

प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा की कंपनी की 261 करोड़ की संपत्ति कुर्क की पेज>>3

गरिमापूर्ण

यूएनएससी बैठक के बाद चीन-पाक के प्रतिनिधियों ने मैदान छोड़ा, लेकिन डटे रहे भारतीय प्रतिनिधि, पाक पत्रकार ने पूछा- कब शुरू होगी वार्ता, हाथ मिलाकर बोले- आपसे ही करने दीजिए शुरुआत

कूटनीतिक कौशल संग अकबरुद्दीन ने पेश की भारतीयता की मिसाल

संयुक्त राष्ट्र, एजेंसियां : जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मसले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की बंद कमरे में हुई अनौपचारिक बैठक के दौरान कूटनीतिक कौशल दिखाने के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने प्रेस कांफ्रेंस में पाकिस्तानी पत्रकारों से हाथ मिलाकर भारतीयता की मिसाल भी पेश की। कूटनीतिक नीरसता के विपरीत वह पत्रकार वार्ता में राजनेताओं की तरह विनोदप्रिय और मिलनसार दिखे। सोशल मीडिया में उनके शांत, सौम्य और गरिमापूर्ण व्यवहार की जमकर सराहना हो रही है।

यूएनएससी की एक घंटे चली बैठक के बाद संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत झांग जुन और पाकिस्तानी प्रतिनिधि मलीहा लोधी ने अपने बयान पढ़े और बिना सवालों का जवाब दिए चले गए। इसके बाद अकबरुद्दीन आए और भारत का रुख स्पष्ट करने के बाद पत्रकारों से कहा, 'अगर आपमें से कोई सवाल पूछना चाहता है तो एक सच्चे लोकतंत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मैं तैयार हूं। मैं यहां आए अपने दोनों पूर्ववर्तियों से पांच गुना ज्यादा सवालों के जवाब दूंगा।' इसके बाद उन्होंने पहले पूछने का मौका पाक पत्रकारों को दिया।

संयुक्त राष्ट्र में पत्रकार वार्ता के दौरान सैयद अकबरुद्दीन कुछ इस अंदाज में दिखे। (फाइल फोटो) एएनआइ

एक वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा, 'आप पाक के साथ बातचीत कब शुरू करेंगे?' इस पर अकबरुद्दीन ने कहा, 'आपके पास आकर मुझे ही इसकी शुरुआत करने दीजिए।' इसके बाद वह मंच से उतरकर पाकिस्तानी पत्रकारों के पास पहुंचे और मुस्कराते हुए उनसे हाथ मिलाया। इसके बाद कहा, 'हम यह कहकर पहले ही दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके हैं कि हम शिमला समझौते पर प्रतिबद्ध हैं। अब पाक की ओर से जवाब का इंतजार है।' एक पत्रकार ने सवाल किया, 'पड़ोसियों के बीच कोई संवाद क्यों नहीं है? भारत ने वार्ता के अनुरोध का कोई जवाब क्यों नहीं दिया?' इस पर अकबरुद्दीन ने कहा, 'वार्ता शुरू करने के लिए आतंकवाद को रोकिए। जब देश आपस में बात करते हैं तो उसका सामान्य कूटनीतिक तरीका होता है, लेकिन सामान्य देश अपना मकसद हासिल करने के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल नहीं करते। जब आतंकवाद फलफूल रहा हो तो कोई भी लोकतांत्रिक देश वार्ता के लिए तैयार नहीं होगा।' इस दौरान उन्होंने अपने राजनयिक करियर में पाकिस्तान के रहे साथ अनुभवों को भी याद किया। उन्होंने कहा, 'मैं इस्लामाबाद गए कई प्रतिनिधिमंडलों का सदस्य रहा हूं। मैं खुद इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिक के तौर पर काम कर चुका हूं।' एक पाकिस्तानी पत्रकार को तो अकबरुद्दीन ने अपनी हाजिरजवाबी से उसके ही सवाल में घेर लिया। जैसे ही पाकिस्तानी पत्रकार ने अनुच्छेद 370 का जिक्र करते हुए कहा, 'यह भारत का अंदरूनी मसला हो सकता है...' इस पर अकबरुद्दीन ने तत्काल कहा, 'यह मानने के लिए धन्यवाद।'

पत्रकार ने अपना सवाल जारी रखते हुए कहा, 'अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित किया गया था...' अकबरुद्दीन ने फिर कहा, 'धन्यवाद, भारत द्वारा (प्रतिष्ठापित)।' जब पत्रकार ने कहा, कश्मीर में लगाए गए प्रतिबंध सच्चे लोकतंत्र के रूप में भारत की छवि को धूमिल करते हैं। अकबरुद्दीन ने कहा, 'लोकतंत्र की समृद्धि के लिए लोक व्यवस्था जरूरी है। लोक व्यवस्था के बिना लोकतंत्र कार्य नहीं कर सकता। वहां कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, हम इसे स्वीकार करते हैं और उनमें ढील भी दी जा रही है।'

मुंह की खाने के बावजूद बाज नहीं आएंगे पाकिस्तान और चीन पेज>>13

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच उत्तराखंड में स्थापित करेगा राष्ट्रवादी मदरसा

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली

- देहरादून के पास प्रस्तावित मदरसे में 500 छात्रों के लिए होगी सुविधा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रभावित मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) जल्द ही राष्ट्रवाद की शिक्षा देने वाले मदरसे की स्थापना करेगा। यह मदरसा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के पास खोला जाएगा। इसके लिए जरूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तकरीबन तीन एकड़ जमीन इसके लिए उपलब्ध है। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद नवंबर से मदरसे के भवन का निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। इसमें तकरीबन 500 छात्रों के पढ़ने और रहने की व्यवस्था होगी। एमआरएम की योजना इसी तरह के मदरसे प्रयागराज व हैदराबाद जैसे शहरों में भी स्थापित करने की है।

एमआरएम के अध्यक्ष अफजाल अहमद ने बताया कि देश में मदरसों की शिक्षा को अच्छा नहीं माना जाता है। वहां धार्मिक शिक्षा में कट्टरता को बढ़ावा दिए जाने का आरोप लगता है। ऐसे में मुस्लिम छात्रों को राष्ट्रवाद और आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए आधुनिक मदरसों के स्थापना की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन मदरसों में कक्षा 1 से 12 वीं तक के छात्रों की पढ़ाई होगी। इसमें धार्मिक व आधुनिक शिक्षा की पढ़ाई के साथ राष्ट्रवाद का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। जरूरी औपचारिकताओं के लिए उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से संपर्क किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मदरसे का संचालन एमआरएम और स्थानीय लोगों की समिति करेगी, जबकि इसके निर्माण में जागरूक मुस्लिम समाज के लोगों के साथ संगठन से जुड़े लोग आगे आ रहे हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक इंद्रेश कुमार के मार्गदर्शन वाले मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को मुस्लिम समाज में सुधार आंदोलन के लिए जाना जाता है। तीन तलाक को इस संगठन ने मुखर तरीके से उठाया था। यह संगठन देश में टकराव को खत्म करने के लिए राममंदिर निर्माण के पक्ष में भी है।

29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 25.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ राजधानी में शनिवार को। औसत बारिश 1.4 मिमी दर्ज हुई। रविवार को भी दिनभर बादल छाए रहने और हल्की बारिश के साथ तेज हवा चलने के आसार हैं।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 18 अगस्त 2019

कपिल मिश्रा व ऋचा पांडेय भाजपा में शामिल

बदला पाला ▶ दिल्ली सरकार में जल मंत्री रह चुके हैं मिश्रा, हाल ही में विधानसभा की सदस्यता हुई है रद

मनोज तिवारी ने कहा, केजरीवाल के तानाशाही रवैये से सभी लोग परेशान हैं

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार के पूर्व जल मंत्री कपिल मिश्रा और आम आदमी पार्टी (आप) की प्रवक्ता व महिला इकाई की अध्यक्ष ऋचा पांडेय मिश्रा ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली भाजपा के प्रभारी श्याम जाजू, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी, नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय एवं प्रदेश सदस्यता प्रमुख एवं महामंत्री कुलजीत सिंह चहल ने उनका स्वागत किया।

जाजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे, उसी दिन मिश्रा ने उनका विरोध शुरू कर दिया था। उन्होंने हमेशा दिल्ली सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध किया।

मनोज तिवारी ने कहा कि आप जिस उद्देश्य को लेकर बनी थी, आज वह मकसद ही खत्म हो गया है। केजरीवाल के तानाशाही रवैये और जनविरोधी नीतियों से न सिर्फ दिल्ली के लोग परेशान हैं, बल्कि उनकी पार्टी में रहने वाले लोग भी एक-एक करके उनका साथ छोड़ रहे हैं।

पार्टी मुख्यालय में मनोज तिवारी, श्याम जाजू, विजय गोयल की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए कपिल मिश्रा और ऋचा पांडेय मिश्रा। ध्रुव कुमार

कपिल मिश्रा ने कहा कि वह भाजपा में इसलिए शामिल हो रहे हैं, जिससे कि खुलकर भारत माता की जय बोल सकें और भ्रष्टाचार व टुकड़े-टुकड़े गैंग के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। उन्होंने कहा कि दिल्ली से नकारात्मक राजनीति को दूर करने की जरूरत है और यह काम सिर्फ नरेंद्र मोदी के साथ चलकर ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि विधायक होने से ज्यादा गर्व की बात भाजपा कार्यकर्ता होने में है। उन्होंने कहा कि उनकी माता (पूर्व महापौर अन्नपूर्णा मिश्रा) ने कई बार समझाया था, लेकिन ठोकर खाने के बाद उनकी बात समझ में आई। मौके पर मौजूद उनकी माता भावुक हो गईं। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करने की वजह से आप विधायक सौरभ भारद्वाज की शिकायत पर मिश्रा की विधानसभा सदस्यता रद कर दी गई है, जिसे उन्होंने अदालत में चुनौती भी दी है।

केजरीवाल को महिला विरोधी बताते हुए ऋचा पांडेय ने कहा कि आप में अपनी बात कहने की भी आजादी नहीं है। अब भाजपा में शामिल होकर उन्हें लग रहा है कि जिस वैकल्पिक राजनीति की तलाश में वह थीं, भाजपा में आकर वह पूरी हो गई है।

कपिल मिश्रा आप में रहते हुए भाजपा के एजेंट थे : भारद्वाज

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा में शामिल होने वाले पार्टी के पूर्व विधायक कपिल मिश्रा को भाजपा का एजेंट बताया है। ग्रेटर कैलाश से आप विधायक और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिस दिन यह बात सामने आई थी कि कपिल मिश्रा ने दिल्ली जल बोर्ड में गड़बड़ी करके पार्टी को निगम चुनाव में हराने का षडयंत्र रचा था, उसी समय यह पता चल गया था कि वह पार्टी में रहकर भाजपा के एजेंट के तौर पर कार्य कर रहे हैं। मंत्री पद से हटाए जाने पर उन्होंने कई अनर्गल आरोप भी लगाए थे। उसी समय पार्टी ने कहा था कि वह भाजपा की लिखी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन तब वह कसम खाते थे कि कभी भाजपा में नहीं जाएंगे। यही नहीं पिछले सप्ताह ही उन्होंने हाई कोर्ट में दावा किया था कि इनका भाजपा से कोई लेना-देना नहीं है। भारद्वाज ने कहा कि हमें खुशी है कि अंत में इनका असली चेहरा लोगों के सामने आ गया। यह भी पता चल गया कि उनके सभी नाटक और पिछले आरोप भाजपा द्वारा प्रायोजित और निर्देशित थे। कपिल एक हल्के और झूठे नेता हैं, यह बात दिल्ली की जनता भी जान गई है।

सौरभ भारद्वाज। फाइल फोटो

दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री व आप नेता राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि आप में कार्यकर्ताओं का सबसे अधिक सम्मान है। ऋचा पांडेय ने जो आरोप लगाए हैं, वह बेबुनियाद हैं। पार्टी ने मुझ जैसे एक आम कार्यकर्ता को सम्मान दिया और सरकार में मंत्री बनाया है, जो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वह व्यक्तिगत लाभ के लिए भाजपा में गई हों, मगर आप में उनके सम्मान में कोई कमी नहीं थी। पार्टी छोड़कर भाजपा में जाने वाले ज्यादातर लोग पहले से ही भाजपा के लिए काम कर रहे थे।

एक लाख से ज्यादा व्यावसायिक वाहनों पर लगे आरएफआइडी टैग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- 23 अगस्त के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी समय सीमा
- 19 स्थानों पर हो रही टैग की बिक्री

दिल्ली में प्रवेश के लिए व्यावसायिक वाहनों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआइडी) टैग अनिवार्य करने की आखिरी तारीख 23 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इसके बाद से बिना आरएफआइडी टैग के व्यावसायिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसे अनिवार्य किए जाने के बाद टैग की बिक्री भले ही बढ़ गई है, लेकिन अभी भी ज्यादा संख्या में टैग लेने वाहन चालक नहीं पहुंच रहे हैं। पहले शुक्रवार को आखिरी तारीख होने की वजह टोल नाकों पर व्यावसायिक वाहन चालकों की भीड़ जरूर लग गई थी। हालांकि आखिरी तारीख को 23 अगस्त तक बढ़ाने के बाद अब फिर स्थिति सामान्य हो गई है। शनिवार को सात हजार के करीब टैग की बिक्री की गई।

निगम के मुताबिक एक लाख से ज्यादा व्यावसायिक वाहन चालकों ने आरएफआइडी टैग ले लिए हैं। निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार हमारी कोशिश है कि हम ट्रकों को सबसे पहले आरएफआइडी टैग से लैस करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रकों से ही पर्यावरण क्षतिपूर्ति टैक्स वसूला जाता है। ऐसे में मैनुअल टोल वसूली में सबसे ज्यादा समय ट्रकों से टोल वसूली के लिए लगता है। टैक्सी सीएनजी से चलती है, तो इनसे केवल टोल ही वसूला जाता है। निगम ने कहा कि सोमवार तक दो लाख और टैग की आपूर्ति हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि दिल्ली के 13 टोल नाकों पर प्रवेश के लिए व्यावसायिक वाहनों के लिए आरएफआइडी टैग 23 अगस्त की रात 12 से अनिवार्य कर दिया जाएगा। इससे पहले 16 अगस्त आखिरी तारीख तय की गई थी। इससे एकदम से वाहनों की भीड़ टोल पर बढ़ गई थी। इसलिए निगम ने आखिरी तारीख बढ़ा दी थी। निगम का कहना है कि इसके बाद आखिरी समयसीमा नहीं बढ़ाई जाएगी।

बॉर्डरों पर है अफरा-तफरी का माहौल : 23 अगस्त से आरएफआइडी टैग अनिवार्य करने के मसले पर ट्रांसपोर्ट यूनियन ने कहा है कि टैग वितरण की पर्याप्त सुविधा न होने की वजह से व्यावसायिक वाहन मालिकों और चालकों पर अफरातफरी का माहौल है। लोगों को टैग लेने के लिए आठ-आठ घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है।

ट्रांसपोर्टरों से बात करनी चाहिए थी : दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने कहा कि ट्रांसपोर्टरों के पास 10 से लेकर 1500 तक वाहन हैं। ऐसे में एक समय में एक ही को टैग दिया जा रहा है। इसके अलावा टैग के लिए मूल वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, लेकिन कई गाड़ियों के पुलिस के चालान किए हैं और मूल प्रमाण पत्र जमा हैं। ऐसे में टैग कैसे लिया जा सकेगा। यूनियन का कहना है कि यह फैसला लेने से पहले ट्रांसपोर्टरों से राय लेनी चाहिए थी।

शाहबेरी प्रकरण में प्राधिकरण ने भी दस अफसरों के नाम शासन को भेजे

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

- 2011 से 2018 तक तैनात रहे अधिकारी व कर्मियों के नाम शामिल
- 22 पुलिस कर्मियों के पहले ही भेजे जा चुके हैं सरकार को नाम

शाहबेरी गांव में अवैध फ्लैटों के निर्माण के मामले में पुलिस और प्राधिकरण अधिकारियों की भी गर्दन फंसना तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले पुलिस और प्राधिकरण के उन अधिकारियों के नाम शासन को भेजने के निर्देश दिए थे, जिनके कार्यकाल में अवैध निर्माण हुआ। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 10 अधिकारी व कर्मचारियों के नाम शासन को भेजे हैं। इनमें 2011 से 2018 के बीच तैनात उन अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम हैं, जिनके ऊपर अवैध नाम रोकने की जिम्मेदारी थी।

शाहबेरी गांव में 2009 में जमीन का अधिग्रहण किया गया था। किसानों की याचिका पर 2011 में इलाहाबाद हाइ कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण रद कर दिया। प्राधिकरण ने फिर से जमीन अधिग्रहण करने के लिए 2013 में शासन को प्रस्ताव भेजा। अधिग्रहण की कार्रवाई धारा-4 व 6 आगे बढ़ ही रही थी कि गांव के किसानों 31 याचिकाएं दायर कर अधिग्रहण प्रक्रिया को रोकने की मांग की। 16 अक्टूबर 2014 को कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। इससे प्राधिकरण द्वारा फिर से की जा रही अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी तरह से ठप हो गई। उधर, न्यायिक प्रक्रिया में समय लगने का फायदा उठाते हुए किसानों ने निजी बिल्डरों को जमीन बेचनी शुरू कर दी। निजी बिल्डरों ने औद्योगिक विकास अधिनियम भवन नियमावली का पालन किए बिना फ्लैटों का निर्माण कर खरीदारों को बेच दिए। भवनों का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं कराया गया।

सुरक्षा की भी कोई गारंटी नहीं दी गई। 2011 के बाद प्राधिकरण ने शाहबेरी में कई बार अवैध निर्माण को हटाया, लेकिन बिल्डरों ने फिर से निर्माण कर लिया। इसके बाद प्राधिकरण ने 2017 से 2018 के बीच 181 लोगों के खिलाफ कठोर धाराओं में कुल 44 एफआइआर थाने में दर्ज कराई। निर्माण रोकने में लापरवाही बरतने पर शासन के निर्देश पर प्रबंधक स्तर के दो अधिकारियों को निलंबित किया गया। तीन सुपरवाइजरों की सेवाएं समाप्त की गईं।

प्राधिकरण ने अब दो सर्वे अमीनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। आठ अधिकारियों के नाम शासन को भेजे गए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई का निर्णय सरकार लेगी।

गत वर्ष दो इमारत गिरने से हो गई थी नौ लोगों की मौत : बिल्डरों ने प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना करीब दस हजार फ्लैटों का निर्माण कर दिया। अधिकांश इमारत रेत की दिवार पर खड़ी हैं। बुनियाद कमजोर होने की वजह से गत वर्ष 17 जुलाई को छह-छह मंजिला दो इमारत जमींदोज हो गई थीं। इनमें नौ लोगों की दबने से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पुलिस-प्रशासन ने 20 बिल्डर व 243 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस, प्रशासन और प्राधिकरण की कार्रवाई से मुख्यमंत्री नाराज बताए जाते हैं। उन्होंने प्राधिकरण और पुलिस से उन अधिकारियों के नामों की सूची मांगी थी, जिनके कार्यकाल में शाहबेरी में अवैध इमारतें खड़ी हुईं। दो दिन पहले 22 पुलिस कर्मियों के नाम को भेजे गए थे।

इनमें अधिकांश नाम बिसरख थाने में तैनात रहे प्रभारी, चौकी इंचार्ज व बीट कांस्टेबल के नाम हैं। प्राधिकरण के जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी अवैध निर्माण को रोकने की थी, उनके नाम भी शानिवार को शासन को भेज दिए गए। सूत्रों की मानें तो सरकार इन अधिकारियों के खिलाफ अवैध निर्माण न रोकने के आरोप में कार्रवाई कर सकती है।

सभी वर्ग के छात्रों से चर्चा करके एनएसयूआइ जारी करेगी घोषणापत्र

जासं, नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में छात्र संघ चुनाव की गतिविधियां आने वाले दिनों में तेज होने वाली हैं। डीयू के कुलपति प्रो. योगेश त्यागी की तरफ से डीयू छात्र संघ चुनाव (डूसू) की चुनाव समिति का गठन कर दिया गया है। माना जा रहा है कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में डूसू चुनाव को आयोजित किया जा सकता है। वहीं नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआइ) की तरफ से छात्र संघ चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है कि वह डीयू में पढ़ रहे सभी वर्ग के छात्रों से संवाद करेगी। उनसे डीयू के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के बाद अपना मेनिफेस्टो जारी करेगी। साथ ही डीयू की छात्राओं के लिए भी एनएसयूआइ अलग से घोषणापत्र जारी करेगी।

एनएसयूआइ के प्रदेश अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने बताया कि आने वाले दिनों में पूर्वांचल के छात्रों के साथ और उत्तर-पूर्व भारत से आए छात्रों के साथ संवाद किया जाएगा। हम छात्रों से पूछेंगे कि वे डीयू में किन समस्याओं, मुद्दों से जूझ रहे हैं। वे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें वे चाहते हैं कि डीयू प्रशासन उन पर ध्यान दे। ऐसे मुद्दों को घोषणापत्र में शामिल करेंगे। इसके साथ ही 26 से 27 अगस्त के दौरान डीयू में महिलाओं के लिए एक अधिवेशन का भी छात्र संगठन आयोजन करेगा। इसमें महिलाओं के मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। उन्होंने बताया कि मेट्रो का किराया सहित अन्य मुद्दों को घोषणापत्र में शामिल किया जाएगा।

आग पर काबू पाने में लाचार दिखा प्रशासन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

एम्स का सालाना बजट करोड़ों रुपये का होता है जिसमें से एक बड़ा भाग सुरक्षा के ऊपर खर्च होता है। लेकिन आए दिन देश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक एम्स में आग लगने जैसी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। तीन से ज्यादा घंटों तक एम्स की टीचिंग बिल्डिंग में आग लगी रही, लेकिन फायर विभाग व एम्स की सुरक्षा व्यवस्था उस पर काबू नही पा सकी। बिल्डिंग की पांचवी मंजिल पर लगी आग को बुझाने के लिए न ही एम्स की बिल्डिंग में लगा फायर सिस्टम काम करता दिख रहा था और न ही फायर विभाग के पास जल्द वहां पहुंचने की कोई व्यवस्था थी।

परिसर में बनी पार्क की दीवार के कारण नहीं जा पा रही थी फायर ब्रिगेड : एम्स परिसर में बनी रोड से टीचिंग बिल्डिंग की तरफ जाने वाले रास्ते पर पार्क बना हुआ है। इसकी दीवार के कारण फायर ब्रिगेड मुड़ नही पा रही थी और एक बारी में एक की गाड़ी को अंदर जाने का रास्ता मिल पा रहा था। इसके कारण फायर विभाग को आग पर काबू पाने में काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। पतली गली से फायर ब्रिगेड को आने-जाने में ज्यादा समय लग रहा था। समय पर पहुंचने के बाद भी फायर की गाड़िया कम जगह होने के कारण सड़क पर रुकी रहीं।

बिल्डिंग में लगा फायर सिस्टम नही कर रहा था काम : सबसे नामी अस्पतालों में से एक एम्स की टीचिंग बिल्डिंग में दुसरी मंजिल पर लगी आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। पांचवीं मंजिल पर पहुंची आग साढ़े सात बजे के बाद भी लगी रही। इसका सबसे बड़ा कारण एम्स में लगा नाकाम फायर सिस्टम है। पांचवीं मंजिल पर ऐसी कोई भी व्यवस्था नही थी कि आग बुझाई जा सके।

धरा रहा गया एम्स का सर्कुलर : 24 मार्च को एम्स में लगी आग में कई ऑपरेशन थियेटर जल कर राख हो गए थे। इसके कारण कई दिनों तक एम्स की सेवा प्रभावित रही थी। हादसे के बाद सुरक्षा को देखते हुए व आग से बचाव के लिए एम्स प्रशासन की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया था ताकि आने वाले समय में एम्स परिसर को ऐसे हादसों से बचाया जा सके। लेकिन शनिवार को लगी आग से साफ जाहिर होता है कि एम्स प्रशासन का सर्कुलर जमीनी स्तर पर कितना काम कर रहा है।

एम्स में कब-कब हुई आगजनी की घटनाएं

01 जुलाई 2019 ट्रॉमा सेंटर परिसर में एक एटीएम व कैंटीन में आग लगी।

30 मई 2019 : नवनिर्मित प्राइवेट वार्ड में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी।

24 मार्च 2019 : ट्रॉमा सेंटर के बेसमेंट में स्थित ऑपरेशन थियेटर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई।

एम्स के टीचिंग ब्लॉक में लगी आग के बाद शीशे तोड़ते व आग बुझाते दमकलकर्मी। जागरण

बिल्डिंग में रखे केमिकल जलने के कारण हुई परेशानी

जासं, दिल्ली : एम्स की टीचिंग ब्लॉक में लैब व रिसर्च रूम बने हुए हैं जिनमें कई प्रकार के केमिकल रखे रहते हैं। साथ ही ब्लड व स्पर्म सैंपल रखे रहते हैं। बिल्डिंग में लगी आग ने सभी प्रकार के केमिकल को भी अपनी चपेट में ले लिया। इसके कारण आग से उठने वाला धुआं और भी हानिकारक हो गया। इसके कारण आग पर नियंत्रण पाने आए दमकल विभाग के कर्मचारियों, अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों के साथ अन्य लोगों को आंखों में जलन, सिर में दर्द, उल्टी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा। धुएं की चपेट में आए कई लोगों की तबीयत खराब हो गई। उन्हें तुरंत वहां से ले जाया गया। लोगों ने बताया कि आग के पास जाने से लगने वाले धुएं के कारण उन्हें चक्कर आ रहे थे। कई कर्मचारी आपातकालीन स्थिति होने के कारण मास्क नहीं बांध पाए। उन्हें इस तरह की परेशानी का ज्यादा सामना करना पड़ा। अस्पताल व अग्निशमन विभाग की तरफ से आग पर काबू पाने में लगे हुए सभी लोगों को मास्क दिए जा रहे थे, लेकिन कई लोग जल्दबाजी के कारण मास पहनना भूल गए।

एम्स को दो बार जारी करने पड़े बयान, मरीजों को कोई नुकसान नहीं

नई दिल्ली : एम्स में आग की घटना इतनी भयानक थी कि एम्स को दो बार इस पर बयान जारी करने पड़े। एम्स के मुताबिक शाम पांच बजे के करीब टीचिंग ब्लॉक में आग लगी। हालांकि इस घटना में किसी मरीज को कोई नुकसान नहीं हुआ है। एहतियातन एबी विंग के सभी वार्ड में दाखिल मरीजों को दूसरे ब्लॉक में अस्थाई तौर स्थानांतरित किया गया है। प्रशासन के मुताबिक रविवार को वापस इन मरीजों को एबी विंग वार्डों में ही शिफ्ट कर दिया जाएगा। यह विंग एम्स का मुख्य अस्पताल का हिस्सा है। इसमें 997 बिस्तर हैं। कितने मरीज इन वार्डों में दाखिल थे और कितनों को दूसरी वार्डों में स्थानांतरित किया गया है, इसकी जानकारी एम्स ने नहीं दी है। माना जा रहा है ऐसे मरीजों की संख्या सैकड़ों में हो सकती है। एम्स में एबी ब्लॉक में मरीजों को स्थानांतरित करने पर तीमारदारों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। एम्स के अनुसार 011-26593308 पर लोग जानकारी ले सकते हैं।

हालातों पर नजर बनाए हुए थे स्वास्थ्य मंत्री : एम्स में आग की घटना की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री खुद निगरानी कर रहे थे। पल-पल के हालातों पर पूरी नजर थी। एम्स ने बताया है कि घटना पर डॉ. हर्षवर्धन ने प्रशासन को विशेष फायर ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एम्स को यह प्रक्रिया निरंतर अपनाने को भी कहा है।

650 करोड़ रुपये की जमीन से कब्जा हटाया

जागरण संवाददाता, नोएडा : नोएडा प्राधिकरण ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सोरखा जाहिदाबाद में कब्जा किए जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटा दिया। यहां दबंगों ने करीब एक लाख 30 हजार 683 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा कर लिया था। जमीन की कीमत करीब 650 करोड़ बताई जा रही है। प्राधिकरण के प्रवर्तन दल ने भूलेख, जिला प्रशासन व पुलिस मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्राधिकरण ने सुबह करीब नौ बजे कार्रवाई शुरू की और दोपहर एक बजे तक चली। भूमि पर कब्जा करने वाले आरोपितों के खिलाफ कोतवाली सेक्टर-49 में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। प्राधिकरण ने जिलाधिकारी बीएन सिंह को पत्र लिख कर आरोपितों का नाम भू-माफिया की सूची में शामिल करने की मांग की है।

अधिकारियों का कहना है कि इस जमीन पर विक्रम पहलवान, सोनू पहलवान, बिरजू, गजराज, प्रेमपाल आदि निवासी सर्फाबाद ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। आरोपितों ने जमीन पर अवैध निर्माण कर करीब 30 पक्की दुकानें बना दी थीं और अन्य निर्माण था।

सिर चढ़कर बोल रही वीआइपी नंबर की चाहत

वीके शुक्ला, नई दिल्ली

कार नहीं है तो क्या हुआ? हम अपना शौक मोटरसाइकिल में भी तो पूरा कर सकते हैं। जी हां, दिल्ली के ऐसे तमाम लोग मोटरसाइकिल के लिए ही वीआइपी (फैंसी) नंबर लेकर अपना शौक पूरा कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोटरसाइकिल का एक नंबर एक लाख में बिक गया है यानी यह नंबर एक सामान्य मोटरसाइकिल की कीमत से करीब दो गुना है। ऐसे ही अन्य नंबर हैं जो महंगे दामों पर दो पहिया के लिए बिक रहे हैं। दिल्ली में पहली बार दो पहिया वाहनों के लिए वीआइपी नंबर नीलामी के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं। इसके लिए ऑनलाइन बोली लगती है।

जुलाई के पहले सप्ताह में नई पॉलिसी लागू की गई है। इसके तहत चार पहिया वाहनों के लिए पांच लाख, तीन लाख, दो लाख व डेढ़ लाख से नीलामी शुरू होती है। दो पहिया वाहनों के लिए 50 हजार, 30 हजार 20 हजार और 15 हजार से नीलामी शुरू होती है। नीलामी में भाग लेने के लिए सोमवार, मंगलवार व बुधवार को पंजीकरण होता है। गुरुवार और शुक्रवार को बोली लगती है। अभी तक महीने के पहले सप्ताह में ही नीलामी होती थी मगर अब महीने के अंतिम सप्ताह में भी नीलामी की जाएगी।

कारों के लिए करीब एक साल से एक नंबर बंद है। इसकी नीलामी नहीं हो रही है। इसके चलते अब लोग मोटरसाइकिल में ही एक नंबर लेने का शौक पूरा कर रहे हैं। मोटरसाइकिल के लिए पांच जुलाई को पहली बार हुई नीलामी में 0001 नंबर 90 हजार का बिका है। दूसरी बार 26 जुलाई को नीलामी हुई तो एक नंबर एक लाख का बिका। हालांकि नौ अगस्त को हुई नीलामी में एक नंबर नीलामी के लिए नहीं आया। इस तारीख में दो नंबर की नीलामी बोली 30 हजार थी। यह नंबर 3. 30 लाख में बिका है। इस राशि की बोली लगाने वाले ने अभी तक यह राशि नहीं जमा कराई है। विभाग मान रहा है कि इस बोली में राशि गलती से भरी गई है क्योंकि दो नंबर के लिए इतनी राशि के लिए बोली लगाया जाना संभव नहीं दिख रहा है।

कारों के नंबरों के लिए भी कम शौकीन नहीं लोग

नौ अगस्त को कार के लिए सबसे अधिक कीमत में 1111 नंबर बिका है। इस नंबर के लिए दो लाख की बोली निर्धारित थी। मगर यह नंबर चार गुना अधिक राशि में बिका। इस नंबर के लिए आठ लाख 20 हजार की बोली लगी। यह अंतिम बोली थी। इसके बाद नंबर खरीद लिया गया। वहीं 7777 नंबर दो लाख 80 हजार, 9999 नंबर दो लाख 50 हजार और सात नंबर तीन लाख 60 हजार में बिका है। 26 जुलाई को हुई नीलामी में सात नंबर चार लाख 70 हजार में बिका। इससे पहले 26 जुलाई को सात नंबर तीन लाख 79 हजार और नौ नंबर तीन लाख 60 हजार में बिका था। नंबरों की इस नीलामी से परिवहन विभाग ने अभी तक करीब 90 लाख का राजस्व इकट्ठा किया है।

▶ मोटरसाइकिल का एक नंबर एक लाख में बिका

लंबा इंतजार

34 साल से आशियाना मिलने का इंतजार कर रहे 19 हजार से ज्यादा आवेदक, डीडीए, नगर निगम, दिल्ली सरकार और डूसिब के लगा रहे हैं चक्कर

आशियाने की आस में थम रहीं सांसें

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

2022 तक हर परिवार को घर देने की चर्चाओं और घोषणाओं के बीच दिल्ली के 19 हजार से ज्यादा निवासी ऐसे भी हैं, जिन्हें बीते तीन दशक से आशियाना मिलने का इंतजार है। इस इंतजार में इनकी सांसें भी थमने लगी हैं। कई आवेदक तो इंतजार करते हुए दुनिया से विदा हो गए, तो हजारों वृद्धावस्था की दहलीज पर खड़े सरकार का मुंह ताक रहे हैं। लेकिन सरकारी विभागों की आपसी रस्साकशी और लेट लतीफी इनके इंतजार को खत्म नहीं होने दे रही। इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि आवेदकों की पथराई आंखों में जहां अभी भी एक आस है, वहीं सरकारी अधिकारियों को तो यह भी याद नहीं कि कौन सी योजना थी जिसके तहत ये आवेदन किए गए थे।

जानकारी के मुताबिक वर्ष 1985 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की स्लम विंग ने स्लम व अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए एक आवासीय योजना निकाली थी। स्लम एरिया (इंप्रूवमेंट एंड क्लीयरेंस) एक्ट 1956 के तहत निकाली गई इस योजना में 27,693 लोगों ने आवेदन किया। इन सभी को 26 वर्ग मीटर का एक मंजिला मकान बनाकर दिए जाने का प्रावधान था। लेकिन 2002 तक 5,662 आवेदकों को केवल प्लॉट मिला, मकान नहीं। 2,550 आवेदकों ने थक हारकर अपना आवेदन ही वापस ले लिया, जबकि 19,481 आवेदक अभी तक अपने आशियाने के आवंटन का इंतजार कर रहे हैं। डीडीए ने यह योजना क्रियान्वयन के लिए नगर निगम के स्लम विभाग को सौंप दी और नगर निगम ने दिल्ली सरकार के हवाले कर दिया। फिलहाल यह योजना दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) के पास है। हैरत की बात यह इस योजना में सरकारी विभागों की खींचतान के चलते गत 17-18 साल से योजना के नियम कायदों में ही बदलाव किया जाता रहा है।

आवेदक श्रवण कुमार लांबा, रमेश कुमार वर्मा और बृजमोहन प्रभाकर का कहना है कि डूसिब की भूमिका केवल क्रियान्वयन एजेंसी की है, लेकिन वह काम इस तरह से कर रहा है जैसे योजना उसी की हो। मई 2018 में विज्ञापन जारी कर डूसिब ने सूचीबद्ध आवेदकों के लिए नई-नई शर्तें लगा दीं और जिन्हें नियत समय में पूरा न किए जाने पर आवेदकों के आवेदन रद करने शुरू कर दिए गए। अब आवेदकों से पुनः आवेदन शुल्क सहित 50 हजार रुपये सुरक्षा राशि, एसडीएम द्वारा जारी तीन लाख से कम सालाना आय का प्रमाण पत्र और एफीडेविट मांगा जा रहा है। आवेदकों के मुताबिक जो मकान ऑफर किए जा रहे हैं, उनकी कीमत भी 13 लाख रुपये मांगी जा रही है, जबकि विभाग की वेबसाइट पर आज भी उनकी लागत 5.34 लाख ही है।

> इस योजना में आवेदकों के साथ उपहास ही किया गया है। उन्हें मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही है, वह अलग। डीडीए के अध्यक्ष और उपराज्यपाल को ज्ञापन देकर मदद और डीडीए को निर्देश देने की गुहार लगाई गई है।
>
> **-केके चांदना, अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ 1985 हाउसिंग स्कीम**

> इस योजना की जानकारी नहीं है। पूरा मामला पता करके ही देखा जाएगा कि इसमें क्या कुछ किया जा सकता है।
>
> **-तरुण कपूर, उपाध्यक्ष, डीडीए**

रविदास मंदिर अभी भी बना दे केंद्र सरकार : गौतम

राज्य ब्यूरो,नई दिल्ली : तुगलकाबाद स्थित संत रविदास मंदिर को गिराए जाने पर आप ने फिर से केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। पार्टी ने कहा है कि अभी भी समय है, तोड़े गए मंदिर को फिर से बना दें। मंदिर तोड़े जाने से देशभर में दलित समाज में रोष है। मंदिर तोड़े जाने के विरोध में पार्टी की एससी-एसटी विंग रविवार को भाजपा कार्यालय का घेराव करेगी।

पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता कर दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि 12 अगस्त को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर मांग की थी कि मंदिर को फिर से उसी जगह स्थापित किया जाए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। यह भाजपा की दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त को संत रविदास का मंदिर डीडीए ने गिरा दिया था। यदि भाजपा और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी चाहते तो वह मंदिर को बचा सकते थे। इस मौके पर पार्टी एससी-एसटी विंग के अध्यक्ष व निगम पार्षद कुलदीप कुमार ने कहा कि डीडीए ने मंदिर तोड़ने का जो काम किया है, उसका वह विरोध करेंगे।

सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता : रंजन गोगोई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

द्वारका सेक्टर-14 स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के सातवें वार्षिक दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मास्टर ऑफ लॉ के 78, बीए एलएलबी के 83 व छह पीएचडी छात्रों को डिग्री दी गई। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ छात्रों को मेडल व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, यूनिवर्सिटी के कुलपति व हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल, दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव व यूनिवर्सिटी के उप कुलपति (प्रो.) डॉ. रनबीर सिंह, विश्वविद्यालय के डीन प्रो. उपेंद्र बक्सी मौजूद रहे।

इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने छात्रों को संबोधित करते हुए उन्हें दीक्षा समारोह की बधाई दी। उन्होंने कहा कि सफलता प्राप्त करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बीए एलएलबी कोर्स पांच वर्ष का है। इस दौरान छात्रों को हर क्षेत्र के बारे में कानूनी जानकारी दी जाती है। इससे छात्र जब डिग्री लेकर बाहर निकलते हैं तो उनके पास अपने दायित्व को निभाने के लिए पूरी जानकारी होती है। उन्होंने छात्रों से कहा कि डिग्री को सिर्फ एक पेपर नहीं समझें। इसे अपना दायित्व समझें। उन्होंने कहा कि वकील का दिमाग हर समय खुला रहना चाहिए। इस प्रोफेशन में यह बहुत जरूरी होता है। डॉ. रनबीर ने बताया कि आज दिल्ली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भारत की दूसरी सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है। यह मात्र एक ग्रेड से बेंगलुरू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पीछे है। साथ ही इन्होंने समय के साथ यूनिवर्सिटी के लिए क्या-क्या चुनौतियां है, उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज हमें गर्व है कि हमारे विश्वविद्यालय से पढ़े हुए छात्र बड़े-बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं।

04 लाख करोड़ रुपये आमदनी हुई 2018-19 में भारत के किसानों को गेहूं और चावल की फसल से। इसी समयावधि में दुग्ध उत्पादन से किसानों ने छह लाख करोड़ प्रति वर्ष की आमदनी हुई है।

कूटनीति ▶ दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए दस समझौते

दोस्ती-विकास के नए पथ पर भारत-भूटान

पीएम ने कहा, कौन नहीं चाहेगा अपने लिए ऐसा दोस्त और पड़ोसी

थिंपू, प्रेट्र : भूटान जैसा दोस्त और पड़ोसी कौन नहीं चाहता? ऐसे दोस्त के विकास का साथी बनना भारत के लिए भी सम्मान की बात है। भूटान के दो दिनी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यह बात कही। दूसरे कार्यकाल में मोदी का यह पहला भूटान दौरा है। बतौर प्रधानमंत्री पहले कार्यकाल में भी मोदी ने भूटान का दौरा किया था। पिछले दौरे पर मोदी ने कहा था कि भारत और भूटान के रिश्ते इसलिए मजबूत नहीं हैं कि इनकी सीमाएं खुली हैं, बल्कि यह मजबूती इसलिए है कि हमारे दिल खुले हैं। शनिवार को जिस खुले दिल से भूटान ने मोदी का स्वागत किया, वह इस बात को और भी पुष्ट करता है। भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग ने हवाईअड्डे पर पहुंचकर उनका स्वागत किया। इसके बाद मोदी राजधानी थिंपू के लिए रवाना हुए। इस दौरान पूरे रास्ते लोग भूटान और भारत का झंडा हाथों में लिए उनका स्वागत करते दिखाई दिए। मोदी ने भी अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही भूटान दौरे पर खुशी जताई। मोदी ने यहां पौधारोपण भी किया।

राजा से की मुलाकात : मोदी ने भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद मोदी ने कहा, 'भूटान के राजा की दूरदृष्टि ने भूटान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को गति दी है। उनकी ही सोच का नतीजा है कि भूटान दुनिया में एक उदाहरण बना हुआ है, जहां विकास को आंकड़ों के आधार पर नहीं, लोगों की खुशी के पैमाने पर मापा जाता है। जहां विकास परंपरा और पर्यावरण के साथ चलता है। ऐसा दोस्त और पड़ोसी कौन नहीं चाहेगा?' महल पहुंचने पर मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।

भूटान में लांच हुआ रुपे कार्ड : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में रुपे कार्ड लांच किया है। उन्होंने यहां के सर्वाधिक पुराने मठों में शुमार सिमतोखा जोंग (मठ) में एक खरीदारी करते हुए इसे लांच किया। इस कार्ड को दो चरणों में लांच किया जाना है। पहले चरण में भारतीय बैंक भारतीयों के लिए ऐसे रुपे कार्ड जारी करेंगे, जिनका भूटान में प्रयोग हो सकेगा। दूसरे चरण में भूटान के बैंकों को ऐसे रुपे कार्ड जारी करने का अधिकार दिया जाएगा, जिनका प्रयोग भारत आने वाले भूटानी नागरिक कर सकेंगे। मोदी के दौरे पर भारत और भूटान के बीच 10 समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुआ। एमओयू शोध, उड्डयन, आइटी, ऊर्जा और शिक्षा क्षेत्र में किए गए। रॉयल भूटान यूनिवर्सिटी और भारत के विभिन्न आइआइटी के बीच हुआ समझौता भी इसमें शामिल है। मोदी और शेरिंग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के सहयोग से तैयार ग्राउंड अर्थ स्टेशन और सैटकॉम नेटवर्क का उद्घाटन भी किया। भारत ने भूटान के लोगों की जरूरत को देखते हुए घरेलू गैस (एलपीजी) की आपूर्ति भी 700 टन मासिक से 1,000 टन मासिक करने का फैसला किया है। भूटान की विदेशी मुद्रा की जरूरत को देखते हुए भारत ने भूटान के साथ मौजूदा स्टैंड बाय स्वैप अरेंजमेंट में 10 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था की है।

भूटान में शनिवार को हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी भूटानी प्रधानमंत्री लोते शेरिंग ने की। प्रेट्र

जलविद्युत परियोजना का किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री मोदी ने यहां मांगदेछू जलविद्युत प्लांट का भी उद्घाटन किया। 4,500 करोड़ रुपये लागत वाली 720 मेगावाट की इस परियोजना को दोनों देशों ने मिलकर पूरा किया है। भारत ने इसके लिए 70 प्रतिशत राशि कर्ज के रूप में और 30 फीसद राशि अनुदान के रूप में दी है। मोदी ने कहा, 'जलविद्युत दोनों देशों के बीच सहयोग का अहम क्षेत्र है। दोनों देशों के प्रयास से भूटान की जलविद्युत क्षमता 2,000 मेगावाट से ज्यादा हो गई है। मुझे भरोसा है कि हम अन्य परियोजनाओं को भी तेजी से पूरा करेंगे।'

प्राथमिकता पर पड़ोसी मित्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो दिवसीय दौरे के तहत भूटान पहुंच चुके हैं। अपने पहले कार्यकाल में पहला विदेश दौरा भूटान का किया था। इसी के तहत उन्होंने अपनी पड़ोस की प्राथमिकता को जगजाहिर भी कर दिया था। भूटान की उनकी यात्रा के निहितार्थ भारत और चीन जैसे महादेशों के बीच बसे इस हिमालयी राष्ट्र की आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक महत्ता में भी तलाशे जा सकते हैं। भारत-भूटान संबंधों पर पेश है एक नजर :

सुख-दुख का नाता : वैसे तो भूटान के साथ भारत का प्रामाणिक ऐतिहासिक संबंध 747 ईस्वी से है, जब महान भारतीय संत पद्म संभव ने वहां जाकर बौद्ध धर्म की शुरुआत की। कालांतर में यह वहां के जीवन का अभिन्न अंग बन गया। इस साझा संस्कृति और धार्मिक विरासत के अलावा भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान दोनों देशों के बीच अन्य क्षेत्रों में भी संबंधों को गति मिली। दोनों देशों के बीच विशिष्ट संबंधों को देखते हुए विदेश नीति के कई जानकार भूटान को भारत का एकमात्र 'हर परिस्थिति में मित्र' के रूप में परिभाषित करते हैं।

उच्च स्तरीय यात्राएं : भारतीय नीति नियंता संबंधों को और बेहतर करने के लिए भूटान की यात्रा करते रहे हैं।

मैत्री संधि : आजादी के बाद भारत ने 1949 में भारत से मैत्री संधि की। इस संधि के द्वारा भारत ने भूटान के विदेशी मामलों को एक तरह से निर्देशित करने में सहायता की। हालांकि 2007 में दोनों देशों के बीच हुई इस संधि को संशोधित किया गया लेकिन इस बार संधि में किए गए इस प्रावधान को बरकरार नहीं रखा गया जिसके अनुसार भारत भूटान के विदेशी मामलों को निर्देशित करने में सहायता करता था। इसके बावजूद दोनों देशों के संबंधों में रत्ती भर फर्क नहीं महसूस किया जा सका।

सामरिक महत्व : दो बड़े और प्रतिद्वंद्वी देशों भारत और चीन के बीच बसे इस राष्ट्र की महत्ता का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। भले ही इसका झुकाव भारत के प्रति ज्यादा हो लेकिन चीन अपने पाले में करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता है। ऐसे में भारत के लिए अपने इस स्वाभाविक साझीदार को जोड़े रखने की बड़ी चुनौती है। हालांकि चीन के साथ भूटान का अनसुलझा विवाद और चीन की आक्रामक नीति भूटान को सुरक्षा के लिए भारत की तरफ निहारने को विवश करती है। 1954, 1958 और 1961 में चीन ने भूटान को अपने मानचित्र में दिखाकर अपना क्षेत्र होने का दावा किया था।

आर्थिक सहयोग : भारत भूटान का लगातार सबसे बड़ा कारोबारी और विकास सहयोगी रहा है। नियोजित विकास के प्रयास भूटान में 1960 में शुरू हुए। 1961 में पहली पंचवर्षीय परियोजना लागू की गई। तब से लगातार भारत इन परियोजनाओं की वित्तीय मदद कर रहा है।

कारोबार: भारत भूटान का सबसे बड़ा कारोबारी सहयोगी है। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था लागू है। भारत-भूटान ट्रेड एंड कामर्स एग्रीमेंट पर 1972 में हस्ताक्षर हुए। 2006 में इसका अगले दस वर्षों के लिए नवीकरण किया गया। 2012 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार 13 फीसद उछाल के साथ करीब सात हजार करोड़ रुपये का रहा।

पनबिजली सहयोग

दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों का यह क्षेत्र आधार है। भूटान की अर्थव्यवस्था में ऊर्जा बहुत अहम क्षेत्र है। यहां के सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का 12 फीसद योगदान है। देश के कुल निर्यात में ऊर्जा क्षेत्र की हिस्सेदारी 32 फीसद है। 1416 मेगावाट क्षमता के तीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भारत को बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं।

भूटान से सीखने की जरूरत

प्राकृतिक संसाधनों के कुशलतम उपभोग से ही ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। इस रीति-नीति को आत्मसात करने के लिए किसी को भी भूटान जैसे छोटे से देश से सबक सीखने की जरूरत है। भूटान जितना कार्बन उत्सर्जित करता है, उससे तीन गुना ज्यादा कार्बन डाईआक्साइड उसके जंगल अवशोषित कर लेते हैं। इसीलिए इसे कार्बन निगेटिव देश कहा जाता है। वहां के वन क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि जारी है। कम जनसंख्या होने के बावजूद यूरोपीय देश लक्जमबर्ग भूटान से चार गुना अधिक कार्बन उत्सर्जन करता है। अगर प्रत्येक देश अपने वन क्षेत्रों में बढ़ोतरी करे तो जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से बचा जा सकता है।

नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स : भूटान अपनी किसी भी नीति को ग्रास नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स की कसौटी पर कसकर आगे बढ़ाता है। चूंकि इस इंडेक्स में देश के वन क्षेत्र को 60 फीसद से कम न होने का संकल्प लिया गया है लिहाजा वह इस क्षेत्रफल को लगातार बढ़ा ही रहा है। भूटान का करीब 75 फीसद भाग पहाड़ी क्षेत्र में है।

कृषिवानिकी को बढ़ावा : जलवायु परिवर्तन के खतरों को भांपकर भूटान कृषिवानिकी की ओर अग्रसर है। जंगलों में ही कृषि उत्पादन करके ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम करने में मदद कर रहा है।

ताकि दुरुस्त रहे पर्यावरण

- बढ़ते कार प्रयोग को कम करने लिए भारी वाहन शुल्क
- सार्वजनिक परिवहन प्रणाली अनिवार्य
- बिजली चालित वाहनों को बढ़ावा

भूटान

- भारत के उत्तर-पूर्व और चीन के दक्षिण में बसा
- क्षेत्रफल : करीब 38 हजार वर्ग किमी
- जनसंख्या : 7.42 लाख
- राजधानी : थिंपू

यौन उत्पीड़न से बच्चों को सावधान करेगी आइआइटी कानपुर की किट

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने आइआइटी कानपुर के साथ मिलकर बच्चों के बीच यौन दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक किट विकसित की है। इस किट के जरिये बच्चों को निजी सुरक्षा, खुद का सम्मान करने, अपराध बोध से बाहर आने के बारे में बताया जाएगा।

एनसीपीसीआर की 38 वीं बैठक के ब्योरे के मुताबिक, यौन उत्पीड़न के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बच्चों के बीच संवाद आधारित कार्यशाला में शिक्षक या एनजीओ इस किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह किट कार्ड, पोस्टर, छोटे एनिमेशन क्लिप और गेम्स आदि का संग्रह है। आयोग ने कहा कि बच्चों के बीच शारीरिक या मनोवैज्ञानिक शोध पर आधारित किट की सामग्री के माध्यम से बच्चों को जागरूक बनाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य अबोध बच्चों को यौन उत्पीड़न को लेकर सावधान और सजग बनाना है ताकि समय रहते वे स्वयं को इससे बचा सकें।

रक्षा खरीद नियमों की समीक्षा के लिए कमेटी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'मेक इन इंडिया' को सशक्त बनाने के लिए रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी) 2016 और रक्षा खरीदी नियमावली (डीपीएम) 2009 की समीक्षा करने के लिए महानिदेशक (अधिग्रहण) की अध्यक्षता में एक समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। समिति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए छह महीने का समय दिया गया है। यह समिति प्रक्रियाओं को संशोधित कर निर्धारित लक्ष्य के साथ खरीद प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने का काम करेगी। इस समिति में महानिदेशक के अलावा उच्च स्तर के 11 अन्य अधिकारी हैं। इसमें संयुक्त सचिव और मेजर जनरल के समकक्ष पदों पर आसीन अधिकारी शामिल हैं।

सरकार के इस फैसले का उद्देश्य प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देते हुए इस प्रक्रिया को सरल तथा व्यापक बनाना है। समिति डीपीपी 2016 और डीपीएम 2009 के प्रावधानों तथा प्रक्रियाओं में संशोधन के सुझाव देगी। इससे प्रक्रियागत अड़चनों को दूर कर रक्षा अधिग्रहण के मामलों में तेजी लायी जा सकेगी। इसके साथ ही मानकीकरण पर जोर देने के साथ उपकरणों के जीवन चक्र को अधिक से अधिक बढ़ाये जाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। भारतीय उद्योग की भागीदारी को बढ़ाने के लिए नीतियों तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। ताकि घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत बनाया जा सके। इससे भारतीय स्टार्ट अप और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के प्रावधान भी शामिल किए जाएंगे।

ओएफबी का निजीकरण नहीं : समाचार एजेंसी एएनआइ के अनुसार रक्षा (उत्पादन) सचिव अजय कुमार ने बताया कि रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अफसर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (ओएफबी) को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में बदलने के संबंध में कर्मचारी संघों से बातचीत कर रहे हैं। ताकि सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से ओएफबी का निगमीकरण किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ओएफबी का निजीकरण नहीं करने वाली है। सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। सरकार रक्षा मंत्रालय के अधीन ही ओएफबी को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में बदलना चाहती है। ओएफबी के अधीन देश भर में स्थित 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, नौ प्रशिक्षण संस्थान, तीन रीजनल मार्केटिंग सेंटर और चार क्षेत्रीय सुरक्षा मानक नियंत्रणालय हैं। भारत सरकार से संचालित दुनिया के सबसे बड़े उत्पादन संगठन होने के अलावा, यह सबसे पुराना संगठन भी है। इसमें करीब 1.6 लाख कर्मचारी काम करते हैं।

सशक्त होगा 'मेक इन इंडिया'

- निर्धारित लक्ष्य के साथ प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने का काम सौंपा
- सिफारिशें पेश करने के लिए छह महीने का समय दिया गया

राजनाथ सिंह। फाइल

यूएपीए कानून को असंवैधानिक घोषित करने की उठी मांग

- जनहित याचिका दाखिल कर कहा, मौलिक अधिकारों का हनन करता है यह कानून

नई दिल्ली, एएनआइ : सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल करके गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन कानून (यूएपीए), 2019 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। कानून में संशोधन से केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिल गया है।

दिल्ली निवासी सजल अवस्थी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त समानता के मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति के अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन के अधिकार का हनन करता है। अधिनियम में हालिया संशोधन के जरिये व्यक्ति को आतंकी घोषित करने की अनुमति मिल गई है जबकि यूएपीए, 1967 के तहत सिर्फ संगठनों को ही आतंकी घोषित किया जा सकता था। यूएपीए, 2019 में यूएपीए, 1967 के छठे अध्याय में संशोधन के साथ साथ धारा 35 और 36 भी बदली गई है।

याचिका के मुताबकि, यूएपीए, 2019 की धारा 35 में यह नहीं बताया गया है कि किसी व्यक्ति को किस आधार या वजह से आतंकी घोषित किया जा सकता है। जिससे यह धारा बिना किसी सीमा या बंधन के सरकार को मनमाने और निरंकुश अधिकार प्रदान करती है जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। संशोधित कानून में आतंकवाद की रोकथाम के नाम पर असहमति प्रकट करने पर अप्रत्यक्ष प्रतिबंध लगाने की शक्ति भी प्रदान की गई है जो अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। साथ ही इसमें आतंकवादी घोषित किए गए व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर भी नहीं दिया गया है और उसके बाद उसे समाज के रहमोकरम पर छोड़ दिया गया है। लिहाजा यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा की कंपनी की 261 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा के एक बहुस्तरीय मार्केटिंग समूह के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले की जांच के तहत 261 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कर ली हैं। समूह पर पोंजी स्कीम से निवेशकों को चूना लगाने का आरोप है।

ईडी ने कहा कि हिसार स्थित कंपनी फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड, उसके दो निदेशकों राधेश्याम और बंशीलाल तथा उनके परिजनों एवं सहयोगियों की संपत्तियां कुर्क करने का प्राथमिक आदेश दिया है। इन संपत्तियों में आवासीय भूखंड, खेती लायक जमीन तथा घर आदि शामिल हैं। जिन 16 अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है, वे हिसार, आदमपुर, कुलम, दिल्ली और चंडीगढ़ में स्थित हैं। इनके अलावा 34 बैंक खातों में जमा 252 करोड़ रुपये को भी कुर्क किया गया है। इनका कुल मूल्य 261 करोड़ रुपये है। ईडी ने कहा कि तेलंगाना पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर उसने इस साल मार्च में मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दायर किया। तेलंगाना पुलिस ने प्रति माह 20,000 से 10 लाख रुपये कमाई का सपना दिखाकर आम लोगों के साथ धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया था। समूह ने सीधे-सादे लोगों को अपने पोंजी पिरामिड स्कीम का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया था।

रतुल पुरी की अर्जी का प्रवर्तन निदेशालय ने किया विरोध

जासं, नई दिल्ली : अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में मप्र के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने की अर्जी पर शनिवार को अदालत में सुनवाई हुई। पुरी के वकील ने कहा, जांच में शामिल होने के लिए ईडी को कई बार ई-मेल किया गया, लेकिन जवाब नहीं मिला। रतुल को हाई कोर्ट से भी गिरफ्तारी से राहत मिल चुकी है, ऐसे में गैर जमानती वारंट रद होना चाहिए। ईडी ने कहा, जब भी रतुल को जांच के लिए बुलाया गया तो सहयोग नहीं मिला। ऐसे में गैर जमानती वारंट पर रोक नहीं लगनी चाहिए।,क्योंकि यह सब जांच को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि, ईडी ने कहा कि अगली सुनवाई पर विस्तृत जवाब दाखिल किया जाएगा।

क्या है मामला

- प्रथम पृष्ठ का शेष

आइएलएंडएफएस समूह ने आपराधिक साठगांठ से पहले से कर्ज में फंसी कंपनियों को और बड़े कर्ज दिए। कर्ज ऐसी कंपनियों को भी दिए गए जो पहले ही समूह की सहायक कंपनी आइएफआइएन से लिए कर्ज के भुगतान में चूक कर चुकी थीं। इससे समूह पर 95,000 करोड़ रुपये का कर्ज हो गया और पिछले साल अक्टूबर में उसने दिवाला प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था।

कंपनी सचिव ने इस्तीफा दिया

आइएलएंडएफएस समूह की कंपनी आइएलएंडएफएस इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन की कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी सहेली बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने शेयर बाजार को जानकारी दी कि सहेली का इस्तीफा 16 अगस्त, 2019 से प्रभावी हो गया है। कंपनी ने बनर्जी के इस्तीफे का कारण नहीं बताया।

देश में मल्टी क्रू पायलट लाइसेंस सिस्टम लागू करने की तैयारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : उड्डन विभाग की निगरानी एजेंसी डीजीसीए नए पायलटों के नए प्रशिक्षण कार्यक्रम 'मल्टी क्रू पायलट लाइसेंस सिस्टम' के बारे में विचार कर रही है। इसमें केवल उड़ान के निश्चित घंटे देखने के बजाय प्रतिस्पर्द्धा आधारित मूल्यांकन होगा।

नागरिक उड्डयन महानिदेशक (डीजीसीए) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को बताया कि नया मल्टी क्रू पायलट लाइसेंस (एमपीएल) प्रोग्राम पहले से कई यूरोपीय देशों में लागू है। यह एक वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है जो ज्यादा सक्षम और त्वरित है। एमपीएल प्रोग्राम के जरिए पायलटों के केवल उड़ान के घंटों से ज्यादा ध्यान अब पायलटों के प्रतिस्पर्द्धा आधारित प्रशिक्षण और मूल्यांकन पर होगा।

आदेश के मुताबिक संबंधित कमेटी एमपीएल को लागू करने या उसे अंगीकार करने के संबंध में अपनी सिफारिश 16 सितंबर, 2019 तक दे देगी। अगर एमपीएल प्रोग्राम देश में लागू हो गया तो यह एक विकल्प के रूप में ही होगा। मौजूदा समय में एक व्यक्ति को उड़ान का प्रशिक्षण लेना पड़ता है। समयबद्ध निर्देशित घंटों में उड़ान भरनी होती है और परीक्षा पास करने के बाद उसे कर्मिशियल पायलट का लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन नए प्रोग्राम के जरिए पायलटों की मांग और आपूर्ति के अंतर को कम किया जा सकता है। हर साल फ्लाइंग स्कूल से पास होकर करीब 350 पायलट हर साल निकलते हैं, लेकिन जरूरत सालाना 600 से 800 पायलटों की है।

उल्लेखनीय है कि नरेंद्र मोदी सरकार विमानन सेवाओं को आम आदमी की पहुंच तक पहुंचाने की दिशा में बड़ी शिद्दत से काम कर रही है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार की ओर से उड़ान योजना को पेश किया गया है। इसके तहत देश के उन छोटे शहरों में विमान सेवा को शुरू किया गया है, जो अभी तक विमानन नक्शे में ही नहीं थे। इतना ही नहीं सरकार की ओर से विमान यात्रा के किराए में भी कमी की गई है, जिससे निम्न और मध्यम वर्ग के लोग भी विमानों में सफर का आनंद ले सकें। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का असर भी दिखाई पड़ने लगा है। देश में विमान यात्रियों की संख्या में इजाफा इस बात को खुद ही साबित कर रहा है। इस बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए तमाम निजी विमानन कंपनियां भारत में सेवाएं शुरू कर रही हैं।

सार्थक कदम

मोदी सरकार खुद को उपेक्षित मानने वाले बुजुर्गों को सम्मान संग सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील है, सरकार की ओर से इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं...

बुजुर्गों को सरकार देगी और सहारा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- वरिष्ठजनों की जिंदगी आसान बनाने के लिए सरकार की ओर से मुफ्त में मिलेंगे उनकी मदद करनेवाले और भी उपकरण
- केंद्र सरकार का वयोश्री योजना को अगले पांच सालों में सभी जिलों में पहुंचाने का लक्ष्य, अभी 327 जिलों में लागू

देश के बुजुर्गों को कुछ और सहारा देने के लिए सरकार कुछ बड़े एलान की तैयारी में है। इसके तहत उन्हें मुफ्त में कुछ और ऐसे उपकरण दिए जा सकते हैं, जो उनके जीवन को आसान बना सकते हैं। इनमें गले और घुटने के कॉलर सहित कमर के दर्द को कम करने के लिए बेल्ट जैसे करीब दस और उपकरणों को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। मौजूदा समय में सरकार की ओर से बुजुर्गों को छड़ी, वॉकर, श्रवण यंत्र, व चश्मा जैसे आठ उपकरण दिए जाते हैं।

इसके साथ ही राष्ट्रीय वयोश्री योजना को भी विस्तार देने का फैसला किया गया है। इसके तहत अगले पांच सालों में योजना को सभी जिलों में पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। अब तक यह योजना देश के सिर्फ 327 जिलों में ही लागू है। हालांकि इस साल के अंत तक चार सौ जिलों में योजना को पहुंचाने की तैयारी है। इस दौरान उन जिलों को प्राथमिकता से शामिल किया जा रहा है, जिनके लिए सांसदों की ओर से मांग आ रही है। वर्ष 2011 के आंकड़ों के मुताबिक बुजुर्गों की संख्या करीब 11 करोड़ है। इनमें से 70 फीसद से अधिक बुजुर्ग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। इनमें करीब छह फीसद बुजुर्ग बुढ़ापे से जुड़ी अलग-अलग प्रकार की विकलांगता से पीड़ित हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2026 तक देश में बुजुर्गों की आबादी बढ़कर करीब 18 करोड़ हो जाएगी।

वयोश्री योजना के विस्तार को लेकर सरकार इसलिए भी उत्साहित है, क्योंकि इसे विस्तार देने में किसी भी तरह की कोई वित्तीय बाधा नहीं है। यह इसलिए है, क्योंकि इस योजना का संचालन बैंकों सहित सभी वित्तीय संस्थानों में जमा उस पैसे से किया जाता है, जिसके कोई दावेदार नहीं हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के पास इस तरह के करीब 14 हजार करोड़ रुपये मौजूद हैं। उल्लेखनीय है कि देश में बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है। परिवारों में उनकी उपेक्षा के मामलों में दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में उन्हें अतिरिक्त देखभाल की जरूरत ज्यादा है।

उत्तर प्रदेश के 23 जिले शामिल

वयोश्री योजना में फिलहाल उत्तर प्रदेश के 23 जिले शामिल हैं। हालांकि अब तक इनमें से सिर्फ आठ जिलों में ही बुजुर्गों को मदद के लिए जरूरी चीजें उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें लखनऊ, पीलीभीत, गोरखपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, फतेहपुर, बरेली और अमेठी शामिल हैं। बाकी जिन जिलों में ऐसे शिविर आयोजित होने वाले हैं, उनमें वाराणसी, ललितपुर, चंदौसी, नोएडा, इलाहाबाद, चित्रकूट, बलरामपुर, बहराइच, सोनभद्र, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, रायबरेली, सुल्तानपुर, बागपत और कानपुर शामिल हैं।

सीवीसी की शिकायत पर पूर्व ईडी निदेशक के खिलाफ जांच

नई दिल्ली, आइएएनएस : केंद्रीय जांच ब्यूरो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पूर्व निदेशक कर्नल सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच कर रही है। पूर्व निदेशक पिछले वर्ष ही रिटायर हो चुके हैं। सीबीआइ सूत्रों ने कहा, 'सिंह के खिलाफ केंद्रीय निगरानी आयोग (सीवीसी) से आय से अधिक संपत्ति मामले की शिकायत मिली है।' एजेंसी को करीब डेढ़ महीना पहले शिकायत मिली थी।

सूत्रों ने बताया कि इसी आधार पर जांच की जा रही है। अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है और न ही कोई प्रारंभिक जांच शुरू की है। जांच के बाद ही इस बारे में फैसला किया जाएगा। 1984 बैच के आइपीएस अधिकारी ने 27 अक्टूबर 2016 को ईडी निदेशक का प्रभार ग्रहण किया था। पिछले वर्ष अक्टूबर में वह सेवानिवृत्त हुए। सिंह के कार्यकाल में एजेंसी ने 36000 करोड़ रुपये की चल अचल संपत्तियां जब्त की। उनसे पहले ईडी ने 10 साल की अवधि में केवल 9000 रुपये की संपत्तियां ही जब्त की थी।

कह के रहेंगे माधव जोशी

2100 किलोमीटर की यात्रा करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपनी जन आशीर्वाद रथ यात्रा के दौरान। इसमें तीन-तीन दिन के पांच चरण होंगे और 8 सितंबर को रोहतक में रैली के साथ ही यह समाप्त हो जाएगी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 18 अगस्त 2019

फील्ड में सरकार, अब रथ से चलेगा मुख्यमंत्री कार्यालय

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़

- इंटरनेट, प्रिंटर और लैपटॉप की सुविधा वाले रथ में तमाम सुविधाएं, बैठक के लिए अलग कक्ष
- अपनी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का हिसाब-किताब के साथ ही अगले पांच साल के एजेंडे से भी वाकिफ कराएंगे

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा के लिए तैयार रथ (बाएं)। रथ में सीएम के लिए अस्थायी कार्यालय का भी निर्माण किया गया है। जागरण

जींद में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह द्वारा चुनावी बिगुल बजा देने के बाद मनोहर सरकार फील्ड में उतर पड़ी है। कमजोर होते विपक्ष के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार से रथ पर सवार होकर पूरे प्रदेश का चक्कर लगाएंगे। मुख्यमंत्री न केवल अपनी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का हिसाब-किताब लोगों के सामने पेश करेंगे, बल्कि अगले पांच साल के एजेंडे से भी वाकिफ कराएंगे। भाजपा सरकार का फोकस अगले सालों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर रहने वाला है। प्रदेश सरकार यह चुनाव भ्रष्टाचार रहित पारदर्शी व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर लड़ेगी।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की महा परिवर्तन रैली भी रविवार को है। इस रैली से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुबह नौ बजे कालका में काली माता की पूजा-अर्चना कर रथ पर सवार हो चुके होंगे। मुख्यमंत्री की रथ यात्रा के लिए बस नुमा स्पेशल रथ गुरुग्राम के मानेसर में बनाया गया है जो वाटर प्रूफ होगा। यह रथ आठ सितंबर तक राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों तक पहुंचेगा। इस दौरान पूरी सरकार फील्ड में होगी। मुख्यमंत्री के रथ से ही सीएमओ (मुख्यमंत्री कार्यालय) का संचालन किया जाएगा। रथ में दो अलग-अलग कार्यालय होंगे। इंटरनेट, प्रिंटर और लैपटॉप की सुविधा वाले इस कार्यालय में बैठक करने की अलग से व्यवस्था होगी। एक बार में दस लोग बैठक कर सकेंगे। मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करने के बाद खाली समय में अपने अस्थायी कार्यालय रथ में ही फाइलें निकालेंगे। रथ में नहाने और खाने-पीने की भी व्यवस्था अलग कमरे में की गई है। आराम के लिए अलग से एक छोटा बिस्तर होगा। मुख्यमंत्री भाषण देने के लिए लिफ्ट के जरिये ऊपर तक पहुंचेंगे और आखिरी जनसभा लोगों के बीच जाकर होगी। रथ के चारों तरफ तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर लगाए गए हैं जिनकी सुनने की क्षमता 700-800 मीटर तक निर्धारित रहेगी। यात्रा के आखिरी दिन आठ सितंबर को रोहतक में जन आशीर्वाद रैली होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की संभावना है। प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक रैली के लिए जींद पहुंचे अमित शाह के साथ मंथन किया है। रैली में मोदी और शाह दोनों नेताओं को निमंत्रण दिया गया है, लेकिन चुनावी महीना होने के कारण इस रैली में मोदी के आने की पूरी संभावना है।

मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन के मुताबिक रथ यात्रा के लिए हरियाणा के सभी केंद्रीय मंत्रियों, राज्य सरकार के मंत्रियों, संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों और विधायकों की ड्यूटी लगाई गई है। सुभाष बराला के अनुसार यात्रा हर रोज करीब 150 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इसके लिए हर दिन एक यात्रा प्रमुख की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है।

हुड्डा आज कांग्रेस नेतृत्व को दिखाएंगे अपनी ताकत

ओपी वशिष्ठ, रोहतक

- अपने गढ़ में महा परिवर्तन रैली से करेंगे विधानसभा चुनाव का शंखनाद

भूपेंद्र सिंह हुड्डा फाइल फोटो

लंबे समय से कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ प्रधानी को लेकर लड़ाई लड़ रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने गढ़ में रविवार को महापरिवर्तन रैली करके हरियाणा में अपना वजूद दिखाएंगे। हुड्डा ने इस रैली को लेकर पूरी ताकत लगा रखी है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आलाकमान को दबाव में लाने के लिए हुड्डा यह आखिरी पासा फेंकने जा रहे हैं। हुड्डा के तेवरों से तो स्पष्ट हो रहा है कि रैली में महा परिवर्तन की घोषणा होगी, चाहें पार्टी से बगावत कर अलग राह अपनाएंगे या फिर सत्ताधारी भाजपा के विजयी रथ को रोकने की कोई खास रणनीति बताएंगे। जिस तरह से रोहतक के मेला ग्राउंड में विशाल पंडाल तैयार किया गया है, उससे तो लगता है कि अच्छी-खासी भीड़ रैली में पहुंचने वाली है।

प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व की आखिरी लड़ाई के इंतजार की घड़ी रविवार को खत्म हो जाएगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी से इतर अपने दम पर रैली कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी के ही प्रतिद्वंद्वी नेताओं को निमंत्रण तक नहीं दिया है। इतना ही नहीं कांग्रेस नेतृत्व को भी इस रैली में नहीं बुलाया गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बारे में हुड्डा ने अभी तक मुंह नहीं खोला है और कांग्रेस में ही रहने की बात कह रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक विधायक, पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री पार्टी छोड़ने के संकेत जरूरत मीडिया के सामने दे चुके हैं। विश्वसनीय सूत्रों की मानें तो हुड्डा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। कई दिन से इस तरह की चर्चाएं जोर पकड़े हुए हैं। इस बीच, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साए की तरह साथ रहने वाले विधायकों में से कइयों के अब साथ छोड़ने की चर्चा भी सामने आ रही है।

गांधी परिवार से बाहर के नेता का कांग्रेस का नेतृत्व करना मुश्किल : अधीर रंजन

दो टूक ▶ कांग्रेस सांसद ने कहा- सोनिया गांधी नहीं चाहती थीं कमान संभालना

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन। फाइल फोटो

अनुच्छेद 370 खत्म कर भाजपा ने पेश किया खतरनाक उदाहरण

अधीर ने कहा कि जिस तरह भाजपा ने अनुच्छेद 370 को खत्म किया, वह असंवैधानिक था। इससे राज्यों के कामकाज में केंद्र का हस्तक्षेप बढ़ेगा। भाजपा ने ऐसा करके खतरनाक उदाहरण पेश किया है। कश्मीर मुद्दे पर पार्टी में नेताओं के अलग-अलग राय रखने के सवाल पर उन्होंने कहा- 'सरकार ने बिल संसद में पारित कराने में काफी जल्द दिखाई, जिससे हमें इस बारे में चर्चा के लिए ज्यादा समय नहीं मिला। यही वजह है कि पार्टी के पक्ष को लेकर नेताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, लेकिन एक बार जब कांग्रेस कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया तो फिर किसी के मन में कोई शंका नहीं बची।

लोकसभा में सोमवार को लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन ने कहा कि सोनिया गांधी पार्टी की डोर हाथ में नहीं लेना चाहती थीं, लेकिन राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद संगठन को संकट में देखकर उन्होंने वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों का अनुरोध स्वीकार कर लिया। सोनिया गांधी ने संकट के समय पार्टी की बागडोर संभाली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांधी परिवार से बाहर के किसी नेता का पार्टी का नेतृत्व करना मुश्किल है।

उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में मुश्किल समय में 2004 और 2009 में दो बार कांग्रेस ने केंद्र में सरकार बनाई थी। गांधी परिवार से बाहर किसी व्यक्ति का पार्टी का नेतृत्व करना वास्तव में मुश्किल होगा। राजनीति में भी ब्रांड इक्विटी होती है। अगर आप अभी भाजपा को देखेंगे तो क्या मोदी और शाह के बिना वह सुचारू रूप से चल सकती है? जवाब है ना?' हमारी पार्टी में भी गांधी-नेहरू परिवार ब्रांड इक्विटी है। इसमें कोई नुकसान नहीं है। हमारी पार्टी में किसी और के पास वह बात भी नहीं है। यह एक कठोर वास्तविकता है। अधीर ने राहुल गांधी के इस्तीफा देने की सराहना करते हुए इसे उदार कदम बताया और कहा कि अन्य नेताओं को भी इससे सीखना चाहिए। गौरतलब है कि हाल ही में सोनिया गांधी को कांग्रेस कार्य समिति ने पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष चुना है।

कांग्रेस ही रोकेगी भाजपा को : अधीर रंजन ने कहा कि कांग्रेस जैसी मजबूत विचारधारा वाली पार्टी, जिसकी हर जगह पहुंच है, वही भाजपा के सांप्रदायिक रथ को रोक सकती है। कांग्रेस सांसद ने कहा-'क्षेत्रीय दल जिस तरह से काम कर रहे हैं, वे आने वाले दिनों में अपना महत्व खो देंगे। उनके महत्व खोने का मतलब है कि देश द्विध्रुवीय राजनीति की ओर बढ़ जाएगा। द्विध्रुवीय राजनीति की स्थिति उत्पन्न होने से हम दोबारा सत्ता में आ सकते हैं, इसलिए कांग्रेस का भविष्य उज्ज्वल है। क्षेत्रीय दलों में वैचारिक प्रेरणा का अभाव है और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को व्यापक समर्थन प्राप्त है।'

छत्तीसगढ़ में जातिगत आरक्षण में बदलाव पर गर्माई सियासत

नईदुनिया, रायपुर

- एक फीसद की बढ़ोतरी से संतुष्ट नहीं अनुसूचित जाति
- विपक्ष ने भी की 16 फीसद का वादा पूरा करने की मांग

छत्तीसगढ़ में जातिगत आरक्षण में बदलाव की घोषणा से सियासत गर्मा गई है। आरक्षण में 13 फीसद की बढ़ोतरी से ओबीसी खुश हैं, लेकिन अनुसूचित जाति (एससी) का एक बड़ा वर्ग केवल एक फीसद की वृद्धि से खुश नहीं है। उनकी मांग अविभाजित मध्य प्रदेश की तरह आरक्षण को 16 फीसद करने की है। सरकार ने एससी को 13 फीसद आरक्षण देने की घोषणा की है। समाज की इस मांग को लेकर राजनीतिक दल के नेता आवाज बुलंद कर रहे हैं।

भाजपा और जकांछ कांग्रेस सरकार से वादे के अनुसार एससी वर्ग को 16 फीसद आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। दोनों दलों का तर्क है कि कांग्रेस ने 2013 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में 16 फीसद का वादा किया था। इधर, सामान्य वर्ग के लोग आरक्षण में किए गए इस बदलाव को राजनीतिक लाभ के लिए समाज को बांटने की राजनीतिक बता रहे हैं।

कटौती करने वाले कर रहे हैं हल्ला : छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति आरक्षण बचाओ महासमिति के अध्यक्ष केपी खांडे ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि 16 फीसद आरक्षण की मांग वे लोग कर रहे हैं, जिन्होंने एससी का कोटा कम किया था। आबादी के लिहाज से 13 फीसद आरक्षण से हम संतुष्ट हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जनगणना में एससी की सही संख्या नहीं आ पाती है। आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में दाखिल केस वापस लेने के सवाल का सीधा जवाब देने से बचते हुए उन्होंने केवल इतना कहा कि इस पर वकील से राय लेंगे।

कांग्रेस ने समाज के साथ किया धोखा : बांधी

भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी ने कहा कि जब एससी के आरक्षण के कोटे में कमी की गई तो कांग्रेसी हमारे खिलाफ समाज के लोगों को भड़काते थे। कहते थे कि कांग्रेस की सरकार आई तो एससी को 16 फीसद आरक्षण देंगे। अब उनकी सरकार आ गई है तो समाज से किया हुआ वादा पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। केवल एक फीसद की वृद्धि एससी समाज के साथ धोखा है।

16 फीसद का वादा हो पूरा

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जकांछ) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस अपने 2013 के घोषणा पत्र के अनुरूप 16 फीसद आरक्षण अनुसूचित जाति को दे। एक फीसद की बढ़ोतरी बेहद कम है। हम उम्मीद करते है इस मुद्दे को लेकर मंत्री शिव डहरिया और रद्र गुर मंत्रिपरिषद में सकारात्मक पहल करेंगे, चाहें इसके लिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा ही क्यों न देना पड़े।

राजनीतिक लाभ-हानि के मापदंड पर हुआ फैसला

छत्तीसगढ़ कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र पांडेय कहते हैं कि आरक्षण में बदलाव का फैसला राजनीतिक लाभ-हानि के मापदंड पर हुआ है। इससे किसी को कुछ मिलेगा तो नहीं, लेकिन समाज में मनमुटाव जरूर बढ़ेगा। एलान करने वालों को भी पता है कि मामला कोर्ट में जाएगा। अभी 2012 में आरक्षण में किए गए बदला का मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है।

मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों की माली हालत बेहद खराब

- खर्च चलाने लायक भी राजस्व वसूली नहीं
- ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने प्रभारी मंत्रियों से वसूली बढ़वाने का किया आग्रह
- कहा- बिजली बिल जमा नहीं करने वालों के कारण ईमानदारों को मिल रही महंगी बिजली

प्रियव्रत सिंह फाइल फोटो

धनंजय प्रताप सिंह, भोपाल

बिजली बिल जमा नहीं करने वाले डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के कारण ईमानदार उपभोक्ताओं को बिजली के ज्यादा दाम चुकाना पड़ते हैं, ये बात 100 फीसदी सच है। इसकी जानकारी खुद मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने दी है। सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को पत्र लिखकर सिंह ने कहा कि बिजली कंपनियों की माली हालत अत्यधिक खराब है।

कंपनियों के खर्च चलाने लायक भी राजस्व वसूली नहीं हो पा रही है। बिजली बिल जमा नहीं करने वालों के कारण ही ईमानदार उपभोक्ताओं को बिजली की ज्यादा कीमत देना पड़ती है। मालूम हो, बिजली की बदहाली पर सरकार ने पहले ही श्वेत पत्र जारी करने की बात कही है।

टैरिफ पर विपरीत प्रभाव : ऊर्जा मंत्री ने पत्र में लिखा कि वितरण कंपनियों की हानि का स्तर अत्यधिक होने के कारण प्रदेश के उपभोक्ताओं के टैरिफ निर्धारण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। ईमानदार उपभोक्ताओं को अधिक दरों का भुगतान करना पड़ता है। बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं का खामियाजा ईमानदार लोगों को वहन करना पड़ता है।

प्रियव्रत सिंह ने कहा कि बिजली कंपनियां लगभग 47 हजार करोड़ रुपये के घाटे में हैं। अब तक राजस्व वसूली पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था, इसलिए हम वसूली बढ़ाने के सारे प्रयास कर रहे हैं। इसके जरिये ही घाटे की भरपाई की जा सकती है।

नगरीय निकाय चुनाव में दलीय आधार खत्म करने की तैयारी में कांग्रेस

नईदुनिया, भोपाल

- भाजपा विरोध में, क्योंकि इन चुनावों से यह संदेश देना चाहती है कि प्रदेश का जनमत अभी भी भाजपा के साथ

> सरकार विचार कर रही है कि नगरीय निकाय के चुनाव में 1999 के पहले की व्यवस्था लागू की जाए। इसमें पार्षद ही मेयर और अध्यक्ष का चुनाव करते थे। चूंकि कांग्रेस इस दिशा में सोच रही है इसलिए भाजपा विरोध कर रही है, उसके पास कोई तार्किक आधार नहीं है।
> -पंकज चतुर्वेदी, प्रवक्ता, मप्र कांग्रेस

मध्य प्रदेश सरकार कुछ महीनों बाद प्रस्तावित नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव गैरदलीय आधार पर करवाने की तैयारी कर रही है। संभावना है कि अगले विधानसभा सत्र में संशोधन विधेयक या अध्यादेश लाकर नियमों में संशोधन कर दिया जाए। लेकिन, भाजपा चाहती है कि नगर निगम और नगर पालिका परिषद के चुनाव दलीय आधार पर ही हों। इसकी वजह साफ है कि कांग्रेस जहां दलीय आधार पर चुनाव होने के कारण अपनी यानी राज्य सरकार की साख खराब नहीं होने देना चाहती है, वहीं भाजपा इन चुनावों के जरिये यह संदेश देना चाहती है कि प्रदेश का जनमत अभी भी भाजपा के साथ है।

लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 29 में से 28 सीटें हासिल करने के बाद भाजपा नगरीय निकायों के चुनाव को लेकर उत्साहित है। पार्टी की रणनीति 16 नगर निगम में अपना कब्जा बरकरार रखने की है। यही कारण है कि भाजपा चाहती है कि प्रदेश में दलीय आधार पर ही चुनाव कराए जाएं। पार्टी ने इसके लिए एक समिति भी गठित कर दी है।

दलीय आधार पर और समय पर हों चुनाव: मोघे

भाजपा की नगरीय निकाय समिति के अध्यक्ष कृष्णमुरारी मोघे ने दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन 'नईदुनिया' से कहा कि राज्य सरकार के फैसला पर हमारी रणनीति तय होगी। सरकार द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है कि नगरीय निकाय के चुनाव में महापौर (मेयर) का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होगा, उसे पार्षदों द्वारा चुना जाएगा पर अब तक ये सिर्फ कयास ही हैं। भाजपा चाहती है कि मेयर का चुनाव सीधे जनता करे। साथ ही नगरीय निकाय के चुनाव समय पर कराए जाएं और नगरीय निकाय के चुनाव दलीय आधार पर हों।

खरीद-फरोख्त बढ़ेगी : भाजपा का मानना है कि यदि गैरदलीय आधार पर नगरीय निकाय के चुनाव होंगे तो दलीय अनुशासन नहीं होने से ये संस्थाएं बर्बाद हो जाएंगी। साथ ही पार्षदों की खरीद फरोख्त शुरू हो जाएगी।

विधेयक या अध्यादेश लाना होगा : सूत्रों का कहना है कि गैरदलीय आधार पर नगरीय निकाय चुनाव कराए जाने का संशोधन विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में लाया जा सकता है। अन्यथा अध्यादेश के जरिए सरकार इसे लागू कर सकती है। गैरदलीय आधार पर नगरीय निकाय चुनाव कराने के लिए कानून में बदलाव के लिए राज्यपाल की मंजूरी भी लेनी होगी। सूत्रों का कहना है कि राज्यपाल लालजी टंडन इससे सहमत होंगे या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। इसकी वजह ये है कि उप्र में बसपा सरकार के कार्यकाल में 2011 में मायावती ने भी मेयर के चुनाव में दलीय प्रणाली खत्म कर दी थी, तब टंडन ने इसका विरोध किया था।

सूत्रों का कहना है कि सरकार की मंशा पंचायत चुनाव की तरह नगरीय निकाय चुनाव कराने की है। इसके लिए तर्क दिया जा रहा है कि ग्राम पंचायत से लेकर जनपद और जिला पंचायत के चुनाव गैरदलीय आधार पर होते हैं और जनपद व जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसी आधार पर नगरीय निकाय चुनाव कराए जाने की तैयारी है।

केंद्रीय मंत्री को पांच वोट मिलने के मामले ने तूल पकड़ा

जागरण संवाददाता, बरेली

- सपा प्रत्याशी रहे भगवत सरन गंगवार बोले, केंद्रीय मंत्री ने उनके आरोपों की पुष्टि की
- जिला निर्वाचन अधिकारी की जांच पूरी होने के बाद चुनाव आयोग में करेंगे शिकायत

लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी (अब केंद्रीय मंत्री) संतोष गंगवार को महज पांच वोट मिलने का मामला तूल पकड़ गया है। उन्हें यह पांच वोट प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल के मुहल्ले के मतदान केंद्र पर मिले थे। यह मसला अब चुनाव आयोग तक पहुंचेगा।

जागरण में खबर प्रकाशित होने के बाद शनिवार को पूरे दिन सियासी गलियारों में इसकी चर्चा होती रही। जिला निर्वाचन कार्यालय का स्टाफ मतगणना से जुड़े अभिलेख तलाशता दिखाई दिया। कलक्ट्रेट में भी मतगणना में गिनती की चूक को लेकर चर्चा रही। अगर ऐसा है तो फिर भाजपा के गढ़ में कमल के बजाय साइकिल कैसे दौड़ गई? डीएम वीरेंद्र कुमार सिंह के समाधान दिवस में जाने के कारण उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। उधर, शनिवार दोपहर दो बजे लोकसभा चुनाव में बरेली सीट से सपा प्रत्याशी रहे पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार ने अय्यूब खां मार्ग स्थित कार्यालय पर पत्रकारों से कहा कि हमने चुनाव से पहले और बाद में नतीजे को लेकर जो संदेह जताया था, केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने उसकी पुष्टि कर दी है। साफ हो गया है कि इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी करके चुनाव जीता गया है। उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाते हुए मांग की है कि ईवीएम की बजाय मतपत्रों से ही चुनाव कराया जाना चाहिए। यह भी कहा कि इस मामले में पहले जिला निर्वाचन अधिकारी की जांच पूरी होने का इंतजार करेंगे। उसके बाद चुनाव आयोग में शिकायत लेकर जाएंगे।

यह है पूरा मामला : शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने डीएम वीरेंद्र कुमार सिंह को पत्र लिखकर कहा था कि कालीबाड़ी मुहल्ले के तमाम लोगों ने उन्हें बताया कि विष्णु बाल सदन के बूथ संख्या 290 पर जाकर उन्हें वोट दिया था। इसके बावजूद बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर उन्हें महज पांच व सपा को 583 वोट दर्ज हुए हैं। ऐसे में गिनती में चूक होना प्रतीत हो रहा है। इस बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी ने 'जागरण' को बताया था कि अभिलेखों का अवलोकन करा रहे हैं। विष्णु बाल सदन मतदान केंद्र के बराबर में ही सूबे के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल का आवास है। उनके परिवार के वोट भी इसी स्कूल में पड़ते हैं। मंत्री के मुहल्ले में भाजपा प्रत्याशी को महज पांच वोट की बात किसी के गले नहीं उतर रही।

महागठबंधन

लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद राजद प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने दिया बयान, कहा, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा इसका फैसला महागठबंधन की बैठक में होगा

हेमंत के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को हेमंत तैयार

जागरण संवाददाता, रांची

- लालू के पारिवारिक सदस्य विमल सिंह यादव और हुसैनाबाद से राजद नेता लव कुमार मेहता भी मिले

रिम्स में लालू यादव से मिलकर बाहर निकलते राजद के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह, राजद नेता लव कुमार मेहता व अन्य। जागरण

चारा घोटाले के चार मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद से मिलने शनिवार को उनके पारिवारिक करीबी विमल सिंह, राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह व हुसैनाबाद से राजद नेता लव कुमार मेहता पहुंचे। लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद अभय कुमार सिंह ने बताया कि उनसे राजनीतिक मामलों पर चर्चा हुई है। राजद महागठबंधन के तहत हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। इसके लिए सीटों का बंटवारा महागठबंधन की बैठक में होगा। महागठबंधन में शामिल सभी दलों की बैठक के बाद तय होगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा।

अभय सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद से उन सभी सीटों पर चर्चा हुई जहां से पार्टी को चुनाव लड़ना है। छतरपुर के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि वहां के मनोज भुइयां झाविमो में शामिल हो गए हैं। जबकि राजद वहां दूसरे स्थान पर है। इस पर लालू प्रसाद ने वहां से किसी सक्षम व्यक्ति को खड़ा करने की बात कही।

सरकार को उखाड़ फेंकने को लेकर राजद कटिबद्ध : अभय सिंह ने बताया कि हमलोगों की तैयारी पूरी है। भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकना है।

हुसैनाबाद के राजद नेता लव कुमार ने बताया कि हुसैनाबाद में 15 सितंबर को जगदेव जी के शहादत दिवस को लेकर लालू प्रसाद से चर्चा की। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के शिवपूजन मेहता की आलोचना भी की।

तबीयत में सुधार नहीं, परिवार से मिलने के बाद मन हुआ ठीक : लालू प्रसाद के पारिवारिक सदस्य विमल यादव ने कहा कि लालू यादव की तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन परिवार के सदस्य से मुलाकात के बाद थोड़ा मन ठीक हुआ। बातचीत के क्रम में लालू प्रसाद काफी प्रसन्न दिखे। वे हंसे और खुलकर बात की। कहा कि वे परिवार के सभी सदस्यों के लिए चिंतित हैं। वे सुलझे हुए व्यक्ति हैं। आने वाले दिनों में सब सुलझ जाएगा। लालू जी ने कहा कि वक्त आएगा और हम रक्षाबंधन व पंद्रह अगस्त अपने पुराने तरीके से मनाएंगे।

मध्य प्रदेश में छह साल से नहीं दिया गया सावित्री बाई फुले पुरस्कार

नईदुनिया, भोपाल

2013 में शुरुआत के वक्त एक शिक्षिका को मिला था पुरस्कार

- कमजोर वर्ग की छात्राओं को शिक्षा से जोड़ने पर दिया जाता है सम्मान

> विभाग को निर्देश नहीं मिले : यह पुरस्कार इसलिए नहीं दिया गया, क्योंकि किसी भी शिक्षिका को विभाग चिह्नित नहीं कर पाया। इस संबंध में विभाग को कोई निर्देश भी शासन की तरफ से नहीं मिले हैं।
> -रश्मि अरुण शमी, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा, मप्र

पांच सितंबर को हर साल एक शिक्षिका को दिया जाने वाला सावित्री बाई फुले पुरस्कार बीते छह साल से किसी भी शिक्षिका को नहीं दिया गया है। या यूं कहे कि मध्य प्रदेश सरकार पुरस्कार की शुरुआत कर भूल गई। 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की कमजोर वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने व सामाजिक विकास के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को पुरस्कृत करने के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। पहले वर्ष तो एक शिक्षिका को पुरस्कार दिया गया, लेकिन इसके बाद से आज तक न तो सरकार ने और न स्कूल शिक्षा विभाग ने इस पर ध्यान दिया।

मप्र शासन ने 15 फरवरी 2013 को राज्य स्तरीय सावित्री बाई फुले पुरस्कार देने की घोषणा की थी। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर की माध्यमिक कक्षाओं की शिक्षिकाओं से आवेदन आमंत्रित किए। इसमें शिक्षिकाओं से सेवा रिकॉर्ड का विवरण, शिक्षिका का कार्य अनुभव, शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव सहित अन्य योग्यताएं मांगी गईं। इसमें होशंगाबाद जिले की शासकीय कन्या माध्यमिक शाला सेमरीहरचंद की शिक्षिका प्रतिभा साहू को पांच सितंबर 2013 को एक लाख रुपये की नकद राशि और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया।

छह साल में उत्कृष्ट शिक्षिका नहीं खोज पाया विभाग : स्कूल शिक्षा विभाग इस राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए छह साल में एक भी उत्कृष्ट शिक्षिका को नहीं खोज पाया। राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से 2017-18 में आवेदन आमंत्रित कराने के लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए गए, लेकिन पुरस्कार देने की घोषणा नहीं हुई।

सबसे बड़ी राशि का पुरस्कार : शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के लिए राज्य स्तरीय सम्मान के रूप में 25 हजार रुपये और राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार में 50 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती है। मप्र शासन की ओर से शुरू किए गए सावित्री बाई फुले पुरस्कार सम्मान के तहत एक लाख रुपये की राशि का पुरस्कार दिया जाता है।

10.4 फीसद आबादी गरीबी रेखा के नीचे है जम्मू-कश्मीर की। देश में 22 फीसद जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। छत्तीसगढ़ इस मामले में सबसे पिछड़ा है। यहां यह आंकड़ा 40 फीसद है।

पटरी पर लौटती जिंदगी ▶ घाटी में 35 पुलिस थाना क्षेत्रों में दी गई ढील, कल से खुल जाएंगे प्राथमिक स्कूल, किए गए हैं जरूरी सुरक्षा प्रबंध

कश्मीर में टेलीफोन, जम्मू में मोबाइल और 2जी इंटरनेट बहाल

कश्मीर में बजी फोन की घंटी, 23 हजार फोन और 17 एक्सचेंज बहाल

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर में धीरे-धीरे सामान्य जनजीवन रफ्तार पकड़ने लगा है। कश्मीर में घटती प्रशासनिक पाबंदियों के साथ ही शनिवार को 12 दिनों से बंद पड़े 23 हजार लैंडलाइन फोन बहाल हो गए। 17 टेलीफोन एक्सचेंज ने भी काम करना शुरू कर दिया है। 35 पुलिस थाना क्षेत्रों में ढील दी गई है और सोमवार से श्रीनगर जिले के विभिन्न जोन में सोमवार को 190 स्कूल खोले जाएंगे। इसके लिए आवश्यक सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। इस बीच, प्रशासन ने जम्मू संभाग के पांच जिलों जम्मू, ऊधमपुर, सांबा, कठुआ और रियासी में शुक्रवार मध्य रात्रि के बाद 2जी मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बहाल कर दी। वहीं, दूसरी ओर पाबंदियों में ढील मिलते ही शरारती तत्वों ने हताशा में कुछ दुकानों और सड़क पर जा रही गाड़ियों पर पत्थर फेंके। हालांकि सुरक्षाबलों ने हल्का बल प्रयोग कर शरारती तत्वों को खदेड़ दिया।

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटने के बाद से कश्मीर में स्थिति को देखते हुए निषेधाज्ञा लागू कर रखी है। सभी प्रकार की टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं और

श्रीनगर में शनिवार को पत्रकार वार्ता के दौरान जम्मू-कश्मीर के हालात की जानकारी देते राज्य के प्रमुख सचिव रोहित कंसल (मध्य में), कश्मीर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक एसपी पाणी (बाएं) और सूचना विभाग की निदेशक सहरिस जरगर (दाएं)। जागरण

शिक्षण संस्थान भी चार अगस्त की रात से बंद थे।

लोगों से मिला सहयोग तो हटने लगी पाबंदियां : वादी में तनाव के बावजूद कोई बड़ा हिंसक प्रदर्शन न होने और कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में जनसहयोग को देखते हुए प्रशासन ने पाबंदियों को हटाना शुरू कर दिया है। ऐसे में दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं और सड़कों पर आवाजाही भी बढ़ी है। आइजीपी कश्मीर एसपी पाणी ने बताया कि कानून व्यवस्था में सुधार को देखते हुए शनिवार को पूरी वादी में 35 पुलिस थाना क्षेत्रों के कार्याधिकार क्षेत्र में प्रशासनिक पाबंदियों में ढील दी गई है।

राज्यपाल के प्रमुख सचिव रोहित कंसल और कश्मीर रेंज के पुलिस आइजी एसपी पाणि ने बताया कि पूरी वादी में 96 टेलीफोन एक्सचेंज हैं। इनमें से 17 टेलीफोन एक्सचेंज को बहाल कर दिया गया है। शनिवार देर शाम तक 50 एक्सचेंज को क्रियाशील बनाया जाएगा और संभवतः रविवार की शाम तक हर एक्सचेंज बहाल हो जाएगी।

एक हफ्ते में स्कूल-कॉलेज खेलने का प्रयास : श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर डॉ. शाहिद इकबाल चौधरी की अध्यक्षता में शनिवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों और स्कूलों के प्रधानाचार्यों की बैठक में बताया गया कि श्रीनगर जिले के विभिन्न जोन में सोमवार को 190 स्कूल खोले जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि स्कूल बंद रहने से पढ़ाई का जो नुकसान हुआ है, उसके लिए इसी महीने के अंत में अतिरिक्त कक्षाएं भी लगाई जाएंगी। वहीं, रोहित कंसल ने कहा कि हमारा प्रयास है कि अगले एक सप्ताह में पूरी वादी में अकादमिक गतिविधियां बहाल हो जाएं।

प्रशासनिक पाबंदियों में ढील और लैंडलाइन फोन की बहाली का असर शनिवार को जवाहर सुरंग से लेकर उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा तक नजर आया। वहीं, ढील का फायदा उठाते हुए शरारती तत्व भी सक्रिय हो उठे। उन्होंने विभिन्न जगहों पर भड़काऊ नारेबाजी करते हुए श्रीनगर के बडगाश नगर, छन्नपोरा, नटीपोरा, रामबाग, आंचर-सौरा के अलावा उत्तरी कश्मीर के सोपोर, हारत्रठ सिंगपोरा में खुली दुकानों और सड़कों पर दौड़ते वाहनों पर पथराव किया। ऐसे में सुरक्षाबलों ने हल्का बल प्रयोग कर शरारती तत्वों को तितर-बितर किया।

कश्मीर पर होगी ऑल वेदर मैविक-प्रो ड्रोन की भी नजर

नवीन नवाज, श्रीनगर

कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और आतंकरोधी अभियानों के बेहतर संचालन के लिए सुरक्षाबलों को अत्याधुनिक ऑल वेदर मैविक-प्रो ड्रोन से लैस किया जा रहा है। यह ड्रोन आसमान में लगभग 350 मीटर की ऊंचाई तक उड़ने और वहीं से नीचे जमीन के हालात की सटीक निगरानी और फोटोग्राफी में सक्षम है। इनमें लगे कैमरे और चिप अवांछित तत्वों की निशानदेही कर उसी समय नियंत्रण कक्ष के लिए अलर्ट जारी करेंगे। प्रत्येक मैविक प्रो की कीमत लगभग डेढ़ लाख रुपये है। हालांकि कश्मीर में पुलिस, सीआरपीएफ, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के पास पहले से यूएवी और ड्रोन हैं। इनकी संख्या सीमित है। साथ ही यह पुरानी तकनीक से लैस हैं।

डोभाल ने तत्काल जारी किए निर्देश : सूत्रों की मानें तो पुलिस और सीआरपीएफ के पास चार से पांच ड्रोन ही थे। कई बार केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सेना से ड्रोन और यूएवी के लिए मदद लेनी पड़ती थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल के कश्मीर दौरे के दौरान संबंधित अधिकारियों ने इस विषय में चर्चा की थी। डोभाल ने उसी समय गृहमंत्रालय का ध्यान इस ओर दिलाया। इसके तत्काल प्रभाव से मैविक प्रो ड्रोन कश्मीर में पहुंचना शुरू हो गए।

अत्याधुनिक तकनीक का भरपूर इस्तेमाल हो रहा : कानून व्यवस्था की स्थिति से लेकर आतंकरोधी अभियानों के संचालन की रणनीति तय करने में शामिल वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस समय वादी में स्थिति तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में हैं। सामान्य जनजीवन भी धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहा है। पाबंदियों के साथ-साथ सड़कों से सुरक्षाबलों की मौजूदगी भी लगातार घटाई जा रही है। इसका फायदा राष्ट्रविरोधी तत्व और आतंकी संगठन उठाने की फिराक में है। वह किसी भी चूक का फायदा लेकर वादी में व्यापक तौर पर हिंसा, सिलसिलेवार बंद और हिंसक प्रदर्शनों का दौर शुरू कर सकते हैं। इसलिए नागरिक इलाकों से सुरक्षाबलों की मौजूदगी को घटाने के फैसले के मद्देनजर कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए अत्याधुनिक तकनीक के भरपूर इस्तेमाल का विकल्प अपनाया जा रहा है।

हर यूनिट को मिलेगा मैविक प्रो ड्रोन : अधिकारी ने बताया कि वादी में तैनात केंद्रीय अर्धसैनिकबलों की प्रत्येक यूनिट को अत्याधुनिक मैविक प्रो ड्रोन प्रदान किया जा रहा है। यह ड्रोन आसमा में जहां होगा, वहां से नीचे जमीन पर 500 मीटर के दायरे में हर वस्तु, व्यक्ति की निगरानी करते हुए उसकी फोटो और वीडियोग्राफी में सक्षम है।

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से लैस है यह ड्रोन

यह ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से पूरी तरह लैस है। दावा किया जाता है कि अगर यह किसी क्षेत्र विशेष की निगरानी करते हुए किसी वांछित आतंकी जिसकी तस्वीर संबधित कंट्रोल रूम के डाटा बैंक व संबधित कंप्यूटर में होगी, को देखता है तो तुरंत उसके बारे में सूचित करने में भी यह समर्थ है। मैविक ड्रोन अन्य ड्रोन के मुकाबले तेजी से उड़ान भरता है। यह आठ घंटे तक लगातार उड़ सकता है। मैविक प्रो के संचालन के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की प्रत्येक यूनिट में छह से सात लोगों को विशेष ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है।

'आतंकियों की ढाल बन गया था अनुच्छेद-370'

नागपुर, प्रेट्र: केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को कहा कि अनुच्छेद-370 आतंकियों और उनके संरक्षकों की ढाल बन गया था। सरकार ने देश के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर की जनता के हित में इस पर फैसला लिया है। वह महाराष्ट्र के नागपुर में राज्य कानूनी सेवा प्राधिकारियों की 17वीं अखिल भारतीय बैठक के उद्घाटन से इतर पत्रकारों से बात कर रहे थे।

कानून मंत्री ने कहा, 'हमें समझना चाहिए कि यह एक अस्थायी प्रावधान था और इसे देशहित में हटाया गया है। हम हमेशा देश और जम्मू-कश्मीर के लोगों की सुरक्षा के लिए प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर प्रगति करे।' उन्होंने कहा कि अनुच्छेद-370 के रहते न तो वहां भ्रष्टाचार निरोधक कानून लागू होता था, न ही बाल विवाह निषेध कानून। इतना ही सिर पर मैला ढोने की प्रथा आज भी वहां चल रही थी। आखिर यह कौन सा कश्मीर था? उन्होंने कहा कि स्थिति का जायजा लेने के बाद प्रशासन राज्य में आगे के उपाय करेगा।

पाक की किसी भी हरकत का कड़ा जवाब देंगे : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के इस बयान पर कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बालाकोट जैसा हमला करने की तैयारी कर रहा है, प्रसाद ने कहा कि वह क्या कहते हैं हम इस पर ध्यान नहीं देते। हालांकि पाकिस्तान की ओर से कोई भी कार्रवाई करने पर कड़ा जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क है और आतंकी गतिविधियों पर उचित जवाब दिया जाएगा।

- **कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, यह अस्थायी प्रावधान था, देशहित में हटाया गया**
- **कहा-हम चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर प्रगति करे**

नागपुर में शनिवार को स्टेट लीगल सर्विस प्राधिकरण की 17 वी अखिल भारतीय बैठक को संबोधित करते केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। प्रेट्र

जमानत के प्रावधानों पर कानून मंत्री ने दिए सुझाव

एक महिला जिसने सजा की एक चौथाई अवधि जेल में बिता ली हो, उसे तुरंत रिहा कर देना चाहिए। यह सुझाव केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को दिया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436-ए का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जमानत प्रावधान के बारे में उनके पास कुछ सुझाव हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल 436-ए के तहत यदि कोई अपराधी सजा की आधी अवधि जेल में बिता लेता है तो उसे नियमानुसार बांड पर रिहा कर देना चाहिए। ऐसे मामलों की समीक्षा के लिए जिला न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली समितियों का भी प्रावधान है। समीक्षा समिति को और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने की जरूरत है।

हिंडन और त्रिशूल एयरबेस हाई अलर्ट पर, सघन चेकिंग

जासं, गाजियाबाद : सुरक्षा कारणों को देखते हुए गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस और बरेली में त्रिशूल एयरबेस शनिवार को हाई अलर्ट पर रहे। पुलिस ने भी एयरबेस के चारों ओर गश्त बढ़ा दी है। सूत्रों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर दोनों एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है।

गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर शनिवार को आने-जाने वालों, अस्थायी कर्मचारियों, एयरबेस में रहने वाले लोगों के परिवार और उनके रिश्तेदारों समेत एक-एक व्यक्ति की सघन जांच कर एंट्री दी गई। सूत्रों की मानें तो कश्मीर के हालात को देखते हुए हिंडन एयरबेस को अलर्ट पर रखा गया है। माना जा रहा है कि कश्मीर में किसी भी तरह से स्थिति बिगड़ने पर यहां से विमान रवाना किए जाएंगे। ऐसे में एयरबेस की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। सीओ डॉ. राकेश मिश्र ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करते हुए हिंडन एयरबेस के आसपास संदिग्धों की जांच की जा रही है। उधर, बरेली में त्रिशूल एयरबेस के आसपास हाई अलर्ट जारी कर दिया गया।

रफ्तार पकड़ती घाटी...

कश्मीर घाटी में शनिवार को 35 पुलिस थाना क्षेत्रों में ढील के बाद सड़कों पर वाहन दौड़ते नजर आए। कश्मीर में हालात अब सामान्य होने लगे हैं। जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। यहां पाबंदियों पर धीरे-धीरे ढील दी जा रही है। जागरण

जम्मू-कश्मीर में सिख समुदाय को इंसाफ मिलने का रास्ता साफ

राज्य ब्यूरो, जम्मू

अनुच्छेद-370 हटाए जाने और 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित राज्य बनने के बाद राज्य में अल्पसंख्यक सिख समुदाय के साथ इंसाफ होने का रास्ता साफ हो जाएगा। अनुच्छेद-370 होने के कारण राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के क्षेत्राधिकार में जम्मू कश्मीर नहीं आता था। जम्मू कश्मीर का अपना अल्पसंख्यक आयोग भी नहीं था।

सिख समुदाय पिछले तीन दशक से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन करने या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के दायरे में राज्य को लाने की मांग उठाता रहा है। सिख समुदाय ने पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, महबूबा मुफ्ती से लेकर केंद्रीय नेताओं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समक्ष मामला उठाया, लेकिन समाधान नहीं निकला। गुरुओं के प्रकाशोत्सव पर हर बार अल्पसंख्यक आयोग के गठन की मांग होती थी। अब केंद्र शासित राज्य बन जाने से सभी केंद्रीय कानून सीधे ही लागू हो जाएंगे। ऐसे में अब अल्पसंख्यक समुदाय को अपने अधिकार मिल सकेंगे। स्कॉलरशिप मिलेगी, आनंद मैरिज एक्ट लागू होगा, अल्पसंख्यक समुदाय के मसलों का समाधान होगा। अगर समुदाय के किसी व्यक्ति

अनुच्छेद-370 हटने के बाद सिख समुदाय के साथ इंसाफ होगा। समुदाय के मसलों का समाधान होगा। स्कालरशिप उपलब्ध होने से समुदाय के बच्चों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का यह फैसला सराहनीय है।

-वीरेंद्र जीत सिंह, चेयरमैन नेशनल सिख फ्रंट

के साथ भेदभाव या ज्यादती होती है तो वे अपने मसलों को सीधे अल्पसंख्यक आयोग के समक्ष ले जा सकते है। इसके अलावा सिख समुदाय को जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा भी मिल जाएगा। सिख नेता मंजीत सिंह का कहना है कि हमारी दो दशकों से मांग रही है कि अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जाए, लेकिन राज्य सरकारों ने सिवाय आश्वासनों के कुछ नहीं दिया। भाई कन्हैया निष्काम सेवा सोसायटी के प्रधान महेंद्र सिंह ने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग के जरिए सिख समुदाय की समस्याओं का समाधान होगा।

जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय की आबादी आठ लाख के करीब है। इसमें कश्मीर के करीब 120 गांवों समेत पुंछ, सांबा, कठुआ, जम्मू, ऊधमपुर में बड़ी आबादी है, लेकिन समुदाय अपना प्रतिनिधि इसलिए नहीं चुन सकता है क्योंकि बिखरे हुए हैं।

लद्दाख का हैप्पीनेस इंडेक्स अन्य जगहों से अच्छा है : अर्जुन मुंडा

माला दीक्षित, लेह

लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद आदिवासी बहुल क्षेत्र लेह में 'आदि महोत्सव' की शुरुआत हुई है। महोत्सव के उद्घाटन के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भरी बारिश में उन्हें सुनने पहुंचे लद्दाखियों के उत्साह और जोश से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। लोगों की खुशी देखकर मुंडा ने कहा कि यहां का हैप्पीनेस इंडेक्स अन्य जगहों से ज्यादा है। शनिवार को शुरू हुआ नौ दिवसीय महोत्सव 25 अगस्त तक चलेगा।

केंद्रीय मंत्री ने आयोजन में पहुंचे लोगों के लिए दो शेर भी पढ़े - 'बारिश के मौसम में गर तुम न आते तो बारिश का मौसम यूं ही चला जाता', 'गीले बदन में तेरा मुस्कुराना, बिजली का जैसे यूं ही चमक जाना'। जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने लद्दाख को भरोसा दिलाया कि उनकी तरक्की, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार कृतसंकल्प है और इसके लिए वह हर तरह का सहयोग देंगे। महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर मौजूद लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने क्षेत्र की उन्नति के लिए केंद्र सरकार से लद्दाख को शेड्यूल छह में ट्राइबल एरिया घोषित करने की गुजारिश की।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने और लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्जा मिलने के बाद से केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय की ओर से यह पहला बड़ा आयोजन है। लद्दाख की करीब 95 फीसद आबादी जनजातीय है, इसीलिए तरक्की की पहली योजना लेकर जनजातीय मंत्रालय यहां पहुंचा है। जनजातीय मंत्रालय ने ट्राईफेड के जरिये लेह में नौ दिवसीय आदि महोत्सव का आयोजन किया है। इसमें 20 राज्यों के करीब 200 जनजातीय कलाकार अपने उत्पादों और कलाकृतियों की बिक्री करेंगे। इसमें लद्दाख के भी करीब 40 कलाकार हिस्सा ले रहे हैं।

आदि महोत्सव का उद्घाटन करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा, 'हम आपके वजूद, आपकी पहचान और आपकी आदि परंपरा को बचाने आए हैं। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद आदि महोत्सव के जरिये दुनिया में हम लद्दाख की पहचान बनाना चाहते हैं। यहां की मिट्टी की महक को बनाए रखना है।' उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश बनने की जो राज्य के लोगों की भावना थी, उस दृढ़ भावना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा और उसे पूरा किया। मुंडा ने कहा कि यह वह जगह है जहां से सिंधु नदी निकलती है। यहां की संस्कृति को सरकार बचाएगी। उन्होंने कहा, 'सरकार पश्मीना ऊन की बकरियों-बकरों को पालने वालों के लिए एक प्रोजेक्ट लाएगी ताकि बर्फबारी के दौरान ऐसी बकरियों को मरने से बचाया जा सके और पश्मीना के उत्पादन में वृद्धि हो। यहां शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की बेहतर व्यवस्था भी की जाएगी।'

क्षेत्र के सांसद जामयांग ने जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा और राज्य मंत्री रेणुका सिंह को धन्यवाद दिया। जामयांग ने कहा कि यहां की ज्यादातर आबादी आदिवासी है। अभी तक लेह लद्दाख का जितना विकास होना चाहिए, नहीं हुआ है। राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि देश को आजादी 1947 में मिली थी लेकिन लद्दाख को असल आजादी पांच अगस्त, 2019 को मिली है।

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शनिवार को लेह में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी पर्व 'आदि महोत्सव' में शामिल हुए। जागरण

खुलेंगे नए रास्ते

आदि महोत्सव के दौरान आदिवासियों को बाजार से जुड़ने के गुर सिखाए जाएंगे। उनके वन उत्पादों को देश और दुनिया के बाजारों तक पहुंचाया जाएगा। आदिवासियों की कलाओं को आगे बढ़ाने, उनके उत्पादों को देश-विदेश तक पहुंचाने और उनकी कला को संरक्षित रखने के उद्देश्य से जनजातीय मंत्रालय ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलेपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (ट्राइफेड) के साथ मिलकर इस आदि महोत्सव का आयोजन करता है। इस महोत्सव में जनजातीय मंत्रालय की वन धन योजना के तहत वन उत्पादों में वैल्यू एडीशन करके उन्हें बेहतर पैकेजिंग में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया जाता है। उत्पादों की बिक्री के लिए ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन से भी ट्राइब्स इंडिया ने समझौता किया है।

केरल में स्थिति सामान्य होने की ओर, आंध्र में 87 गांव डूबे

नई दिल्ली, प्रेट्र : बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित केरल में जीवन धीरे-धीरे सामान्य होने लगा है। राज्य में अभी तक 113 लोगों की जान जा चुकी है। दक्षिण के दूसरे राज्य आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा होने के बाद कृष्णा नदी उफान पर है। राज्य में 87 गांव और सैकड़ों एकड़ खेती की जमीन बाढ़ की चपेट में है। इस राज्य में मरने वालों की संख्या दो हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली सहित उत्तर के चार राज्यों में भारी वर्षा होने का अनुमान जाहिर किया है। दक्षिण के कर्नाटक में भी भारी वर्षा हो सकती है।

केरल में सबसे ज्यादा प्रभावित मालापुरम और वायनाड : केरल में राहत शिविरों से लोग अपने घरों को लौटने लगे हैं। राज्य में भूस्खलन प्रभावित मलापुरम और वायनाड जिलों में और शव मिलने की आशंका है। मालापुरम में 50 और वायनाड में 12 की मौत हो चुकी है। दोनों जिलों में लापता 28 लोगों की तलाश की जा रही है। आठ अगस्त से दूसरे दौर की मानसूनी वर्षा में दोनों जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं जहां दो गांव पूरी तरह खत्म हो गए।

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावितों को बचाने में जुटे अग्निशमन विभाग के कर्मी। प्रेट्र

आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के पानी में डूबा पुल : आंध्र प्रदेश में पुलिगाड्डा पुल करीब 10 साल बाद कृष्णा नदी की बाढ़ में डूब गया है। कृष्णा जिले में एडलंका, पुलिगाड्डा, पाल्लेपालेम, रेगुलंका, पाटा कोटा, वासुमाटला, बोब्बारलंका, कोट्टापालेम, नागायलंका सहित 34 गांव डूब गए हैं। गुंटूर जिले के 53 गांव भी कृष्णा नदी की चपेट में हैं।

मैदान और पहाड़ में बारिश से बिगड़े हालात

जेएनएन, नई दिल्ली : लगातार हो रही मूसलधार बारिश से मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से गांव के गांव जलमग्न हो गए हैं। पंजाब, राजस्थान, बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल में बुरा हाल है।

बंगाल में हो रही मूसलधार बारिश, अलर्ट : बंगाल में विगत दो दिनों से मूसलधार बारिश हो रही है। कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, बर्द्धमान व नदिया जिलों में हो रही बारिश के बीच राज्य सरकार ने सभी जिलों में अलर्ट जारी किया है। वहीं, राजस्थान के कई जिलों में पिछले कई दिनों से जारी लगातार बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं।

गोरखपुर में पंचायत ने लगाई महिला की कीमत 71 भेड़ें

जागरण संवाददाता, गोरखपुर : गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मामला ऐसा कि पुलिस भी परेशान है। पंचायत में 71 भेड़ों के बदले एक महिला को उसके प्रेमी के हवाले कर दिया गया। अब पंचायत के इस फैसले को प्रेमी के पिता रामनरेश ने मानने से इन्कार कर दिया है और खोराबार थाने में तहरीर देकर भेड़ें वापस दिलाने की मांग की है।

यह मामला हल होने की जगह तीन थानों में घूमता रहा। खोराबार पुलिस ने पिपराइच क्षेत्र का मामला बताकर पिपराइच थाने भेज दिया। पिपराइच थानाध्यक्ष ने भी रामनरेश की फरियाद नहीं सुनी और पंचायत बेलीपार क्षेत्र के ग्राम चारपानी में होना बताकर बेलीपार भेज दिया। आखिर में पिपराइच क्षेत्र के ग्राम बैलो निवासी रामनरेश ने शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि पंचायत का फैसला हमें मान्य नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचों ने एक व्यक्ति का बसा-बसाया घर उजाड़ दिया और बिना तलाक कराए विवाहित महिला को मेरे बेटे के गले में बांधने का फैसला सुना दिया।

उधर, पंचायत के फैसले के बाद महिला अब अपने पति के साथ रहने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की तो आत्महत्या कर लेगी। बकौल महिला उसकी शादी के पांच वर्ष हो गए पर मां बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ।

> भेड़ों को दिलाने के लिए बेलीपार थाना क्षेत्र में पंचायत हुई थी, इसलिए कार्रवाई भी वहीं से होगी। बेलीपार थानेदार को रामनरेश की भेड़ें वापस दिलाने का निर्देश दिया गया है। विवाहित महिला के प्रेमी के साथ जाने की जांच पिपराइच पुलिस कर रही है।
>
> **- डा.सुनील कुमार गुप्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक**

बंगाल में पत्र लिख मां-पिता के साथ बेटी ने मांगी इच्छा मृत्यु

संवाद सहयोगी, बैरकपुर : एक पीएचडी डिग्रीधारी बेटी अपने माता-पिता के साथ मौत को गले लगाना चाहती है। इसके लिए उसने कलेक्टर को पत्र लिखकर मांग की है कि उसे माता-पिता के साथ इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। 50 वर्षीय गार्गी बनर्जी ने पत्र में कलेक्टर से नौकरी की व्यवस्था या फिर मौत की अनुमति देने की अपील की है।

गार्गी उत्तर 24 परगना जिले के बारासात इलाके में रहती हैं। उन्होंने कलेक्टर को पत्र लिखा है, जिसमें 82 वर्षीय पिता कमल बनर्जी और 76 वर्षीय मां गीता बनर्जी के साथ इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की मांग की है। कलेक्टर चैताली चक्रवर्ती ने इस मामले में नगरपालिका के चेयरमैन को सूचित करने के साथ-साथ पीड़ित परिवार की समस्या का समाधान करने को कहा है।बताया जाता है कि एक समय बनर्जी परिवार काफी खुशहाल था। कमल बनर्जी दुर्गापुर स्टील प्लांट के कार्यालय प्रबंधक के पद पर थे। उनकी पत्नी गीता स्कूल टीचर थीं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 18 अगस्त 2019

21 से 23 अगस्त तक जबलपुर निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (12121) और 22 से 24 अगस्त तक निजामुद्दीन जबलपुर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (12122) निरस्त किया गया है। जबलपुर यार्ड में निर्माण कार्य के चलते ऐसा किया गया है।

न्यूज गैलरी

केरल की नन ने अपने निष्कासन को वेटिकन में चुनौती दी

कोच्चि : केरल की नन ने कहा है कि उन्होंने पादरियों की धर्मसभा से निष्कासित किए जाने के फैसले के खिलाफ वेटिकन में अपील दायर की है। धर्मसभा ने अपना रुख कड़ा करते हुए नन की बुजुर्ग मां को पत्र जारी कर उन्हें घर ले जाने के लिए कहा है। सिस्टर लूसी कालापुरा ने दुष्कर्म के आरोपित जालंधर के पूर्व बिशप फ्रैंको मुलक्कल के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लिया था। इस महीने के शुरू में फ्रांसिस्कन पादरी धर्मसभा (एफसीसी) से उन्हें निष्कासित किया गया है। धर्मसभा ने एफसीसी के कानून के खिलाफ अपनी जीवनशैली के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं सौंपने के कारण निष्कासित किया है। निष्कासित नन ने कहा, 'मैंने अपील दायर की है। शुक्रवार को वेटिकन को एक ईमेल भेजा है। मैंने शनिवार को डाक भी भेजा है। इसके साथ ही वेटिकन के नई दिल्ली में प्रतिनिधियों को भी अपील भेज दी है।' नन ने कहा कि धर्मसभा ने उनकी मां को 10 अगस्त को भेजे गए पत्र में वायनाड के कराकामाला में स्थित कान्वेंट से अपनी बेटी को घर ले जाने के लिए कहा है। 10 अगस्त को भेजे गए पत्र में मानांथवाडय में एफसीसी के प्रांतीय वरिष्ठ ने कहा है कि यदि नन 10 दिनों के भीतर फैसले के खिलाफ राहत पाने में विफल रहती हैं तो उन्हें कान्वेंट छोड़ना होगा। नन ने कहा कि धर्मसभा उन्हें कानूनी रूप से कान्वेंट छोड़ने के लिए नहीं कह सकता क्योंकि उन्होंने फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है। (प्रेट्र)

सतीश सना की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली : मोइन कुरैशी से जुड़ी कंपनी के 50 लाख रुपये के शेयरों की खरीद मामले में कारोबारी सतीश सना बाबू की जमानत अर्जी पर राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। शनिवार को हुई बहस में ईडी ने बाबू को जमानत देने का विरोध किया। बाबू को 26 जुलाई को मनी लांड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था और जांच में सहयोग नहीं करने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोप है कि मोईन के एक मामले को निपटाने के लिए सना ने सीबीआइ के तत्कालीन विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को रिश्वत दी थी। इसी मामले में आलोक वर्मा ने अस्थाना व उनके अधीनस्थों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। वहीं, दूसरी तरफ से अस्थाना के करीबी अधिकारियों ने वर्मा पर यही आरोप लगाया था। (जासं)

कोलकाता में जगुआर कार ने तीन को कुचला, दो की मौत

कोलकाता : कोलकाता में एक बेलगाम जगुआर ने मर्सिडीज कार को टक्कर मारने के बाद फुटपाथ पर खड़े तीन बांग्लादेशी नागरिकों को रौंद दिया। हादसे में एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार देर रात करीब दो बजे बिरला तारामंडल की ओर से आ रही तेज रफ्तार जगुआर कार ने लाउडन स्ट्रीट और शेक्सपीयर सरणी मोड़ पर मर्सिडीज कार को किनारे से जोरदार टक्कर मारने के बाद फुटपाथ पर खड़े तीन राहगीरों को रौंद दिया। इसके बाद यहां बने ट्रैफिक पुलिस के बूथ में जा घुसी। हादसे में महिला समेत तीन बांग्लादेशी नागरिक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मृतकों की शिनाख्त काजी मोहम्मद मइनुल आलम) तथा फरहाना इस्लाम तानिया के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपित जगुआर चालक अर्सलान परवेज को गिरफ्तार कर लिया। वह अर्सलान के मालिक का बेटा बताया गया है। उसके खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने एवं गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। (जासं)

सीजेएम करेंगे उमर और महबूबा के विरुद्ध मामले की सुनवाई

मुजफ्फरपुर : जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सहित अन्य के खिलाफ दाखिल परिवाद की जांच मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सीजेएम एसके तिवारी करेंगे। छह अगस्त को अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने यह परिवाद दाखिल किया था। इसमें अनुच्छेद 370 व 35 (ए) के विरुद्ध आपत्तिजनक बयान को लेकर राज्य के मंत्री श्याम रजक, जम्मू कश्मीर से पीडीपी सांसद नजीर अहमद लवाय, मो. फैयाज और पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी को आरोपित बनाया था। इस मामले में इसकी अगली सुनवाई पांच सितंबर को होगी। (जासं)

मप्र में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 11 लोगों की आंखों की रोशनी गई

कार्रवाई ▶ स्वास्थ्य मंत्री ने दिया इंदौर आई अस्पताल का लाइसेंस रद करने का आदेश

ऑपरेशन थिएटर सील, कल्चर की जांच में मिला बैक्टीरिया

नईदुनिया, इंदौर

मध्य प्रदेश के इंदौर में 'इंदौर आई हॉस्पिटल' में मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने के बाद 11 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। मामले में सात सदस्यीय जांच समिति गठित करने के साथ ही अस्पताल का ऑपरेशन थियेटर सील कर दिया गया है। वहां से लिए गए कल्चर (बैक्टीरिया की पहचान के लिए जुटाए गए सैंपल) की प्रारंभिक जांच में स्यूडोमोनास एरूजिनोसा नामक बैक्टीरिया मिला है। वहीं, मप्र के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर एफआइआर करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर घटना पर दुख जताया है।

गौरतलब है कि अंधत्व निवारण योजना के तहत धार जिले से 12 और इंदौर से दो मरीजों को सात अगस्त को इंदौर आई हॉस्पिटल (निजी अस्पताल) लाया गया था। आठ अगस्त को ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद आंख में ड्रॉप डालने के बाद 11 मरीजों को दिखाई देना बंद हो गया। अस्पताल प्रबंधन ने एक दिन बाद भोपाल में विभाग के आलाधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद अस्पताल का ऑपरेशन थियेटर सील कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ (मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी) डॉ. प्रवीण जड़िया ने आठ दिन बाद भी इस घटना की सूचना कलेक्टर, संभागायुक्त व स्वास्थ्य मंत्री को नहीं दी। शनिवार को मामला उजागर होने के बाद अधिकारी हरकत में आए और पीड़ित मरीजों को चोइथराम नेत्र अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिलावट ने मामले की जांच के लिए सात सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इसमें संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर लोकेश जाटव, मेडिकल कॉलेज डीन डॉ. ज्योति बिंदल, सीएमएचओ डॉ. प्रवीण जड़िया, डॉ. सुमित शुक्ला, डॉ. विजय भाईसारे व डॉ. राजीव चौधरी शामिल हैं। शनिवार दोपहर टीम के सदस्य डॉ. सुमित शुक्ला ने अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन थियेटर को पहले ही सील किया जा चुका है। सिलावट ने मरीजों को रेडक्रॉस सोसायटी से 20-20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता व सभी खर्चे स्वास्थ्य विभाग द्वारा उठाए जाने का आश्वासन दिया है।

प्रभावित मरीजों को चोइथराम अस्पताल ले जाया गया। नईदुनिया

गेंदालाल ने कहा, पहले धुंधला दिखाई दे रहा था

इंदौर आई अस्पताल में भर्ती धार निवासी गेंदालाल ने बताया कि सात अगस्त को ऑपरेशन किया गया। पहले बायीं आंख से धुंधला दिख रहा था। ऑपरेशन के दूसरे दिन दवाई डाली। उसके बाद से दिखाई देना बंद हो गया। डॉक्टर धीरे-धीरे रोशनी आने की बात कह रहे हैं।

अस्पताल का दावा- ऑपरेशन थियेटर पूरी तरह से संक्रमण रहित

इंदौर आई अस्पताल के डॉ. सुधीर महाशब्दे ने बताया कि अस्पताल में हर साल करीब 3500 ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन थियेटर को पहले से अधिक आधुनिक किया गया है। इसे बैक्टीरिया रहित भी किया जाता है। ऑपरेशन के बाद मरीजों को दिखाई नहीं दे रहा था। कल्चर जांच प्राइवेट लैब में कराई तो मरीजों की आंख पर स्यूडोमोनास एरूजिनोसा बैक्टीरिया का असर पाया गया। अब यह बैक्टीरिया कहां से आया, इसकी जांच की जानी है। ऑपरेशन में कोई भी गलती नहीं हुई है। प्रशासन को पूरा सहयोग व हर तरह की जांच में सहयोग करेंगे। कुछ मरीजों को अब धीरे-धीरे दिखना शुरू भी हुआ है।

लगा यूएपीए, विधायक अनंत सिंह अब होंगे गिरफ्तार

- घर से एके-47 और ग्रेनेड बरामदगी मामले में केयरटेकर गिरफ्तार
- विधायक के खिलाफ कोर्ट से सोमवार को जारी हो सकता है वारंट

जागरण संवाददाता, पटना

घर से एके 47 और ग्रेनेड मिलने के मामले में पटना पुलिस ने मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी कर ली है। उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट और यूएपीए (गैरकानूनी अधिनियम रोकथाम कानून) के तहत केस दर्ज किया गया है। सोमवार को उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करवाने के लिए पुलिस कोर्ट जाएगी। शनिवार को कोशिश की गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों से संभव नहीं हुआ। उनके घर के केयरटेकर को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस ने विधायक अनंत सिंह और केयरटेकर सुनील राम सहित अन्य अज्ञात लोगों पर बाढ़ थाने में आइपीसी की धारा 414, आर्म्स एक्ट, यूएपीए की धारा 13 के अलावा विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। अनंत सिंह के पटना के लदमा गांव स्थित पैतृक आवास से शुक्रवार को एके 47, दो ग्रेनेड, 26 कारतूस और एक मैगजीन की बरामदगी हुई थी। एएसपी लिपि सिंह को केस की जांच सौंपी गई है।

ग्रेनेड को निष्क्रिय किया गया : अनंत सिंह के घर से मिले ग्रेनेड को निष्क्रिय करने के लिए शनिवार को पुलिस ने कोर्ट में आवेदन दिया था। अदालत से अनुमति मिलने के बाद एटीएस की टीम ने इसे निष्क्रिय कर दिया। अनंत सिंह के घर से बरामद हथियार और विस्फोटक पदार्थों की जांच के लिए शनिवार को सेना के अधिकारी लदमा गांव पहुंचे। शनिवार की रात तक पुलिस के जवान विधायक के घर पर डटे हुए थे। ग्रेनेड मिलने का बिहार में यह पहला मामला है।

अनंत सिंह। फाइल फोटो

क्या है 13 यूएपीए : अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट (यूएपीए) 1967 में बना था। इस एक्ट की धारा 13 का आरोपित आरोपपत्र के 180 दिनों तक नजरबंद और 30 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है। प्रतिबंधित हथियारों को रखने, एक से दूसरी जगह ले जाने व इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ इसका उपयोग होता है। इस वर्ष जुलाई में यूएपीए की कई धाराओं में केंद्र ने संशोधन किया है, जिसके तहत यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति विशेष को आतंकी घोषित किया जा सकता है। हालांकि, संशोधन वाली धारा का प्रयोग अभी अनंत सिंह के खिलाफ नहीं किया गया है।

उन्नाव दुष्कर्म की जांच पूरी करने को सीबीआइ ने मांगा एक सप्ताह

जासं, नई दिल्ली : उन्नाव कांड से जुड़े सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच पूरी करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अदालत से एक सप्ताह की मोहलत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो चार मामले उत्तर प्रदेश से दिल्ली भेजे गए थे, उनमें सामूहिक दुष्कर्म का मामला भी है। इस मामले में शुभम सिंह, नरेश तिवारी और बृजेश सिंह यादव आरोपित हैं, जो जमानत पर हैं।

शनिवार को तीस हजारी अदालत में सीबीआइ की तरफ से विशेष अभियोजक ने बताया कि जांच अंतिम चरण में है और एक सप्ताह में इसे पूरा कर लिया जाएगा। अदालत से सीबीआइ ने पहले 30 दिन का समय मांगा था, लेकिन अदालत 17 अगस्त को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था। वहीं आरोपितों की तरफ से वकील ने अदालत में कहा कि जब तीन मामलों में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है तो 16 माह से इस मामले की जांच में ऐसा क्या किया जा रहा है? हालांकि अदालत ने सीबीआइ को समय देते हुए सुनवाई 26 अगस्त के लिए तय कर दी है। इस मामले में पीड़िता के साथ 11 जून 2017 को सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में शुभम, नरेश और बृजेश के खिलाफ केस दर्ज है।

मध्य प्रदेश में युवक को खूंटे से बांधकर पीटा, वीडियो वायरल

नईदुनिया, शाजापुर

- प्रेम-प्रसंग से जुड़ा मामला होने का शक
- पीड़ित गंभीर रूप से घायल

मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के ग्राम खड़ी में 25 वर्षीय युवक को खूंटे (मवेशी आदि को बांधकर रखने के लिए गाड़ा गया डंडा) से बांधकर बेहरमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। युवक देवास जिले का है, जो नौकरी के सिलसिले में शुजालपुर से लौटकर अपने गांव जा रहा था, तभी खड़ी के बस स्टैंड से कुछ लोग उसे जबर्दस्ती ले गए। मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। घटना शुक्रवार की है और शनिवार को वीडियो वायरल हुआ।

पुलिस के अनुसार, सोनकच्छ (देवास) के पास ग्राम ऐनाबाद का बंटी पुत्र भगवानसिंह शुजालपुर गया था। लौटते समय ग्राम खड़ी के बस स्टैंड पर चाय पीने रुका, तभी कुछ लोग उसे पकड़कर ले गए और खूंटे से बांध दिया। फिर एक घंटे तक उसे पीटते रहे। बंटी लहुलुहान अवस्था में और मारपीट नहीं करने की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। इस बीच किसी ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस उसको अपने साथ लेकर आई और अस्पताल में भर्ती कराया। यहां से उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पोलायकलां चौकी प्रभारी सचिन आर्य ने बताया कि पीड़ित के बयान के आधार पर तीन नामजद लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। मेडिकल परीक्षण के आधार पर धाराएं बढ़ाई जाएंगी।

शाजापुर में इस तरह खूंटे से बांधकर युवक की पिटाई की गई। वीडियो ग्रैब

पहलू के परिजन बोले, घर-जमीन सब बिक जाए पर न्याय लेकर रहेंगे

नरेन्द्र शर्मा, जयपुर

देश के चर्चित पहलू खान उन्मादी हिंसा (मॉब लिंचिंग) मामले में मेव समाज और पहलू के परिजनों ने आरोपितों को बरी करने वाले अलवर के एडीजे कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार के दबाव में दिया गया निर्णय बताया है। परिजनों ने कहा है कि उनकी घर-जमीन सब कुछ बिक जाए, पर वह न्याय लेकर रहेंगे। उधर, राजस्थान सरकार निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सोमवार को हाई कोर्ट में अपील करेगी।

हरियाणा और राजस्थान के मेवात इलाकों में मेव समाज के संरक्षक शेर खान का कहना है कि जज डॉ.सरिता स्वामी ने न्याय नहीं किया बल्कि फैसला दे दिया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो निर्णय आया है, वह केंद्र सरकार की सोच से प्रभावित है। पहलू खान के बेटे इरशाद का कहना है कि चाहे घर-जमीन सब बिक जाए, लेकिन न्याय लेकर रहेंगे। इरशाद का कहना है कि कोर्ट ने वीडियो देखने के बाद भी आरोपितों को बरी कर दिया। हमें इससे सदमा लगा है। हमें चोट पहुंची है।

अधिकारियों संग की बैठक : मेव समाज के संरक्षक शेर मोहम्मद व इरशाद सहित अन्य लोगों ने शनिवार को राज्य के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप और मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका के साथ बैठक हुई। इस बैठक में तय किया गया कि गहलोत सरकार सोमवार को एडीजे कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेगी। मेव समाज इस अपील में साथ रहेगा। मेव समाज अलग से कोई अपील नहीं करेगा।

इसलिए फैसले पर उठा रहे सवाल : शेर मोहम्मद और इरशाद ने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि एडीजे कोर्ट ने जिस वीडियो को सही नहीं माना वह हमारे किसी आदमी ने तो बनाया नहीं, फिर ये फर्जी कैसे हो सकता है।

गहलोत सरकार पर है भरोसा : गहलोत सरकार ने जैसे ही केस की दोबारा जांच कराने की बात कही तो पहलू खान के परिवार को उम्मीद की किरण नजर दिखाई देने लगी। इरशाद के मुताबिक चुनाव के दौरान 'अब होगा न्याय का नारा' और मुलाकात के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें इंसाफ का जो भरोसा दिलाया था, उस पर कहीं न कहीं गहलोत सरकार खरी उतरती दिख रही है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि गहलोत सरकार के दखल के बाद पुलिस की जांच सही दिशा में जाएगी और दोषियों को सजा मिलेगी।

सख्ती से निपटने का सर्कुलर जारी : राज्य सरकार के गृह विभाग ने शनिवार को एक सर्कुलर जारी कर पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए उन्मादी हिंसा (मॉब लिंचिंग) कानून का पूरी तरह से पालन किया जाए। उन्मादी हिंसा को अंजाम देने वालों से सख्ती से निपटा जाए।

गांव वालों और रिश्तेदारों के भरोसे चल रहा घर : पहलू खान के बेटे इरशाद ने कहा कि ढाई साल पहले तक हमारे घर में सात-आठ गाय और भैंस थीं, इनका दूध बेचने से हमारे परिवार को 20-25 हजार रुपये मिल जाते थे। पिता पहलू खान की मौत के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई। घर में एक भैंस और एक बछड़ा है। वकीलों और कोर्ट के चक्कर लगाते-लगाते हमारे जानवर बिक गए। घर खर्च चलाने में मुश्किल हो रही है। दैनिक जागरण से बात करते हुए इरशाद ने बताया कि अब घर खर्च गांव वालों, रिश्तेदारों और उनके दोस्तों के भरोसे चल रहा है।

'मुद्दे का समाधान करें अधिकारी नहीं तो लोगों से कहेंगे धुलाई करो'

नागपुर, प्रेट्र : लालफीताशाही पर प्रहार करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उन्होंने कुछ अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि कुछ मुद्दों का समाधान नहीं किया तो वह लोगों से धुलाई करो (पिटाई करने को) कहेंगे।

गडकरी के पास सड़क परिवहन के अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग भी है। वह एमएसएमई क्षेत्र में काम करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध संगठन लघु उद्योग भारती के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

सम्मेलन में भाग लेने आए उद्यमियों से गडकरी ने अपने कारोबार का तेजी से विस्तार करने के लिए कहा। केंद्रीय मंत्री ने सरकारी अधिकारियों द्वारा कारोबारियों को परेशान किए जाने के बारे में बात की। उन्होंने कहा, 'आखिर हमारे पास यह लालफीताशाही क्यों है। आखिर ये सारे इंस्पेक्टर क्यों आते हैं। वे हफ्ता लेते हैं। मैं उनके सामने कहता हूं, आप (सरकारी) नौकर हैं और मैं लोगों द्वारा चुना गया हूं। मैं लोगों के लिए उत्तरदायी हूं। यदि आपने चोरी की तो मैं आपको चोर कहूंगा।'

लोकसभा में नागपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले गडकरी ने कहा, 'शनिवार को मेरी यहां आरटीओ कार्यालय में निदेशक और यातायात आयुक्त के साथ बैठक हुई। मैंने उनसे कहा कि आप आठ दिनों के भीतर इस समस्या का समाधान करें नहीं तो मैं लोगों से आपके हाथ से कानून छीनने और पिटाई करने को कहूंगा। मेरे शिक्षकों ने मुझे यही सिखाया है कि जो प्रणाली न्याय नहीं करे उसे उखाड़ फेंको।'

नितिन गडकरी। फाइल फोटो

ड्रा से हुआ सबरीमाला मंदिर के प्रधान पुजारी का चुनाव

तिरुवनंतपुरम, प्रेट्र : मलप्पुरम जिले के एके सुधीर नंबूदिरी को शनिवार को ड्रा के जरिये सबरीमाला स्थित अयप्पा मंदिर का प्रधान पुजारी चुना गया। उनका कार्यकाल एक साल का होगा, जिसकी शुरुआत 17 नवंबर से होगी। वहीं अलुवा के एमएस परमेश्वरन नंबूदिरी को सबरीमाला स्थित मल्लिकापुरम देवी मंदिर का प्रधान पुजारी चुना गया है। नए चयनित प्रधान पुजारी 16 नवंबर से शुरू होने वाले 41 दिनी मंडलम तीर्थयात्रा सीजन की शुरुआत में पदभार ग्रहण करेंगे।

दरअसल, मंदिर को शनिवार से शुरू हो रहे मलयालम महीने चिंगम के पांच दिवसीय मासिक अनुष्ठान के लिए शुक्रवार शाम को खोला गया था। शुक्रवार को किसी प्रकार की पूजा-अर्चना नहीं हुई। त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने कहा कि वर्तमान प्रमुख पुजारी वीएन वासुदेवन नंबूदिरी ने अष्टद्रव्य महा गणपति होमम और अन्य अनुष्ठान किए। 21 अगस्त की शाम को अनुष्ठान के बाद मंदिर बंद कर दिया जाएगा।

उप्र के खनन घोटाले में ईडी जल्द जब्त करेगा संपत्तियां

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- पूर्व मंत्री गायत्री की बेनामी संपत्तियों की जुटाई जानकारी

उप्र में सपा शासनकाल में हुए करोड़ों के खनन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत अन्य आरोपितों की संपत्तियां अटैच करने की तैयारी में है। ईडी ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की कई बेनामी संपत्तियों का ब्योरा जुटाया है। इसके अलावा जांच के दायरे में आए कई आइएएस अधिकारियों की संपत्तियों के बारे में भी जांच एजेंसी को अहम जानकारियां मिली हैं।

ईडी ने बीते दिनों पूर्व मंत्री गायत्री से उनकी संपत्तियों को लेकर लंबी पूछताछ की थी। यह जानने का प्रयास किया था कि अवैध खनन से हुई काली कमाई का निवेश कहां किया गया है। ईडी को पूर्व मंत्री के कई करीबियों की बोगस कंपनियों के बारे में भी ठोस जानकारी मिली थी।

सूत्रों का कहना है कि जल्द ईडी पूर्व मंत्री की कुछ संपत्तियों को अटैच करने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही खनन घोटाले में आरोपित आइएएस अधिकारी फतेहपुर के तत्कालीन डीएम अभय सिंह, देवरिया के तत्कालीन डीएम विवेक और एडीएम देवी शरण उपाध्याय की संपत्तियों का ब्योरा भी जुटाया गया है। ईडी तीनों आरोपित अधिकारियों से पूछताछ की तैयारी भी कर रहा है। माना जा रहा है कि जल्द उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। इसके अलावा आइएएस अधिकारी जीवेश नंदन व संतोष कुमार राय की संपत्तियों की जांच भी चल रही है। इन दोनों को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजे जाने की तैयारी है। गौरतलब है कि ईडी ने हमीरपुर में हुए खनन घोटाले के मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। बीते दिनों ईडी ने फतेहपुर, देवरिया, कौशांबी व शामली में हुए खनन घोटाले में भी केस दर्ज किया है।

नीतीश समेत कई नेताओं ने जाना अरुण जेटली का हाल

जासं, नई दिल्ली : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली की हालत नाजुक बनी हुई है। उनका हाल जानने के लिए शनिवार को भी कई केंद्रीय मंत्री, सांसद और वीआइपी एम्स पहुंचे।

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा नेता भूपेंद्र यादव, दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह, पीयूष गोयल, डॉ. हर्षवर्धन और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई दिग्गज नेता जेटली का हालचाल जानने के लिए एम्स पहुंचे। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, जेटली के उपचार पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार नजर रख रही है। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है।

चिंताजनक

इसी महीने आयोजित होने वाले एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में गेहूं की गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां और रोगों के प्रकोप को थामने जैसे विषय पर चर्चा होगी।

दुनिया के दूसरे देशों को लुभा नहीं पा रहा भारतीय गेहूं

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

- दशकों की मशक्कत के बाद भी गेहूं में नहीं बढ़ पा रही प्रोटीन की मात्रा
- हरित क्रांति के बाद से साढ़े चार सौ प्रजातियां विकसित, पर वैश्विक मानक के अनुरूप नहीं
- कुछ एशियाई व अफ्रीकी देशों को छोड़कर और किसी देश में भारतीय गेहूं की मांग नहीं है

प्रतीकात्मक

भारतीय गेहूं की प्रजातियां दुनिया के दूसरे देशों को नहीं लुभा पा रही हैं। दशकों की मशक्कत के बाद भी गेहूं की घरेलू प्रजातियों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाए नहीं बढ़ पा रही है। यही वजह है कि बंपर पैदावार के बावजूद घरेलू गेहूं की अंतराष्ट्रीय बाजार में निर्यात मांग की संभावनाएं नहीं बन पा रही हैं। इसी महीने आयोजित होने वाले एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में गेहूं की गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां और रोगों के प्रकोप को थामने जैसे विषय पर चर्चा होगी।

वर्ष 1960-70 में आई हरितक्रांति के बाद से गेहूं की साढ़े चार सौ प्रजातियां विकसित की गई हैं, लेकिन घरेलू गेहूं में प्रोटीन की मात्रा 12 फीसद की सीमा को नहीं छू पाई है। वैश्विक मानक के अनुरूप गुणवत्ता न होने की वजह से घरेलू गेहूं की निर्यात मांग न के बराबर है। कुछ एशियाई व अफ्रीकी देशों को छोड़कर और किसी देश में भारतीय गेहूं की मांग नहीं है।

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि संस्थान के एग्रोनोमी क्षेत्र में जाने पहचाने वैज्ञानिक प्रोफेसर रमेश कुमार सिंह के मुताबिक अगस्त के आखिरी सप्ताह में इंदौर में होने वाले 'अंतरराष्ट्रीय गेहूं व जौ अनुसंधान कार्यकर्ता सम्मेलन' में इन सारी चिंताओं पर गंभीर चर्चा होगी। घरेलू गेहूं में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के साथ कई और मुद्दे होंगे, जिन पर विचार-विमर्श होगा। सम्मेलन में सीमित होते प्राकृतिक संसाधनों के बीच गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाने और उसकी गुणवत्ता में सुधार की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों पर चर्चा होगी। ज्यादातर प्रजातियों में प्रोटीन की मात्रा 12 फीसद से कम ही पाई गई है। इसे बढ़ाने को लेकर प्रयास जारी है।

सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका की कर्नल यूनिवर्सिटी और नार्मन बोरलॉग फाउंडेशन के साथ घरेलू 29 अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे। गेहूं की क्वालिटी में सुधार लाने के अलावा जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाले रोगों की चुनौतियां भी विचार-विमर्श का हिस्सा होंगी। फिलहाल दुनियाभर में 'व्हीट ब्लास्ट' जैसे घातक रोग का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है।

इस बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आइएआरआइ) के प्रोफेसर एनके सिंह के मुताबिक फिलहाल यह रोग भारत तक नहीं पहुंचा है, लेकिन भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में व्हीट ब्लास्ट के प्रकोप की सूचना है, इसीलिए सीमाई राज्य बंगाल के नजदीकी तीन चार जिलों में गेहूं की खेती पर पाबंदी लगा दी गई है। इसे लेकर सरकार पूरी मुस्तैदी बरत रही है।

इंदौर सम्मेलन में गेहूं की ईजाद हुई प्रजातियों के किसानों तक न पहुंचने का मसला भी उठेगा। देश के विभिन्न गेहूं अनुसंधान संस्थानों व विश्वविद्यालयों में अब तक 448 प्रजातियां विकसित की गई हैं, लेकिन हैरानी इस बात की है कि केवल तीन दर्जन प्रजातियां ही किसानों को पसंद आई हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसमें तमाम प्रजातियां ऐसी हैं जो किसानों की पसंद नहीं बन पाईं। ज्यादातर प्रजातियां प्रसार प्रणाली की कमी के चलते खेतों तक नहीं पहुंच सकी हैं।

निदा और फरहत को तीन दिन में भारत से भगाने की धमकी

- ऑल इंडिया फैजान-ए-मदीना काउंसिल के अध्यक्ष ने दी धमकी, वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, बरेली

निदा खान और फरहत को तीन दिन में भारत से भगाने की धमकी दी गई है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, जिसमें ऑल इंडिया फैजान-ए-मदीना काउंसिल के अध्यक्ष मोईन सिद्दीकी नूरी निदा और फरहत को धमकी दे रहे हैं।

बता दें कि पिछले वर्ष 20 जुलाई को निदा खान और फरहत नकवी की चोटी काटने या पत्थर मारकर देश से निकालने पर 11,786 रुपये का इनाम मोईन सिद्दीकी नूरी ने रखा था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। अब शनिवार को उनका फिर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह फरहत नकवी और निदा खान को तीन दिन में भारत से भगाने का दावा करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वह यह भी कह रहे हैं कि कौन उलमा कहता है कि शिया मुसलमान होते हैं। अब हमारा संगठन चैन से नहीं बैठेगा। वीडियो में वह कह रहे हैं कि तीन दिन के अंदर निदा और फरहत को भारत से भगा देंगे।

आला हजरत हेल्पिंग सोसायटी की अध्यक्ष निदा खान ने कहा कि यह साजिश है। पुलिस मोईन को पकड़े। उससे पूछे कि समाज में वैमनस्य फैलाने वाले बयान किसके इशारे पर दे रहे हैं।

वहीं, मेरा हक फाउंडेशन की अध्यक्ष फरहत नकवी ने कहा कि शिया को काफिर होने की टिप्पणी कर मोईन सुर्खियां पाना चाहते हैं। उनमें हिम्मत है तो मुझे तीन दिन में देश से निकालकर दिखाएं।

कौन हैं निदा व फरहत : निदा व फरहत ने तीन तलाक पीड़िताओं के हक में लड़ाई लड़ी है। निदा हजरत खानदान की बहू रहीं हैं। उनका पति शीरान रजा खान से तलाक का मुकदमा चल रहा। फरहत नकवी भी अपने संगठन के जरिये तीन तलाक पीड़िताओं की आवाज उठाती हैं।

स्वर्ग यहां नर्क यहां

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) को गुलाम कश्मीर कहा जाता है। वहां के सामाजिक, आर्थिक और मानवाधिकारों की स्थिति पर नई दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस ने साल 2011 में एक शोध रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में किए गए खुलासे वैश्विक जगत को अवाक करने के लिए काफी हैं।

शासन व्यवस्था

1947 के बाद से जम्मू-कश्मीर के भारत शासित भाग में संविधान की धारा 370 के अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। जबकि पीओके का भाग जिसमें दो हिस्से (पहला गुलाम जम्मू और कश्मीर व दूसरा गिलगित-बाल्टिस्तान के क्षेत्र) थे, दोनों ही दिशाहीन रहे। गुलाम कश्मीर के नेताओं ने उत्तरी क्षेत्र पाकिस्तान को अप्रैल 1949 में समझौते के तहत सौंप दिया।

प्रशासनिक रूपरेखा

अक्टूबर 1947 को गुलाम कश्मीर में सरकार का गठन हुआ। यह सरकार युद्ध समिति की तरह काम कर रही थी। राष्ट्रपति के पास विधि और कार्यकारिणी संबंधी सभी अधिकार थे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी का विश्वास जीतने वाले व्यक्ति को ही राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया जाता था। सेंट्रल पाकिस्तान में एक सर्वोच्च प्रशासकीय कार्यालय खोला गया था जो कि गुलाम कश्मीर के राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णयों को अंतिम स्वीकृति प्रदान करता था।

प्राकृतिक संपदा

गुलाम कश्मीर में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं। वहां पर महंगे रत्न के बड़े भंडार हैं। वहां विश्व का सबसे अच्छा रूबी और मार्बल पाया जाता है। बड़ी मात्रा में पानी मौजूद है। पनबिजली भी बड़ी मात्रा में बन सकती है। प्रचुर संसाधन ही चीन की दिलचस्पी की वजह हैं। पाकिस्तान वर्षों से यहां के संसाधनों का दोहन करता आया है।

छंटती धूल

पाकिस्तान यहां की स्थिति को दुनिया के सामने न आने के लिए सभी कोशिशें करता रहा है। वहां पर बड़ी संख्या में अंदरूनी आंदोलन चल रहे हैं। राष्ट्रवादी लोग वहां पर पाकिस्तानियों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों का खुलासा कर रहे हैं।

मानवाधिकार उल्लंघन

एमा निकोलसंस की रिपोर्ट के अनुसार वहां पर स्थानीय प्रशासन दिशाहीन है और पाकिस्तानी सेना और सरकार का ही नियंत्रण है। लोगों को रहन-सहन, शिक्षा और अन्य चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

बढ़ती जिहादी गतिविधि

1990 के बाद से पीओके बढ़ती आतंकी गतिविधियों का गढ़ बन गया है। लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन वहां के लोगों को जिहाद के लिए उकसा कर अपने संगठन में शामिल कर रहे हैं। यह सिलसिला वर्ष 2005 में इलाके में भूकंप से मची तबाही के बाद अधिक हो गया है। जमात-उद-दावा आतंकी संगठन भी लोगों को अपने संगठन में भर्ती कर रहा है। आतंकी संगठनों के लिए वहां काम करना ज्यादा आसान है क्योंकि वहां के आर्थिक और राजनीतिक हालात खराब हैं। तहरीक-ए-तालिबान के द्वारा भी कई आतंकी संगठनों को मदद मुहैया होती है। दर्जनों आतंकी संगठन हैं जो इस क्षेत्र में अपनी पैठ बनाए हुए हैं।

बढ़ता चीनी प्रभाव

पाकिस्तान और चीन के बीच काराकोरम हाईवे का 1978 में निर्माण हुआ। यह करीब 1280 किमी लंबा है। यह हाईवे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वां प्रांत को जेजियांग क्षेत्र के कश्गर से जोड़ता है। करीब 800 किमी का हाईवे क्षेत्र पाकिस्तान में है जो पीओके के गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र से होकर गुजरता है। इस हाईवे का रखरखाव चीन ही करता है। इसके जरिये चीन से पाकिस्तान में परमाणु हथियार भी पहुंचाए जाते हैं। चीन पीओके में कई तरह की परियोजनाओं पर भी काम कर रहा है। चीनी कंपनियां वहां पर मौजूद नदियों पर ऊर्जा परियोजनाएं बना रही हैं। इसके अलावा भी गुलाम कश्मीर में पानी से जुड़ी कई योजनाओं पर चीन काम कर रहा है।

पीओके की पीर

अब भारत का अपने अखंड भूभाग जम्मू कश्मीर पर दावा और पुख्ता होता जा रहा है। जब हम अखंड जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसमें गुलाम कश्मीर यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) शामिल होता है। पाकिस्तान ने इस पर अवैध कब्जा कर रखा है। अपनी भेदभाव पूर्ण नीतियों से पूरे क्षेत्र को बदहाल और आतंकवाद की नर्सरी बना रखा है। भारत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर एक तरह से कई निशाने साधे हैं। एक तो अब विवादित क्षेत्र का विमर्श गुलाम कश्मीर पर केंद्रित हो चुका है। दूसरी बड़ी उपलब्धि आर्थिक मोर्चे की है। गुलाम कश्मीर के लोग पाकिस्तानी हुकूमत के भेदभाव और मनमाने रवैए से अकुलाए हैं। जब वे देखते हैं कि भारत के हिस्से वाले उनके भाई-बंधु इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो उनके मन में भी हूक उठती है कि काश वे भी उसी क्षेत्र में रहते होते। ये गुलाम कश्मीर, बाल्टिस्तान और गिलगित के हर शख्स के दिल की आवाज है। संगीनों के साए में आवाजों को खामोश नहीं किया जा सकता है। भारत भी उनकी मनोदशा को समझते हुए रणनीति बनाने में जुटा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद गुलाम कश्मीर को लेकर भारत की सक्रियता तेज होगी। अंतरराष्ट्रीय से लेकर द्विपक्षीय रिश्तों में इस सक्रियता की पड़ताल आज हम सबके लिए बड़ा मुद्दा है।

लोगों की इच्छा का सम्मान करे दुनिया

प्रो धीरज शर्मा
निदेशक- आइआइएम, रोहतक

इतिहास ऐसे तमाम मौकों का साक्षी रहा है जब लोगों की इच्छाओं की खातिर दूसरी सरकारों की जमीन को किसी और देश में मिलाया गया है। पाकिस्तान के प्रति गुलाम कश्मीर के आक्रोश का दुनिया को सम्मान करना चाहिए।

जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के संबंध में हाल के निर्णय से कश्मीर के भविष्य पर कई तरह के विचार आए हैं। अधिकांश विचार कश्मीर के मुद्दे पर केंद्रित हैं, वहीं कुछ कश्मीरियों पर केंद्रित हैं। 1948 में कश्मीर क्षेत्र पर पाकिस्तान द्वारा युद्ध छेड़ने के साथ कश्मीर को लेकर संघर्ष शुरू हुआ। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भारतीय क्षेत्र पर पाकिस्तान द्वारा किए गए आक्रमण का मामला उठाया। हालांकि हमारी विदेश नीति की विफलता और पश्चिम के दंभी रुख के चलते पाकिस्तान की इस आक्रामकता को विवादित विलय का रूप दे दिया गया। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सरकारों ने संविधान संशोधन और अलग कानून बनाकर विवाद की धारणा को और मजबूत किया। इसके अलावा, प्रचार किया गया कि कश्मीर एकमात्र रियासत थी, जिसे सशस्त्र बलों के इस्तेमाल से भारत में जोड़ा गया और अन्य सभी रियासतें 15 अगस्त 1947 से पहले शांति और इच्छा से भारत या पाकिस्तान में शामिल हो गईं, जिसके परिणामस्वरूप यह विचार आया कि कश्मीर की स्थिति अनोखी है।

नीचे 15 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान के साथ विलय होने वाली सभी रियासतों की सूची दी गई है। ज्यादातर मामलों में पाकिस्तान और भारत ने रियासत के सशस्त्र बलों या सरकारी टेक-ओवर का इस्तेमाल किया। नतीजतन, यह देखना चहिए कि केवल कश्मीर को लेकर विवाद क्यों है। हालांकि ये अभी भी ऐसे मुद्दे हैं जो भूमि संसाधन (कश्मीर) से संबंधित हैं, न कि मानव संसाधन (कश्मीर) से।

कुछ परिस्थितियों में प्रमुख विश्व शक्तियों ने स्थानीय सरकारों के विरोध के बावजूद लोगों की इच्छा आधार पर नए भूमि क्षेत्रों को एकीकृत किया है। उदाहरण के लिए, हवाई द्वीप पहले सैन्य कार्रवाई से और फिर एक अधिनियम पारित करके संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र बना, न्यू फॉकलैंड 1982 में सैन्य कार्रवाई की मदद से ब्रिटेन का एक विदेशी क्षेत्र बना और हाल ही में क्रीमिया 2014 में सैन्य कार्रवाई की मदद से रूस का क्षेत्र बना। ये क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और रूस के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो गए हैं। लोगों ने निर्णय को स्वीकार किया है और वे समृद्ध हैं। उपरोक्त क्षेत्रों में हिंसा को हवा देने के लिए कोई बाहरी सहायता प्रदान नहीं की गई थी। लेकिन कश्मीर के मामले में अशांति और हिंसा पाकिस्तान और उसकी सेना के निरंतर उकसावे और समर्थन के कारण रही है।

हालांकि, सभी पाकिस्तानी प्रयासों के बावजूद कश्मीरी भारत में काफी खुश हैं क्योंकि उन्हें एहसास है कि उनका भविष्य भारत सरकार के हाथों में सुरक्षित है। अगर भारत या भारतीय सेना ने कश्मीरियों पर अत्याचार किए होते तो जैसे पिछली सदी के सातवें दशक में पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से पीड़ित बांग्लादेशियों ने और पिछले दो दशकों में तालिबान से पीड़ित अफगानियों ने भारत की तरफ रुख किया है वैसे ही कश्मीरी भी दूसरे देशों में बसना शुरू कर देते। इससे यह स्पष्ट है कि पूर्ण रूप से भारतीय नियंत्रण में न होने के बावजूद जम्मू-कश्मीर का भारत से रिश्ता बहुत मजबूत है।

कश्मीर रियासत का भारत के साथ विलय बिना शर्त था। हालांकि भारत सरकार इस क्षेत्र में शांति और समृद्धि बनाए रखने की आशा के साथ नये प्रावधान जोड़ती रही। विशेष रूप से 1989 के बाद से यह स्पष्ट है कि भारत के सद्भावना उपायों ने कश्मीर में भय और हिंसा पैदा करने के लिए पाकिस्तान प्रायोजित तत्वों को प्रोत्साहित करने का काम किया है। इसलिए, भारत सरकार के हालिया फैसले ने दुनिया के बाकी हिस्सों को यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत के लिए पूरे जम्मू और कश्मीर के विलय पर कोई विवाद नहीं है। विवाद तो अब पीओके और चीन अधिकृत अक्साई चिन को लेकर है, जिस पर भारत लंबे समय से अपना दावा करता रह है। इस दावे को पूरा करने के लिए, अगले चरण में जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पीओके और अक्साई चिन के प्रतिनिधि हो सकते हैं।

रियासत का नाम	विलय का वर्ष	विलय की प्रक्रिया
कालत	6 अक्टूबर 1958	सेना की कार्रवाई
माकरन	17 मार्च 1948	समझौते के आधार पर
खारन	21 मार्च 1948	समझौते के आधार पर
लास बेला	7 मार्च 1948	समझौते के आधार पर
दिर	28 जुलाई 1969	सेना की कार्रवाई कार्रवाई
फुलरा	सितंबर 1950	पाकिस्तान सरकार टेक ओवर
अंब	31 दिसंबर 1947	समझौते के आधार पर
नगर	25 सितंबर 1974	पाकिस्तान सरकार टेक ओवर
हुंजा	25 सितंबर 1974	पाकिस्तान सरकार टेक ओवर
स्वात	28 जुलाई 1969	सेना की कार्रवाई
चित्राल	28 जुलाई 1969	सेना की कार्रवाई
खैरपुर	1955	सेना की कार्रवाई
बहावलपुर	14 अक्टूबर 1955	समझौते के आधार पर
जूनागढ़	15 सितंबर 1947	सेना की कार्रवाई
हैदराबाद	24 नवंबर 1949	सेना की कार्रवाई
जम्मू-कश्मीर	26 अक्टूबर 1947	समझौते के आधार पर
गोवा	19 दिसंबर 1961	सेना की कार्रवाई
पुडुचेरी	16 अगस्त 1962	समझौते के आधार पर

भारत के सामने विकल्प

1 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति खुलकर रखे। 1947 के बाद पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए भू-भाग के लिए पाकिस्तान की निंदा करे।

2 विश्व का ध्यान पीओके में बढ़ते मानवाधिकार उल्लंघन की ओर ले जाए। गुलाम कश्मीर व गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में पाकिस्तान की नीतियों का खुलासा करे। पीओके में जरूरी लोकतंत्र की वकालत करे।

3 पाकिस्तान को साफतौर पर कड़ा संदेश दिया जाए कि वह गैरकानूनी ढंग से क्षेत्र पर कब्जा किए हुए है। यह भी ध्यान दे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान भी भारत के कदम पर ही है।

4 भारत के खिलाफ अपनी कूटनीतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए पीओके में अपनी कई परियोजनाओं पर काम कर रहे चीन को भी कड़ा संदेश जाना चाहिए। किसी विवादित भूभाग पर बिना भारत की मंजूरी से वह कैसे वहां अपनी परियोजनाएं शुरू कर सकता है।

5 पीओके भारत के लिए सामरिक मायने भी रखता है। यह मध्य एशिया का प्रवेश द्वार है और जल संसाधनों से परिपूर्ण है। लिहाजा मजबूत पक्ष रखना जरूरी है।

6 पीओके के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्रदान करे। साथ ही वहां के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे। जम्मू-कश्मीर विधानसभा की उन सीटों को भी प्रवासी प्रतिनिधियों से भरने की व्यवस्था सुनिश्चित करे जो पीओके के लोगों के लिए आरक्षित हैं।

पाकिस्तान का दोहरा चरित्र

भारत की सरसों के बीज के आकार की खामियों को बढ़ा चढ़ाकर बताने और खुद की बेल जितनी बड़ी बुराई को देखते हुए भी अनदेखा करना पड़ोसी देश पाकिस्तान की फितरत रही है। तभी तो जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने की भारत की पहल को वह अंतरराष्ट्रीय मंच पर ले जाने की कोशिश में जुटा हुआ है। इस क्रम में उसे यह भी याद नहीं कि पिछले सत्तर साल में गुलाम कश्मीर (जम्मू कश्मीर के उस हिस्से जिस पर उसने अवैध कब्जा किया हुआ है) को पुनर्गठित करने के लिए वह कितनी बार कदम उठा चुका है।

खाने के दांत और दिखाने के और

गिलगित-बाल्टिस्तान एमपॉवरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर के तहत पाकिस्तान ने एक विधानसभा और एक गिलगित बाल्टिस्तान काउंसिल का गठन किया। हालांकि इस ऑर्डर में यह पेंच फंसा दिया गया कि 63 मसलों पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कानून बना सकता है और गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा द्वारा पारित किसी भी कानून को खारिज कर सकता है। 2018 के ऑर्डर में संशोधन के लिए अंतिम ताकत पाकिस्तानी राष्ट्रपति में निहित होगी।

खत्म किया रियासत का प्रावधान

जम्मू कश्मीर रियासत ने द स्टेट सब्जेक्ट रूल 1927 लागू किया था, जिसके तहत कोई भी बाहरी व्यक्ति रियासत में जमीन नहीं खरीद सकता था। पाकिस्तान ने गिलगित-बाल्टिस्तान के लिए यह नियम खत्म कर दिया है। अपने तथाकथित आजाद कश्मीर में भी उसने ऐसा की प्रावधान कर रखा है। इसके अतिरिक्त गुलाम कश्मीर में उसने चीनी निवेश को भी हरी झंडी दे रखी है।

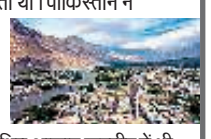

1949 अनधिकृत रूप से जम्मू कश्मीर के हिस्से पर कब्जा करने के दो साल बाद ही पाकिस्तान ने उसे दो हिस्सों में बांट दिया। एक को तथाकथित आजाद कश्मीर कहा गया तो दूसरे को फेडरली एडमिनिस्टर्ड नार्दर्न एरियाज नाम दिया गया।

1969 इस साल फेडरली एडमिनिस्टर्ड नार्दर्न एरियाज के लिए पाकिस्तान ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया। 1994 में इस सलाहकार परिषद को नार्दर्न एरियाज काउंसिल में तब्दील कर दिया गया। यही नहीं, पांच साल बाद नार्दर्न एरियाज काउंसिल का नाम लीगल फ्रेमवर्क (संशोधन) आदेश के तहत बदलकर नार्दर्न एरियाज लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया। 2009 में गिलगित-बाल्टिस्तान एमपॉवरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया।

जनमत

क्या भारत को अब गुलाम कश्मीर पर दावेदारी की सक्रिय पहल शुरू कर देनी चाहिए?	क्या पाकिस्तान के प्रति गुलाम कश्मीर में पनपता जनाक्रोश भारत के लिए शुभ संकेत है?
हां 96%	नहीं 04%
	हां 92% नहीं 08%

आपकी आवाज

निःसदेह गुलाम कश्मीर में पाकिस्तान के विरुद्ध पनपता जनाक्रोश भारत के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि वहां की अवाम पाक हुक्मरानों से त्रस्त है। न रोजी-रोजगार न विकास। वहां की अवाम कश्मीर की तर्ज पर बदलाव चाहती है। भारत इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंच पर रखकर कूटनीतिक माइलेज ले सकता है। **डॉ.हर्ष वर्धन**

गुलाम कश्मीर पर भारत को धैर्य से काम लेने की जरूरत है। जम्मू-कश्मीर के रास्ते ही गुलाम कश्मीर का हल निकलेगा। **प्रशांत कुमार**

गुलाम कश्मीर की जनता खुद भारत के साथ आना चाहती है। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से त्रस्त वहां की अवाम भारत की ओर देख रही है। भारत को चाहिए कि वह इस मसले को संयुक्त राष्ट्र में उठाये और जनमत संग्रह कराकर गुलाम कश्मीर का विलय भारत में कराये। **सुशांत सिंह**

पेट भरेगा तो दिल मिलेगा

डॉ. विकास सिंह
मैनेजमेंट गुरु और वित्तीय एवं समग्र विकास के विशेषज्ञ

पिछले सत्तर साल से गुलाम कश्मीर के लोग पाकिस्तान की भेदभाव वाली आर्थिक नीतियों के चलते बदहाली का जीवन जीने को अभिशप्त हैं। इसलिए पेट के रास्ते से ही गुलाम कश्मीरियों का दिल भारत जीत सकता है।

दुनिया की सबसे तेज विकास कर रही अर्थव्यवस्था (भारत) के साथ जम्मू-कश्मीर का एकीकरण सामाजिक-राजनीतिक के साथ आर्थिक मोर्चों पर भी कई सकारात्मक संकेत लेकर आया है। यह एकीकरण अर्थव्यवस्था को इनफ्लेक्शन प्वाइंट तक पहुंचाने में मदद करेगा। सीधे शब्दों में कहें तो जब कोई अर्थव्यवस्था इनफ्लेक्शन प्वाइंट तक पहुंचती है तो उत्पादन के अधिकांश कारक बेहतर रूप से काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे इनपुट की प्रत्येक इकाई से अधिक उत्पादन होता है। स्वास्थ्य, कल्याण, रोजगार, शिक्षा और लैंगिक समानता जैसे कई संकेतकों के परिणाम भी बेहतर होते हैं।

जम्मू और कश्मीर का आर्थिक एकीकरण लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालेगा, जिसके परिणामस्वरूप लोगों का जीवन बेहतर होगा और बेहतर मौके भी मिलेंगे। पड़ोस में स्थित पीओके या गुलाम कश्मीर में भी इस सकारात्मक बदलाव की प्रतिध्वनि सुनाई देगी। नेपाल जितना बड़ा पचास लाख की आबादी वाले इस भारतीय क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। अपनी भेदभाव वाली नीतियों से पाकिस्तान ने यहां के लोगों को मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित कर रखा है, वे मुश्किल से अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर में विकास का पीओके क्षेत्र पर सकारात्मक और व्यापक प्रभाव पड़ेगा। यह वहां के लोगों को मुख्यधारा में लाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के नए भारत ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि भारत के लिए अब कश्मीर नहीं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर समस्या है। दुनिया को यह बताने की जरूरत है कि पीओके की अर्थव्यवस्था रुकी हुई है और इसके परिणामस्वरूप यहां सामाजिक और कल्याण संकेतक नीचे जा रहा है। जम्मू-कश्मीर क्षेत्र के लोग अधिक खुश हैं। राज्य कई अन्य संकेतकों पर भी बेहतर करता दिखाई देता है। खासतौर पर मानव विकास सूचकांक, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय में। आर्थिक एकीकरण के साथ, इसके और भी बेहतर होने की संभावना है। साथ ही बेहतर जीवन और न्यायसंगत अवसरों की मांग को पूरा करने के लिए पीओके क्षेत्रों की आकांक्षाओं को पूरा करना होगा।

पीओके के लोगों के पास एक दृढ़ इच्छाशक्ति है और वे हर दिन प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ते हैं। उनके लिए राजनीतिक आजादी जितनी ही अहमियत आर्थिक स्वतंत्रता भी रखती है। हिंसा का आर्थिक असर बहुत बड़ा होता है। अर्थव्यवस्था का दसवां हिस्सा इसकी भेंट चढ़ जाता है लिहाजा ज्यादा लोग गरीबी के शिकार बनते जाते हैं। गरीबी लोगों को स्वाभिमानी तरीके से जीवन जीने की राह में बाधा बनती है। हालांकि इसकी राजनीतिक कीमत कहीं ज्यादा बड़ी होती है। गरीबी आंतरिक शांति छीनती है, लोगों का संस्थाओं और लोकतंत्र से विश्वास क्षीण होता है।

हिंसा हर क्षेत्र में नकारात्मक असर दिखाती है। आर्थिक विकास को सुस्त करती है। अन्याय का बीज रोपती है। लोगों की रोजाना की जिंदगी को बर्बाद करती है। यही नहीं, भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह बहुत खराब तस्वीर पेश करती है। शांति और विकास एक दूसरे से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। पीओके के किसी भी समाधान में बेहतर नेतृत्व शामिल होना चाहिए और मानवता में समग्र निवेश, जो मानव विकास संकेतकों को बढ़ाने पर केंद्रित हो। भारतीय अर्थव्यवस्था उस निवेश को कर सकती है। भारत के लिए यही वास्तविक मौका है कि वह अपनी सुरक्षा रणनीति को मजबूत रखते हुए गुलाम कश्मीर के लोगों के सामाजिक-आर्थिक उन्नयन का प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से प्रयास करे। पेट के रास्ते से ही गुलाम कश्मीरियों का दिल भारत जीत सकता है। इसके लिए दुनिया के हर फोरम पर पाकिस्तान के प्रति उन लोगों के आक्रोश को मजबूती के साथ रखना होगा।

विवाद की बानगी

1947 में भारत और पाकिस्तान को अंग्रेजों से आजादी मिली। भारतीय स्वतंत्रता एक्ट 1947 के अनुसार तमाम रियासतों को यह चयन करने की सुविधा दी गई कि वे भारत के साथ रहना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं। उस समय जम्मू-कश्मीर देश की सबसे बड़ी रियायत हुआ करती थी। इस रियासत पर महाराजा हरि सिंह शासन करते थे। वहां की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी के हिसाब से पाकिस्तान को यह पूरा भरोसा था कि यह रियासत उसके साथ जाएगी, लेकिन हरि सिंह अपने राज्य को न तो पाकिस्तान और न ही भारत में मिलाना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने स्वतंत्र रहने का फैसला किया।

भारत से मांगी मदद

हरि सिंह से तिरस्कृत होने के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर को हथियाने का एक दूसरा हथकंडा अपनाया। उसने पाकिस्तानी सेना को कबाइली आक्रमणकारियों के वेश में जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने को भेजा। इन आक्रमणकारियों को स्थानीय मुस्लिमों का भी सहयोग मिला। परेशान महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी।

भारत से समझौता

26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने भारत के साथ समझौता किया। उन्होंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करके जम्मू-कश्मीर को भारत में शामिल करने की आधिकारिक सहमति दी। शर्त यह रखी कि भारत अपनी सेना भेजकर आक्रमणकारियों को जम्मू-कश्मीर से खदेड़ दे।

संयुक्त राष्ट्र का दखल

भारतीय सेना ने आक्रमणकारियों को खदेड़ना शुरू किया। भारत ने 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के सामने कश्मीर मुद्दा रखा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 21 अप्रैल 1948 को प्रस्ताव 47 पारित किया। इसके तहत दोनों देशों को संघर्ष विराम के लिए कहा गया। साथ ही पाकिस्तान से कहा कि वह जम्मू-कश्मीर से शीघ्र पीछे हटे।

जनमत संग्रह

जब भारतीय सेना कश्मीर में दाखिल हुई थी तो कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला ने मुद्दे पर जनमत संग्रह कराने का समर्थन किया था। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद द्वारा युद्धविराम संधि की अलग व्याख्या होने से भारत-पाक संतुष्ट नहीं थे। बहरहाल नवंबर 1948 में दोनों देश जनमत संग्रह को राजी हुए। बाद में भारत ने इससे किनारा कर लिया और कहा कि पाकिस्तान पहले अपनी सेनाएं कश्मीर से हटाए।

चीन से युद्धः चीन भी कश्मीर के हिस्से पर अपना हक जताता रहा है। 1962 में उसने भारत से युद्ध करके आक्साइ चिन इलाके पर कब्जा कर लिया। दोनों देशों को अलग करने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा खींची गई।

दैनिक जागरण

सभी स्वर्ग की कामना करते हैं लेकिन मरना कोई नहीं चाहता

कूटनीति की कामयाबी

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मसले को उठाने की चीन और पाकिस्तान की कोशिश को मिली नाकामी यही बताती है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कूटनीति को बड़ी सफलता मिली है। इसकी एक बड़ी वजह मोदी सरकार की ओर से दुनिया को यह समझाने में मिली सफलता ही है कि कश्मीर उसका आंतरिक मामला है और अनुच्छेद-370 को हटाने के फैसले पर किसी को आपत्ति जताने का कोई अधिकार नहीं। यह सामान्य बात नहीं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन को छोड़कर लगभग सभी स्थायी एवं अस्थायी सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर संबंधी भारत सरकार के फैसले का समर्थन किया। यह लगभग तय है कि सुरक्षा परिषद के इस स्पष्ट रुख के बावजूद पाकिस्तान का रोना-धोना खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन उसे यह समझ आ जाए तो बेहतर कि कश्मीर पर बेसुरा राग अलाप कर वह भारत को तंग करने में सफल नहीं हो सकता।

पता नहीं पाकिस्तान को कब और कैसे सद्बुद्धि आएगी, लेकिन कम से कम चीन को तो यह आभास हो ही जाना चाहिए कि वह एक नाकाम देश पाकिस्तान का अनुचित समर्थन करके अपनी फजीहत ही करा रहा है। उसकी ऐसी ही फजीहत आतंकी सरगना मसूद अजहर के मामले में भी हो चुकी है। भले ही चीन भारत से दोस्ती बनाए रखने की बातें करता रहता हो, लेकिन उसकी नीयत पर संदेह स्वाभाविक ही है। यदि चीन वास्तव में भारत से मैत्री चाहता है तो उसके लिए यह समझना आवश्यक है कि उसकी तरह भारत भी एशिया की बड़ी ताकत हैं और दोनों देश मिलकर न केवल एशिया, बल्कि विश्व समुदाय को दिशा दिखाने का काम कर सकते हैं। यह तब होगा जब चीन भारत की भावनाओं का सही तरह से सम्मान करेगा। वह भारत से जैसा व्यवहार अपने लिए चाहता है वैसा ही व्यवहार उसे भारत के साथ करना होगा। बेहतर हो कि वह इस बात को जाने कि उसकी ही तरह भारत भी एक पुरातन सभ्यता वाला देश है और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है। इन्हीं सांस्कृतिक संबंधों के कारण चीन की जनता के एक बड़े वर्ग में भारत के प्रति मैत्री भाव है। इसी मैत्री भाव को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि चीनी नेतृत्व भारत को एक चुनौती समझ रहा है और इसी गलती के कारण वह अराजक, गैरजिम्मेदार और आतंकवाद के समर्थक पाकिस्तान को मोहरा बनाकर भारत की मुश्किलें बढ़ाने का मुगालता पाले हुए है। अगर वह इसी तरह केवल अपने आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संकीर्ण मानसिकता का प्रदर्शन करता रहता है तो भारत से अपने संबंधों को सुधारने में तो नाकाम होगा ही, अपनी प्रतिष्ठा को भी क्षति पहुंचाने का काम करेगा।

हादसे से पहले तत्परता

वैसे तो हमारे देश में घटना-दुर्घटना होने के बाद सरकारों और प्रशासनिक अधिकारियों की नींद खुलती है, लेकिन यदि पूर्व में हुई घटना-दुर्घटना से सीख लेकर पहले ही उसे रोकने के लिए कदम उठाए जाए तो उसे हादसे से पहले की तत्परता कहा जा सकता है। पिछले वर्ष जब न्यू अलीपुर इलाके में एक फ्लाईओवर अचानक धराशायी हो गया था तो राज्यभर के फ्लाईओवर की हालत को लेकर सवाल उठने लगे थे। पूरे प्रशासनिक हलके में कोहराम मच गया था। सभी नए व पुराने फ्लाईओवर की क्या स्थिति है, इसकी जांच के लिए जो कमेटी गठित की गई थी, वह पूरी तरह से सक्रिय हो गई। बावजूद इसके, जब उल्टाडांगा फ्लाईओवर में दरार पड़ने की खबरें मिलीं तो पूरा फ्लाईओवर बंद कर दिया गया। बाद में जांच की गई तो फ्लाईओवर के एक छोर को खोल दिया गया लेकिन दूसरा छोर पिछले एक माह से बंद है। इस बीच महानगर के तमाम फ्लाईओवर को बंद कर उनकी जांच की जा रही है, जिसमें अति व्यस्ततम सियालदह फ्लाईओवर भी शामिल है। उसे 15 अगस्त से चार दिनों के लिए बंद कर उसकी मरम्मत की जा रही है। इसके बाद जीवनानंद फ्लाईओवर को भी रविवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। एक तो बारिश और दूसरा कई फ्लाईओवर का बंद होना, इससे ट्रैफिक की स्थिति काफी गंभीर हो गई है। यहां ध्यान देना जरुरी है कि यह सब लोगों के भले के लिए किया गया है इसलिए इसमें लोगों को सहयोग करना चाहिए। पहली बार देखा जा रहा है कि समय रहते सतर्कता बरती जा रही है ताकि विवेकानंद फ्लाईओवर जैसा बड़ा हादसा न हो। इन दोनों फ्लाईओवर की मरम्मत के बाद 22 से 24 अगस्त तक अरविंद सेतु को भी बंद रखा जाएगा। इसी तरह हावड़ा के बंकिम सेतु की 23 से 25 अगस्त तक जांच की जाएगी। उस दौरान सेतु पर यातायात बंद रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक रूट तो तैयार किए हैं, लेकिन उनसे खास राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। सियालदह फ्लाईओवर व जीवनानंद सेतु के बंद होने से जादवपुर, संतोषपुर, रूबी, गरियाहाट, देशप्रिय पार्क, रासबिहारी, गरिया, वैष्णवघाटा, पाटुली, टालीगंज, मौलाली, इंटाली, धर्मतल्ला, राजाबाजार, श्यामबाजार, मानिकतल्ला, बेलियाघाटा और पार्क सर्कस इलाकों में सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम की समस्या हो रही है, लेकिन यह थोड़े समय की परेशानी है इसलिए लोगों को पुलिस प्रशासन की मदद करनी चाहिए।

नए भारत के निर्माण का नजरिया

संजय गुप्त

लाल किले से पीएम मोदी का संबोधन यही दर्शाता है कि भारत की समस्याओं को वह जितना बेहतर समझते हैं उतना ही उन्हें सुलझाने के लिए संकल्पबद्ध भी हैं

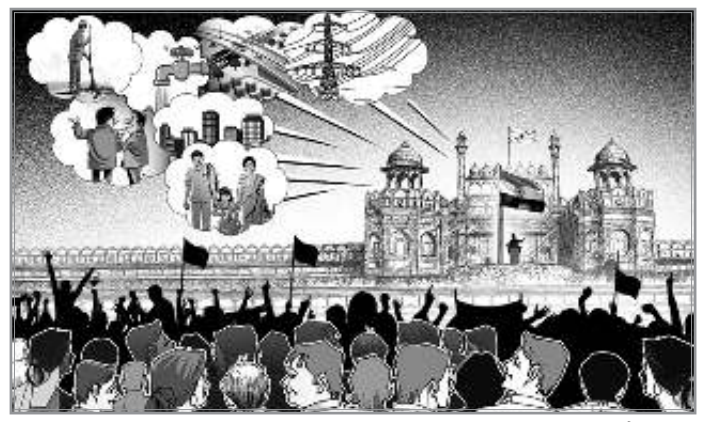

अवधेश राजपूत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम जो संबोधन दिया उसमें उनके इस कार्यकाल की भावी रूपरेखा का लेखाजोखा कहीं अधिक स्पष्ट रूप में सामने आया। इस संबोधन में उन्होंने अनुच्छेद-370 हटाए जाने के संदर्भ में विपक्ष और खासकर कांग्रेस को तो आईना दिखाया ही, यह भी रेखांकित किया कि कैसे एक ऐतिहासिक भूल को मात्र 75 दिन में सुधार दिया गया। प्रधानमंत्री का यह कहना सही है कि इस फैसले के बाद भारत का प्रत्येक नागरिक यह कह सकता है कि अब यहां 'एक देश-एक संविधान' है। उन्होंने नए भारत के लक्ष्य के लिए 'एक देश-एक चुनाव' पर चर्चा को भी आवश्यक बताया। इसके लिए उन्होंने जीएसटी का उदाहरण रेखांकित करते हुए यह याद भी दिलाया कि 'एक देश-एक टैक्स' की तरह 'एक देश और एक मोबिलिटी कार्ड' की व्यवस्था पहले ही शुरू की जा चुकी है। स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री देश में व्यवस्थाओं में एकरूपता पर जोर दे रहे हैं।

अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद पाकिस्तान कश्मीर के मामले में पूरी तरह पराजित हो चुका है। प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में बिना नाम लिए पाकिस्तान को आगाह कर दिया कि वह आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करे। मोदी ने बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में बढ़ रहीं आतंकी गतिविधियों का हवाला देकर विश्व समुदाय को भी आश्वस्त किया कि भारत आतंकवाद के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध होने के साथ ही इस क्षेत्र में शांति एवं स्थायित्व के लिए अपनी भूमिका को लेकर गंभीर है। उनके भाषण से पाकिस्तान को सचेत हो जाना चाहिए कि अगर उसने अपनी नीति नहीं बदली तो उससे निपटने में भारत की जवाबी कार्रवाई बालाकोट से भी अधिक घातक हो सकती है। लाल किले से ही प्रधानमंत्री ने पहली बार तीनों सुरक्षा बलों में बेहतर समन्वय एवं उनकी क्षमताओं में और पैनापन लाने के उद्देश्य से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के गठन की घोषणा की। यह सैन्य सुधार का एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रधानमंत्री मोदी की यह खूबी रही है कि वह भारत के समक्ष चुनौतियों को बखूबी समझते हैं और उनसे उतने ही अच्छी तरह निपटना भी जानते हैं। पिछले कार्यकाल में उन्होंने स्वच्छता अभियान के जरिये खुले में शौच से मुक्ति के लिए अभियान चलाया था और उसमें सफलता भी पाई। ऐसे ही गरीब महिलाओं को भी उन्होंने एलपीजी कनेक्शन देकर उनकी दशा सुधारी। अब उनकी नजर उन लोगों पर है जो जल संकट से त्रस्त हैं। देश के पचास प्रतिशत से अधिक घर इस संकट का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पीने के पानी की उपलब्धता को नए भारत के लक्ष्य का अहम हिस्सा बताते हुए साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये के जल जीवन मिशन का एलान किया। इस मिशन में सरकार के साथ ही जनता की भागीदारी की आवश्यकता रेखांकित की गई है।

प्रधानमंत्री का यह कहना उचित ही है कि भारतीयों की आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। एक विकासशील देश में लोगों की आकांक्षाओं से ही संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। इसके लिए बुनियादी ढांचे का विकास पहली आवश्यकता है। सरकार ने बुनियादी ढांचे पर सौ लाख करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। यह प्रतिबद्धता प्राथमिकता के आधार पर पूरी होनी चाहिए, क्योंकि यह देश की प्रगति के साथ ही रोजगार सृजन के लिए भी आवश्यक है। यह भी उल्लेखनीय है कि एक लंबे अरसे के बाद किसी प्रधानमंत्री ने देश की बढ़ती आबादी पर चिंता जताई है। इसमें संदेह नहीं कि युवाशक्ति हमारे लिए एक वरदान है, लेकिन यह भी सच है कि बढ़ती आबादी संसाधनों के लिए गंभीर चुनौती पेश कर रही है। आर्थिक दृष्टि से भी इतनी बड़ी आबादी के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना किसी भी सरकार के लिए टेढ़ी खीर है। प्रधानमंत्री की इस अपील पर हर किसी को गौर करना चाहिए कि शिशु के जन्म से पहले यह सोचा जाना चाहिए कि उसकी अपेक्षाएं कैसे पूरी होंगी। यह अपने आप में प्रधानमंत्री की नई सोच है।

मौजूदा दौर आर्थिक चुनौतियों का है। इन चुनौतियों का सामना औद्योगिक माहौल को बेहतर बनाकर ही किया जा सकता है। समस्या यह है कि देश में राजनीति और नौकरशाही समेत कई वर्ग ऐसे हैं जो उद्यमियों और उद्योगपतियों के खिलाफ माहौल बनाने का कार्य करते हैं और अक्सर उनकी नकारात्मक छवि बनाने की कोशिश की जाती है। प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी उद्योग जगत का भरोसा बढ़ाने वाली है कि वेल्थ क्रिएटरों को संदेह की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। वे देश की सेवा करते हैं और इस लिहाज से सम्मान और प्रोत्साहन के हकदार हैं। बेहतर हो कि उद्योग जगत के प्रति नकारात्मकता फैलाने वाले लोग और समूह यह समझें कि अगर संपदा का निर्माण नहीं किया जाएगा तो उसे देश के गरीबों तक नहीं पहुंचाया जा सकेगा और रोजगार की संभावनाएं भी नहीं बन सकेंगी। संपदा का निर्माण अगर कानूनी तौर-तरीकों से किया जाता है तो इसमें अनुचित क्या है? प्रधानमंत्री ने देश को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प को फिर से दोहराया। यह संकल्प तभी पूरा होगा जब भारत का उद्योग जगत भी इसमें पूरे उत्साह के साथ बढ़-चढ़कर भागीदारी करेगा। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सरकार को देखना होगा कि निजी निवेश का दायरा कैसे बढ़े।

यह सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री कर्मठ हैं, लेकिन उनकी दूरदर्शिता ने राष्ट्र को दिशा दिखाने का जो काम किया है उसकी दूसरी मिसाल नहीं है। इसकी एक बानगी इससे भी मिलती है कि मोदी की आलोचना में अक्सर सबसे आगे रहने वाले कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने भी तीन विषयों-जनसंख्या नियंत्रण, प्लास्टिक पर अंकुश और अर्थव्यवस्था को गति देने वाले उद्यमियों को सम्मान देने के आह्वान पर मोदी का खुलकर समर्थन किया है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह समाज में परिवर्तन लाने में सक्षम नेतृत्व की कसौटी भी पूरी की है उससे वह मौजूदा दौर में एक अलग ऊंचाई पर बैठे राजनेता के रूप में सामने आए हैं। फिलहाल इस मामले में उनकी बराबरी कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। उनसे पहले शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने इतनी स्पष्टता से जनता के साथ अपने सपनों को साझा किया होगा।

हालांकि इन सपनों को पूरा करना आसान नहीं है, क्योंकि कई बाधाएं ऐसी हैं जो प्रगति की राह रोकती हैं। इनमें राज्य सरकारों और उनकी नौकरशाही का रवैया सबसे ऊपर है। नौकरशाही अभी भी भ्रष्टाचार में धंसी है और भ्रष्टाचार लोगों के जीवन को दीमक की तरह चाट रहा है। इस भ्रष्टाचार को प्रशासनिक सुधारों के जरिये ही नियंत्रण में लाया जा सकता है। ये सुधार तत्काल आरंभ किए जाने चाहिए, क्योंकि देश की भावी तस्वीर का जो सपना दिखाया जा रहा है उसे साकार करने के लिए भी नौकरशाही के ढांचे को दुरुस्त करना होगा।

response@jagran.com

होश में आने के बाद फिर होश फाख्ता!

हास्य-व्यंग्य

इधर लगातार बुरी खबरें आ रही थीं। वे बड़ी उम्मीद से बैठे थे, पर उनका दिल बैठा जा रहा था। बार-बार वे घटनास्थल की ओर ताक रहे थे, पर उनके सिवा कुछ भी 'घट' नहीं रहा था। टीवी के रिमोट को लगातार घुमा रहे थे, पर उनका सिर घूमने लगा। 'अनार-बाग' से एक 'अनार' तक फूटने की आवाज नहीं आ रही थी। वे कुछ भी 'इच्छित' देख-सुन नहीं पा रहे थे। मन बड़ा बेचैन हो रहा था, मगर वहां अजीब सी शांति पसरी थी। इसी नामुराद शांति को वे मन ही मन कोसने लगे-'अजी, शांति तो मरघट में भी होती है। यह भी कोई उपलब्धि हुई! शांति तो उनके 'टैम' में थी। और क्या खूब थी! केवल गोलियों और पत्थरों की आवाजें आती थीं। मजाल थी कि किसी का सुकून भंग हो! महीनों स्कूल बंद रहते थे, पर कभी लोकतंत्र पर रत्ती भर आंच नहीं आई। बम और बारूद के बाद भी 'स्वर्गिक-सुख' मिल रहा था। हर तरह की आजादी थी।'

हमसे मिलते ही अपना दुखड़ा रोने लगे, 'तुम अब भी कुछ नहीं बोलोगे? दिनदहाड़े लोकतंत्र की हत्या हुई है। कम से कम तरीका तो लोकतांत्रिक होता। लोग बंद हैं। खबरें बंद हैं। यहां तक कि हमारी राजनीति भी बंद है। अब तुम्हीं बताओ, ऐसे में कोई करे तो क्या करे? ठीक से भड़क तक नहीं पा रहे हैं।' मामला गंभीर था। मैंने भी गंभीरता ओढ़ ली। विचार आने से पहले वैचारिक दिखना भी पड़ता है। मैंने कहा, 'भई, मैं तो लेखक हूं। बयान नहीं विचार देता हूं। आप पार्टी से जुड़े हैं, हम विचारधारा से। 'धाराएं' टूट रही हैं, पर 'विचार' बचाना है। आप पार्टी बचाओ, तभी राजनीति बचेगी। देश कहीं नहीं जा रहा, उसे हम बचा लेंगे। देश बचे, इसके लिए पहले 'लोकतंत्र' को बचाना है। इसीलिए हम अपनी 'लाइन' से टस-से-मस नहीं हुए। आपकी 'राजनीति' की तरह हम 'छुट्टा' नहीं हैं। खूंटे से बंधे हैं। अपनी नांद में ही मुंह मारते हैं। अब वैचारिक बने रहना इतना आसान नहीं रहा। कई बार 'भूखा' रहना पड़ता है। विचारशून्य होकर भी हम अपना अस्तित्व बचा रहे हैं। जैसे आप जो भी करते हो, 'राजनीति' होती है, वैसे ही हम जो भी लिखते हैं, 'विचार' होता है। सोचिए मत रणनीतिए।' यह कहकर हमने उनमें संजीवनी भरी। वे बड़ी देर से कसमसा रहे थे। हमने उनके 'हिस्से' का समय भी ले लिया था। हमारे चुप होते ही बोल पड़े, 'भई, मैं यह सब कैसे देख सकता हूं। मैं तो 'नजरबंद' हूं। पहले 'उनका' आतंक नहीं देख पाया, अब इनकी 'शांति' नहीं देख पा रहा हूं। राजनीति क्या खाक करें! क्या खाकर करें? कानून भी तो कुछ नहीं बोल रहा। उसका भी तो कोई 'पहलू' होगा?'

'सबके अपने 'पहलू' हैं। तुम्हारा अलग है, हमारा अलग। कानून का भी है। सब अपनी रोशनी में देखते हैं। 'पहलू' तो बस फुटबॉल की तरह इधर-उधर होता रहेगा। हमें भी उसी का आसरा है। जरूरत इस बात की है कि हम दोनों एक रहें।' हमने बिल्कुल नेक सलाह दी।

संतोष त्रिवेदी

मैं तो 'नजरबंद' हूं। पहले 'उनका' आतंक नहीं देख पाया, अब 'इनकी' शांति नहीं देख पा रहा हूं। राजनीति क्या करुंगा

यह सुनते ही उनकी हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। वे फिर बोलने लगे, 'सारी समस्या की जड़ यही 'एक' है। वे सब कुछ 'एक' करने में तुले हैं। उनके ऊपर 'एक देश, एक कानून', एक देश, एक चुनाव', 'एक देश, एक पार्टी' की रट सवार है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बात 'एक देश, एक नेता' तक पहुंच जाएगी। फिर न हम बचेंगे, न हमारी बची हुई पार्टी। हमारे सामने मुश्किल है कि इन सबके बीच 'देश' घुसा है। यह सरासर ज्यादती नहीं तो और क्या है?' तभी एक चैनल से चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। लग रहा था कि बेचारा एंकर भी कुछ समय से ठीक से चिल्ला नहीं पाया था।

उनकी आंखें चमक उठीं। हमने भी अपनी निगाह गड़ा दी। पड़ोसी देश से खबर आ रही थी। वहां का नेता माइक के आगे इकबालिया बयान दे रहा था, 'वे कुछ भी कर सकते हैं। पहले से भी 'बड़ा' हो सकता है। वे हमारे यहां घुस सकते हैं। अब जेहाद के लिए तैयार रहो।' यह सुनकर उनका सारा जोश ठंडा पड़ गया। स्थिति को हमने भी ताड़ लिया। कुछ देर वे सन्नाटे में रहे। उनके होश में आने से पहले हमें होश आ गया। हमने तुरंत चैनल बदल दिया। वहां 'ब्रेकिंग न्यूज' थी। जिस 'गुप्त बैठक' से पड़ोसी देश को उम्मीद थी, वह गुप्त ही रही। होश में आते ही वे बोल उठे-'एक हो जाओ, इसी में भलाई है।' ऐसा नहीं किया तो फिर से होश उड़ जाएंगे।

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य | सोनिया गांधी के नेतृत्व में लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन

स्रोत : द इंडियन इंडेक्स

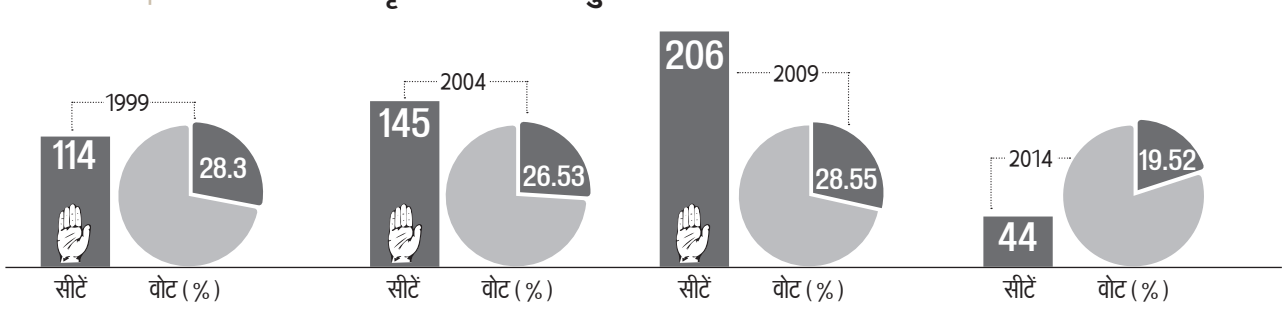

ऊर्जा

सतर्कता

अक्सर हमारे किसी प्रिय जन को किसी प्रयोजन के निमित्त किसी यात्रा पर जाना होता है। उनकी रवानगी से पहले हम उनके लिए तमाम तरह की हिदायतों के अंबार लगा देते हैं। हम यात्रा के दौरान उनसे बार-बार सतर्क रहने के लिए कहते हैं। उन्हें बताते हैं कि यात्रा के समय वे किसी अपरिचित से ज्यादा मेल-मिलाप न बढ़ाएं। यह तब होता है जब उनका गंतव्य स्थान निश्चित होता है तथा यात्रा अल्पकालिक होने के साथ ही यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति के लौटने का समय भी तय होता है।

व्यवहार दृष्टि से इसे नकारा नहीं जा सकता और ऐसा करना अनुचित भी नहीं है, किंतु जीवन व्यवहार में हम अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहते हुए भी यह भूल जाते हैं कि मनुष्य की जीवन यात्रा केवल इसी लोक तक सीमित नहीं है, अपितु इसे एक न एक दिन अपना शरीर छोड़कर उस अनंत यात्रा पर निकलना है, जिस यात्रा का न तो आरंभ करने का समय निश्चित होता है और न यह जानकारी होती है कि यात्रा करने वाले को जाना कहां है, किससे मिलना है, वहां पहुंचकर क्या करना है, जाने का रास्ता भी ज्ञात नहीं होता और साथ में किसी तरह का सामान भी नहीं होता।

इस पर नीतिकार कहते हैं कि लोक-जीवन की सभी यात्राओं में सतर्क रहते हुए भी हमें अपने परलोक जीवन की यात्रा के लिए भी सतर्क रहना चाहिए और यह विचार करते रहना चाहिए कि उस यात्रा पर जाने के लिए हम कैसी तैयारी करें, क्योंकि उस यात्रा में इस संसार की कोई भी सामग्री हमारे साथ नहीं जाएगी और न ही कोई हमारा प्रिय व्यक्ति भी हमारे साथ जा सकेगा। इतना ही नहीं, हमारा अपना यह शरीर भी हमें यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। हां, यह यात्रा केवल मनुष्य के लिए ही नहीं, अपितु जीवमात्र के लिए अनिवार्य है, क्योंकि मनुष्य अन्य जीवधारियों की अपेक्षा विचारवान और विवेकी है। इसी से हमारे ऋषियों और आचार्यों ने शुरू से ही कहा कि हे मनुष्य अपने जीवन में धर्म का आचरण करो। मृत्यु के बाद उस अनिवार्य अनंत यात्रा पर केवल धर्म ही साथ जाता है और वही कल्याणकारी होता है।

डॉ. गदाधर त्रिपाठी

पृथ्वी जैसे ग्रह तलाशने की मुहिम

मुकुल व्यास

ब्रह्मांड में पृथ्वी सरीखे कितने ग्रह हो सकते हैं, यह अनुमान लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नई विधि विकसित की है

वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे ग्रहों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए एक नया अध्ययन किया है। इस अध्ययन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सूर्य जैसे तारों के इर्द-गिर्द चक्कर लगाने वाले पृथ्वी जैसे ग्रह कितने हो सकते हैं। नए अध्ययन से खगोल वैज्ञानिकों को ग्रहों को बेहतर ढंग से समझने और पारलौकिक जीवन के संकेतों को खोजने में मदद मिलेगी। 'नासा' के केप्लर स्पेस टेलीस्कोप ने हमारे सौरमंडल के बाहर हजारों ग्रहों का पता लगाया है जो अपने तारों की परिक्रमा कर रहे हैं। उसने करीब दस साल तक आसमान की छानबीन करते हुए 'ट्रांजिट इवेंट्स' पर खास नजर रखी।

जब कोई ग्रह किसी तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की रोशनी कुछ हद तक मंद पड़ जाती है। ग्रह के तारे के आगे से गुजरने को ट्रांजिट इवेंट कहा जाता है। वैज्ञानिक ट्रांजिट इवेंट के आधार पर ग्रहों के आकार और उनकी विशेषताओं का अनुमान लगाते हैं। वैज्ञानिक यह जानना चाहते हैं कि कितने ग्रह अपने तारों के आवास क्षेत्रों में हैं और क्या उन्हें जीवन की ऊर्जा के लिए अपने तारों से समुचित प्रकाश मिलता है। इस अध्ययन के प्रमुख शोधकर्ता एरिक फोर्ड का कहना है कि केप्लर ने विभिन्न आकारों, संरचनाओं और कक्षाओं वाले ग्रहों की खोज की है। इससे हम ग्रहों के निर्माण के बारे में अपनी समझ को और बेहतर बनाने के लिए इन खोजों का उपयोग करना चाहते हैं।

दरअसल इन खोजों से आवासयोग्य ग्रहों की तलाश के लिए भावी मिशनों की योजना बनाने में भी मदद मिलेगी। लेकिन सिर्फ बाहरी ग्रहों की संख्या, उनके आकार और उनकी कक्षीय दूरी का आकलन करना ही काफी नहीं है। तारों के नजदीक बड़े ग्रहों को खोजना आसान है, लेकिन तारों से दूर ग्रहों का पता लगाना मुश्किल है। इस तरह के कितने ग्रह हो सकते हैं, इस बात का अंदाजा लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नई विधि विकसित की है। उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया जिसमें उन्होंने तारों और ग्रहों के नए काल्पनिक ब्रह्मांडों की रचना की। इसके पश्चात उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि केप्लर टेलीस्कोप इनमें से कितने तारों और ग्रहों को देख पाता है और कितने उसकी दृष्टि से चूक जाते हैं।

इस अध्ययन के प्रथम लेखक डेनली सू ने बताया कि हमने कंप्यूटर आधारित मॉडल बनाने के लिए केप्लर टेलीस्कोप द्वारा पहचाने गए ग्रहों की अंतिम सूची तथा यूरोपीय स्पेस एजेंसी के गाइया उपग्रह से मिले तारों के आंकड़ों का उपयोग किया। हमने इन नतीजों की तुलना केप्लर द्वारा सूचीबद्ध किए गए ग्रहों के साथ की। हमने इस आधार पर प्रति तारे पर ग्रहों के पाए जाने की दर का निर्धारण किया और पता लगाया कि यह किस तरह से ग्रह के आकार और कक्षीय दूरी पर निर्भर है। इस नई विधि से शोधकर्ताओं को ऐसे अनेक प्रभावों को जानने का मौका मिला जिन्हें पिछले अध्ययनों में शामिल नहीं किया गया था। माना जा रहा है कि वैज्ञानिक इस अध्ययन के निष्कर्षों का उपयोग शेष ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे ग्रहों का पता लगाने के लिए कर सकते हैं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

आखिर करें क्या?

दूसरों के भाग्य का फैसला करने आए इन महानुभावों के ही दिन नहीं बहुर रहे हैं। शायद इसे ही कहते हैं 'सिर मुड़ाते ही ओले पड़े।' इनमें से हर कोई अपने-अपने संस्थानों और नामी गिरामी विश्वविद्यालय का मुखिया था। गंभीर मंत्रणा के बाद मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के अहम पदों पर विराजमान हैं, लेकिन यहां पदभार संभालने के बाद से ही उनके होश उड़े हुए हैं। लौटकर अपने पुराने पदों पर जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां से तो इस्तीफा देने की शर्त के साथ यहां पहुंचे हैं। अब यहां उनकी ही नहीं सुनी जा रही है। इस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष से लेकर सदस्यों तक को न तो आवासीय सुविधा मुहैया कराई गई और न ही अन्य सहूलियतें। जिस काम के लिए उन्हें लाया गया है, वह भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। खुद की सेवा शर्तों का तो पता नहीं है, ऐसे में भला दूसरों के बारे में क्या फैसला करेंगे। मंत्रालय के ढीले-ढाले रवैये से उनकी नाराजगी कुछ और भी गुल खिला सकती है।

बाबुओं की उड़ी नींद

प्रधानमंत्री के लालकिले की प्राचीर से दिए गए भाषण और उसमें की गई सीडीएस पद की घोषणा ने रक्षा मंत्रालय के बड़े बाबुओं की नींद उड़ा दी है। लंबे अरसे बाद आखिरकार सेना का कोई बड़ा अधिकारी सीडीएस की कुर्सी पर बैठने जा रहा है। इस पद के सृजन की चर्चा हर तरफ गर्म है, लेकिन उन वरिष्ठ आइएएस अधिकारियों को यह योजना खास रास नहीं आ रही है जो देश की नौकरशाही की अगुआई करते हैं। उनको अभी से यह डर सता रहा है कि अगर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सृजित हो गया और सेना का कोई बड़ा अधिकारी इस पद पर बैठ गया तो सुरक्षा मामलों में बाबुओं की चलनी एकदम बंद हो जाएगी। रक्षा मंत्रालय के मामलों में भी जो उनका एकाधिकार है, उसमें कटौती होनी तय है। नौकरशाही में इस बात को लेकर खलबली है कि अब रक्षा मंत्रालय से जुड़े ज्यादातर काम सीडीएस के पास चले जाएंगे। वह रक्षा मंत्रालय के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बन जाएगा। बड़े बाबुओं को यह टीस तो हमेशा रहती ही है कि सेना के तीनों अंगों के प्रमुख रक्षा सचिव को रिपोर्ट करने की जगह रक्षा मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। ऐसे में सीडीएस अगर मैदान में आ गया तो उनकी रही-सही पूछ और रक्षा मामलों में दखलअंदाजी काफी हद तक बंद हो जाएगी।

खबरों पर कोई जोर नहीं

जब चौतरफा पहरा बैठा दिया गया हो तो फिर कहां से सूचनाएं बाहर आ रही हैं, जिसे लेकर साहब लोग परेशान हैं। बिना समय लिए इस मंत्रालय में किसी अफसर से मिलना संभव नहीं है। यहां के अफसर किसी खबरनवीस से मिलने से पूरी तरह कतराने लगे हैं, लेकिन तमाम बंदिशों के बावजूद आर्थिक मंदी से जुड़ी खबरें कुछ ज्यादा ही आने लगी हैं। ऐसी खबरों की बाढ़ का असर वित्त बाजार पर पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि पहले जब वित्त मंत्रालय के गलियारों में खबर सूंघने वाले घूमते थे तब तो यह बात समझ में आती थी कि उन्हें किसी न किसी अधिकारी से सूचनाएं हासिल हो रही थीं, लेकिन अब ऐसी खबरें ज्यादा निकल रही हैं। भला यह हो कैसे रहा है?

राजरंग

यादों में खोए साहब

पिछली सरकार में एक बड़बोले मंत्री के एपीएस रहे एक साहब इन दिनों काफी परेशान हैं। वजह कुछ और नहीं, बल्कि मंत्री जी के साथ बिताए गए वो पल है, जो उन्हें बेचैन किए रहते हैं। नई सरकार में उनके पुराने मंत्री जी का पत्ता कट गया। ऐसे में इन साहब के भी मौज-मस्ती के दिन लद गए। आखिर में उन्हें मन मसोस कर फिर से अपने मूल विभाग में वापस जाना पड़ा। यहां उनका मन नहीं लग रहा है। ऐसे में साहब ज्यादातर समय शास्त्री भवन में भटकते दिख जाते हैं। इस दौरान किसी भी पुराने साथी या परिचित को देखकर उनकी पीड़ा छलक उठती है। हालांकि इस सब के बीच अच्छी बात यह है कि उन्होंने अच्छे दिनों की उम्मीद अभी तक नहीं छोड़ी है।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

45 प्रतिशत जनसंख्या हिंदीभाषी है मुंबई और ठाणे में। यहां की कई विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश के जौनपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, बस्ती, गोंडा, कुशीनगर, आजमगढ़ और देवरिया आदि जिलों के मूलनिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है।

अनंत विजय

आजकल

स्वायत्तता की आड़ में अराजकता

अकादमियों में अनियमितता की खबरें अक्सर आती रहती हैं, लेकिन शायद ऐसा कम ही होता है कि किसी अकादमी के अध्यक्ष ने उस अकादमी के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में संबंधित केंद्रीय मंत्री के समक्ष मंत्रालय द्वारा अकादमी के कामकाज में बाधा डालने की बात सार्वजनिक रूप से कही हो। हाल में ऐसा एक मामला सामने आया है जिस पर चर्चा होनी चाहिए

हाल ही में ललित कला अकादमी ने अपना स्थापना दिवस आयोजित किया। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भारत सरकार के संस्कृति मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल समेत कला जगत के कई मूर्धन्य उपस्थित थे। अपने संबोधन में ललित कला अकादमी के अध्यक्ष उत्तम पचारणे ने संस्कृति मंत्रालय पर अकादमी के कामकाज में बाधा डालने की बात कही। मंत्री की मौजूदगी में कही गई उनकी इन बातों का मंत्री ने नोटिस तो लिया, लेकिन बेहद संजीदगी से उन्होंने नसीहत दी कि इस तरह की बातें सार्वजनिक मंच से न होकर आपसी संवाद के जरिये की जानी चाहिए। बात आई-गई हो गई, लेकिन ललित कला अकादमी के अध्यक्ष की बातों से ऐसा लगा कि मंत्रालय और अकादमी के बीच सामंजस्य की कमी है। ये भी लगा कि कुछ तो है जिसकी परदादारी है और वो बाहर आने के लिए बेचैन है। दरअसल ललित कला अकादमी में अलग अलग समय पर अलग अलग कारणों से विवाद होते रहे हैं। अब तो अध्यक्ष ने साफ तौर पर कह दिया है कि मंत्रालय और अकादमी के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो ऐसे में मंत्रालय और अकादमी दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि संवादहीनता और कामकाज की बाधाओं को दूर किया जाए।

दिल्ली के रवींद्र भवन में तीन अकादमियां चलती हैं- संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी। संगीत नाटक अकादमी हाल में अपने पुरस्कारों को लेकर विवाद में रही। साहित्य अकादमी भी 2015 के बाद चर्चा में रही है। पिछले दिनों इस तरह की खबरें आईं कि साहित्य अकादमी के प्रतिनिधिमंडल को चीन जाने की अनुमति संस्कृति मंत्रालय से नहीं मिली और चीन के साथ चली आ रही विचार-विनिमय की परंपरा बाधित हुई। लेकिन ललित कला अकादमी का मामला इन दोनों अकादमियों से अलग है। इसके पूर्व सचिव सुधाकर शर्मा को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। अशोक वाजपेयी जब ललित कला अकादमी के अध्यक्ष थे तो उन्होंने सुधाकर शर्मा को सचिव पद से हटा दिया था। फिर बहाली हुई, फिर हटाए गए। अशोक वाजपेयी का कार्यकाल भी विवादित रहा। उन पर भी कई तरह के आरोप लगे। इन आरोपों की सीबीआइ जांच भी कर रही है। अशोक वाजपेयी के बाद केके चक्रवर्ती ललित कला अकादमी के अध्यक्ष बने। इनका कार्यकाल भी विवादित रहा, इनके समय में भी सुधाकर शर्मा को सस्पेंड किया गया। केके चक्रवर्ती भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और उनको बीच में ही हटाकर मंत्रालय ने ललित कला अकादमी को अपने अधीन कर लिया। ललित कला अकादमी के संविधान में ये प्रावधान है कि अगर मंत्रालय को ये लगता है कि वहां गड़बड़ियां हो रही हैं तो वो संस्थान के प्रशासन को अपने अधीन कर प्रशासक नियुक्त कर सकता है। मंत्रालय ने कृष्णा शेट्टी को अकादमी का प्रशासक नियुक्त कर दिया। प्रशासक का काम ललित कला अकादमी का चुनाव करवा महा-परिषद और कार्यकारी बोर्ड का गठन करवाना होता है। परंतु शेट्टी इसका गठन नहीं करवा पाए।

कृष्णा शेट्टी के बाद मंत्रालय ने अपने एक संयुक्त सचिव को प्रोटेम चेयरमैन नियुक्त कर दिया। ललित कला अकादमी के संविधान की किस धारा के अंतर्गत प्रोटेम चेयरमैन बनाए गए इस पर कलाकारों के बीच लंबे समय तक चर्चा होती रही थी। इन सबके बीच मामला कोर्ट में भी गया था, लेकिन पता नहीं किन परिस्थितियों में महा-परिषद का चुनाव नहीं हो पाया। बाद में उत्तम पचारणे को यहां का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। अकादमी की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक अब तक महा-परिषद के सदस्यों का चुनाव नहीं हो पाया। जाहिर सी बात है कि जब महा-परिषद का गठन ही नहीं हो पाया तो कार्यकारी बोर्ड कैसे बनती, क्योंकि इसके कुछ सदस्य तो महा-परिषद के सदस्यों के बीच से ही चयनित होते हैं। महा-परिषद के नहीं होने से ललित कला अकादमी के कामकाज में पारदर्शिता नहीं दिखाई देती है। इनमें से ज्यादातर घटनाएं पूर्व संस्कृति मंत्री महेश शर्मा के कार्यकाल में हुईं। सबसे दिलचस्प सुधाकर शर्मा का केस है। वो सचिव पद से कई बार हटाए और बहाल किए गए और जब वो रिटायर हुए तो सस्पेंड ही थे। स्वायत्तता के नाम पर अराजकता के उदाहरण के तौर पर ललित कला अकादमी के क्रियाकलापों को देखा जा सकता है।

ललित कला अकादमी में इन तमाम विवादों को देखते हुए संसद में 17 दिसंबर 2013 को संस्कृति मंत्रालय से संबद्ध स्थायी समिति रिपोर्ट का स्मरण हो रहा है। इसमें कहा गया था, 'हमारे संस्थापकों ने संस्कृति को राजनीति से दूर रखने के लिए इन्हें स्वायत्ता दी थी, परंतु आज ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीति इसमें पिछले दरवाजे से प्रवेश कर गई है। इन संस्थाओं के संस्थापकों को लेखकों और कलाकारों के समुदाय की एकता पर दृढ़ विश्वास था और आज वे इन संस्थाओं को बाधित करनेवाली समस्याओं का पूर्वानुमान नहीं लगा पाए। नतीजन प्रक्रिया में पारदर्शिता के संबंध में जवाबदेही का अभाव है। पारदर्शिता और जवाबदेही के बिना उसकी स्वयत्तता एक दोधारी हथियार बन गई है जिसका कोई भी अपनी सुविधानुसार उपयोग कर सकता है। जवाबदेही का अर्थ नियंत्रण नहीं है, बल्कि वह जिम्मेदारी है जिसके लिए स्वयत्तता का प्रयोग किया जाना है। संकट की यह स्थिति संस्कृति मंत्रालय की उदासीनता, ध्यान नहीं देने और कभी कभी असहायता वाली भूमिका के कारण और भी गंभीर हो जाती है। मंत्रालय द्वारा उनके कार्यों में जवाबदेही व पारदर्शिता तय करने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है।'

संसद की इस समिति ने अध्यक्ष और सचिव के बीच कार्य विभाजन स्पष्ट करने पर भी बल दिया था, क्योंकि इनके गठन के दस्तावेजों में इन दोनों के अधिकारों की सीमा अस्पष्ट थी। इसका नतीजा यह होता था कि कई बार अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का उपयोग करने की चेष्टा करते थे जो उनको प्राप्त नहीं होती है। ललित कला अकादमी में तो स्थिति बहुत विषम है। वहां तो लंबे समय से महा-परिषद या कार्यकारी परिषद है ही नहीं, लिहाजा अराजकता ज्यादा है। अध्यक्ष के निर्देशों के कार्यान्वयित करवाने में किसी प्रकार की चूक या नियमों के उल्लंघन के लिए सचिव जिम्मेदार होते हैं, इस वजह से बहुधा दोनों के बीच तनातनी चलती रहती है। ललित कला अकादमी के सचिव के बार-बार बर्खास्त होने की वजह ये भी हो सकती है।

संगीत नाटक अकादमी में भी सचिव पर गाज गिरी ही थी। वहां की सचिव रही हेलेन आचार्य का मामला तो कोर्ट तक गया था। इस समिति ने सरकार को इन अकादमियों के संविधान में स्पष्टता लाने के लिए एक हाई पावर समिति बनाने को कहा था। उसने मई 2014 में अपनी रिपोर्ट भी दे दी। रिपोर्ट में ललित कला अकादमी के अध्यक्ष का कार्यकाल पांच वर्ष से तीन वर्ष तक करने की सिफारिश की गई। साथ ही अध्यक्ष को लगातार दो कार्यकाल देने पर भी आपत्ति जताई गई थी। हाई पावर समिति की सिफारिशों के आधार पर ललित कला अकादमी के नए नियमों को मंत्रालय ने 26 अप्रैल 2018 को अधिसूचित कर दिया जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र में 27 अप्रैल को हो गया। लेकिन अब तक ललित कला अकादमी के महा-परिषद का गठन नहीं हो पाया है। चेयरमैन ही वहां के सर्वेसर्वा हैं और कोई नियमित सचिव भी नहीं हैं। एक सचिव नियुक्त भी हुए थे, लेकिन वो कुछ दिनों में इस्तीफा देकर चले गए। जाहिर सी बात है कि इन सबकी अनुपस्थिति में चेयरमैन को असीमित शक्तियां मिली हुई हैं।

केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद संस्कृति के क्षेत्र में बड़ी चुनौती है। अकादमियों की वजह से जिस तरह से विवाद उठ रहे हैं उसके पीछे कई वजहें हैं। कुछ संस्थानों में निदेशक और चेयरमैन नहीं हैं जैसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में नियमित निदेशक का पद महीनों से खाली है और चेयरमैन भी नहीं है। अब वक्त आ गया है कि केंद्र सरकार को एक ठोस संस्कृति नीति के बारे में विचार करना चाहिए। संस्कृति नीति के अभाव में इन सांस्कृतिक संस्थानों में तदर्थ आधार पर कामकाज हो रहा है। प्रह्लाद सिंह पटेल अनुभवी हैं लिहाजा उनसे ये अपेक्षा की जा सकती है कि वो देश की संस्कृति-नीति के निर्माण की दिशा में सकारात्मकता के साथ विचार करेंगे। इससे इन संस्थानों के काम-काज में तो पारदर्शिता आएगी ही भारतीय प्राच्य विद्या के संरक्षण और संवर्धन का काम भी गंभीरता से हो सकेगा।

फिर से

लद्दाख की रोचक यात्रा

लद्दाख घूमने के लिए जाने की इच्छा बहुतों के मन में होती है। हालांकि हिमाचल प्रदेश के मनाली के रास्ते यहां तक सड़क के जरिये पहुंचना पहले से कुछ आसान जरूर हो गया है, लेकिन फिर भी यह दूरी इतनी अधिक है और पूरा इलाका पहाड़ी है लिहाजा मुश्किलों का सामना तो यात्रियों को करना ही पड़ता है। ऐसे में यदि आप हवाई मार्ग से वहां जाते हैं तो परेशानी कम होती है। सर्दियों में लद्दाख जाने का एकमात्र साधन वायुयान ही है, इसलिए वहां जाने की और ज्यादा इच्छा होने लगी। सर्दियों में लद्दाख कैसा होता है, यह जानने की बड़ी तीव्र आकांक्षा थी।

यह बात कुछ वर्ष पहले की है। जब मुझे पता चला कि दिल्ली के मुकाबले लद्दाख में तापमान 20 से 25 डिग्री तक कम होगा तो समझ नहीं आया कि शरीर कैसे इतनी अधिक सर्दी झेल पाएगा? दोस्तों ने भी काफी डराया था। फिर भी लगन थी कि जनवरी में लद्दाख जाना है। देखना है कि वहां जीवन कैसे चलता है? कैसे लोग जमी हुई नदी के ऊपर पैदल आना-जाना करते हैं? कैसे गैर-लद्दाख लोग जैसे सेना के जवान वहां रहते हैं?

अक्सर लोग लेह और लद्दाख को अलग-अलग मानते हैं। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर राज्य के भौगोलिक रूप से तीन भाग हैं- जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। जम्मू क्षेत्र में जवाहर सुरंग से पहले का इलाका आता है और इसमें कठुआ, साम्बा, जम्मू, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, रियासी आदि जिले आते हैं। कश्मीर क्षेत्र में जवाहर सुरंग के बाद का इलाका आता है और इसमें अनंतनाग, श्रीनगर, बडगाम, बारामूला, कुपवाडा आदि जिले आते हैं। श्रीनगर- लेह मार्ग पर सोनमर्ग से कुछ आगे जोजिला दर्रा पार करते ही लद्दाख क्षेत्र शुरू हो जाता है और इसमें कारगिल और लेह जिले शामिल हैं।

यात्रा के तय दिन दिल्ली एयरपोर्ट से लेह के लिए रवाना हुआ। महज 15 मिनट भी नहीं लगे हमें हरियाणा पार करके हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के ऊपर पहुंचने में। और जल्दी ही कुल्लू से आगे रोहतांग पार करके महा-हिमालय में जा घुसे। यहां इंच-इंच पर बर्फ का साम्राज्य था। जब हिमालय पार हो गया तो विमान लद्दाख के पर्वतों के ऊपर से उड़ने लगा। अब बर्फ काफी कम हो गई थी और ज्यादातर पहाड़ नग्न हिम-वनस्पति-विहीन नजर आ रहे थे।

लेह आने से कुछ ही मिनट पहले उद्घोषणा हुई कि विमान लेह के कुशोक बकुला रिन्पोछे हवाई अड्डे पर उतरने वाला है। कुशोक बकुला रिन्पोछे नाम से ही पता चल रहा है कि हम लद्दाखी जमीन पर आ गए हैं। असल में कुशोक बकुला पिटुक गोनपा के प्रधान लामा थे। लेह के हवाई अड्डे के एक तरफ तो लेह शहर है जबकि दूसरी तरफ पिटुक गोनपा है। पिटुक को अंग्रेजी में स्पिटुक लिखा जाता है, जिससे कुछ लोग इसे स्पिटुक मोनेस्ट्री भी कहते हैं।

हमारा विमान महज कुछ ही देर में लद्दाख हवाई अड्डे पर उतरने वाला था।

करीब सवा घंटे पहले हम 200 मीटर की ऊंचाई पर थे, और अब 3,200 मीटर की ऊंचाई पर, इसलिए शरीर पर कुछ असर तो होना ही था। असर होना तभी शुरू हो गया जब विमान का दरवाजा खोला गया। अभी तक हम दिल्ली वाले वायुदाब पर ही थे, क्योंकि वायुयान एयरटाइट था। जब अचानक दरवाजा खोला गया तो दिल्ली की भारी हवा निकल गई और लेह की हल्की हवा अंदर भर गई। सीट से उठकर दरवाजे की ओर जाते समय यह अंतर साफ महसूस हो रहा था। घोषणा हुई कि बाहर तापमान माइनस दस डिग्री है। मैंने दिल्ली के हिसाब से कपड़े पहन रखे थे, लेकिन जब बाहर निकला तो अहसास हो गया कि यही कपड़े लेह में भी पर्याप्त होंगे। अगले दिन चिलिंग पहुंचने तक मैंने यही कपड़े पहने रखे, जबकि तापमान माइनस 15 से भी कम पहुंच गया था।

(नीरज मुसाफिर के यात्रा ब्लॉग 'मुसाफिर हूं यारों' से संपादित अंश)

ट्वीट-ट्वीट

ट्विटर से पहले एक बहुत खूबसूरत दुनिया थी। मगर न जाने कितने लोगों की दोस्ती इस सोशल मीडिया और राजनीति की भेंट चढ़ गई। मैंने भी इस तरह कई दोस्त खो दिए, पर शायद जो इस तरह खत्म हो जाए वो सच्ची दोस्ती थी ही नहीं।
ऋचा अनिरुद्ध@richaanirudh

चीन कश्मीर में तो लोकतंत्र चाहता है, लेकिन अपने देश में नहीं। वह कश्मीर में कुछ हजार प्रदर्शनकारियों से हमदर्दी जता रहा है, लेकिन हांगकांग में लाखों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे लोगों के प्रति बेरुखी क्यों दिखा रहा है?
तसलीमा नसरीन@taslimanasreen

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर पर हुई बहस को लेकर पाकिस्तानी खुद को बधाई देकर मुगालते में ही जी रहे हैं। उन्हें शायद अहसास भी नहीं कि सुरक्षा परिषद ने उनके प्रस्ताव पर विचार भी नहीं किया। केवल चीन के अनुरोध पर चर्चा हुई। रूस ने इस पर सख्ती दिखाई। अमेरिका और फ्रांस ने भी हमारा साथ दिया और ब्रिटेन ने विरोध। वहां पाक तो पूरी तरह अप्रासंगिक था।
सुशांत सरीन@sushantsareen

अब पाकिस्तानी विदेश मंत्री कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब जब रोने-धोने के बाद दाल नहीं गली तो सुर बदल लिए। भारत में पाक के समर्थक भी उनकी बात गांठ बांध लें जो सोचते हैं कि 370 खत्म होने से मानों आसमान गिर गया हो।
यूसुफ ऊंझावाला@YusufDFI

रचनाकर्म

शून्य से शिखर के सफर की पड़ताल

प्रणव सिरोही

कामयाबी का कोई निश्चित कारगर मंत्र होता तो शायद कोई नाकाम ही नहीं होता। फिर भी किसी विराट सफलता के मर्म की पड़ताल कर ऐसे किसी मंत्र की तलाश अनवरत जारी रहती है। लेखक-पत्रकार विजय त्रिवेदी ने अपनी पुस्तक 'बीजेपी : कल, आज और कल' में बीते कुछ समय से स्वर्णिम सफलता के रथ पर सवार भाजपा की इसी विजय गाथा के जरिये सफलता के उन्हीं सूत्रों की थाह लेने की कोशिश की है। यह किताब शून्य से शुरू करने वाली पार्टी के महज कुछ वर्षों के भीतर शिखर पर पहुंचकर दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनने का गौरव हासिल करने की दास्तान सुनाती है।

पुस्तक के नाम से आभास होता है कि यह भाजपा के अतीत, वर्तमान और भविष्य की दिशा पर दृष्टिपात करती है। मगर ऐसा है नहीं। यह मुख्य रूप से पार्टी के मौजूदा करिश्माई प्रदर्शन और समकालीन संदर्भों पर ही अधिक केंद्रित है। हालांकि कई जगहों पर अतीत के आईने से उनका पूर्वावलोकन भी किया गया है। फिर भी कुछ व्यक्तियों और उनके इर्दगिर्द घटनाओं पर ही अधिक चर्चा करती है। इसकी समकालीन प्रासंगिकता इसके आरंभ से ही स्पष्ट हो जाती है, जहां पहले अध्याय की शुरुआत ही वाघा सीमा पर विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी से जुड़े माहौल से की गई है। मोदी सरकार और उससे जुड़ी तमाम योजनाओं के प्रभाव की भी यह मीमांसा करती है। बीते आम चुनाव से पहले विपक्ष की रणनीतियों पर भी इसमें चर्चा है। इस लिहाज के कहीं-कहीं किताब का झुकाव भाजपा की यात्रा से अधिक मौजूदा सियासी रुझानों की ओर अधिक प्रतीत होता है।

भाजपा से जुड़ी जिज्ञासाओं को यह किताब शांत करने का प्रयास करती है। लेखक को इसके लिए श्रेय देना होगा कि कुछ स्वाभाविक सवालों के जवाब के लिए उन्होंने लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों के साथ संवाद किया है। जैसे भाजपा सरकारों के दौर में एक शाश्वत बहस यह रही है कि सरकार में प्रधानमंत्री का रसूख अधिक होता है या उन पर संघ प्रमुख अधिक हावी रहते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश कहते हैं, 'जो लोग समझते हैं कि मोदी आरएसएस की परवाह नहीं करते या फिर जो समझते हैं कि आरएसएस मोदी को आदेश देता है, वे लोग या तो संघ को नहीं समझते या फिर मोदी को नहीं जानते। सच इन दोनों के बीच में कहीं पर है।' ऐसे ही इन दिनों भाजपा को लेकर अटल-आडवाणी और मोदी-शाह की जोड़ी में कौन बेहतर है, जैसी बहस भी छिड़ गई है। इस पर भाजपा के नेता अनिल बलूनी कहते हैं, 'दोनों जोड़ियों में तुलना ही बेमानी है, क्योंकि दोनों का वक्त और फॉर्मेट अलग-अलग है।' हालांकि पत्रकार शीला भट्ट मोदी-शाह की सफलता के समीकरण को अलग ढंग से व्यक्त करती हैं, 'मोदी हमेशा अपनी जीत के लिए कोई रास्ता निकाल लेते हैं और इसके लिए संघ में मिली दीक्षा की मदद लेते हैं। वहीं शाह बात हमेशा हिमालय की करते हैं, ताकि कम से कम सहयाद्री की ऊंचाई तो हासिल की जा सके।'

यह पुस्तक भाजपा की यात्रा से रूबरू कराती है। यह बताती है कि कैसे यह पार्टी राजनीतिक मोर्चे पर सफलता के नए प्रतिमान गढ़कर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई बन गई। पुस्तक वर्तमान संदर्भों पर अधिक केंद्रित है...

पुस्तक : बीजेपी : कल, आज और कल
लेखक : विजय त्रिवेदी
प्रकाशक : एका प्रकाशन
मूल्य : 250 रुपये

नए दौर में सहयोगी दलों के साथ तालमेल से लेकर जाति धर्म की राजनीति जैसे संदर्भों पर भी इसमें विमर्श है। भाजपा की पहचान सामूहिक नेतृत्व के जरिये निर्णय करने वाली पार्टी की रही है, लेकिन वक्त के साथ इसमें बदलाव आया है। पार्टी के एक महासचिव इस पर कहते हैं, 'नए दफ्तर की इतनी बड़ी बिल्डिंग में आपको कार्यकर्ता के अलावा सब कुछ मिल जाएगा।' लेखक इसे नई भाजपा की संज्ञा देते हैं जहां सिर्फ आलाकमान के निर्देश ही निर्णायक हैं।

इसकी भूमिका वरिष्ठ पत्रकार रामबहादुर राय ने लिखी है। तमाम विशेषज्ञों से बातचीत पुस्तक को प्रामाणिकता अवश्य देती है, लेकिन इससे प्रवाह थमता है। इससे पुस्तक का क्षैतिज विस्तार तो हुआ है, लेकिन गहराई की कमी रह जाती है। चूंकि लेखक इन तमाम घटनाओं के स्वयं साक्षी रहे हैं तो उनकी कलम से यह अनुभव बखूबी बोलता भी है। कई जगह नाटकीयता रोचकता भी प्रदान करती है। उनकी शैली भी पाठक को बांधे रखती है। हालांकि 'कठिन डगर चुनाव सुधारों की' जैसे पाठ के बजाय भाजपा पर ही कुछ और सामग्री होती तो पुस्तक अपने नाम के साथ कहीं अधिक न्याय कर पाती।

बहुरंगी सपनों की कहानियां

पल्लवी प्रिया

'स्वप्न हमारी उन इच्छाओं को सामान्य अथवा प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करते हैं, जिनकी तृप्ति जागृति की अवस्था में नहीं हो पाती है।' अपने कहानी संग्रह 'एक नींद हजार सपने' में लेखिका अंजू शर्मा उन सपनों की ही बात करती हैं, जो कभी स्याह हैं तो कभी रंगीन, लेकिन जीने की उम्मीद जगाए रखते हैं। इसमें 14 कहानियां हैं। सभी के पात्र और उनका परिवेश साधारण हैं, लेकिन लेखिका जब अपनी शब्द रूपी तूलिका से कहानी के कैनवस पर उनका रंग-रोगन करती हैं, तो वह असाधारण बनते जाते हैं। इनसे गुजरते हुए लेखिका की लेखन शैली पर मुग्ध होना स्वाभाविक है। कहानी के परिवेश के हिसाब से वह कभी पंजाबी तो कभी उर्दू के शब्दों का उपयोग करती हैं। यह पात्रों को समझने और उनके साथ जुड़ने की राह आसान करता है।

संग्रह की पहली कहानी 'गली नंबर दो' ऐसे युवक भूपी की कहानी है, जो लंबाई कम होने के कारण हीनभावना से ग्रस्त है। वह रंग-बिरंगी मूर्तियां बनाता है, लेकिन उसकी असल दुनिया बेरंग है। उसके मन की टीस बयां करने के लिए लेखिका ने कई बार अपनी कल्पनाशीलता का बेजोड़ नमूना पेश किया है। वह लिखती हैं, 'भूपी एक रेगिस्तान में अकेला खड़ा है। जहां तक उसकी नजर जाती है, उसके मन और जीवन में मौजूद अकेलेपन का शासन है।' कहानी 'बंद खिड़की खुल गई' दंगे की भयावहता में फंसी एक युवती की वेदना के साथ ही अल्पसंख्यक समाज पर भरोसा जगाने का आग्रह करती है। वहीं दूसरी तरफ विभाजन की पीर, अपनेपन की लड़ियों व बचपन के किस्सों को जोड़कर गढ़ी गई 'पत्ता टूटा डाली से' आपके जहन में घर कर लेती है। 'भरोसा अभी कायम', 'नेम प्लेट', 'आउडेटेड' में भी लेखिका ने जीवंत पात्रों को रचा है। 'मुस्तकबिल' के जरिये तीन तलाक के सामयिक मुद्दे पर भी चोट की गई है। अंतिम एवं शीर्षक कहानी 'एक नींद हजार सपने' शब्द-भाव की अनुपम चित्रकारी का जीवंत प्रमाण है। दिल्ली की तमिल कॉलोनी के इर्द-गिर्द बुनी इस कहानी में बच्चे की शिक्षा का स्वप्न देखती एक महिला के दृढ़ संकल्प को बयां किया गया है। भिन्न-भिन्न पृष्ठभूमि व भाषायी प्रयोग के माध्यम से लिखी ये कहानियां पाठकों को बांधे रखने में सक्षम हैं।

पुस्तक : एक नींद हजार सपने
लेखिका : अंजू शर्मा
प्रकाशक : सामयिक प्रकाशन
मूल्य : 200 रुपये

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या सीडीएस की नियुक्ति से सैन्य बलों की क्षमताएं और बेहतर होंगी?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या भारतीय टीम के मुख्य कोच के रूप में रवि शास्त्री का चयन सही है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y**, **N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

तुम पर सबको नाज है जियो अकबरुद्दीन,
इसी तरह दो पटखनी पाक रहे या चीन।
पाक रहे या चीन झुके भारत के आगे,
और मियां इमरान फिरें बस भागे-भागे।
जहां कहीं मिल जायं कुचलते रहिए विषधर,
बरसाएगा फूल समूचा भारत तुम पर।
– ओमप्रकाश तिवारी

ओमप्रकाश तिवारी
ब्यूरो प्रमुख, मुंबई

महाराष्ट्र डायरी

यूं ही नहीं सुहाते नेताओं को कजरी-बिरहा

इन दिनों जब पूरा उत्तर प्रदेश बछड़ों से अपने धान के खेत बचाने के लिए रात-रात भर पहरे दे रहा है, तो वहां की सांस्कृतिक पहचान कजरी-बिरहा जैसे लोकगीतों को बचाने की जिम्मेदारी मुंबई महानगर पूरी गंभीरता से निभा रहा है। सांस्कृतिक संस्था लोकायन एवं बयार मित्र परिवार की तरफ से दहिसर उपनगर में आयोजित कजरी के ऐसे ही एक कार्यक्रम में स्थानीय शिवसेना विधायक प्रकाश सुर्वे मंच पर पधारकर बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं तो उत्तर भारतीयों का विधायक हूं। वे कहते हैं कि मैंने ही इस कार्यक्रम के आयोजक अभय मिश्र से आग्रह किया था कि तीन वार्डों के बीच कजरी का एक कार्यक्रम यहां रख लिया जाए, तो दूसरा ठाकुर विलेज में। प्रकाश सुर्वे के विदा होते ही दूसरी विधायक मनीषा चौधरी भी कजरी के मंच पर गायकों के साथ फोटो खिंचवाती दिख रही थीं। स्थानीय सभासद जीतेंद्र पटेल तो पूरे समय उपस्थित थे ही। ये सभी नेता उत्तर भारतीय सांस्कृतिक आयोजनों में भरपूर सहयोग का वादा करके जाते हैं, और निभाते भी हैं।

ऐसे आयोजन एक जगह या एक संस्था की ओर से नहीं, बल्कि विभिन्न संस्थाओं की ओर से मुंबई में अलग-अलग स्थानों पर इन दिनों हो रहे हैं। सुरेश शुक्ल और राधा मौर्या से लेकर सुप्रसिद्ध लोकगायिका मालिनी अवस्थी तक इन कार्यक्रमों में अपने सुर बिखेर रही हैं। मुंबई में उत्तर प्रदेश दिवस मनाने के लिए विख्यात मुंबई भाजपा के महासचिव अमरजीत मिश्र अपनी सांस्कृतिक संस्था अभियान के माध्यम हर साल सावन लगते ही कजरी पखवाड़े का आयोजन करते हैं। राज्य की भाजपानीत सरकार में महाराष्ट्र चित्रपट-रंगभूमि सांस्कृतिक विकास महामंडल के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे मिश्र के आयोजनों में तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के नेताओं का आगमन सामान्य बात है। इस बार भी उनकी कजरी में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर, देवरिया से सांसद रमापति राम त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश के ग्राम विकास मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश फिल्म निर्माण निगम के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव के साथ महाराष्ट्र के भी कई मंत्री शिरकत कर चुके हैं।

पारंपरिक तरीके से कजरी का आयोजन कराने में भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ल भी पीछे नहीं रहते। ठाणे स्थित येऊर की हरी-भरी पहाड़ियों के बीच स्वानंद बाबा आश्रम में आयोजित उनके कार्यक्रम में तो उत्तर भारतीय महिलाओं को मायके का अहसास दिलाने के लिए बाकायदा झूले के साथ-साथ चूड़ी, महावर, मेहंदी, सिंदूर और बिंदी का भी प्रबंध रहता है। इसमें दो राय नहीं कि यह सांस्कृतिक आयोजन उत्तर प्रदेश से दूर रह रहे उत्तर प्रदेश मूल के लोगों को उनकी संस्कृति एवं रीति-रिवाजों से जोड़े रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के चुनावी वर्षों में इनका रंग और गाढ़ा हो जाता है। यही स्थिति इस बार के आयोजनों की है। करीब 60 विधानसभा सीटें रखनेवाले मुंबई और ठाणे उत्तर भारतीय मतदाताओं बड़ा गढ़ हैं। माना जाता है कि इन दोनों शहरों में मिलाकर अब 45 फीसद आबादी हिंदीभाषी हो चुकी है। यहां की कई सीटों पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, बस्ती, गोंडा, कुशीनगर, आजमगढ़ और देवरिया आदि जनपदों के मूलनिवासियों की संख्या इतनी है कि वे किसी भी दल के उम्मीदवार के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस हमेशा यहां उत्तर भारतीयों को विशेष महत्व देती रही है। एक समय रायबरेली के मूल निवासी डॉ. राममनोहर त्रिपाठी यहां हिंदी भाषियों के सर्वमान्य नेता माने जाते थे। वह वसंतदादा पाटिल के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे। फिर वाराणसी के चंद्रकांत त्रिपाठी भी मंत्री रहे। उत्तर भारतीय नेताओं का स्वर्णिम युग आया वर्ष 2000 में जब विलासराव देशमुख के मंत्रिमंडल में करीब पांच हिंदीभाषी मंत्री बने। इनमें गृह राज्यमंत्री कृपाशंकर सिंह, नागरिक आपूर्ति राज्यमंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान, गृह निर्माण राज्यमंत्री नवाब मलिक के नाम महत्वपूर्ण रहे। वर्ष 2009 में कृपाशंकर सिंह के मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रहते कांग्रेस के पांच हिंदीभाषी विधायक भी चुनकर आए। लेकिन केंद्र की राजनीति में कांग्रेस कमजोर हुई, तो मुंबई में भी कांग्रेस से हिंदीभाषियों का मोहभंग होने लगा। कांग्रेस इसे संभाल भी नहीं पाई। उसने किसी उत्तर प्रदेश के हिंदीभाषी को कमान सौंपने के बजाय बिहार मूल के संजय निरुपम पर भरोसा जताया। जबकि मुंबई में उत्तर प्रदेश मूल के हिंदीभाषियों की आबादी करीब 25 फीसद, तो बिहार मूल के लोगों की आबादी सिर्फ चार फीसद है। कांग्रेस अभी भी हिंदीभाषियों को पुनः अपने से जोड़ने के लिए कोई कारगर रणनीति नहीं बना पाई है।

मुंबई अध्यक्ष की जिम्मेदारी कांग्रेस ने फिलहाल राजस्थान मूल के मिलिंद देवड़ा को दे रखी है, जो हिंदीभाषी तो जरूर हैं, लेकिन मुंबई के उत्तर भारतीयों में उनकी पैठ बनना अभी बाकी है। दूसरी ओर भाजपा को कांग्रेस से छिटके उत्तर भारतीयों के वोट का लाभ तो जरूर मिला, लेकिन वह मुंबई में कांग्रेस जैसा कोई कद्दावर हिंदीभाषी नेतृत्व आज भी खड़ा नहीं कर सकी है। नाम के लिए फड़नवीस सरकार में विद्या ठाकुर को राज्यमंत्री बनाया जरूर गया है, लेकिन संगठन में उत्तर भारतीयों को कोई खास महत्व आज भी नहीं दिया जाता। अब भाजपा चुनाव प्रभारी और सहप्रभारी के रूप में क्रमशः भूपेंद्र यादव एवं उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्या को लाकर हिंदीभाषियों को रिझाने की जुगत भिड़ा रही है। मुंबई अध्यक्ष की जिम्मेदारी उसने पहले ही राजस्थान मूल के मंगलप्रभात लोढ़ा को दे रखी है।

इस प्रकार, भाजपा हो या कांग्रेस, इस समय दोनों ही के पास पूरी मुंबई पर प्रभाव रखनेवाला कोई सर्वमान्य नेता किसी के पास नजर नहीं आता। ऐसी स्थिति में सभी दलों के नेता अपने-अपने स्तर पर इस बड़े वोटबैंक को रिझाने में लगे हैं। अभी इसका बड़ा जरिया मुंबई में आयोजित कजरी समारोह बन रहे हैं, तो कुछ ही दिनों बाद यहां होनेवाली रामलीलाएं बनेंगी।

100 करोड़ डॉलर (करीब सात हजार करोड़ रुपये) की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है टॉय स्टोरी-4 ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर। यह इस साल डिज्नी की पांचवीं फिल्म है, जिसने 100 करोड़ डॉलर का आंकड़ा पार किया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला डिज्नी पहला स्टूडियो बन गया है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 18 अगस्त 2019

चमकता रहेगा 'रवि' का सितारा

चर्चित शख्सियत

अभिषेक त्रिपाठी, नई दिल्ली

वर्ल्ड कप में हार के बाद सवाल उठ रहे थे कि क्या रवि शास्त्री को दोबारा भारतीय क्रिकेट टीम का कोच बनाया जाएगा? बीते सप्ताह उनके नाम पर मुहर लगी और साफ हो गया कि फिलहाल उनसे बेहतर टीम को कोई नहीं समझता। वह टीम के कप्तान विराट कोहली के करीबी हैं। इस जोड़ी ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अब देखना है कि एकदिवसीय वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से चूकी भारतीय टीम को यह जोड़ी क्या 2021 में टी-20 वर्ल्ड कप हासिल करा पाएगी...

भारतीय क्रिकेट में इससे पहले कभी भी किसी कोच और कप्तान की जोड़ी इतनी मजबूत नहीं रही जितनी रवि शास्त्री और विराट कोहली की है। इससे पहले कोच और कप्तान की लड़ाई की ही खबरें आती थीं, लेकिन अब दोस्ती की हवा चल रही है। सौरव गांगुली और जॉन राइट, विराट कोहली और अनिल कुंबले के बीच द्वंद्व की खबरों ने भारतीय क्रिकेट जगत को कई बार परेशान किया, लेकिन विराट और शास्त्री के बीच काफी लगाव है। दोनों हर मोर्चे पर एक-दूसरे का बचाव करते हैं। दोनों एक-दूसरे के लिए खड़े रहते हैं और यही कारण है कि इन दोनों के वर्चस्व से टीम के कुछ लोग परेशान भी रहते हैं।

कपिल देव की अध्यक्षता में जब क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) का गठन हुआ था तभी लगभग यह तय हो गया था कि शास्त्री टीम के मुख्य कोच बने रहेंगे और ऐसा हुआ भी। कुल मिलाकर 2021 टी-20 विश्व कप तक शास्त्री और विराट की जोड़ी का भारतीय क्रिकेट में वर्चस्व बरकरार रहेगा। अब देखना यह है कि इसका फायदा टीम इंडिया को मिलता है कि नुकसान होता है।

अपने हिसाब से ही चले: शास्त्री ने विश्व कप के पहले दैनिक जागरण को दिए साक्षात्कार में कहा था कि वह क्रिकेटर के तौर पर जैसे थे, वैसे ही कमेंट्री के दौरान रहे और वैसे ही अब हैं। उनका कहना था कि उन्होंने परिस्थितियों से समझौता नहीं किया और अपने हिसाब से ही चले। इसमें कोई शक नहीं है। वह हर समय सामने वाले पर हावी रहते हैं और यही कारण है कि उनके दुश्मनों की कमी नहीं हैं। हालांकि, इससे शास्त्री को फर्क भी नहीं पड़ता है। कमेंट्री में झंडे गाड़ने के बाद शास्त्री को 2015 विश्व कप के ठीक पहले टीम निदेशक बनाया गया था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुए विश्व कप में टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी।

2016-2017 में अनिल कुंबले भारत के मुख्य कोच बने और उनसे विराट के मतभेदों ने शास्त्री का कोच के तौर पर द्वार खोला। इंग्लैंड में हुई चैंपियंस ट्रॉफी के बाद शास्त्री को दो साल के लिए कोच बनाया गया। इस दौरान 2018 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका में द्विपक्षीय वनडे सीरीज 5-1 से जीती। यह भारत की दक्षिण अफ्रीका में पहली द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीत थी। 2018 में भारतीय टीम ने यूएई की मेजबानी में एशिया कप जीता। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग, पाकिस्तान व श्रीलंका की टीमों ने भी भाग लिया था। 2018 में भारत ने श्रीलंका में हुई निदहास टी-20 त्रिकोणीय सीरीज जीती, जिसमें तीसरी टीम बांग्लादेश की थी। 2019 में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में वनडे व टेस्ट सीरीज जीतीं। ये ऑस्ट्रेलिया में किसी भी भारतीय टीम की पहली द्विपक्षीय वनडे व टेस्ट सीरीज जीत थी। 2019 में टीम इंडिया इंग्लैंड में हुए वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल तक पहुंची। शास्त्री के कोच रहते हुए यानी 2017 से 2019 के दौरान भारत ने घरेलू द्विपक्षीय वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया (4-1), न्यूजीलैंड (2-1), श्रीलंका (2-1) व वेस्टइंडीज (3-1) को हराया। इस दौरान भारत ने वेस्टइंडीज (2-0), श्रीलंका (5-0) व न्यूजीलैंड (4-1) को वनडे सीरीज में उनकी सरजमीं पर भी हराया। 2017 से 2019 के दौरान भारत ने श्रीलंका को अपने (3-0) और उसके घर (1-0), में लगातार दो टेस्ट सीरीज में हराया। इसके अलावा भारत ने घरेलू टेस्ट सीरीज में अफगानिस्तान (1-0), वेस्टइंडीज (2-0) और ऑस्ट्रेलिया (2-1) को भी शिकस्त दी। कुल मिलाकर इस रिकॉर्ड के दम पर शास्त्री को कोच बनने से कोई नहीं रोक सकता था और ऐसा हुआ भी।

विराट कोहली की पसंद : बतौर कोच शास्त्री कप्तान विराट कोहली की पहली पसंद थे। वेस्टइंडीज जाने से पहले विराट ने कहा था कि उन्हें खुशी होगी अगर शास्त्री को ही कोच की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इन दोनों के बीच लगाव का कारण है दोनों का एक जैसा होना। दोनों ही आक्रामक और बिंदास हैं। दोनों ही मैदान के अंदर और बाहर एक जैसे हैं। कुंबले के कोच रहने पर टीम के साथियों और कप्तान पर काफी बंदिशें हो जाती थीं, लेकिन शास्त्री के रहने पर टीम में बंदिशें होती ही नहीं हैं। आजकल के खिलाड़ियों को यह रवैया पसंद आता है। कप्तान को भी यह पसंद आता है कि वह मैदान में खेलने और अभ्यास करने के बाद जो चाहें वह कर सकते हैं, जबकि कुंबले के समय ऐसा नहीं था। तब खिलाड़ी बंधन महसूस करते थे। यही कारण है कि शास्त्री भी अपने कप्तान का हर समय बचाव करते हैं। कभी-कभी यह बचाव गलत भी होता है, लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और जंग में सब जायज है। याद कीजिए जब भारतीय टीम वेस्टइंडीज जा रही थी तो प्रेस कांफ्रेंस में विराट से रोहित शर्मा के साथ उनके विवाद को लेकर सवाल किया गया। बीच में ही शास्त्री ने माइक अपनी तरफ मोड़ा और आक्रामक जवाब दिया, खेल से बड़ा कोई नहीं, ना मैं ना कोई और। जब भी विराट दबाव में होते हैं या आलोचना का शिकार हो रहे होते हैं तो शास्त्री उनके बचाव में आते हैं। हालांकि, इस बचाव से आगे आकर शास्त्री को अब विराट को बेहतर कप्तान बनाने पर ध्यान लगाना होगा क्योंकि अगर विराट ढंग से पिच और अंतिम-11 का चयन नहीं कर पाएंगे या विश्व कप सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में धौनी को सातवें नंबर पर भेजने का फैसला करेंगे तो फिर टीम इंडिया के लिए विश्व कप चैंपियन बनना मुश्किल होगा। अब जब शास्त्री फिर से कोच बन ही गए हैं तो उन्हें यह प्रयास करना चाहिए कि अगले दो सालों में विराट भी भारत के सर्वोत्तम कप्तान बन जाएं।

'बलवान योग' ने बनाया बजरंग को बली

सुर्खियों में

जगदीश त्रिपाठी, हिसार

देश में खेल के सर्वोच्च सम्मान के लिए नामांकित किए गए पहलवान बजरंग पूनिया को यहां तक पहुंचाने में उनके पिता बलवान और गुरु योगेश्वर दत्त ने निभाई है अहम भूमिका...

बजरंग पूनिया। 65 किग्रा भार वर्ग में विश्व के नंबर वन रेसलर। महज 25 की उम्र में बजरंग ने जो मुकाम हासिल किया है निश्चित रूप से इसमें उनका लक्ष्य के प्रति समर्पण, अभ्यास और अनुशासन अहम रहा है, लेकिन उन्हें यहां तक पहुंचाने में उनकी माता ओमप्यारी देवी, पिता बलवान पूनिया, भाई हरेंद्र की तपस्या भी कम नहीं रही। अंतरराष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त की तो बात ही क्या। उन्होंने बजरंग को तराश कर विश्वस्तरीय पहलवानों के समक्ष खड़ा किया। हर मुश्किल दौर में बजरंग की सहायता के लिए तैयार रहे और इस तरह पिता बलवान और गुरु योगेश्वर के योग ने बजरंग को बली बना दिया, जो आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी चमक बिखेर रहे हैं। लगातार देश का नाम दुनिया में बुलंद करने के चलते बीते सप्ताह खेल के क्षेत्र में देश के सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न के लिए उनके नाम की घोषणा की गई।

26 फरवरी, 1994 को हरियाणा के झज्जर जिले के खुड्डन गांव में जन्मे बजरंग का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। खेती करते थे। बजरंग के पिता बलवान ने उन्हें 2005 में छारा गांव के लाला दीवानचंद अखाड़े में भेजना शुरू किया। छारा उनके गांव खुड्डन से 35 किमी दूर है। बजरंग वहां जाने के लिए सुबह तीन बजे उठ जाते थे। बड़े भाई हरेंद्र छोटे भाई के खाने-पीने का ध्यान रखते थे। उनके लिए बादाम रगड़ते थे। 2008 में 14 साल की उम्र में जब बजरंग दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम गए तो हरेंद्र नौकरी करने विदेश जा चुके थे, लेकिन जब बजरंग को खाने-पीने में परेशानी होने लगी तो हरेंद्र ने नौकरी छोड़ दी और वापस आ गए। फिर वह ही झज्जर से दूध, फल, घिसे हुए बादाम और घी लेकर बजरंग के पास जाते थे। छत्रसाल स्टेडियम में योगेश्वर दत्त की नजर बजरंग पर पड़ी। पहली नजर में पारखी जौहरी ने हीरे की पहचान कर ली। फिर क्या था। योगेश्वर ने बजरंग को प्रशिक्षण देना शुरू किया और एक योग्य शिष्य को योग्य गुरु मिलते ही बजरंग के बली बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया। बजरंग को 2010 के बाद से सरकारी मदद मिलनी शुरू हुई थी। उसके पहले तक सारा खर्च बजरंग के चचेरे भाई नरेंद्र, बड़े भाई हरेंद्र और योगेश्वर दत्त ने उठाया। जब योगेश्वर दिल्ली से वापस हरियाणा में शिफ्ट हो गए तो बजरंग का परिवार सोनीपत शिफ्ट हो गया और बजरंग सोनीपत के साई के सेंटर में दाखिल हो गए।

2006 में महाराष्ट्र के लातूर में हुई स्कूल नेशनल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके बाद लगातार 7 साल स्कूल नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया।

2009 में बाल केसरी का खिताब जीता। इसके बाद 2010 में थाइलैंड में जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में पहली बार विदेशी धरती पर गोल्ड मेडल जीता।

2013 में नई दिल्ली में आयोजित एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 60 किग्रा वर्ग में ब्रॉन्ज अपने नाम किया।

2017 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। 2018 में एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया।

खेल पर योगेश्वर की छाप: पिछले वर्ष जब एशियाई खेलों के लिए बजरंग जकार्ता जा रहे थे योगेश्वर ने उन्हें इसी उम्मीद के साथ विदा किया था कि वह गोल्ड जीतकर लाएंगे और बजरंग ने भी अपने गुरु को निराश नहीं किया। जापानी खिलाड़ी के साथ फाइनल में जब बजरंग ने लगातार छह अंक जीते, तो कमेंटेटर भी कहने लगे कि बजरंग भी योगेश्वर की तरह खेलते हैं।

के परासरन : जिनके लिए उम्र मायने नहीं रखती

इनसे मिलिए

जेएनएन, नई दिल्ली

दो बार देश के अटॉर्नी जनरल रह चुके पद्म सम्मान विजेता (पद्म भूषण व पद्म विभूषण) 92 वर्ष के वरिष्ठ वकील के. परासरन फिर सुर्खियों में हैं। वकील समुदाय के पितामह कहे जाने वाले परासरन सुप्रीम कोर्ट में चल रहे अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में रामलला की ओर से वकील हैं। आइए जानते हैं उनके अब तक के सफर के बारे में...

अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान बीते दिनों एक अलग ही वाकया देखने को मिला। रामलला की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जैसे ही वरिष्ठ वकील के परासरन अपनी सीट से खड़े हुए, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने उनसे पूछा, 'क्या आप बैठकर बहस करना चाहेंगे?' इस पर उन्होंने कहा, 'कोई बात नहीं। बार की परंपरा खड़े होकर ही बहस करने की है।' वकालत की दुनिया में 92 वर्षीय परासरन का कद बताने के लिए यह वाकया काफी है।

2016 के बाद से कोर्ट में उनकी उपस्थिति भले ही कम रही हो, लेकिन दो बड़े मुकदमों ने उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। पहला- सबरीमाला और दूसरा अयोध्या राम जन्मभूमि मामला। इन दोनों मुकदमों के चलते दो बार देश के अटॉर्नी जनरल रह चुके परासन चेन्नई से दिल्ली वापस आए। हिंदू धर्मग्रंथों के जानकार परासरन सर्वोत्कृष्ट सरकारी वकील हैं। 1970 के बाद से वह हर सरकार के विश्वसनीय रहे। अदालत में अक्सर हिंदू धर्मग्रंथों पर व्याख्यान देते हैं। अपने धर्म से समझौता किए बिना कानून में दिए गए इनके योगदान के लिए मद्रास के पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल ने इन्हें भारत में वकील समुदाय का पितामह कहा था।

सबरीमाला मामले में परासरन 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं पर मंदिर में प्रवेश पर रोक का बचाव करने के लिए नायर सर्विस सोसाइटी की तरफ से पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि अदालत इस मामले में गलत सवाल पूछ रही है। उन्होंने न्यायाधीशों से कहा, 'अगर कोई व्यक्ति यह पूछे कि क्या वह प्रार्थना के दौरान धूमपान कर सकता है तो उसे एक थप्पड़ पड़ेगा, जबकि अगर वह यह पूछता है कि क्या वह धूमपान करते हुए प्रार्थना कर सकता है तो उसकी सराहना होगी। इसी तरह सही सवाल पूछे जाने पर सही जवाब प्राप्त होगा, जबकि गलत सवाल पूछने पर गलत जवाब मिलेगा।' जिरह के दौरान परासरन ने कोर्ट में भगवान अय्यप्पा की ब्रह्मचारी प्रकृति को समझाने के लिए सुंदरकांड और रामायण के अंशों को पढ़ा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने फैसला उनके खिलाफ दिया और महिलाओं को मंदिर में जाने की अनुमति दी।

इससे पहले एक और मामले में वह सुर्खियों में रहे। राम सेतु केस में जब दोनों विरोधी पार्टियां परासरन के पास पहुंचीं तो उन्होंने सरकार के खिलाफ जाकर, सेतुसमुद्रम परियोजना से सेतु की रक्षा करने का निर्णय लिया। जब जजों ने परासरन से पूछा कि वह सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने स्कंद पुराण का जिक्र किया, जिसमें इस सेतु का वर्णन है। मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। परासरन ने कहा था, 'यह सबसे कम है, जो मैं राम के लिए कर सकता हूं।'

के परासरन ने सुप्रीम कोर्ट में 1958 में प्रैक्टिस शुरू की। बीती सदी के सातवें दशक में बड़े मामलों में परासरन का सामना अक्सर नानी पालकीवाला से होता था। आपातकाल के दौरान परासरन तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल थे। 1980 में देश के सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए। 1983 से 1989 तक देश के अटॉर्नी जनरल के रूप में काम किया। 1992 में जब मुंबई निवासी मिलन बनर्जी को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया, तब परासरन को 'सुपर एजी' के रूप में संदर्भित किया गया। बनर्जी को मध्यस्थता और वाणिज्यिक कानूनों में महारत हासिल थी, लेकिन संवैधानिक मामलों में सरकार के पास परासन ही सबसे अच्छा विकल्प रहे।

सरकारें बदलीं, लेकिन परासरन हमेशा सराहे गए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें संविधान के कामकाज की समीक्षा के साथ प्रारूपण और संपादकीय समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। वहीं, मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संप्रग-1 सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा और उन्हें संसद के उच्च सदन में मनोनीत किया।

चौथी पीढ़ी ने संभाली विरासत

के परासरन का जन्म 1927 में तमिलनाडु के श्रीरंगम में हुआ। परासरन के पिता केशव अयंगर वकील और वैदिक विद्वान थे। उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत की। परासरन के तीनों पुत्र मोहन, सतीश और बालाजी भी वकील हैं। मोहन परासरन संप्रग-2 सरकार में कुछ समय के लिए सॉलिसिटर जनरल रहे। अब परिवार की चौथी पीढ़ी ने भी इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए वकालत की दुनिया में कदम रखा है।

दो मिनट के वीडियो ने रानू को बना दिया स्टार

सड़क से शोहरत तक

जेएनएन, कोलकाता

कुछ दिन पहले तक रेलवे स्टेशन पर पेट की आग बुझाने के लिए गाना गाने वालीं रानू मारिया मंडल का वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसा वायरल हुआ कि वह रातों-रात स्टार बन गईं...

वीडियो में रानू ऐसी दिखीं (बाएं)। उन्हें गाने का ऑफर देने वाले आयोजक ने उनका मेकओवर करवाया।

किस्मत कब, किस पर मेहरबान हो जाए और शोहरत के शिखर पर पहुंचा दे कुछ कहा नहीं जा सकता। बीते दिनों कुछ ऐसा ही हुआ रानू मारिया मंडल की जिंदगी में। बांग्लादेश की सीमा से सटे बंगाल के नदिया जिले के राणाघाट रेलवे स्टेशन पर गुनगुनाती रानू के दो मिनट के वीडियो ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया। जिन गानों का सहारा लेकर वह रेलवे स्टेशनों पर भीख मांगा करती थीं, उन्हीं ने उन्हें नई पहचान दिला दी। अब उन्हें गाने के कई ऑफर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद रानू को लोग रानू दी कहकर बुला रहे हैं। इसने उनकी जिंदगी बदलकर रख दी है। इसी वीडियो की वजह से रानू से उनकी बेटी ने 10 साल में पहली बार बात की।

रानू का वीडियो राणाघाट स्टेशन पर अतींद्र चक्रवर्ती ने शूट किया था, जो गत 21 जुलाई को वायरल हो गया। लता मंगेशकर के गाए शोर फिल्म के बहुचर्चित गाने 'एक प्यार का नगमा है...' को गाने के बाद रानू को रेडियो चैनल्स, फिल्म प्रोडक्शन हाउस और केरल के एक लोकहितकारी संगठन से गाने के लिए कई ऑफर आ चुके हैं। उन्हें गाने का ऑफर देने वाले आयोजनकों ने उनका मेकओवर भी कराया है। रानू के लिए आने वाले फोन को रिसीव करने वाले अतींद्र चक्रवर्ती ने बताया कि इस महीने रानू स्टेज पर गाती हुई भी दिख सकती हैं। उन्होंने बताया कि किसी रियलिटी शो के प्रोड्यूसर ने भी उनसे संपर्क किया है। वह रानू के लिए फ्लाइट की टिकट देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन रानू के पास कुछ जरूरी दस्तावेज न होने की वजह से वह फिलहाल मुंबई नहीं जा सकतीं। रानू बताती हैं कि यह उनकी प्रसिद्धि का पहला मौका नहीं है। जब वह 20 साल की थीं तब एक क्लब के लिए गाना गाती थीं। तब लोग उन्हें रानू बॉबी बुलाते थे। उन्होंने बताया कि वह इससे अच्छे पैसे कमा रही थीं, लेकिन उनके घर वालों को न तो उनका गाना पसंद था और न उनका काम। इसलिए उन्होंने यह सब बंद कर दिया। किस्मत ने रानू को दूसरा मौका दिया है। वह इसे अपना दूसरा जन्म बताती हैं। (एता आमार द्वितीयो जीबन)।

एक जैसा नहीं है राज्यों में जिलों के आकार का समीकरण

बीते सप्ताह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने वेल्लौर जिले को तीन हिस्सों में बांटकर दो और जिले रानीपेट और तिरुपत्तूर बनाने की घोषणा की। इस साल जनवरी और जुलाई में तमिलनाडु सरकार पहले ही तीन नए जिले बना चुकी है और अब हालिया घोषणा से राज्य में जिलों की संख्या 37 हो जाएगी। आमतौर पर नया जिला बनाए जाने का मकसद शासन के कामकाज को आसान करना होता है। यानी बड़े इलाके की तुलना में छोटे इलाके में काम आसानी से किए जा सकते हैं, लेकिन कई बार स्थानीय लोगों की मांगों की वजह से भी नए जिले बनाने का फैसला लेना पड़ता है।

वर्तमान में सबसे ज्यादा जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां 75 जिले हैं। इसके बाद 52 जिलों वाले मध्य प्रदेश का नंबर आता है। महज दो जिलों के साथ गोवा सबसे कम जिलों वाला प्रदेश है। राज्य में जिलों की संख्या हमेशा उसके आकार और जनसंख्या पर निर्भर करे ऐसा जरूरी नहीं है। उदाहरण के तौर पर आंध्र प्रदेश देश का सातवां बड़ा राज्य है, लेकिन जिलों की संख्या महज 13 है। इसके हर 12 हजार वर्ग किलोमीटर पर एक जिला है, जो देश के किसी भी राज्य में औसत में सबसे बड़ा है। वहीं, दूसरी तरफ त्रिपुरा की बात करें तो यह एक छोटा राज्य है। इसमें केवल आठ जिले हैं, लेकिन यहां के हर 1300 वर्ग किलोमीटर पर एक जिला है, जो देश के अन्य राज्यों से औसत में सबसे छोटा है। इसका मतलब यह हुआ कि आंध्र प्रदेश का एक जिला त्रिपुरा के एक जिले की तुलना में औसतन नौ गुना बड़ा है। जनसंख्या के आधार पर तुलना करें तो आंध्र प्रदेश के एक जिले की औसत आबादी जहां 38 लाख है, वहीं त्रिपुरा में यह महज साढ़े चार लाख है।

बड़े जिलों वाले राज्य

राज्य	जिले	क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर में)		जनसंख्या (लाख में)	
		राज्य	औसत जिला	राज्य	जिले में औसत
आंध्र प्रदेश	13	1,60,205	12,323	496	38
राजस्थान	33	3,42,239	10,371	685	21
महाराष्ट्र	36	3,07,713	8,548	1,123	31
कर्नाटक	30	1,91,796	6,393	611	20
मध्य प्रदेश	52	3,08,252	6,044	726	14
गुजरात	33	1,96,024	5,940	604	18

छोटे जिलों वाले राज्य

राज्य	जिले	क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर में)		जनसंख्या (लाख में)	
		राज्य	औसत जिला	राज्य	जिले में औसत
त्रिपुरा	8	10,492	1,311	36	4.5
मणिपुर	16	22,327	1,395	28	1.8
नगालैंड	11	16,579	1,507	20	1.8
सिक्किम	4	7,096	1,774	6	1.5
गोवा	2	3,702	1,851	14.5	7.3
हरियाणा	22	44,212	2,010	253	11.5

38 जिलों के साथ बिहार का तीसरा स्थान

37 जिले होने के बाद तमिलनाडु देश में जिलों की संख्या के आधार पर चौथा राज्य बन जाएगा। 38 जिलों के साथ बिहार तीसरे स्थान पर है। जनवरी में जहां तमिलनाडु में 4,000 वर्ग किलोमीटर पर एक जिला

था, वहीं 37 जिले होने के बाद यह करीब 3,500 वर्ग किलोमीटर रह जाएगा।

कहां, कितने जिले

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, जहां 36 जिले हैं। इसके बाद असम, राजस्थान और गुजरात में 33-33, तेलंगाना में 31, कर्नाटक और ओडिशा में 30-30 जिले हैं।

सोशल मीडिया पर रोजाना ढाई घंटे बिताते हैं भारतीय

सोशल मीडिया का क्रेज पूरी दुनिया में है। इसे लेकर हाल ही में मार्केट रिसर्च कंपनी ग्लोबल वेब इंडेक्स ने एक सर्वेक्षण किया है, जिसमें सामने आया है कि वैश्विक स्तर पर इंटरनेट यूजर्स दिन में औसतन 2 घंटा 23 सोशल मीडिया पर बिताते हैं। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा समय देने वालों में फिलीपींस पहले स्थान पर है, जबकि नाइजीरिया, मेक्सिको और तुर्की क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। 2 घंटा 25 मिनट सोशल मीडिया पर

भारतीय फेसबुक, वाट्सएप पर बिताते हैं सबसे ज्यादा समय

भारत में मोबाइल यूजर्स अपने मोबाइल पर 70 फीसद समय फेसबुक, वाट्सएप, म्यूजिक और एंटरटेनमेंट एप्स के इस्तेमाल में बिताते हैं।

सबसे कम समय बिताता है जापान: कुछ देशों में सोशल मीडिया का उपयोग कम हुआ है। डिजिटल रूप से संपन्न देश जापान में लोग सोशल मीडिया पर सबसे कम समय बिताते हैं। वहीं, जर्मनी, अमेरिका और ब्रिटेन के लोग भी सोशल मीडिया का कम उपयोग करते हैं।

ऐसे हुआ सर्वेक्षण: दुनियाभर के 46 बाजारों में 16-24 आयु वर्ग के 5,75,000 इंटरनेट यूजर्स के लिए गए साक्षात्कार के आधार पर यह सर्वेक्षण किया गया है।

सोशल मीडिया पर समय बिताने वाले देश

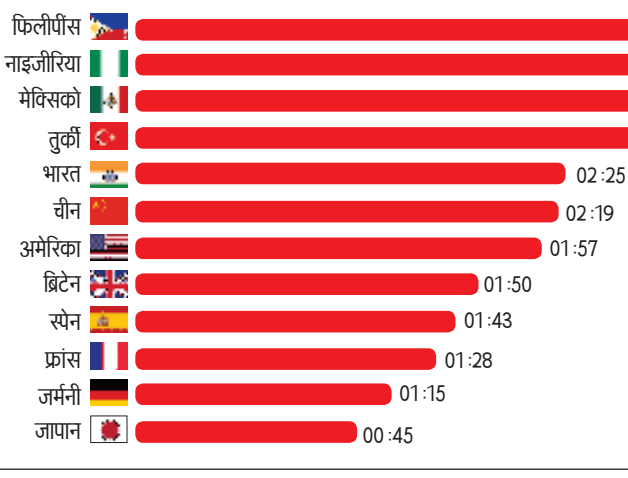

'द्वापर' का वैभव देख दंग रह जाएगी दुनिया

रविवार विशेष

दर्शन द्वारका भाग-1

शत्रुघ्न शर्मा, द्वारकापुरी

- जल्द ही समुद्र से निकलेगी द्वारकापुरी, युद्ध स्तर पर प्रयास जारी
- समुद्र में छिपे द्वारका मंदिर को सीसीटीवी से देखने की भी की जाएगी व्यवस्था

द्वारका नगरी का काल्पनिक चित्र जो पौराणिक कथाओं में दिए वर्णन के आधार पर बनाया गया है। जागरण

पौराणिक द्वारका नगरी के एक हिस्से बेट द्वारका (प्राचीन द्वारका का एक हिस्सा जो समुद्र में बने टापू पर स्थित है) तक दर्शनार्थियों को आसानी से पहुंचाने के लिए समुद्र पर केबल ब्रिज बनेगा। समुद्र के गर्भ में छिपे द्वारका मंदिर को सीसीटीवी से भी देखने की व्यवस्था की जाएगी। महाभारत के 36 साल बाद ही द्वारकापुरी समुद्र में विलीन हो गई थी। कार्बन डेटिंग व रडार स्कैनिंग से इस प्राचीन नगरी की पुष्टि होती है। पुरातत्ववेत्ता एसआर राव इसे मेसोपोटामिया जैसी ही प्राचीन सभ्यता मानते हैं।

दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक द्वारका को लेकर एक बार फिर पुरातत्ववेत्ताओं में रुचि पैदा हुई है। 9000 साल पुराना यह उत्कृष्ट नगर 4000 साल पहले समुद्र में समा गया था। पहले माना जा रहा था कि ईसा पूर्व भारत में उच्चकोटि की कोई सभ्यता नहीं रही होगी, लेकिन कार्बन डेटिंग से अब यह स्पष्ट हो गया कि द्वारका 9000 साल पुरानी नगरी है। हिमयुग के बाद जलस्तर 400 फीट बढ़ जाने से इस पौराणिक नगरी के समुद्र में डूबने की भी बात कही जाती है। पौराणिक कथाओं को सच करने वाले सुबूत इसी द्वारका में गत कुछ दशकों में मिले हैं। 560 मीटर लंबी दीवार और 30 बुर्ज के अवशेष अरब सागर में मिले हैं। यहां जो दीवारें व मूर्तियां मिली हैं, वे प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित हैं। पुरातत्ववेत्ता एसआर राव बताते हैं कि 19वीं सदी में अरब सागर में बर्तन, गहने, इमारतों के अवशेष और लकड़ी की कलाकृतियों जैसे कुछ टुकड़े मिले थे। ये हड़प्पा और मेसोपोटामिया से भी प्राचीन सभ्यता के अंश हैं।

महाभारत के 36 साल बाद ही द्वारकापुरी समुद्र में समा गई : भगवान श्रीकृष्ण ने यहां 12 योजन भूमि पर नगर बसाया था। द्वारका 68 तीर्थ, सात पुरी, चार धाम व शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार पीठों में से एक है। समूद्र की अनंत गहराई में डूबी द्वारका गोमती नदी व अरब सागर के संगम पर बसी एक अद्भुत और एक समृद्ध नगरी थी। इसके समुद्र में डूबने को गांधारी के श्राप का भी परिणाम माना जाता है। महाभारत के 36 साल बाद ही द्वारकापुरी समुद्र में विलीन हो गई और भगवान श्रीकृष्ण बैकुंठधाम चले गए। स्वर्ण निर्मित दिव्य महल अपने नगर के साथ समुद्र में समा जाता है। नए युग और अवतार के आने से पहले श्रीकृष्ण ने खुद बैकुंठधाम की राह पकड़ ली। बाद में उनके प्रपौत्र वज्रभामने ने आज की द्वारका का निर्माण कराया।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

सैकड़ों किलोमीटर की दीवार से घिरी थी द्वारका

वर्तमान की बेट द्वारका जहां स्थित है, उसी समुद्र के भाग में प्राचीन नगर बसा था। शोधकर्ता मितुल वतुर्वेदी बताते हैं कि द्वारका एक शहर नहीं पूरा राज्य था। इसकी दीवार 700 किलोमीटर दूर भरूच व सूरत तक मिलती है।

गुजरात सरकार की ओर से बेट द्वारका पर केबल ब्रिज को तैयार करने का काम जोरों पर चल रहा है। जागरण

100 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा केबल ब्रिज, ताकि आसानी से पहुंच सकें दर्शनार्थी

पुरातत्व अन्वेषक आलोक त्रिपाठी ने खोदाई में मिली 200 मीटर की दीवार में से 50 मीटर को अध्ययन के लिए चुना। वह बताते हैं कि गहराई में मिले स्तंभ, गोल आकृतियां, प्राचीन दीवार, पत्थर और नगर रचना के बेजोड़ नमूने एक अद्भुत देवलोक का आभास कराते हैं। इसी प्राचीन द्वारका नगरी का सीसीटीवी से द्वारिकाधीश मंदिर पर सीधा प्रसारण करने की गुजरात सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी बताते हैं कि अभी बेट द्वारका जाने के लिए नाव का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन अब सरकार 100 करोड़ रुपये की लागत से केबल ब्रिज बनवा रही है ताकि बेट द्वारिका तक दर्शनार्थी आसानी से पहुंच सकें। (क्रमश :)

रचनात्मकता ▶ राजीव ने दुनिया को दिया पहला भारतीय-अमेरिकी नायक

लेजरमैन... पश्चिम की तेजी और पूर्व के तेज वाला सुपरहीरो

संडे बॉक्स
जरा हटके...

न्यूयॉर्क के ब्रांक्स में एक पब्लिक स्कूल में दो दशक से कला अध्यापक राजीव का है अपना कॉमिक्स हाउस

नवनीत शर्मा, धर्मशाला

'स्पाइडरमैन... सुपरमैन... बैटमैन....! कॉमिक्स के संसार में सबके पास अपने-अपने नायक थे, लेकिन हमारा नायक कोई नहीं था। मैं किसी को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। मैं यानी भारतीय मूल का ऐसा इंसान, जिसके पुरखे भारत से जाकर अमेरिका में बस गए। आगे की पीढ़ियों को वहां के समाज के ताने झेलने पड़े। संदेह और अविश्वास झेलने पड़े। ऐसे में मुझे अलग तरह के नायक की तलाश थी, जिसके पास पश्चिम की तेजी और पूर्व का तेज हो। जो संस्कारों से, सात चक्रों के संतुलित होने से मिलता है। ऐसा नायक जिसे भारतीयों की करुणा का पता हो, सांस्कृतिक विविधता का पता हो। ...और मैंने अपना नायक चुना लेजरमैन को। इसकी खूबी यह है कि यह शिव जी की तरह तीसरे नेत्र से अन्याय, बुराई और अपराध को समाप्त कर सकता है। मेरी प्रेरणा वह कृष्ण भी हैं, जिन्होंने कालिया नाग का मर्दन किया। अब मेरा अपना कॉमिक्स हाउस है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने संसार को पहला भारतीय-अमेरिकी सुपरहीरो दिया।' यह कहना है 46 वर्षीय राजीव आनंद का, जिनके दादा कई साल पहले अमेरिका चले गए थे।

न्यूयॉर्क के ब्रांक्स में एक पब्लिक स्कूल में दो दशक से कला अध्यापक राजीव आनंद इन दिनों हिमाचल के दौरे पर हैं। उद्देश्य है, तिब्बती पेंटिंग थांका और कांगड़ा चित्रकला को सीखना। इससे पूर्व फुलब्राइट स्कॉलर के रूप में वह जयपुर के चित्रकार पंडित वेदपाल शर्मा से 1997-1998 में मिनिएचर पेंटिंग सीख चुके हैं। उनके पिता विवोध जेम्स आनंद लखनऊ के हैं और मां रूसी मूल की हैं। राजीव के दादा केनेथ डेनियल विल्सन आनंद दलाई लामा के उस समय से मित्र हैं, जब वह तिब्बत छोड़ कर भारत में शरणार्थी हुए थे।

46 वर्षीय राजीव आनंद। जागरण

कई देशों में सिखा चुके हैं चित्रकला

अमेरिका के अलावा वह फ्रांस, जर्मनी, भारत, वियतनाम, कंबोडिया और नेपाल के विद्यार्थियों को भी चित्रकला सिखा चुके हैं। अपनी कॉमिक्स के वह लेखक और चित्रकार दोनों हैं। थाइलैंड की रानी का जिस व्यक्ति ने मास्क बनाया, वह राजीव के गुरु हैं।

लेजरमैन की खासियत

- यह सुपरहीरो प्रकाश देता है।
- तीसरे नेत्र से बुराई को खत्म करता है।
- प्रकाश की गति से बुराई तक पहुंचता है।
- वह अपने भीतर के सातों चक्र पूरे करने के बाद लेजरमैन बना है।
- वह पहला भारतीय-अमेरिकी सुपरहीरो है, जिसे भारतीय संस्कृति का पता है।
- हर सुपरहीरो किसी न किसी आधार पर खड़ा होता है। लेजरमैन का आधार स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है।
- भारतीय विविधता के सनातन संस्कारों से परिपूर्ण लेजरमैन का नाम विलियम खान है।

लेजरमैन कॉमिक्स का कवर पेज।

अमेरिका में खुद को मानते हैं अदृश्य अल्पसंख्यक

अपने कॉमिक्स को वह अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास भी कहते हैं। इस कॉमिक्स में बहुत कुछ ऐसा है जो उनके साथ हुआ है। अमेरिका में वह स्वयं को अदृश्य अल्पसंख्यक मानते हैं। इसी अहसास ने उनके भीतर पहचान की ललक पैदा की। उन्हें संतोष है कि वह अमेरिका में एक अदृश्य अल्पसंख्यक वर्ग को दृश्य बना सके।

सातों चक्र संतुलित कर बना सुपरहीरो

राजीव को इस बात की प्रसन्नता है कि उन्होंने जो महानायक सृजित किया, उसने अपनी ऊर्जा सातों चक्रों को संतुलित करने के बाद पाई। भारतीय दर्शन के अनुसार मनुष्य के शरीर में वर्णित सात चक्र - मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार हैं। इन्हें जागृत करने के उपरांत संतुलित करने से व्यक्तित्व में रचनात्मकता, विश्वास, प्रेम, करुणा, वाचनशक्ति और आध्यात्मिकता आती है।

अशिक्षा रूपी कीचड़ में ज्ञान का कमल खिला रहे नवल

जीना इसी का नाम है

गौरव दुबे, अलीगढ़

बचपन में शिक्षा व ज्ञान से दूर-दूर तक जिनका नाता न रहा हो, ऐसे बच्चे बड़े होकर एक दिन अमेरिका जाएं, इंडियन एयरलाइंस में नौकरी पा जाएं तो इस पर किसी को सहज विश्वास नहीं होगा। किसान परिवार के बच्चे जो दिनभर घर-पड़ोस में खेलते रहते हों, वह नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान विद्यालय व अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) जैसे संस्थानों में पहले ही प्रयास में टॉप करके दाखिला पा लें तो ये सब किसी कल्पना या सपने से कम नहीं लगेगा, लेकिन ऐसे ही सपने को दृढ़शक्ति व शिक्षा के जुनून से पूरा करने का काम अलीगढ़ के शिक्षक नवल किशोर शर्मा ने किया है। जुनून ऐसा कि सेवानिवृत्त होने व रीढ़ की हड्डी में प्लेट पड़ी होने के बावजूद घर से 25 किलोमीटर दूर जाकर आज भी बच्चों को मुफ्त में शिक्षित कर रहे हैं और उनके पढ़ाए बच्चे उच्च पदों पर पहुंच रहे हैं।

गुरु राम दास नगर सारसौल निवासी नवल 150 से ज्यादा गरीब परिवार के बच्चों के जीवन में अशिक्षा रूपी कीचड़ में ज्ञान का कमल खिला चुके हैं। इन्हीं के पढ़ाए किसान के बेटे सहजपुरा गांव के सोनपाल सिंह आइएएस हैं। मोहसनपुर के कुशल कुमार एसआइ के पद पर तैनात हैं। 1975 में नवल किशोर खुद खेती करते थे और टीनशेड में चार से छह बच्चों को पढ़ाया करते थे। 1993 में शहजपुरा गांव, अलीगढ़ के सरकारी स्कूल में सहायक अध्यापक के तौर पर नियुक्त हुए। 2016 में वह सेवानिवृत्त हुए। इस बीच उन्होंने शिक्षा की लौ से कई बच्चों के जीवन में उजियारा किया।

अमेरिका गई बेटी, सीआइएसएफ में बेटा : बालमपुर टप्पल में किसान रामकिशन शर्मा की बेटी रिंकी व उनके भाई रामअवतार के बेटे मुकुल को नवल ने स्कूल से अलग निःशुल्क शिक्षा दी। उन्होंने रिंकी को टायर से खेलते देख शिक्षित करने की ठानी थी। पिता रामकिशन ने बताया कि ऐसा ज्ञान मिला कि रिंकी व मुकुल ने नवोदय विद्यालय, एएमयू सिटी स्कूल व विद्या ज्ञान विद्यालय तीनों में अलग-अलग कक्षाओं में दाखिला पाया। 2009 में वो नौकरी के लिए इंटरव्यू देने अमेरिका गई। रामअवतार ने बताया कि गुरुजी की कृपा से मुकुल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) छत्तीसगढ़ में तैनात है।

विद्या ज्ञान विद्यालय में उत्तर प्रदेश टॉपर : सोमना मोड़ खैर निवासी विकास सिंह अत्री के पिता संजय सिंह ने बताया कि आर्थिक स्थिति कमजोर थी तो बच्चे पढ़ाई से दूर थे। यह नवल गुरुजी को पता चला तो उन्होंने बेटे को मुफ्त शिक्षा दी। प्रदेश में मात्र दो विद्याज्ञान विद्यालय हैं। इनमें दाखिला सपना साकार होने जैसा होता है। इसमें बेटे ने 2010 में उत्तर प्रदेश में टॉप किया। अब एएमयू से एमबीबीएस व नीट की तैयारी कर रहा है।

बच्चों की शादी रविवार को, अवकाश नहीं : नवल किशोर ने बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में मात्र पांच अवकाश लिए, वह भी रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के लिए। अपने बेटे व बेटी की शादी भी रविवार के दिन की। 2001 में हादसे में रीढ़ की हड्डी में चोट आई, तब भी अवकाश न लेकर स्कूल में चटाई पर लेटकर बच्चों को पढ़ाया। अपोलो में ऑपरेशन के दौरान पांच दिन का अवकाश मजबूरन लेना पड़ा। ये उनकी नियुक्ति से सेवानिवृत्ति तक के कुल पांच अवकाश थे।

अलीगढ़ में बच्चों को पढ़ाते शिक्षक नवल किशोर शर्मा। सेवानिवृत हाने और रीढ़ की हड्डी में प्लेट पड़ी होने के बावजूद वह समाज सृजन का काम कर रहे हैं ।जागरण

20-25 किलोमीटर दूर जाते हैं पढ़ाने के लिए

रीढ़ की हड्डी में रॉड पड़ी होने के बावजूद नवल अब भी अलीगढ़ से 20 से 25 किलोमीटर दूर खैर में बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने जाते हैं। अभिभावक उनको बुलाने का आग्रह करते हैं और वह मना नहीं कर पाते। पिछले साल से कुछ साधन संपन्न अभिभावकों ने खैर आकर पढ़ाने के लिए एक कमरे व रोडवेज बस में गुरुजी के लिए यात्रा पास की व्यवस्था कर दी है।

एक-दो नहीं सैकड़ों गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षित कर उच्च पदों पर बैठा दिया। नवल किशोर जैसे कर्मठ व शिक्षा का जुनूनी मैंने आज तक नहीं देखे।

- डॉ. रक्षपाल सिंह, शिक्षाविद् और आगरा यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष

रेहड़ी से चल रही जिंदगी, क्रिकेटर तराशना जुनून और बंदगी

अपना देस
खुशबू माटी की

साहिल गर्ग, बठिंडा

शौक और जुनून की जिंदा मिसाल देखनी है तो पंजाब के बठिंडा रेलवे स्टेशन पर आइए। यहां पर छोले-भटूरे की रेहड़ी लगाने वाले आसानंद सैनी खुद तो क्रिकेटर नहीं बन सके, लेकिन उनके अंदर क्रिकेट के प्रति इतना जुनून है कि वह बच्चों को क्रिकेट की कोचिंग देकर अपने शौक को पूरा कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह कि उनका एक शिष्य लगातार आइपीएल के चार सेशन में खेलकर अपना दम दिखा चुका है। आसानंद सैनी अभी अंडर-19 तक के 20 से 25 युवाओं को कोचिंग दे रहे हैं। आसानंद को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था। वह बड़े होकर क्रिकेटर बनना भी चाहते थे, लेकिन घरेलू कारणों के कारण वह सिर्फ जिलास्तर तक ही खेल सके। विडंबना यह कि इतनी प्रतिभा होने के बावजूद आसानंद छोले-भटूरे की रेहड़ी से ही अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं।

आइपीएल में लगातार चार सेशन खेला इनका सिखाया सरबजीत : आसानंद सैनी का शिष्य सरबजीत सिंह लाडा 2010 से 2013 तक चार बार आइपीएल में खेल चुका है। सरबजीत सिंह पहले दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम में था। इसके बाद वह कोलकाता नाइटराइडर्स टीम में खेलने लगा। उसने दोनों टीमों में खेलकर बढ़िया प्रदर्शन किया था। सरबजीत अब अमेरीका की डोमेस्टिक लीग में भी खेल रहा है। इसके अलावा आसानंद के शिष्य मनिंदर शर्मा, कुलदीप, राहुल, लखविंदर, हरप्रीत, परमिंदर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी स्तर पर खेल चुके हैं। उनके कई शिष्य रणजी में भी खेल चुके हैं।।

सुबह और रात को लगाते हैं रेहड़ी, शाम को देते हैं कोचिंग : आसानंद सैनी बठिंडा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-5 पर छोले-भटूरे की रेहड़ी लगाते हैं। वह स्टेशन पर सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक काम करते हैं। इसके बाद शाम को चार से साढ़े छह बजे तक बच्चों को रेलवे ग्राउंड में कोचिंग देते हैं। इसके बाद फिर से स्टेशन पर आकर अपनी रेहड़ी लगाते हैं। वह बच्चों से कोचिंग के लिए कोई फीस भी नहीं लेते। इनकी 23 वर्षों से यही दिनचर्या है। वह कहते हैं कि उनके शिष्य देश-विदेश में बठिंडा का नाम रोशन करें, यही उनकी फीस है।

बठिंडा रेलवे स्टेशन पर अपनी रेहड़ी पर काम करते आसानंद। जागरण

पूरी लगन से क्रिकेट सिखाते हैं आसानंद

आसानंद सैनी से रेलवे ग्राउंड में क्रिकेट सीखने वाले बच्चे बताते हैं कि आसानंद सर पूरी लगन से सभी बच्चों को कोचिंग देते हैं। वह किसी बच्चे से कोई फीस भी नहीं लेते।

रंग लाई मेहनत

दिल्ली निवासी 34 वर्षीय शैलजा ने शुरू की है मोबाइल एप बेस्ड महिलाओं की कैब, इनकी चालक सिर्फ हैं सिर्फ महिलाएं, रोजगार भी मिल रहा और सुरक्षा भी

सुरक्षित सफर की साथी महिला कैब सर्विस

मनु त्यागी, नई दिल्ली

सोनिया ने जैसे ही आत्मविश्वास के साथ गाड़ी की स्टेयरिंग संभाली, जिंदगी और परिवार दोनों ने गति पकड़ ली। उनके साथ उनकी कार में पीछे की सीट पर बैठी सवारी को भी इत्मिनान मिलता है। ये है देश की पहली मोबाइल एप्लीकेशन आधारित महिलाओं की कैब। दिल्ली निवासी 34 वर्षीय शैलजा मित्तल को यह जरूरत तब महसूस हुई, जब एक दिन उनकी बेटी को स्कूल ले जाने के लिए रोज आने वाले कार चालक की जगह कोई अनजान शख्स आया। शैलजा को संकोच हुआ और बेटी को उसके साथ नहीं भेजा। खुद स्कूल छोड़ने गईं। उसी दिन तय किया कि क्यों न ऐसी कैब सेवा शुरू की जाए, जिसमें सिर्फ महिला चालक हों और वह सिर्फ महिला और बच्चों के लिए ही हो? जहां सभी महफूज महसूस करें। यहीं से शुरुआत हुई इस नई कैब की।

नारी सशक्तीकरण

दरअसल, शैलजा महिलाओं के माध्यम से एक सशक्त संदेश देना चाहती थीं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद अच्छी भली निजी कंपनी की नौकरी छोड़ी और छोटे से स्टार्ट-अप की शुरुआत कर दी, जो दो कार से शुरू होकर दो साल में ही 17 कैब पार्टनर तक पहुंच गया है। शैलजा कहती हैं कि हमारी कार सेवा बिलकुल मां जैसी सुरक्षा देती है। जब महिलाओं के हाथ में स्टेयरिंग होगी तो सवारी सुरक्षित महसूस करेगी।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

2 साल में दो से बढ़कर 17 तक पहुंची कैब पार्टनर, अब दूसरे राज्यों की भी तैयारी

सबसे कठिन पड़ाव

महिला चालकों की तलाश सबसे कठिन पड़ाव था। धारणा बनी हुई है कि यदि महिला चालक है तो सफर सुरक्षित नहीं है। गाड़ी कहीं न कहीं दुर्घटनाग्रस्त होगी। शैलजा कहती हैं कि हमने लोगों की इस मानसिकता को तोड़ा है। हमने सभी महिला चालकों को खुद प्रशिक्षण दिया और उनको आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर भी बनाया है। यही हमारा लक्ष्य भी है।

महिला चालकों की बदल गई जिंदगी

महिला चालकों में किसी का कार के बाद बस जैसे बड़े वाहन चलाने का सपना है, तो किसी के घर की खुशियां अब इसी कैब सेवा पर टिकी हैं। बच्चों की पढ़ाई का खर्च इसी नौकरी से है। शैलजा कहती हैं कि कैब सर्विस में हर आयु वर्ग की महिला चालक हैं। भविष्य में हम अहमदाबाद, मुंबई, जयपुर जैसे शहरों में भी इसकी सेवा शुरू करने जा रहे हैं। बुराड़ी निवासी सोनिया सिंह बताती हैं कि मेरे बच्चे भी बेहद खुश हैं, गर्व महसूस करते हैं कि हमारी मम्मी गाड़ी चलाती हैं। अब हमारे लिए पढ़ाई से लेकर खेलने तक की सब खुशियां देती हैं। हां, कभी बच्चे पूरी तरह उन्हें समय न दे पाने से नाराज जरूर होते हैं। परिवार में भी सिर्फ पति को बताया किसी और को नहीं, क्योंकि सब वैसा सहयोग नहीं करते। इसी तरह कविता शर्मा, पूनम और कुंती देवी सहित बहुत सारी लड़कियों की कहानियां हैं। कविता के पिता ने गाड़ी चलाने के लिए मना किया तो इन्होंने कंप्यूटर की क्लास बताते हुए इस कंपनी में गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग ली। फिर कुछ दिन के प्रशिक्षण के बाद जब नौकरी लग गई तो घर पर बताया। कहती हैं, सड़क पर सभी तरह के लोग मिलते हैं, कभी लड़कों को लगता है कि हम ही आगे जाएंगे, लड़की कैसे आगे निकल सकती है और कभी ऐसे भी मिलते हैं जो उत्साह बढ़ाते हैं, लेकिन मैं निडर होकर चलती हूं। मेरा सपना है एक दिन बस भी चलाऊं।

महिला चालक टीम के साथ शैलजा मित्तल (बीच में)। फोटो सौजन्य से - कैब कंपनी

कई बार बुरे अनुभव हुए तो कई यात्रियों ने सराहना भी की

शैलजा कहती हैं कि हमारे साथ जुड़ी महिला चालकों को कई बुरे अनुभव भी हुए तो कई बार यात्रियों से सराहना भी मिली। प्रधानमंत्री द्वारा महिला कर्मचारियों को रात में काम करने के लिए सुरक्षित माहौल देने की बात पर कहती हैं कि इससे आधी आबादी का हौसला तो बढ़ेगा, लेकिन अभी दिल्ली-एनसीआर या मेट्रो शहरों में महिलाओं को लेकर जैसा असुरक्षित माहौल है। ऐसे में हम कैब सेवा के समय को अभी तो नहीं बढ़ाएंगे। हां, जब सरकारी स्तर पर और पुलिस-प्रशासन की ओर से दिल्ली महफूज लगने लगेगी तब जरूर ऐसी पहल करेंगे। वैसे प्रधानमंत्री के संसद में ऐसे भाषण के बाद उम्मीद जगी है।

आरकॉम प्रमोटर के अतिरिक्त 11.5 फीसद शेयर गिरवी

नई दिल्ली : रिलायंस कम्यूनिकेशंस (आरकॉम) की दो प्रमोटर इकाइयों ने ने 11.5 फीसद अतिरिक्त शेयर गिरवी रखे हैं। कंपनी ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा कि ये शेयर एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज के हाथों गिरवी रखे गए हैं। दी जानकारी के मुताबिक रिलायंस कम्यूनिकेशंस इंटरप्राइजेज और रिलायंस टेलीकॉम इन्फ्राइन्वेस्ट ने रिलायंस कम्यूनिकेशंस में करीब 11.51 फीसद शेयर गिरवी रखे हैं। यह सौदा शुक्रवार को हुआ है। (प्रेट्र)

श्रीलंका में 5,000 यूनिट उत्पादन क्षमता के साथ यह महज शुरुआत है। इस देश की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में भी हम बड़े योगदान के लिए तैयार हैं।

— पवन गोयनका
एमडी, महिंद्रा एंड महिंद्रा

कॉफी डे ने दिया पूरा कर्ज चुकाने का भरोसा

बेंगलुरु, एएनआइ : कॉफी डे इंटरप्राइजेज लिमिटेड (सीडीईएल) ने कर्जदाताओं को भरोसा दिलाया है कि वह अपना पूरा कर्ज उतार देगी। कंपनी ने शनिवार को कहा कि कॉफी डे ग्रुप पर इस वक्त 4,970 करोड़ रुपये का कर्ज है और सभी कर्जदाताओं के कर्ज का भुगतान किया जाएगा। इस रकम में कंपनी ने सेक्योर्ड लोन के रूप में 4,796 करोड़ रुपये का कर्ज लिया हुआ है, जबकि अनसेक्योर्ड लोन के रूप में कंपनी को 174 करोड़ रुपये मिले हैं।

सीडीईएल ने पहले ही कहा है कि वह ग्लोबल विलेज टेक पार्क का विनिवेश करेगी। इसकी बिक्री से कंपनी को 2,600 करोड़ रुपये से 3,000 करोड़ रुपये तक मिलने की उम्मीद है। ग्लोबल विलेज टेक पार्क का स्वामित्व सीडीईएल की सहायक शाखा टैंगलिन डेवलपमेंट्स लिमिटेड के पास है। अपने बयान में सीडीईएल ने कहा कि ग्लोबल विलेज की बिक्री के बाद कॉफी डे ग्रुप पर कर्ज घटकर 2,400 करोड़ रुपये रह जाएगा।

कंपनी के मुताबिक सिकल लॉजिस्टिक्स और मैग्नासॉफ्ट कंसल्टिंग को छोड़ दें, तो ग्लोबल विलेज की बिक्री के बाद ग्रुप पर अगले 45 दिनों में कर्ज घटकर 1,000 करोड़ रुपये रह जाएगा। वहीं, सिकल भी अपनी कुछ संपत्तियों की बिक्री प्रक्रिया में है। उसके बाद सिकल की वित्तीय स्थिति भी ठीक हो जाएगी। बयान में कंपनी ने भरोसा जताया कि कॉफी डे के सभी कर्ज चुकता किए जाएंगे। कंपनी ने कर्जदारों से यह भी आग्रह किया कि वे बिकने लायक संपत्ति के उचित मूल्यांकन के लिए उसे थोड़ी मोहलत दें, ताकि वह पूरे कर्ज का भुगतान कर सके।

गौरतलब है कि सीडीईएल के मालिक वीजी सिद्धार्थ 30 जुलाई की शाम को कर्नाटक के मेंगलुरु के निकट एकाएक गायब हो गए थे। अगले दिन एक नदी से उनका शव बरामद किया गया था। गायब होने से पहले अपने कर्मचारियों को एक पत्र में उन्होंने लिखा कि उन पर प्राइवेट इक्विटी निवेशकों और टैक्स अधिकारियों का बहुत दबाव था। उन्होंने यह भी लिखा था कि वे अपने कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सके।

छलांग ▶ 80 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित संयंत्र की, क्षमता 5,000 यूनिट सालाना

लंका में महिंद्रा ने लगाई पहली यूनिट

कंपनी ने किया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में भी श्रीलंका में बड़े सहयोग का वादा

कोलंबो, प्रेट्र : देश की अग्रणी ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने वैश्विक स्तर पर कदम बढ़ाते हुए श्रीलंका में शनिवार को पहला ऑटोमोटिव असेंबलिंग संयंत्र शुरू किया है। यह संयंत्र श्रीलंका की आइडियल मोटर्स के साथ संयुक्त उपक्रम के तहत खोला गया है। महिंद्रा का कहना है कि स्थानीय स्तर पर सोर्सिंग के साथ श्रीलंका में यह पहली बड़ी कार असेंबलिंग यूनिट है। इस यूनिट की स्थापना पर 200 करोड़ श्रीलंकाई रुपये (भारतीय रुपये के लिहाज से 80 करोड़) का निवेश किया गया है। इसकी शुरुआती उत्पादन क्षमता 5,000 यूनिट सालाना होगी। इस मौके पर श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे तथा महिंद्रा ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

महिंद्रा आइडियल लंका प्राइवेट लिमिटेड के तहत महिंद्रा एंड महिंद्रा ने यह कंप्लीटली नॉक्ड डाउन (सीकेडी) यूनिट श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के निकट वेलीपेन्ना नामक स्थान पर शुरू की गई है। शनिवार को ही इस यूनिट से महिंद्रा का पहला उत्पाद केयूवी-100 पेट्रोल के-6 प्लस के रूप में बाहर निकला। कंपनी का कहना है कि इस कंपैक्ट एसयूवी के अलावा वह इस संयंत्र से कई अन्य वैरिएंट और ब्रांड का भी उत्पादन करेगी। सीकेडी यूनिट का मतलब है कि वाहन के सभी पुर्जे भारत से वहां आयात किए जाएंगे और उन पुर्जों की असेंबलिंग कर संयंत्र में कारों का निर्माण किया जाएगा।

उम्मीद है कि स्थानीय स्तर पर उत्पादन से महिंद्रा आइडियल लंका के टैक्स में बड़ी बचत होगी। शनिवार को इस संयंत्र से बाहर निकली केयूवी-100 की स्थानीय मुद्रा यानी श्रीलंकाई रुपये में कीमत 32 लाख (भारतीय रुपये के लिहाज से 12.85 लाख) है। भारत से अगर यही बना-बनाया वाहन श्रीलंका में आयात किया जाए, तो उस पर इंजन की क्षमता के हिसाब से 100-300 फीसद तक आयात शुल्क लगता है।

इस मौके पर विक्रमसिंघे ने कहा कि वह श्रीलंका के उत्पादन को निर्यात आधारित बनाना चाहते हैं। उन्होंने श्रीलंका के विकास में भारतीय मदद के लिए अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया। वहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमडी पवन गोयनका ने कहा कि 200 करोड़ श्रीलंकाई रुपये का निवेश और 5,000 वाहन सालाना का उत्पादन तो सिर्फ एक शुरुआत है। इस यूनिट से 200 लोगों को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, वह भी कंपनी के लिए शुरुआत ही है। मैं समझता हूं कि श्रीलंका सरकार की मदद से हम इससे बहुत आगे जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि श्रीलंका सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दे रही है। ऐसे में कंपनी को उम्मीद है कि वह इस देश की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में महत्वपूर्ण योगदान देने में सफल होगी। आइडियल मोटर्स के चेयरमैन नलिन वेलगामा का कहना था कि मुक्त व्यापार समझौता होने के बावजूद श्रीलंका से भारत को ऑटोमोटिव कंपोनेंट का निर्यात नहीं हो रहा है। अब मौका है कि हम ऐसा कर सकेंगे।

श्रीलंका में कंपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में भी बड़ा योगदान देने की तैयारी में है। एएनआइ

अमेरिका ने किया कारोबार की बाधाएं दूर करने का आग्रह

- उप विदेश मंत्री ने कहा - कई बाधाओं से विदेशी कंपनियों को भारतीय बाजार में हो रही दिक्कत
- पिछले वर्ष रिकॉर्ड पर रहा था द्विपक्षीय कारोबार, संभावनाएं इससे आगे की

नई दिल्ली, एएनआइ : अमेरिका ने भारत से अपने बाजार में पहुंच संबंधी बाधाएं दूर करने का आग्रह किया है। अमेरिका का मानना है कि इन बाधाओं के चलते भारतीय बाजार में विदेशी कंपनियों पर नकारात्मक असर पड़ता है। अमेरिका के मुताबिक इससे वैश्विक सप्लाई चेन का अभिन्न हिस्सा बनने की भारतीय कोशिशों को भी धक्का लग रहा है।

इंडिया-यूएस फोरम में अमेरिका के उप विदेश मंत्री जॉन जे सुलिवान ने कहा कि भारत-अमेरिका का द्विपक्षीय कारोबार पिछले वर्ष 142 अरब डॉलर (10 लाख करोड़ रुपये के आसपास) रहा, जो अब तक का रिकॉर्ड है। लेकिन हमारे कारोबारी सहयोग की सीमाएं इससे कहीं बड़ी हैं। व्यापार संबंधी मुद्दों को आगे बढ़ाने के क्रम में हमारा आग्रह है कि भारत उन सभी बाधाओं को दूर करे, जो बाहर की कंपनियों को फलने-फूलने के रास्ते में रुकावट डालती हैं। सुलिवान ने कहा कि हमारे आपसी रिश्ते बहुपक्षीय भी हैं। नवंबर, 2017 के बाद से हम एशिया-प्रशांत क्षेत्र को लेकर चार बार चतुष्पक्षीय (जिसमें चार पक्ष हों) वार्ता कर चुके हैं। इनमें दो अन्य पक्ष जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। सुलिवान के मुताबिक एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मुक्त और खुले व्यापार के लिए साझे और अनुपूरक दृष्टि की जरूरत है।

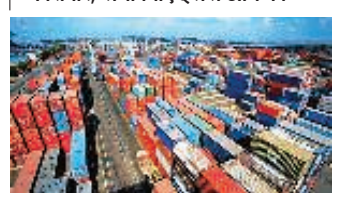

प्रतीकात्मक

जीएसपी से बिगड़ी थी बात

इस वर्ष जून में अमेरिका ने भारत को अपनी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेज (जीएसपी) सुविधा से बाहर कर दिया था। अमेरिका पिछले चार दशकों से ज्यादा वक्त से अर्थव्यवस्था के लिहाज से विकासशील और पिछड़े देशों को जीएसपी के तहत द्विपक्षीय कारोबार में कई तरह की छूट देता रहा है। लेकिन इस वर्ष जून में अमेरिका ने भारत को यह कहते हुए सूची से बाहर कर दिया था, कि वह अब विकासशील देश नहीं रहा है और उसे इस तरह की सुविधा की जरूरत नहीं है। उसके बाद भारत ने भी अमेरिका के 25 उत्पादों पर आयात शुल्क लगा दिया। उसी महीने अमेरिका के विदेश मंत्री ने भारत यात्रा में माना था कि कारोबारी मतभेदों को दूर किया जाना जरूरी है।

गोल्ड ईटीएफ दुनियाभर में बने निवेशकों का सहारा

- इस वर्ष जुलाई में पिछले छह वर्षों का सबसे ज्यादा निवेश हुआ गोल्ड ईटीएफ में
- डॉलर के टूटने के चलते दुनियाभर के अस्थिर बाजारों में निवेशकों ने सोने को बनाया सुरक्षित निवेश का ठिकाना

मुंबई, आइएएनएस : वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती और व्यापार को लेकर बढ़ते तनाव के बीच निवेशक सोने पर आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी गोल्ड ईटीएफ में सुरक्षित ठिकाना तलाश रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (डब्ल्यूजीसी) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई में गोल्ड ईटीएफ में निवेशकों ने दुनियाभर में 2.6 अरब डॉलर (करीब 18,200 करोड़ रुपये) का निवेश किया। मार्च, 2013 के बाद किसी एक महीने में गोल्ड ईटीएफ में किया गया यह सबसे बड़ा निवेश है।

गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एक साधारण निवेश उत्पाद है जो शेयर बाजार और गोल्ड में साधारण निवेश का एक साथ विकल्प देता है। प्राकृतिक संसाधनों में निवेश करने वाली कंपनी गोरिंग एंड रेजेनवॉग की एक रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड ईटीएफ में खरीदारी अभी लंबे समय तक चलेगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह खरीदारी पश्चिमी निवेशकों द्वारा भविष्य में भी की जाएगी। हम जल्द ही विभिन्न ईटीएफ के द्वारा सोने और चांदी का बड़े पैमाने पर संचय देखेंगे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ईटीएफ की गोल्ड होल्डिंग अब 2012 के पुराने शीर्ष स्तर पर पहुंच रही है। गोल्ड ईटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला भारत में भी देखने को मिल रहा है। पहली अप्रैल के बाद ईटीएफ की कीमतें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर बढ़ी हैं, जो कि निफ्टी-50 इंडेक्स के विपरीत है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रमुख केंद्रीय बैंक सोने के विक्रेता के बजाय महत्वपूर्ण खरीदार बन रहे हैं। सोने के उत्पादक अपने उत्पाद बेच नहीं रहे हैं। पिछले आठ सालों में सोने की वास्तविक खरीद गोल्ड ईटीएफ से की गई है और यह इसका एक बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2004 में ईटीएफ की शुरुआत के बाद से ये अब सोने के बाजार के महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गए हैं। वर्ष 2012 के अंत से पहले लगातार आठ वर्षों में ईटीएफ ने 2,600 टन सोने की खरीद की। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के बाद गोल्ड ईटीएफ में निवेशक कंपनियों और हेज फंड्स ने निवेश किया। माना जाता है कि पिछली सदी के आठवें दशक में सोने की खरीद काफी जटिल थी। गोल्ड फ्यूचर, सोने के सिक्के या बॉर और गोल्ड इक्विटी में खरीदारी करनी पड़ती थी। गोल्ड ईटीएफ ने सोने की खरीद बेहद आसान कर दी है।

दीवाली तक सोना हो सकता है 40,000 के पार

मुंबई, आइएएनएस : इस वर्ष दिवाली तक सोने का भाव 40,000 रुपये के पार पहुंच सकता है। वैश्विक विकास की चिंताओं और बढ़ते व्यापार तनाव के बीच जानकारों का ऐसा मानना है। वर्तमान में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने के अक्टूबर कांट्रैक्ट की कीमत 37,995 रुपये प्रति 10 ग्राम है। एंजल ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता के अनुसार अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार को लेकर जारी तनाव में कमी आने पर इस कीमती धातु की मांग में कुछ कमी आ सकती है। दीवाली तक सोने का भाव 39,000 से 40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। उन्होंने बताया कि सोने के दाम इसलिए बढ़ रहा है, क्योंकि वैश्विक विकास दर में कमी आ रही है। दुनियाभर के जानकार आर्थिक अनिश्चितता के इस समय में सोने और अन्य कीमती धातुओं में निवेश की सलाह दे रहे हैं। गोरिंग एंड रेजेनवॉग की रिपोर्ट में निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में कीमती धातुओं में अधिक से अधिक निवेश करने की सलाह दी गई है।

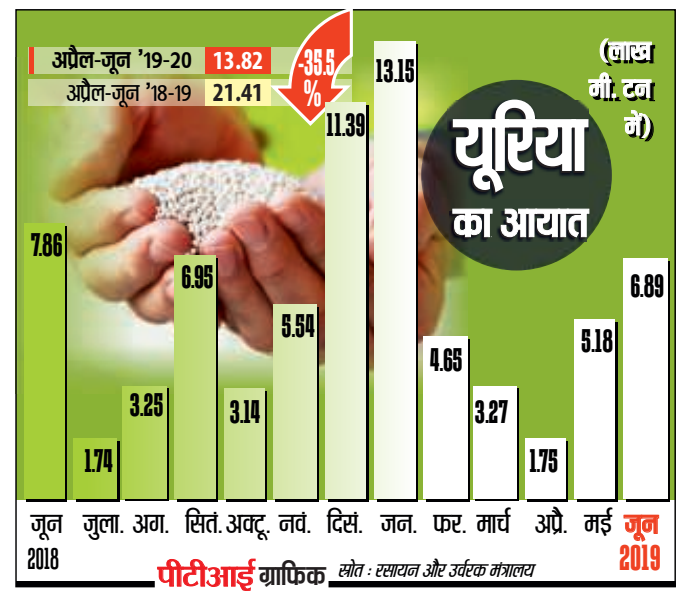

ऑडिटर दुरुस्त होंगे, तो ही निवेशक निश्चिंत हो सकेंगे

वर्षों तक मैंने टेक्निकल या मोमेंटम पर आधारित निवेश के विपरीत फंडामेंटल पर आधारित निवेश की जोरदार वकालत की है। हालांकि लंबी अवधि के निवेशकों के मुकाबले कमाई के मामले में ट्रेडर्स अक्सर ही आगे रहते हैं। इसका कारण यह है कि शेयर बाजारों में ट्रेडिंग या दैनिक खरीद-फरोख्त उन आंकड़ों पर आधारित होती है जिनके सच होने की गारंटी होती है। जबकि निवेश मोटे तौर पर उन आंकड़ों पर आधारित होता है, जो सच भी हो सकते हैं और नहीं भी। इसका अर्थ यह हुआ कि जो शेयर भाव आपको बताया जाता है, वह वास्तविक होता है। लेकिन कंपनी के वित्तीय आंकड़े वास्तविक हो भी सकते हैं और नहीं भी। हालांकि सवाल वास्तविक होने या नहीं होने का नहीं है, क्योंकि कॉरपोरेट कंपनियों के वित्तीय आंकड़े सीधी और सरल भाषा में नहीं आते। इनमें कुछ चीजें साफ नहीं भी हो सकतीं। कई बार बेहतरीन और पारदर्शी कंपनियों के भी कई ऐसे रहस्य हो सकते हैं, जो सामने आ जाएं तो शेयरधारकों और निवेशकों के निवेश का पूरा गणित बदल जाता है।

करीब तीन दशक पूर्व मैंने निवेश विशेषज्ञ के तौर पर पेशेवर जिंदगी की शुरुआत की थी।

धीरेन्द्र कुमार, सीईओ
वैल्यू रिसर्च

बोनस

शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म और लांग टर्म निवेशकों में से निवेश का किनका नजरिया ज्यादा सही है, इस पर बरसों तक बहस चलती रह सकती है। मैंने ऐसे व्यक्ति के सान्निध्य में पेशेवर जिंदगी की शुरुआत की, जो महज मुनाफे के लिए शेयर बाजार में निवेश करते थे और छोटी अवधि में ही शेयर बेच लेते थे। उन दिनों निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के किस्से भी आम थे। अब स्थितियां बदल गई हैं। नियम-कानूनों का सख्ती से पालन होने लगा है और कंपनियों के ऑडिटर्स पर ऐसी नकेल कसी गई है कि वे किसी भी कंपनी के बारे में झूठी रिपोर्ट को मुहर नहीं लगा सकते हैं। इससे कंपनियों के वित्तीय आंकड़ों को देखकर लंबी अवधि के निवेशकों को बड़ा नुकसान होने की संभावना लगभग खत्म हो गई है।

पहली बार पिछली सदी के आखिरी दशक की शुरुआत (वर्ष 1990 के बाद) में भारतीय कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर संशय से मेरा पहला सामना हुआ। मैं एक ऐसे व्यक्ति के लिए काम कर रहा था, जिन्होंने अपना जीवन वॉल-स्ट्रीट में फाइनेंस के क्षेत्र में लगा दिया था। अपने पेशेवर अतीत की वजह से वे उस समय के कई बड़े उद्योगपतियों को जानते थे। वे भारत में इक्विटी में निवेश को गहराई से समझते थे, और उस निवेश की गहराई भी समझते थे। इसके बावजूद उनकी शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में ही रुचि थी। वे शेयर खरीदते और कुछ ही समय बाद मुनाफे के मौके पर उसे बेच लेते। एक बार मैंने उनसे पूछ लिया कि वे ऐसे शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग क्यों करते हैं और लंबी अवधि के लिए निवेश क्यों नहीं करते? उनका कहना था कि यदि बिजनेस और कारोबारियों के बारे में आप भी मेरे बराबर जानते, तो आप कभी भी निवेश के मकसद से एक भी शेयर नहीं खरीदते।

उस समय कुछ ऐसी ही स्थिति थी। सरकारी कंपनियों के प्रमोटर शेयरधारकों की पूंजी के साथ खिलवाड़ करते थे। समय बीतने के साथ हालात में सुधार हुआ और अब काफी हद तक यह खतरा कम हो गया है। ऐसा नहीं है कि लोग अब आदर्श बन गए हों। कड़े नियमों और जानकारियों के अधिक प्रवाह के चलते अब लोग यह समझने लगे हैं कि प्रमोटर का एकमात्र उद्देश्य निजी संपत्ति बढ़ाना रहता है। इसलिए लोग अब लंबी अवधि के लिए मार्केट में बने रहना पसंद करते हैं। वह जल्द मुनाफा कमाने की मानसिकता नहीं रखते।

हालांकि नैतिक स्तर और कॉरपोरेट गवर्नेंस में सुधार एक निरंतर संघर्ष है। हाल के वर्षों की कुछ घटनाओं ने दिखाया है कि कैसे प्रमोटरों के लिए यह हमेशा संभव रहेगा कि वह शेयरधारकों की जेब पर डाका डाल सकें। इसकी वजह से नए रेगुलेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पर्यवेक्षकों को यह हमेशा से ही यह ज्ञान रहा है कि इस पूरी चेन की कमजोर कड़ी ऑडिटर है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इसी कड़ी को सरकार दुरुस्त करने में जुटी हुई है। यह तो जुलाई, 2017 में ही दिखने लगा था जब मोदी सरकार ने यह फैसला कर लिया था कि नैतिकता के मानकों पर अकाउंटिंग इंडस्ट्री को सुधारा जाएगा। प्रधानमंत्री ने तब आइसीएआइ के वार्षिक समारोह में सीए को चेतावनी दी थी।

ऐसा बहुत कुछ जो होता आ रहा था, अब भारतीय निवेशकों के लिए बदलने वाला है। नए नियमों ने कॉरपोरेट की वित्तीय जानकारी की सत्यता की पुष्टि करने की जिम्मेदारी ऑडिटर पर डाल दी है। यह जिम्मेदारी पहले ही उनके पास होनी चाहिए थी। हालांकि इन नए बदलावों ने ऑडिटर समुदाय की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और यह साफ कर दिया है कि वे अपने कारोबार का बड़ा नुकसान करेंगे यदि वे मनगढ़ंत सूचनाओं पर अपनी मुहर लगा देंगे।

मेरा मानना है कि सरकार की नए नियमों को लागू करने की प्रतिबद्धता भारत में इक्विटी निवेश की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाने में सक्षम होंगे। किसी कंपनी के अकाउंट के ऑडिट पर भरोसा करना एक स्वस्थ पूंजी बाजार की मूलभूत जरूरत है। आखिरकार भारत को यह मिलने लगा है।

74,000 करोड़ के पार खादी का राजस्व

नई दिल्ली, प्रेट्र : खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआइसी) ने शनिवार को बताया कि इस वर्ष मार्च में खत्म वित्त वर्ष (2018-19) के दौरान कंपनी के उत्पादों का बिक्री राजस्व 74,323 करोड़ रुपये को पार कर गया है। वित्त वर्ष 2014-15 से इस राजस्व में 145 फीसद से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केवीआइसी के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना के हवाले से बयान में कहा गया है कि यहां तक कि ग्रामोद्योग भी बीते वित्त वर्ष में 71,123.63 करोड़ रुपये पर जा पहुंचा, जो वित्त वर्ष 2014-15 के 31,965.52 करोड़ रुपये के लिहाज से 123 फीसद की विकास दर का प्रदर्शन करता है। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान खादी ने फैब्रिक उत्पादन में 62 फीसद से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की है।

बीते वित्त वर्ष में कंपनी का फैब्रिक उत्पादन 17.8 करोड़ वर्गमीटर रहा। सक्सेना का कहना था कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में केवीआइसी ने 32,000 नए मॉडल चरखे मुहैया कराए, जबकि इसी दौरान 5,600 आधुनिक करघे भी मुहैया कराए गए। इस दौरान 376 नए खादी इंस्टीट्यूट और 40,000 नए बुनकर जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने पहली बार रेमंड, अरविंद मिल्स और आदित्य बिड़ला टैक्सटाइल्स जैसी बड़ी कंपनियों को खादी सेक्टर से जोड़ा।

महिलाओं से ऑनलाइन दोस्ती कर करता था ठगी, गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- अब तक दिल्ली-एनसीआर की 20 से अधिक महिलाओं को शिकार बना चुका है

मैट्रिमोनियल और डेटिंग साइट के जरिये महिलाओं से दोस्ती कर ठगी करने के आरोपित युवक को दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने मेरठ से गिरफ्तार किया है। आरोपित दिल्ली के निहाल विहार का रहने वाला है और अब तक दिल्ली-एनसीआर की 20 से अधिक महिलाओं को शिकार बना चुका है। इनमें ज्यादातर विधवा और तलाकशुदा महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ठगी का शिकार हुई अन्य महिलाओं की भी तलाश कर रही है।

साइबर सेल के पुलिस उपायुक्त अनयेश रॉय के मुताबिक एक महिला ने ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने बताया कि गौरव धमीजा नाम के व्यक्ति ने मैट्रिमोनियल साइट पर प्रभावशाली प्रोफाइल बना रखा है। इसके माध्यम से उनकी उससे पहचान हुई थी। इसके बाद फोन पर ही दोनों के बीच काफी बातचीत होने लगी तो उसने महंगे उपहार दिलाने का वादा भी किया। इसके बाद उसने माता-पिता के उपचार, व्यवसाय में निवेश इत्यादि के बहाने से रुपये मांगने शुरू कर दिए। आरोपित ने पहले छोटी रकम मांगी। उसे देने के बाद उसकी मांगें बढ़ती गईं। इस दौरान वह कभी भी सामने नहीं आया। पीड़िता को जब ठगे जाने का अहसास हुआ तो उसने रुपये वापस मांगे। इस पर उसने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते हुए रुपये देने से इन्कार कर दिया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर सर्विलांस से आरोपित की तलाश शुरू की, जिसमें पता चला कि वह दिल्ली के निहाल विहार इलाके में रहता है। हालांकि, गिरफ्तारी से बचने के लिए वह अपना ठिकाना हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदल रहा था। आरोपित के मेरठ में होने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसके कब्जे से अपराध में प्रयुक्त मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड, क्रेडिट और डेबिट कार्ड बरामद किए गए हैं। आरोपित गौरव धमीजा ने 10वीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। बाद में वह स्पेयर पार्ट्स का कारोबार करने लगा था, लेकिन उसमें भारी नुकसान हुआ था। वहीं, उसकी शादी वर्ष 1999 में हुई थी और जल्द ही तलाक हो गया था। इसके बाद उसने मैट्रिमोनियल और डेटिंग साइट के जरिए महिलाओं से दोस्ती कर उनसे ठगी शुरू कर दी थी।

कारों की कम होती बिक्री चिंता की बात नहीं

राजीव सचान, शंघाई

- ब्रिक्स देशों के अध्यक्ष भारत की प्रगति को लेकर आश्वस्त
- उम्मीदों पर खरा उतर रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक

दुनिया के आर्थिक हालात को लेकर उभरी अनिश्चितता के बीच ब्रिक्स देशों के बैंक-न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनबीडी के अध्यक्ष केवी कामत का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों से भारत की प्रगति में कोई बाधा नहीं आने वाली है। वह गत दिवस शंघाई स्थित बैंक के मुख्यालय में भारत से आए पत्रकारों के एक दल से मुखातिब थे।

इस दौरान उन्होंने कहा कि तमाम चुनौतियों के बीच भारत में वैसे हालात हैं जो विकास को गति देने के अनुकूल हैं, जैसे कि मुद्रास्फीति नियंत्रण में है और ब्याज दरें घट रही हैं। उनके अनुसार ऐसा ही माहौल 2000 के दशक के शुरू में था। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की पहल पर बने इस बैंक के पहले अध्यक्ष कामत ने भारत में कारों की बिक्री में कमी को बड़ा मसला मानने से इन्कार करते हुए कहा कि कारों की बिक्री का ग्राफ तो दुनिया भर में गिर रहा है और आने वाले समय में यह भी हो सकता है कि युवा कार चलाना सीखें ही नहीं, क्योंकि कार शेयरिंग, सार्वजनिक परिवहन की सुगम व्यवस्था और एप आधारित कार सुविधाओं के चलते उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं रह जाएगी। इस क्रम में कामत ने चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां साइकिल क्रांति नए सिरे से उभर आई है, क्योंकि कई कंपनियां सार्वजनिक स्थलों पर एप आधारित ऐसी साइकिल उपलब्ध करा रही हैं जिन्हें मोबाइल से लॉक और अनलॉक किया जा सकता है।

विकासशील देशों को अपने पैरों पर खड़ा करना है एनडीबी का मकसद

कामत ने एनडीबी को विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को चुनौती देने वाले बैंक के रूप में देखने से इन्कार करते हुए कहा कि ब्रिक्स देशों का बैंक तो इन संस्थाओं का पूरक है। उन्होंने कहा कि एनडीबी का मकसद विकासशील देशों को अपने पैरों पर खड़ा करना है। उन्होंने व्यापार के मामले में विभिन्न देशों के बीच टकराव को स्वाभाविक बताते हुए कहा कि विकास में पीछे छूट गए देश समान धरातल पर आने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में टकराव की स्थिति बन रही है। कुछ समय बाद जब शक्ति संतुलन कायम हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा।

भारत में खुल जाएगा एनडीबी का क्षेत्रीय कार्यालय

एनडीबी की अब तक की उपलब्धियों पर प्रसन्नता जताते हुए कामत ने बताया कि हम उम्मीद के मुताबिक काम कर रहे हैं। उनके अनुसार अगले साल भारत में भी एनडीबी का क्षेत्रीय कार्यालय खुल जाएगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इंदौर, मुंबई और चेन्नई में मेट्रो निर्माण का काम एनडीबी के सहयोग से हो रहा है। उन्होंने इस बैंक को विशिष्ट बताते हुए कहा कि यहां सारे फैसले आम सहमति से होते हैं और चूंकि सभी देशों की बराबर की हिस्सेदारी है, इसलिए किसी के हावी होने का सवाल ही नहीं उठता।

38 प्रस्तावों को मंजूरी दे चुका है एनडीबी

उन्होंने बताया कि कई देश एनडीबी की सदस्यता चाहते हैं, लेकिन अभी हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। फिलहाल हमारा सारा ध्यान सदस्य देशों की अपेक्षाओं को पूरा करना है। उनके अनुसार अभी तक बैंक कुल 38 प्रस्तावों को हरी झंडी देने के साथ 2 अरब डॉलर से अधिक के लोन को मंजूरी दे चुका है।

निवेश लाना बड़ी चुनौती

पहले पेज का शेष

आरबीआइ के इन आंकड़ों की तुलना अगर भारतीय अर्थव्यवस्था पर बेहद करीबी नजर रखने वाली निजी क्षेत्र की एजेंसी सीएमआइई की एक रिपोर्ट से करें तो औद्योगिक मंदी की बिगड़ती स्थिति और स्पष्ट हो जाती है। सीएमआइई के मुताबिक निजी क्षेत्र की तरफ से नई निवेश योजनाओं की कुल रकम अभी देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का महज 0.5 फीसद रह गई है। मार्च, 2007 में यह सबसे ज्यादा 36 फीसद थी। मार्च, 2011 में भी यह 25 फीसद के आसपास थी। हालांकि मार्च, 2015 में यह घटकर सात फीसद के करीब रह गई। सीएमआइई की रिपोर्ट कहती है, 'पहले से ही ज्यादा स्थापित क्षमता का उपयोग नहीं होने और निवेश पर रिटर्न कम होने की वजह से निजी क्षेत्र की रुचि अब नए निवेश में नहीं है। कंपनियों की तरफ से नई परियोजनाओं की घोषणा तब तक नहीं की जाएगी, जब तक वे आश्वस्त ना हो जाएं कि मांग में वृद्धि होगी।' सीएमआइई नहीं मानती कि ब्याज दरों में कटौती से भी बात बनने वाली है।

उद्योग	कर्ज की राशि	फीसद गिरावट
1. खनन	28,120	2.6
2. चीनी	01516	3.5
3. खाद्य तेल, वनस्पति	201	0.4
4. टेक्सटाइल	1936	4.9
5. लकड़ी उत्पाद	117	2.3
6. कागज उद्योग	301	2.3
7. पेट्रोलियम	558	11.7
8. रसायन	1745	8.8
9. फर्टिलाइजर	331	17.3
10. लौह-इस्पात	2662	5.9
11. इंजीनियरिंग	1646	2.4
12. रत्न व आभूषण	662	0.8
13. विनिर्माण	972	2.3
14. बिजली	5637	0.9
15. सड़क	1861	0.4
16. संचार	1068	7.6

(नोट : कर्ज की राशि जून, 2019 की है जबकि कर्ज में गिरावट का आंकड़ा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही का है... राशि अरब रुपये में)

इतिहास में छिपा है हांगकांग का विवाद

हांगकांग में हिंसक प्रदर्शनों और अशांति का दौर खत्म होता नहीं दिख रहा है। विवादित प्रत्यर्पण बिल के विरोध से शुरू हुए इन प्रदर्शनों को दो महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब लोग लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं। दो दिन से प्रदर्शनकारियों ने हांगकांग एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले रखा है। उधर चीन की सरकार ने प्रदर्शनकारियों की निंदा की है और यह भी कहा है कि वह चुप नहीं बैठेगा। हालांकि यह सब ऐसे ही नहीं हो रहा है। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रसंग हैं, जो दशकों पुराने हैं।

अलग है हांगकांग

दरअसल हांगकांग अन्य चीनी शहरों से काफी अलग है। 150 साल के ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन के बाद हांगकांग को 99 साल की लीज पर चीन को सौंप दिया गया। हांगकांग द्वीप पर 1842 से ब्रिटेन का नियंत्रण रहा। जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का इस पर अपना नियंत्रण था। यह एक व्यस्त व्यापारिक बंदरगाह बन गया और 1950 में विनिर्माण का केंद्र बनने के बाद इसकी अर्थव्यवस्था में बड़ा उछाल आया। चीन में अस्थिरता, गरीबी या उत्पीड़न से भाग रहे लोग इस क्षेत्र की ओर रुख करने लगे। फिर पिछली सदी के आठवें दशक की शुरुआत में जैसे-जैसे 99 साल की लीज की समयसीमा पास आने लगी ब्रिटेन और चीन ने हांगकांग के भविष्य पर बातचीत शुरू कर दी। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने तर्क दिया कि हांगकांग को चीनी शासन को वापस कर दिया जाना चाहिए। दोनों पक्षों ने 1984 में एक सौदा किया कि एक देश, दो प्रणाली के सिद्धांत

ब्रिटेन ने एक जुलाई, 1997 को हांगकांग चीन को सौंपा था।

के तहत हांगकांग को 1997 में चीन को सौंप दिया जाएगा। इसका मतलब यह था कि चीन का हिस्सा होने के बाद भी हांगकांग 50 वर्षों तक विदेशी और रक्षा मामलों को छोड़कर स्वायत्तता का आनंद लेगा। नतीजतन, हांगकांग का अपना कानून और सीमाएं हैं। साथ ही खुद की विधानसभा भी है।

विवाद की जड़

1997 में जब हांगकांग को चीन के हवाले किया गया था तब बीजिंग ने एक देश-दो व्यवस्था की अवधारणा के तहत कम से कम 2047 तक लोगों की स्वतंत्रता और अपनी कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने की गारंटी दी थी। लेकिन 2014 में हांगकांग में 79 दिनों तक

चले अंब्रेला मूवमेंट के बाद लोकतंत्र का समर्थन करने वालों पर चीनी सरकार कार्रवाई करने लगी। विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों को जेल में डाल दिया गया। आजादी का समर्थन करने वाली एक पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

बीजिंग का कब्जा

यहां के नेता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को 1,200 सदस्यीय चुनाव समिति चुनती है। समिति में ज्यादातर बीजिंग समर्थक सदस्य होते हैं। क्षेत्र के विधायी निकाय के सभी 70 सदस्य, विधान परिषद, सीधे हांगकांग के मतदाताओं द्वारा नहीं चुने जाते हैं। बिना चुनाव चुनी गई सीटों पर बीजिंग समर्थक सांसदों का कब्जा रहता है।

चीनी पहचान से नफरत

हांगकांग में ज्यादातर लोग चीनी नस्ल के हैं। चीन का हिस्सा होने के बावजूद हांगकांग के अधिकांश लोग चीनी के रूप में पहचान नहीं रखना चाहते हैं। खासकर युवा वर्ग। केवल 11 फीसद खुद को चीनी कहते हैं। जबकि 71 फीसद लोग कहते हैं कि वे चीनी नागरिक होने पर गर्व महसूस नहीं करते हैं।

एक और हार ▶ ट्रंप प्रशासन का आरोप- पाकिस्तान ने आतंक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तालिबान, अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों का है शरणगाह

पाक को झटका, अमेरिका ने 31.30 अरब रुपये की मदद रोकी

पिछले साल भी पाकिस्तान की आर्थिक मदद रोक दी गई थी

वाशिंगटन, एएनआइ : कंगाल हो गए पाकिस्तान को एक और करारा झटका लगा है। अमेरिका ने उसको दी जाने वाली आर्थिक सहायता में करीब 44 करोड़ डॉलर (भारतीय मुद्रा में करीब 31.30 अरब रुपये) की कटौती कर दी है। अब अमेरिका से उसे कुल 4.1 अरब डॉलर (करीब 2.92 खरब रुपये) की ही मदद मिल रही है।

'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के मुताबिक, यह आर्थिक मदद पाकिस्तान इनहेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट (पीपा) 2010 के तहत दी जाती थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आर्थिक सहायता में इस कटौती की बाबत पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को वाशिंगटन की यात्रा के तीन हफ्ते पहले ही आगाह कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक, पीईपीए को सितंबर 2010 में केरी लुगर बर्मन (केएलबी) एक्ट को जारी रखने के लिए हस्ताक्षरित किया गया था। यह एक्ट अमेरिकी कांग्रेस ने अक्टूबर 2009 में पारित किया था और इसके तहत पांच साल में पाकिस्तान को 7.5 अरब डॉलर की आर्थिक मदद की जानी थी। केएलबी एक्ट के तहत अभी 4.5 अरब डॉलर की राशि दी जानी थी। हालांकि, अब इस कटौती के बाद यह आर्थिक मदद 4.1 अरब डॉलर पर सिमट गई है। बता दें कि पिछले साल सितंबर में अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद में 30 करोड़ डॉलर (करीब 2100 करोड़ रुपये) की कटौती की थी। यह कटौती आतंकवाद को खत्म करने में पाकिस्तान के नाकाम रहने का हवाला देते हुए की गई थी। अमेरिका को शिकायत है कि पाकिस्तान अफगान तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, अलकायदा समेत आतंकी संगठनों की शरणगाह बना हुआ है। यही नहीं पिछले साल जनवरी में पेंटागन ने पाकिस्तान को दी जाने वाली एक अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद में कटौती कर ली थी। अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने पाकिस्तान के हक्कानी नेटवर्क को नेतस्नाबूंद करने में नाकाम रहने की वजह से यह कदम उठाया था।

पिछले महीने हुई बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवाद के खिलाफ लचर रवैया अपनाने को लेकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की जमकर खिंचाई की थी। तब ट्रंप ने कहा था, 'हम सालों से पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता दे रहे हैं। परेशानी की बात यह है कि पाकिस्तान हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा। पाकिस्तान वास्तव में विनाशकारक रहा है। वह हमारे ही खिलाफ जा रहे हैं। इसीलिए इस रिवायत को हमने डेढ़ साल पहले ही खत्म कर दिया।' उल्लेखनीय है कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से अमेरिकी सरकार लगातार पाकिस्तान की सहायता राशि में कटौती करती जा रही है। पिछले महीने ही ब्रेक्जिट के चलते आर्थिक चुनौती का सामना कर रहे ब्रिटेन की संसद ने भी पाकिस्तान को दी जाने वाली सालाना सहायता में कटौती करने की संस्तुति की थी।

'मोदी के हिंदुस्तान' में डोभाल की डॉक्ट्रिन से जूझ रहा पाक'

इस्लामाबाद, आइएएनएस : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की बंद कमरे की बैठक में कोई कामयाबी नहीं मिलने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मेहमूद कुरैशी ने कहा कि उनका देश 'नेहरू के हिंदुस्तान' के खिलाफ 'मोदी के हिंदुस्तान' में डोभाल की डॉक्ट्रिन से जूझ रहा है।

प्रधानमंत्री इमरान खान की अगुआई में पाकिस्तान में कश्मीर पर बनाई विशेष कमेटी की पहली बैठक के बाद कमेटी के अध्यक्ष कुरैशी ने इंटरसर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक मेजर जनरल आसिफ गफूर के साथ संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में यह बात कही। भारत के सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल का जिक्र कुरैशी ने इस अंदाज में किया, चूंकि पाकिस्तान भी मानता है कि भारत की नई आक्रामक नीति के निर्माता वही हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी ने कहा कि मोदी ने नेहरू के भारत को दफन कर दिया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत की ओर से कोई कार्रवाई होने पर पाकिस्तानी सेना भी अपने देश का बचाव करने में सक्षम है। उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उसके बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। और अब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परमाणु हमला पहले न करने की बाध्यता खत्म करने का एलान करके पाकिस्तान के परमाणु हमले की धमकियों की हवा ही निकाल दी है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शिकस्त मिलने के बाद इस्लामाबाद में शनिवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पत्रकार वार्ता बुलाकर सफाई दी। प्रेस कांफ्रेंस में उनके साथ सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर भी उपस्थित रहे। एपी

राजनाथ के बयान की आलोचना : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान की आलोचना करते हुए कुरैशी ने कहा कि उनका यह बयान गैरजिम्मेदाराना और दुर्भाग्यपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि राजनाथ सिंह ने विगत शुक्रवार को पोखरण (परमाणु परीक्षण स्थल) से लौटकर कहा था कि भारत ने परमाणु बम का इस्तेमाल पहले न करने की नीति की समीक्षा की है। अब भविष्य में क्या होगा इसका फैसला परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

पाक विदेश कार्यालयों में कश्मीर डेस्क : पाकिस्तान में कश्मीर पर बनाई विशेष कमेटी ने विश्व की कई राजधानियों में अपने विदेश कार्यालय में एक-एक कश्मीर डेस्क भी बनाने का एलान किया है। हाल ही में बनाई गई कमेटी में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ के प्रमुख ले.जनरल फैज हमीद, कानून मंत्री फारुघ नासिम समेत कई अफसर शामिल हैं। कश्मीर पर संसदीय कमेटी के अध्यक्ष फखर इमाम और पाकिस्तान के अटर्नी जनरल अनवर मंसूर खान इसमें सदस्य हैं।

बयान जारी किए बिना यूएनएससी बैठक पाक चीन के लिए बड़ा धक्का

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मसले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बंद कमरे में हुई अनौपचारिक बैठक का बिना किसी निष्कर्ष या बयान जारी किए संपन्न हो जाना पाकिस्तान और चीन के लिए बड़ा धक्का है। दोनों ही देशों ने इस मसले का अंतरराष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की, लेकिन अधिकतर देशों ने इसे भारत-पाक के बीच द्विपक्षीय मसला करार दिया। सूत्रों ने बताया कि चीन बैठक के बाद बयान जारी किए जाने पर जोर दे रहा था। इस पर ब्रिटेन ने भी उसका साथ दिया, लेकिन अगस्त महीने के लिए परिषद के अध्यक्ष पोलैंड ने कोई बयान जारी नहीं किया।

भारत ने हर दलील का दिया जवाब : यूएनएससी में भारत ने हर दलील का मजबूत तर्कों के साथ जवाब दिया। भारत का रुख यही रहा कि एक संवैधानिक मामला शांति और सुरक्षा के लिए खतरा कैसे हो सकता है। भारत शिमला समझौते के प्रति प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान ने दलील दी कि अनुच्छेद 370 से हालात में ठोस बदलाव आया है। इस पर भारतीय पक्ष ने पूछा, 'चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरीडोर क्या है। उन्होंने कितने ठोस बदलाव किए हैं?' परिषद में शामिल अफ्रीकी देश, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस और रूस ने भारत का समर्थन किया।

लगे कई झटके: पाकिस्तान ने यूएनएससी की सार्वजनिक बैठक बुलाने की मांग की थी, लेकिन परिषद ने बंद कमरे में अनौपचारिक बैठक की। इसके अलावा पाक की मांग थी कि बैठक में उसके प्रतिनिधि को शामिल किया जाए, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली। खास बात यह है कि बंद कमरे में होने वाली अनौपचारिक बैठक का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता।

मुंह की खाने के बावजूद बाज नहीं आएंगे पाकिस्तान-चीन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ संयुक्त राष्ट्र में फिर करेंगे कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के मसले पर बंद कमरे में हुई बैठक में पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी को भले ही मुंह की खानी पड़ी हो, लेकिन इससे दोनों देशों की रणनीति पर फर्क पड़ने वाला नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि उनकी तरफ से यूएनएससी में कश्मीर मसला दोबारा उठाने की कोशिश जारी रहेगी। ऐसे में भारत अपनी कूटनीति को और चाकचौबंद करने में जुट गया है। इस संदर्भ में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले दो से तीन महीनों के भीतर चीन, रूस, अमेरिका और जर्मनी के शीर्ष नेताओं के साथ होने वाली द्विपक्षीय वार्ताओं का महत्व भी बढ़ गया है।

पाक विदेश मंत्री कुरैशी ने शनिवार को इस्लामाबाद में एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए साफ किया कि उनका देश चीन और अन्य सामान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खासकर संयुक्त राष्ट्र के भीतर उठाने की लगातार कोशिश करता रहेगा। इसके पहले शुक्रवार को यूएनएससी की बैठक में चीन के प्रतिनिधि का रुख न सिर्फ बेहद भारत विरोधी रहा था बल्कि उनकी तरफ से बाद में दिए गए वक्तव्य में भी कहा गया कि चीन के लिए कश्मीर की चिंताजनक स्थिति गंभीर मसला है जिस पर वह आगे भी मशविरा करता रहेगा। जानकार मान रहे हैं कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले के बाद चीन को भारत पर दबाव बनाने का एक जरिया मिल गया है और वह इसे आजमाता रहेगा। रणनीतिक विश्लेषक ब्रह्मा चेलानी के मुताबिक, चीन का अनौपचारिक तौर पर बंद कमरे में बैठक बुलाना उसका एक और आक्रामक कदम है। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख और रणनीतिक टिप्पणीकार वेद प्रकाश मलिक का कहना है कि चीन-पाकिस्तान का गठबंधन भारत को एक नकारात्मक संदेश देने में सफल रहा है।

भारत के कूटनीतिक सर्किल में भी यह माना जा रहा है कि सुरक्षा परिषद के चीन समेत सभी 15 देशों के साथ भारत को कश्मीर मसले पर लगातार संपर्क बनाकर रखना होगा। आने वाले दिनों में सुरक्षा परिषद के तीन स्थायी सदस्यों- अमेरिका, रूस और चीन के अलावा जर्मनी समेत कुछ अन्य अस्थायी सदस्यों के साथ स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बैठक होने वाली है। सितंबर, 2019 में प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने वाले हैं। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग अक्टूबर में भारत आएंगे, जबकि भारत और जर्मनी के बीच शीर्ष वार्ता अक्टूबर या नवंबर में तय करने के लिए बातचीत जारी है।

न्यूज गैलरी

सियोल में आमने-सामने आए भारतीय और पाकिस्तानी

सियोल : दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में शुक्रवार को भारत विरोधी पाकिस्तानी लोगों से भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेताओं का सामना हो गया। भारत और प्रधानमंत्री मोदी विरोधी नारे लगा रहे पाकिस्तानियों को जब भाजपा व संघ नेताओं ने रोकने की कोशिश की तो वे और भड़क गए। इसके बाद दोनों ओर से नारेबाजी शुरू हो गई। विदेशी धरती पर शक्ल-सूरत में समान लग रहे इन लोगों की नारेबाजी सुन कोरियाई लोगों का भी जमघट लग गया। वे हैरत से कारण जानने की कोशिश करते देखे गए। पाकिस्तानी झंडा लिए वहां के मूलवासी जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर नारेबाजी कर रहे थे। बीच-बीच में ले के रहेंगे आजादी...नारा भी गूंज रहा था। जबकि भारतीय दल में दिल्ली की नेता शाजिया इल्मी और कुछ अन्य लोग थे। इन लोगों ने भारत जिंदाबाद के नारे लगाए। इस नारेबाजी का तीन मिनट 25 सेकेंड का वीडियो सामने आया है। (एएनआइ)

तिरंगे का अपमान करने पर पाकिस्तानियों का विरोध

लंदन : स्वतंत्रता दिवस पर लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर हुए प्रदर्शन में पाकिस्तान समर्थकों द्वारा तिरंगे का अपमान करने वालों के खिलाफ एएनआइ का एक रिपोर्टर उठ खड़ा हुआ। पाकिस्तानियों ने गुरुवार को हुए प्रदर्शन के दौरान भारतीय समुदाय पर अंडे फेंके और पथराव किया। एक खालिस्तान समर्थक भारतीय समुदाय की तरफ पहुंच गया और भारतीय राष्ट्र ध्वज छीन पाकिस्तानियों की ओर फेंक दिया। एक पाकिस्तानी ने तिरंगे का अपमान किया और भारतीयों को इसका प्रतिवाद करने के लिए उकसाया। जब पुलिस ने भारतीय समुदाय के लोगों की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया तब एएनआइ का रिपोर्ट पाकिस्तानियों की ओर पहुंच गया और उसके हाथ से झंडा छीन वापस लौट आया। (एएनआइ)

चीन का नया रॉकेट तीन उपग्रह लेकर रवाना हुआ

बीजिंग : वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया चीन का नया रॉकेट तीन उपग्रहों को लेकर शनिवार को पहली बार अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ। स्मार्ट ड्रैगन-1 नाम के इस रॉकेट को 'चाइना एकेडमी ऑफ लांच व्हेकिल टेक्नोलॉजी' से संबद्ध चाइना रॉकेट कंपनी ने विकसित किया है। यह पश्चिमोत्तर चीन स्थित जियुक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से रवाना हुआ। (प्रेट्र)

बांग्लादेश में दावानल

राजधानी ढाका के मीरपुर इलाके में स्थित सबसे बड़े झुग्गी-बस्ती इलाके में भीषण आग लग जाने से हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए। आग में कई लोगों के झुलसकर घायल होने की खबरें हैं, जबकि एक हजार से अधिक झोपड़ी-झुग्गियां जलकर राख हो गईं। फायर बिग्रेड की कई टीमें आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी हुई हैं। एएफपी

ट्रंप ने अफगान शांति पर सलाहकारों से किया विमर्श

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में शांति समझौते पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा दल के साथ बैठक की। इस बैठक में उपराष्ट्रपति माइक पेंस, विदेश मंत्री माइक पोंपियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन भी शामिल रहे।

बैठक के तुरंत बाद ट्रंप ने ट्वीट किया, 'ज्यादातर लोग 19 साल से चल रहे युद्ध के खिलाफ हैं और यथासंभव किसी समझौते पर पहुंचना चाह रहे हैं।' ह्वाइट हाउस ने बताया कि बैठक अफगानिस्तान में चल रही वार्ता और तालिबान व अफगान सरकार के बीच शांति समझौते पर केंद्रित रही। ट्रंप को अफगानिस्तान में चल रही बातचीत की प्रगति से अवगत कराने के बाद पोंपियो ने कहा, 'राष्ट्रपति की अगुआई में हम अफगानिस्तान को लेकर सही रास्ते पर बढ़ रहे हैं। अफगान सरकार के साथ मिलकर हम एक व्यापक शांति समझौते तक पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं।

ऐसा समझौता जिसमें हिंसा ना हो और यह सुनिश्चित हो कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल फिर कभी अमेरिका या इसके सहयोगी देशों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होगा।' बैठक में रक्षा मंत्री मार्क एस्पर, अफगान मामले के समाधान के लिए विशेष प्रतिनिधि जालमे खलीलजाद, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के

डोनाल्ड ट्रंप। फाइल

चेयरमैन जोसेफ डनफोर्ड और सीआइए की डायरेक्टर गिना हस्पेल ने भी हिस्सा लिया।ट्रंप ने ऐसे समय में इस बैठक की अगुआई की है, जबकि सोमवार को तालिबान और अमेरिकी वार्ताकारों के बीच बातचीत का नवीनतम दौर पूरा हुआ है। माना जा रहा है कि इस समझौते के बाद अफगानिस्तान में अमेरिका अपनी सेना कम कर सकता है।

तालिबान से हुए समझौते की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप जल्द से जल्द अफगानिस्तान से सेना हटाना चाहते हैं। बैठक से पहले ट्रंप ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति इमरान खान से भी अफगानिस्तान की शांति वार्ता को लेकर बात की। इस दौरान उन्होंने भारत-पाक संबंधों पर भी इमरान से चर्चा की।

चुनाव हारा तो ध्वस्त हो जाएगी अमेरिका की अर्थव्यवस्था

वाशिंगटन, एपी : अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर वह 2020 में चुनाव हारे तो देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वे मतदाता जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से नापसंद भी करते हैं, वे देश की तरक्की और बेरोजगारी दर घटाने के लिए उन्हें वोट दें। सूत्र बताते हैं कि ट्रंप अमेरिकी अर्थव्यवस्था की दशा को लेकर खुद चिंतित हैं। उन्हें डर है कि चुनाव तक कहीं अमेरिका की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा न जाए।

दुनिया के वित्तीय बाजारों ने इसी सप्ताह अमेरिकी में मंदी का दौर शुरू होने के संकेत दिए हैं। इससे निवेशकों, कंपनियों और उपभोक्ताओं में बेचैनी देखी जा रही है। यह तब हो रहा है जब ट्रंप ने चीन के माल पर दंडात्मक शुल्क लगाया है और ब्रिटेन व जर्मनी जैसे सहयोगी देशों को मौखिक चेतावनी दे रखी है। दोनों सहयोगी देशों की अर्थव्यवस्था भी कमजोर पड़ रही है। अमेरिका में चुनाव पूर्व की मंदी राष्ट्रपति ट्रंप पर भारी पड़ सकती है। क्योंकि उन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का नारा देकर पहला चुनाव जीता था और दूसरे चुनाव के लिए भी वह जनता को यही सपना दिखाने वाले थे। ट्रंप के सलाहकारों को भय है कि कमजोर आर्थिक स्थिति से चुनाव में नुकसान हो सकता है। नरमपंथी रिपब्लिकन और मध्यमार्गी विचारधारा के मतदाता ट्रंप के विकल्प पर विचार कर सकते हैं। अब व्हाइट हाउस के सलाहकार ऐसे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं जिससे ढलान पर आ रही अर्थव्यवस्था रास्ता बदले। नई परिस्थितियों में ट्रंप मंदी की आशंका के लिए अन्य लोगों और संस्थाओं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ट्रंप के निशाने पर फेडरल रिजर्व भी है, जिस पर वह ब्याज दर कम करने के लिए दबाव बना रहे हैं जिससे बाजार में नकदी आ सके।

हांगकांग के शिक्षकों ने भी खोला मोर्चा

हांगकांग, रायटर : हांगकांग में अब शिक्षकों ने भी लोकतंत्र के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शनकारियों का साथ देते हुए शनिवार को हजारों शिक्षकों ने यहां की प्रमुख नेता कैरी लाम के सरकारी आवास तक शांतिपूर्वक मार्च किया। मार्च में शामिल गणित के शिक्षक सीएस चान ने कहा, 'सरकार हमें महीनों से नजरअंदाज कर रही है। हमें प्रदर्शन जारी रखना होगा।' पुलिस के अनुसार रैली में कुल 8,300 शिक्षक शामिल हुए थे।

जून में लाखों प्रदर्शनकारियों, खासकर छात्रों ने प्रस्तावित प्रत्यर्पण कानून को लेकर विरोध शुरू किया था। इस कानून में संदिग्धों और अपराधियों को मुकदमे के लिए सीधे चीन प्रत्यर्पित करने का प्रावधान किया गया था। यहां के लोग इस कानून को हांगकांग की स्वायत्तता पर खतरा मानते हैं। विरोध के दबाव में लाम ने बिल को निलंबित कर दिया था, लेकिन अब आंदोलन का रुख बदल गया है। इसने लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का रूप ले लिया है। छात्र प्रत्यर्पण कानून को आधिकारिक रूप से वापस लेने के साथ ही लाम के इस्तीफे और लोकतांत्रिक सुधारों की मांग कर रहे हैं। बीते

हांगकांग से सटी सीमा पर चीन की पीपुल्स आर्मी की गतिविधियों के बीच शनिवार को लोकतंत्र समर्थकों के पक्ष में शिक्षकों ने शहर में विशाल रैली करके अपने सख्त इरादों से अवगत कराया। एपी

कुछ हफ्तों में प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। हवाईअड्डे पर प्रदर्शनकारियों के जुटने के कारण इस हफ्ते हजारों उड़ानों को भी रद करना पड़ा। कयास लगाया जा रहा था कि हिंसा और लोगों को हुई परेशानी के चलते प्रदर्शनकारियों को मिलने वाला समर्थन कम हो सकता है। हालांकि जमीनी स्तर पर ऐसा नहीं दिखा। यहां तक कि प्रदर्शन के कारण हवाईअड्डे पर फंसे कई यात्री भी इनकी मांग को सही मान रहे हैं। दूसरी ओर, शिक्षकों का साथ मिलने से प्रदर्शनकारियों का पक्ष और मजबूत हुआ है। 40 वर्षीय संगीत अध्यापक यू ने कहा कि वह प्रदर्शनकारियों के सभी तरीकों से सहमत नहीं हैं, फिर भी उनका समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा, 'मैं हांगकांग के प्रति उनके प्यार की सराहना करता हूं। वे सभी सरकार से अधिक साहसी हैं।' एक अन्य शिक्षक ने कहा कि लैम अगर शुरुआत में बात मान लेतीं तो हिंसा का सामना नहीं करना पड़ता।

रूस में स्वतंत्र चुनाव के लिए प्रदर्शनकारियों ने बदली रणनीति

मॉस्को, एएफपी : रूस में निष्पक्ष व स्वतंत्र निकाय चुनाव की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चुनौती देने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव किया है। शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने मॉस्को में तीन जगहों पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने एकजुट होने के बजाय अलग-अलग रहकर विरोध जताया। इस तरह के विरोध के लिए प्रशासन की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए उन्होंने यह तरीका अपनाया। इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बीच भी मॉस्को में सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे।

मॉस्को में सितंबर में निकाय चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने इसमें कई मुख्य विपक्षी नेताओं के हिस्सा लेने पर रोक लगा दी है। इसके चलते बीते एक महीने से हर शनिवार को रैली निकाली जा रही है। प्रदर्शन रोकने के लिए सरकार पुलिस बल का भी प्रयोग कर रही है। बगैर इजाजत प्रदर्शन करने के लिए करीब तीन हजार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कई प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए हैं।

ईरानी टैंकर ग्रेस वन पकड़ने को अमेरिका का वारंट जारी

वाशिंगटन, एएफपी/एपी : ईरानी तेल टैंकर ग्रेस वन को जिब्राल्टर में रुकवा पाने में विफल रहे अमेरिका ने अब उसे कब्जे में लेने के लिए नया रास्ता तलाशा है। अमेरिका के न्याय विभाग ने वारंट जारी कर अमेरिकी नौसेना और अन्य एजेंसियों को टैंकर पर कब्जा करने का आदेश दिया है। 21 लाख बैरल तेल भरा यह टैंकर फिलहाल भूमध्य सागर में ब्रिटेन की जल सीमा के भीतर लंगर डाले हुए है। इसे गुरुवार को जिब्राल्टर से मुक्त किया गया था। टैंकर के 28 सदस्यीय चालक दल में कैप्टन समेत 24 भारतीय हैं।

▶ ईरानी तेल टैंकर पर आतंकवाद में काम आने का आरोप

▶ 24 भारतीयों वाला जहाज इस समय भूमध्य सागर में

अमेरिका में हुई सुनवाई में ग्रेस वन को ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स से संबंधित बताया गया, जिसे अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। कहा गया कि यह टैंकर अमेरिका के आर्थिक तंत्र में अवैध घुसपैठ की कोशिश कर रहा था।

प्रतिबंध के बावजूद सीरिया को तेल की आपूर्ति करने जा रहा था। वारंट में तेल भरा टैंकर और उससे संबंधित कंपनी के बैंक में जमा 9,95000 डॉलर को जब्त करने का आदेश दिया गया है। टैंकर संचालित करने वाली कंपनी पर इंटरनेशनल इमर्जेंसी इकोनोमिक पावर एक्ट, बैंक से धोखाधड़ी, मनी लाड्रिंग और आतंकवाद फैलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

सूत्रों के अनुसार टैंकर के चालक दल के कुछ सदस्य छुट्टी पर चले गए हैं। इसके कारण अब उसे नए सदस्यों की आमद का इंतजार है। इसीलिए टैंकर भूमध्य सागर में खड़ा हुआ है। इस बीच टैंकर के भारतीय कैप्टन ने अब जिम्मेदारी से मुक्त किए जाने की दरख्वास्त की है। कैप्टन के वकील के अनुसार टैंकर में कुछ मरम्मत कार्य की जरूरत महसूस हो रही है। इस बीच कैप्टन ने उसे छोड़ने की इच्छा व्यक्त की है।

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
स्पोर्ट्स
रविवार 18 अगस्त 2019
www.jagran.com

अगर आप कभी भी अपना नाम अवार्ड लिस्ट में लाना चाहते हो, तो आपके पास लिस्ट में नाम लाने वाले लोग होने चाहिए।
— एचएस प्रणय, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी

देसाई नेशनल रैंकिंग के सेमीफाइनल में

तिरुवनंतपुरम : अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किए गए भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हरमीत देसाई ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यहां जिम्मी जॉर्ज स्टेडियम में जारी यूटेटे नेशनल रैंकिंग (साउथ जोन) टेबल टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। छठी वरीयता प्राप्त हरमीत ने क्वार्टर फाइनल में सुभाजीत साहा को 4-0 से मात देकर अंतिम चार में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में हरमीत का सामना सौम्यजीत घोष से होगा।

बदलाव के दौर में टीम को बेहतर बनाने की कोशिश : रवि शास्त्री

कहा, ऐसी विरासत छोड़कर जाना चाहता हूं जिससे टीम खुश रहे क्षेत्ररक्षण पर सुधार करने को कहा

कूलिज (एंटीगा), प्रेट्र : भारतीय टीम के दोबारा कोच बने रवि शास्त्री ने कहा कि उनकी कोशिश बदलाव के दौर से गुजर रही टीम को बेहतर बनाने की होगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान टीम प्रयोग करने से पीछे नहीं हटेगी। कपिल देव की अगुआई वाली क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) ने शुक्रवार को शास्त्री को दूसरी बार टीम का मुख्य कोच चुना। शास्त्री की उम्र 57 साल है और बीसीसीआइ संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय टीम के कोच की उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए। ऐसे में शास्त्री के पास टीम के साथ यह आखिरी मौका होगा।

चाहता हूं बदलाव का दौर अच्छा गुजरे : 2023 विश्व कप में अभी काफी समय है और 2021 टी-20 विश्व कप जीतना टीम के लिए आशावादी लक्ष्य हो सकता है। शास्त्री ने कहा कि अगले दो साल हमें यह देखना होगा कि बदलाव का दौर ठीक से गुजरे क्योंकि टीम में कई युवा खिलाड़ी आएंगे, खासकर वनडे प्रारूप में, इसके साथ टेस्ट टीम में भी कुछ युवा आएंगे।

ऐसी विरासत छोड़ूं कि टीम खुश रहे : भारतीय टीम के इस पूर्व ऑलराउंडर ने कहा कि आपको तीन-चार गेंदबाजों की पहचान करनी होगी ताकि उन्हें पूल में जोड़ा जा सके, यह एक चुनौती है। मैं चाहूंगा कि 26 महीने के अपने कार्यकाल के बाद ऐसी विरासत छोड़कर जाऊं जहां टीम खुश रहे। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में यह टीम ऐसी विरासत बनाएगी जो काफी कम टीमों ने किया होगा। सिर्फ मौजूदा खेल के समय नहीं बल्कि खेल के बाद भी।

भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री। फाइल फोटो

हम सभी की एक चाहत : भारतीय कोच ने कहा कि हम सब की ऐसी चाहत है और हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। टीम में जिस तरह के युवा आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाला समय काफी रोचक होने वाला है। जब आप सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करते हैं तो आप हर दिन अपना स्तर ऊंचा करने की कोशिश करते हैं और आपको सभी बारीकियों पर ध्यान देना होता है। जब आप अच्छा नहीं करते हैं तब आपको उस बाधा को पार करने के ध्यान देना होता है।

पिछले दो साल का प्रदर्शन शानदार : कोच के लिए साक्षात्कार से पहले ही कप्तान विराट कोहली ने खुलकर शास्त्री की तरफदारी की थी। उन्होंने भारत में 2021 में होने वाले टी-20 विश्व कप तक (लगभग दो साल) के लिए कोच नियुक्त किया गया हैं। शास्त्री ने पिछले दो साल के प्रदर्शन का आकलन करते हुए उसे शानदार बताया। उन्होंने कहा कि पिछले दो-तीन साल में टीम ने शानदार तरीके से निरंतर प्रदर्शन किया लेकिन जैसा की मैंने कहा है उन्होंने एक स्तर बना लिया है और अब उस स्तर से ऊपर उठना होगा। इसके लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है आपको पूरी कोशिश करनी होगी। इस कोशिश में कई बार नतीजे आपके अनुकूल नहीं होंगे, कई बार आपको नहीं पता होता है कि सर्वश्रेष्ठ टीम संयोजन क्या होगा। ऐसा भी समय होगा जब आप युवाओं को मौका देंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि टीम संयोजन सही बने, आपको हर चीज में सुधार करना होगा।

क्षेत्ररक्षण पर करना होगा सुधार : शास्त्री ने मौजूदा टीम की क्षेत्ररक्षण में सुधार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले चार-पांच वर्षों में इस टीम में सबसे अच्छी बात क्षेत्ररक्षण में सुधार है और हमारी कोशिश इसे सर्वश्रेष्ठ क्षेत्ररक्षण टीम बनाने की है। ऐसे में जो भी इस टीम के लिए खेलना चाहता है उसे अपनी क्षेत्ररक्षण को शीर्ष स्तर पर रखना होगा, खासकर वनडे प्रारूप में। शास्त्री ने इस मौके पर कपिल देव की अगुआई वाली तीन सदस्यीय चयन समिति का उन्हें मौका देने के लिए शुक्रिया अदा किया। इस समिति में कपिल के अलावा शांता रंगास्वामी और अंशुमन गायकवाड़ शामिल थे।

सुनील पर तलवार या फिर से होगा विचार

अभिषेक त्रिपाठी • नई दिल्ली

वेस्टइंडीज में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार करने के मामले में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशासनिक मैनेजर सुनील सुब्रहमण्यम का भविष्य खतरे में है और 22 अगस्त को होने वाले चयन साक्षात्कार में उनका पत्ता कट सकता है। कपिल देव की अध्यक्षता वाली क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) शुक्रवार को मुख्य कोच रवि शास्त्री को दोबारा दो साल के लिए चुन चुकी है। अब सोमवार से एमएसके प्रसाद की अध्यक्षता वाली चयनसमिति बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण कोच के अलावा टीम इंडिया के मैनेजर का भी चयन करेगी।

सुब्रहमण्यम द्वारा अधिकारियों से बिना किसी शर्त के माफी मांगने के बाद बोर्ड ने उन्हें वेस्टइंडीज से वापस बुलाने का फैसला बदल दिया था लेकिन अब उनके भविष्य पर सवाल उठ गए हैं। ऐसे में उनका चयन मुश्किल लग रहा है। सूत्रों के मुताबिक एमएसके प्रसाद की अध्यक्षता वाली चयन समिति 19 से 22 अगस्त तक क्रमशः बल्लेबाजी, गेंदबाजी, क्षेत्ररक्षण कोच के अलावा मैनेजर का चयन करेगी। टीम इंडिया के वर्तमान बल्लेबाजी कोच संजय बांगर का भविष्य भी डांवाडोल है जबकि गेंदबाजी कोच भरत अरुण को शास्त्री का करीबी माना जाता है। शास्त्री के आने के बाद अरुण की सीट पक्की है। वहीं क्षेत्ररक्षण कोच श्रीधर भी भारतीय कप्तान विराट कोहली और कोच शास्त्री की गुड बुक में हैं।

सुनील हैं विवाद में: बीसीसीआइ के एक अधिकारी ने बताया था कि सरकार के अनुरोध के बाद भारतीय विदेश सेवा (आइएफएस) अधिकारियों ने जल सरंक्षण को बढ़ावा देने के लिए वेस्टइंडीज में खेल रहे भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ एक वीडियो शूट करने के लिए सुब्रहमण्यम से मदद के लिए संपर्क किया था लेकिन उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआइ के प्रशासनिक मैनेजर पद पर उन्हीं लोगों का साक्षात्कार होगा जो पिछली बार प्रक्रिया में शामिल हुए थे। पिछली बार सुनील के अलावा गुजरात के पूर्व खिलाड़ी प्रकाश भट्ट, दिल्ली के मीडियम पेसर शंकर सैनी, राकेश पारिख और सर्विसेस के खिलाड़ी अरमान मलिक साक्षात्कार में शामिल हुए थे। हालांकि अभी भी यह देखना होगा कि सुब्रहमण्यम को ताजा नियुक्ति के लिए साक्षात्कार में शामिल होने का मौका मिलेगा या नहीं। भारतीय क्रिकेटर आर अश्विन के पूर्व कोच सुब्रमण्यम ने 74 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 285 विकेट चटकाए हैं।

संविधान बदलने का समय नहीं: कपिल देव के नेतृत्व वाली सीएसी भारतीय क्रिकेट टीम के सहायक स्टाफ के चयन का हिस्सा नहीं हो सकती है क्योंकि बीसीसीआइ का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। शुक्रवार को कपिल देव, अंशुमन गायकवाकु और शांता रंगास्वामी ने शास्त्री को दो वर्ष के लिए टीम इंडिया का कोच चुना था और उन्होंने सहायक स्टाफ के चयन प्रक्रिया का हिस्सा बनने की इच्छा जताई थी। बीसीसीआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि संविधान में संशोधन का समय नहीं बचा है। शनिवार और रविवार को दफ्तर बंद हैं। सोमवार को सुबह 10 बजे से सहायक स्टाफ के साक्षात्कार शुरू होंगे। सीएसी के इस प्रक्रिया का हिस्सा होने के लिए कानूनी टीम को इसे जानना होगा और उन्हें जरूरी बदलाव करने होंगे। इसके लिए अब समय नहीं बचा है। शुक्रवार को जब कपिल से पूछा गया था कि क्या सीएसी को सहायक स्टाफ चुनने में मदद की जानी चाहिए तो उन्होंने इसकी इच्छा जताई थी। हालांकि बीसीसीआइ ने इसे नकार दिया है।

अरुण के अलावा कई दावेदार: भरत अरुण दोबारा गेंदबाजी कोच बनने के प्रबल दावेदार हैं। उनके निर्देशन में भारतीय तेज गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इस पद के लिए पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद, डेरेन गॉफ और सुनील जोशी ने भी आवेदन किया है। वहीं क्षेत्ररक्षण कोच पद के लिए आर श्रीधर को दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी जोंटी रोड्स से कड़ी चुनौती मिलेगी।

नजरिया

- बल्लेबाजी, गेंदबाजी, क्षेत्ररक्षण कोच और मैनेजर का चयन
- सहायक स्टाफ का चयन सीएसी नहीं करेगी

ओपनरों के दम पर श्रीलंका जीत के करीब

गॉल, एएफपी: कप्तान दिमुथ करुणारत्ने (नाबाद 71) और लाहिरु थिरिमाने (नाबाद 57) के शानदार अर्धशतकों की मदद से श्रीलंका ने यहां गॉल अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन शनिवार को अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 133 रन बना लिए हैं। श्रीलंका को अब मैच जीतने के लिए केवल 135 रनों की दरकार है जबकि पूरे 10 विकेट शेष हैं। खराब रोशनी के कारण अंपायरों ने निर्धारित समय से पहले ही चौथे दिन का खेल खत्म करने की घोषणा कर दी।

दिन का खेल खत्म होने के समय करुणारत्ने 168 गेंदों पर दो चौके और थिरिमाने 132 गेंदों पर चार चौके लगा चुके हैं। करुणारत्ने का यह 23वां अर्धशतक है जबकि थिरिमाने का यह छठा अर्धशतक है। श्रीलंका ने पहली पारी में 267 रन बनाए थे जबकि न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 249 रनों का स्कोर खड़ा किया था। गॉल में स्पिनर हावी रहते हैं और इस मैच में भी अभी तक दोनों टीमों के स्पिनरों का प्रदर्शन काफी दबदबे वाला रहा है।

अभ्यास मैच में भारत की खराब शुरुआत

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: भारतीय टीम ने एंटीगा के कॉलेज ग्राउंड पर वेस्टइंडीज-ए के खिलाफ शुरू हुए तीन दिवसीय अभ्यास मैच में खराब शुरुआत की। लंच तक भारतीय टीम ने तीन विकेट खोकर सिर्फ 89 रन बनाए हैं।

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। भारत की शुरुआत खराब रही और उन्होंने मयंक अग्रवाल के रूप में अपना पहला विकेट गंवा दिया। मयंक को 12 रन के निजी स्कोर पर जोनाथन कार्टर ने बोल्ड कर दिया। इसके बाद 52 रनों के स्कोर पर दूसरे ओपनर केएल राहुल भी चलते बने। उन्हें 36 रनों पर किओन हार्डिंग ने पवेलियन भेजा। कुछ देर बाद उप कप्तान अजिंक्य रहाणे भी मात्र एक रन पर आउट हो गए। उन्हें कार्टर ने ही पवेलियन भेजा। इसके बाद भारतीय टीम ने कोई विकेट नहीं गंवाया। चेतेश्वर पुजारा 16 और रोहित शर्मा 22 रन बनाकर नाबाद रहे। भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का अपना पहला मैच 22 अगस्त से एंटिगा में खेलना है। भारत ने यहां टी-20 सीरीज 3-0 और वनडे सीरीज 2-0 से जीती है। अब उसे दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है।

शॉट लगाते रोहित शर्मा • ट्विटर

दिलेर स्मिथ ने कराई ऑस्ट्रेलिया की वापसी

लंदन, रायटर : बारिश की वजह से करीब दो दिन का खेल खराब होने के बावजूद लॉर्ड्स में खेला जा रहा एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट रोचक स्थिति में बढ़ चला है। स्टीव स्मिथ (92) की दिलेर पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पहली पारी के आधार पर बड़ी बढ़त लेने से रोक दिया। चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया की पारी चाय काल से ठीक पहले 250 रनों पर सिमटी और इंग्लैंड को पहली पारी के आधार पर महज आठ रनों की बढ़त हासिल हुई। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने चाय काल के बाद दूसरी पारी में मेजबान टीम को नौ रनों पर दो झटके देकर मुश्किल में डाल दिया।

पहली पारी में बिना खाता खोले आउट होने वाले जेसन रॉय (2) दूसरी पारी में भी फ्लॉप रहे और एक शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद पर कमिंस को फॉलो थ्रू में कैच थमाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान जो रूट (0) कमिंस की अगली गेंद पर विकेटकीपर टिम पेन को कैच थमा बैठे। ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद रूट के बल्ले का मोटा किनारा लेकर पेन के दस्ताने में समा गई।

आर्चर की गेंद लगने के बाद जमीन पर गिर गए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ • एएफपी

250 रनों पर सिमटे कंगारू : इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन के स्कोर चार विकेट पर 80 रनों से आगे खेलना शुरू किया। तीसरे दिन के नाबाद बल्लेबाज स्मिथ और ट्रेविस हेड (7) ने पारी को आगे बढ़ाया लेकिन हेड को स्टुअर्ट ब्रॉड ने एलबीडब्ल्यू आउट करके ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल में डाल दिया। हालांकि पहले टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले स्मिथ को कप्तान टिम पेन (23) का साथ मिला और दोनों ने छठे विकेट के लिए 60 रनों की अहम भागीदारी निभाई। हालांकि पेन को जोफ्रा आर्चर (2/59) ने चलता करके ऑस्ट्रेलिया को छठा झटका दिया। इसके बाद स्मिथ को पैट कमिंस (20) का साथ मिला और दोनों टीम के स्कोर को 200 रनों के पार ले गए। इंग्लैंड की ओर से ब्रॉड ने 65 रन देकर सर्वाधिक चार विकेट झटके जबकि वोक्स को भी तीन सफलताएं हासिल हुईं।

स्मिथ को लगी बाउंसर

लंदन: इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की 92.4 मील प्रति घंटे की रफ्तार की एक गेंद आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ के कान के नीचे गर्दन पर लगी। गेंद लगने के बाद स्मिथ मैदान पर गिर गए और रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर चले गए। स्मिथ को जब गेंद लगी तब वह 152 गेंदों पर 80 रन बना चुके थे। फिजियो ने मैदान पर स्मिथ को देखा और फिर उन्हें बाहर ले गए। आर्चर की एक गेंद इससे पहले भी स्मिथ की बाजू पर लग चुकी थी। स्मिथ जब बाहर गए तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर छह विकेट पर 203 रन था। स्मिथ जब मैदान से बाहर जा रहे थे तब दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया। करीब 40 मिनट बाद पीटर सिडल के आउट होने पर वह फिर बल्लेबाजी करने आए और 12 रन जोड़कर क्रिस वोक्स की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। स्मिथ ने 161 गेंदों का सामना किया।

साक्षी मलिक को कारण बताओ नोटिस

विकास मिश्र • लखनऊ

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साई सेंटर में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए चल रहे भारतीय महिला कुश्ती टीम के कैंप से बिना कोई सूचना अनुपस्थित रहने के कारण भारतीय कुश्ती संघ का चाबुक देश की स्टार महिला पहलवान साक्षी मलिक सहित 25 अन्य खिलाड़ियों पर चल गया है। हालांकि संघ के अध्यक्ष ब्रज भूषण सिंह का कहना है कि साक्षी सहित उन चार महिला पहलवानों को कैंप में मौजूद न होने की वजह से सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इससे स्टार पहलवान साक्षी का विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लेने में किसी तरह की कोई बाधा नहीं हैं। वहीं निष्कासित पहलवानों को 19 अगस्त को लखनऊ में आयोजित चयन ट्रायल में मौका नहीं मिलेगा।

साक्षी के अलावा किरण, सरिता और सीमा पर भी संघ ने सख्ती दिखाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। संघ के एक पदाधिकारी के मुताबिक तीनों महिला पहलवान अगर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती हैं तो भविष्य में इन सभी को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं निष्कासित हुई पहलवानों को ट्रायल में शामिल करने पर रोक लगा दी गई है। कुछ महिला पहलवान विदेश में तैयारी कर रही हैं लेकिन, ये सभी लौटने के बाद भी कैंप में शामिल नहीं हुईं, जिसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई तय मानी जा रही थी।

एक बार फिर विवादों में आए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार

योगेश शर्मा • नई दिल्ली

हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी रहे मेजर ध्यान चंद के जन्मदिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को मिलने वाले खेल पुरस्कार फिर से विवादों में आ गए। पिछले साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया का नाम नहीं था तो उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाने की धमकी दी थी। तत्कालीन खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बजरंग को आश्वासन देकर शांत किया था। इस बार भी पुरस्कारों पर सवाल उठने लगे हैं।

समिति पर बरसे बिंद्रा: भारत की तरफ से ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा ने जसपाल राणा का नाम द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामित नहीं किए जाने पर चयन समिति की कड़ी आलोचना की। राणा ने मनु भाकर, सौरभ चौधरी और अनीस भानवाला जैसे विश्वस्तरीय निशानेबाजों को तैयार किया है। बिंद्रा ने ट्वीट किया, 'मैं अपनी सफलता का श्रेय बेहतरीन कोच को देता रहा। राणा सर्वश्रेष्ठ कोच में एक हैं और उन्हें द्रोणाचार्य के लिए नजरअंदाज करना निराशाजनक है। उम्मीद है कि इससे उनके शिष्यों को कड़ी मेहनत करने और टोक्यो ओलंपिक में समिति को गलत साबित करने की प्रेरणा मिलेगी।'

प्रणय ने लगाए गंभीर आरोप: अर्जुन पुरस्कार पाने वाली की सूची में नाम नहीं आने से निराश भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणय ने आरोप लगया कि पुरस्कारों के लिए ऐसे लोगों से पहचान जरूरी है जो नामांकन को मैदान के प्रदर्शन से ज्यादा तव्वजो दिला सके। प्रणय ने ट्वीट किया, 'अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम भी पुरस्कारों की सूची में हो तो यह सुनिश्चित करें कि आपके साथ ऐसे लोग हों जो सूची में आपका नाम डलवा सकें।

दीपा मलिक को भी मिलेगा खेल रत्न

- बजरंग के अलावा हरियाणा की पैरा एथलीट भी हुईं नामित
- क्रिकेटर रवींद्र जडेजा सहित 19 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: पैरालंपिक में रजत पदक विजेता दीपा मलिक को एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन पहलवान बजरंग पूनिया के साथ शनिवार को देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया।

रियो पैरालंपिक के गोला फेंक में एफ53 वर्ग में रजत पदक जीतने वाली 48 वर्षीय हरियाणा की दीपा का नाम 12 सदस्यीय समिति ने दो दिवसीय बैठक के दूसरे दिन खेल रत्न पुरस्कार के लिए जोड़ा। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) मुकुंदकम शर्मा की अगुआई वाली समिति ने विश्व में 65 किग्रा में नंबर एक पूनिया को शुक्रवार को ही खेल रत्न के लिए चुन लिया था। खेल रत्न के दावेदारों में महिला पहलवान विनेश फोगाट और एथलीट नीरज चोपड़ा भी दौड़ में थे लेकिन समित ने दोनों खिलाड़ियों पर अपनी रुचि नहीं दिखाई और दीपा को प्राथमिकता दी गई।

समिति ने 19 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए भी चुना है जिसमें क्रिकेटर रवींद्र जडेजा और पूनम यादव, एथलीट तेजिंदर पाल सिंह तूर, मुहम्मद अनस और स्वप्ना बर्मन, फुटबॉलर गुरप्रीत सिंह संधू, हॉकी खिलाड़ी चिंगलेनसाना सिंह कंगुजम और निशानेबाज अंजुम मौदगिल शामिल हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार पुरस्कार की पात्रता के लिए एक खिलाड़ी का पुरस्कार वाले वर्ष में बेहतरीन प्रदर्शन के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पिछले चार वर्षों में लगातार अच्छा प्रदर्शन होना जरूरी है। इसके साथ ही उसमें नेतृत्वक्षमता, खेल भावना और अनुशासन के गुण भी होने अनिवार्य हैं। समिति ने तीन नामों को द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए भेजे गए हैं।

मेरी कॉम ने खेल पुरस्कार समिति की बैठक से खुद को अलग किया

नई दिल्ली: विश्व चैंपियन मुक्केबाज एमसी मेरी कॉम ने हितों के टकराव के कारण खुद को द्रोणाचार्य पुरस्कार चयन समिति की शनिवार को हुई बैठक से अलग कर लिया। उनके कोच छोटेलाल यादव इस पुरस्कार की दौड़ में थे। चयन समिति में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मेरी कॉम के शामिल होने से सवाल उठ रहे थे क्योंकि पुरस्कार के दावेदारों में उनके कोच भी शामिल थे। मेरी कॉम ने हालांकि खुद को चयन प्रक्रिया से अलग करने का फैसला किया। इस चयन समिति में मेरी कॉम के अलावा पूर्व फुटबॉलर बाइचुंग भूटिया, लंबी कूद की पूर्व धावक अंजू बॉबी जॉर्ज, महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा और टेबल टेनिस टीम के कोच कमलेश मेहता शामिल थे।

पुरस्कारों की सूची

राजीव गांधी खेल रत्न

नाम	खेल
बजरंग पूनिया	कुश्ती
दीपा मलिक	पैरा एथलीट

द्रोणाचार्य (नियमित श्रेणी)

नाम	खेल
विमल कुमार	बैडमिंटन
संदीप गुप्ता	टेबल टेनिस
मोहिंदर सिंह ढिल्लों	एथलेटिक्स

लाइफ टाइम श्रेणी

नाम	खेल
कोच का नाम	खेल
मर्जबान पटेल	हॉकी
रामबीर सिंह खोखर	कबड्डी
संजय भारद्वाज	क्रिकेट

अर्जुन

तेजिंदरपाल सिंह तूर	एथलेटिक्स
मुहम्मद अनस याहिया	एथलेटिक्स
एस. भास्करन	बॉडी बिल्डिंग
सोनिया लाथर	मुक्केबाजी
रवींद्र जडेजा	क्रिकेट
चिंगलेनसाना सिंह कंगुजम	हॉकी
अजय ठाकुर	कबड्डी
गौरव सिंह गिल	मोटर स्पोर्ट्स
प्रमोद भगत	पैरा बैडमिंटन
अंजुम मौदगिल	निशानेबाजी
हरमीत राजुल देसाई	टेबल टेनिस
पूजा ढांढा	कुश्ती
फवाद मिर्जा	घुड़सवारी
पूनम यादव	क्रिकेट
स्वप्ना बर्मन	एथलेटिक्स
सुंदर सिंह गुर्जर	पैरा एथलेटिक्स
बी साई प्रणीत	बैडमिंटन
सिमरन सिंह शेरगिल	पोलो

ध्यानचंद

नाम	खेल
मैनुअल फैडरिक्स	हॉकी
अरूप बसक	टेबल टेनिस
मनोज कुमार	कुश्ती
नितन किर्ताने	टेनिस
लालरेमसानगा	तीरंदाजी

मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी

पंजाब विवि	चंडीगढ़ (विजेता)
गुरु नानक देव विवि	अमृतसर (दूसरा स्थान)
पंजाबी विवि	पटियाला (तीसरा स्थान)

राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन

- गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रोमोशन फाउंडेशन
- गो स्पोर्ट्स
- विकास के लिए खेल (रायलसीमा विकास ट्रस्ट)

दीपा की उपलब्धि

- 2016 रियो पैरालंपिक खेलों में रजत पदक (शॉट पुट-एफ, 53)
- 2011 न्यूजीलैंड में आइपीसी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक (शॉट पुट- एफ52-53)
- 2014 इंचियोन एशियन पैरा गेम्स में रजत पदक (जेवलिन थ्रो, एफ53-54)
- 2018 जकार्ता एशियन पैरा गेम्स में कांस्य पदक (जेवलिन थ्रो, एफ53-54) और इन खेलों में ही डिस्कस थ्रो (एफ51-52-53) में भी कांस्य पदक
- 2010 ग्वांगझो पैरा एशियन गेम्स में कांस्य पदक (जेवलिन थ्रो, एफ-33-34-52-53)

दीपा मलिक • फाइल फोटो, ट्विटर

मुझे लगता है कि यह पुरस्कार दिव्यांग महिला एथलीटों के लिए बड़ी प्रेरणा का काम करेगा। यह भारत में पैरालंपिक खेलों को भी बढ़ावा देगा।
दीपा मलिक

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
स्पोर्ट्स
रविवार 18 अगस्त 2019
www.jagran.com
15

बीता सत्र काफी कठिन था और साबिया ने मुश्किल हालात में शानदार जज्बा दिखाया था। ऐसे में हमने उनका करार बढ़ाया।
– जॉन ग्रेगोरी, कोच चेन्नइयन एफसी

फिलिप कौटिन्हो लोन पर बायर्न म्यूनिख में शामिल होंगे

बार्सिलोना, एएफपी : स्पेनिश क्लब एफसी बार्सिलोना ने ब्राजील के मिडफील्डर फिलिप कौटिन्हो को लोन पर बायर्न म्यूनिख में भेजने के लिए जर्मन क्लब से करार कर लिया है। बार्सिलोना संस्थागत और खेल संबंध के निदेशक ने इसकी पुष्टि की और इसी कारण से कौटिन्हो को एटलेटिक क्लब के खिलाफ हुए मुकाबले में शुरुआती-11 खिलाड़ियों में शामिल नहीं किया गया था।

फुटबॉल डायरी ▶ ला लीगा सत्र के पहले मुकाबले में एथलेटिक बिल्बाओ से हारा मौजूदा चैंपियन

बार्सिलोना के खिताबी बचाव अभियान को झटका

लुइस सुआरेज की चोट ने बढ़ाई बार्सा की मुश्किलें

मैड्रिड, एएफपी : स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में मौजूदा चैंपियन बार्सिलोना को अपने खिताबी बचाव के अभियान को शुरुआत में ही बड़ा झटका लगा है। मौजूदा सत्र के पहले ही मुकाबले में स्थानापन्न एरिज अदुरिज द्वारा अंतिम लम्हों में किए गए गोल की बदौलत एथलेटिक बिल्बाओ ने बार्सिलोना को 1-0 से शिकस्त दी। इस दौरान बार्सिलोना के स्टार स्ट्राइकर लुइस सुआरेज चोटिल हो गए।

38 वर्षीय स्ट्राइकर अदुरिज ने 88वें मिनट में गोल करके बार्सिलोना को सन्न कर दिया। अदुरिज पहले ही इस सत्र के बाद संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने हवा में छलांग लगाकर वॉली के जरिये गेंद को बार्सिलोना के गोलकीपर मार्क आंद्रे टेर स्टेगन के बगल से गोल पोस्ट में पहुंचाया जिसके बाद सैम मेंस में बैठे बिल्बाओ के हजारों दर्शक खुशी से झूम उठे। अदुरिज अपने 20 साल के करियर में 200 से ज्यादा गोल कर चुके हैं लेकिन इस गोल से यादगार शायद ही उनके लिए कुछ हो।

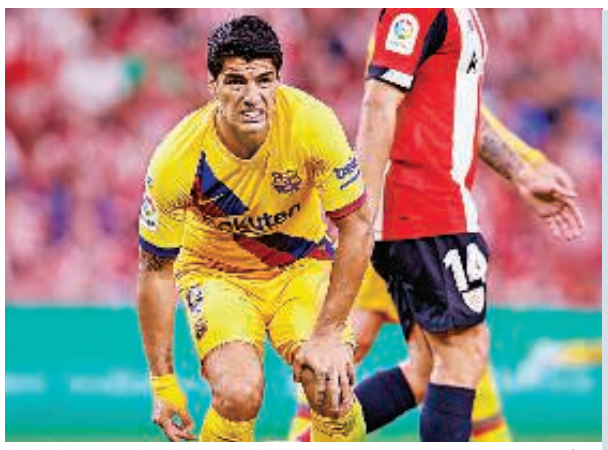

मैच के दौरान बार्सिलोना के लुइस सुआरेज। एएफपी

लेवांदोवोस्की ने बायर्न को हार से बचाया

बर्लिन : रॉबर्टो लेवांदोवोस्की के दो गोल के बावजूद जर्मन चैंपियन बायर्न म्यूनिख को अपने घरेलू मैदान पर हेर्था बर्लिन के खिलाफ बुंडिशलीगा सत्र के पहले मुकाबले में 2-2 से ड्रॉ खेलना पड़ा। लेवांदोवोस्की ने दूसरे हाफ में पेनाल्टी किक के जरिये गोल करके अपनी टीम के लिए एक अंक बचाया और हेर्था को सौभाग्यशाली करार दिया। लेवांदोवोस्की ने खेल के 24वें मिनट में गोल करके बायर्न को शुरुआती बढ़त दिलाई लेकिन डोडी लुकेबाकियो (36वें मिनट) और मार्को ग्रुजिक (38वें मिनट) ने गोल करके हेर्था को पहले हाफ में अप्रत्याशित बढ़त दिलाई। इसके बाद लेवांदोवोस्की ने दूसरे हाफ में पेनाल्टी किक के जरिये गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलाई।

इस मुकाबले में बार्सिलोना अपने स्टार स्ट्राइकर लियोन मेसी के बगैर उतरा जो प्री-सीजन मुकाबले के दौरान चोटिल हो गए थे। वहीं फिलिप कौटिन्हो का भी क्लब को छोड़ना तय लग रहा है। ऐसे में बार्सिलोना के लिए सत्र की शुरुआत में मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। हालांकि मेसी के अगले मुकाबले तक वापसी की उम्मीद की जा रही है जबकि फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के स्टार नेमार की बार्सिलोना में वापसी को लेकर भी चर्चा चल रही है।

सुआरेज की चोट ने बढ़ाई चिंता : एथलेटिक बिल्बाओ के खिलाफ ला लीगा के पहले ही मुकाबले में लुइस सुआरेज 37वें मिनट में चोटिल हो गए जिसके बाद उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। बार्सिलोना ने भी सुआरेज के दायें पैर में चोट की पुष्टि की है। हालांकि बार्सिलोना ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि सुआरेज कितने समय के लिए मैदान से बाहर रहेंगे। उनके चोट की सही स्थिति को पता करने के लिए मंगलवार को टेस्ट होगा।

बार्सिलोना के मैनेजर ने की ग्रीजमैन की आलोचना

लीड्स : बार्सिलोना के मैनेजर इर्नेस्टो वाल्वर्डे ने एथलेटिक बिल्बाओ के खिलाफ मुकाबले में अपने स्टार स्ट्राइकर एंटोनी ग्रीजमैन के प्रदर्शन की आलोचना की है। ग्रीजमैन हाल ही में बार्सिलोना से जुड़े हैं और पहली बार ला लीगा में खेलने उतरे। वाल्वर्डे ने कहा कि निश्चित रूप से उन्हें (ग्रीजमैन) पता है कि हम सभी खिलाड़ियों से बहुत उम्मीद करते हैं और उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुकाबले पर ध्यान लगाना होगा। लेफ्ट साइड में उन्हें रखने का मतलब है कि आप गोल पर ध्यान लगाने जा रहे हैं लेकिन हमारे पास एक ऐसी टीम और खिलाड़ी हैं जो मुकाबले पर पकड़ बना सकते हैं।

विश्व नंबर एक जोकोविक का सेमीफाइनल में प्रवेश

मैच के दौरान नोवाक जोकोविक। एपी

सिनसिनाटी मास्टर्स

- सर्बिया के नोवाक ने क्वार्टर फाइनल में लुकास को सीधे सेटों में हराया
- रूस के डेनिल मेदवेदेव से होगा जोकोविक का मुकाबला

सिनसिनाटी, एएफपी : सर्बिया के सुपरस्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक ने कोहनी में असहजता के बावजूद फ्रांस के लुकास पॉली पर सीधे सेटों में 7-6, 6-1 की जीत से सिनसिनाटी मास्टर्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। यह मुकाबला 86 मिनट तक चला।

अब फाइनल में जगह बनाने के लिए विश्व के नंबर एक खिलाड़ी जोकोविक का सामना रूस के डेनिल मेदवेदेव से होगा जो हमवतन आंद्रे रूबलेव को 6-2, 6-3 से हराकर अंतिम-चार में पहुंचे हैं। मेदवेदेव ने इस साल हुए मोंटे कार्लो मास्टर्स में जोकोविक को मात दी थी। फ्रांस के रिचर्ड गास्केट ने छह साल में मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहली जीत हासिल की। उन्होंने 2013 में मियामी में मास्टर्स क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। इस तरह गास्केट ने रॉबर्टो बातिस्ता आगुट को 7-6, 3-6, 6-2 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। गास्केट अब फाइनल में जगह बनाने के लिए 16वें वरीय डेविड गोफिन से भिड़ेंगे जिन्होंने जापानी क्वालीफायर योशिहितो निशियोका के वाकओवर से अगले दौर में प्रवेश किया।

16 बार के ग्रैंडस्लैम चैंपियन जोकोविक को मैच के दौरान कोहनी में असहजता हुई लेकिन उन्होंने आराम से जीत हासिल की। मैच के बाद उन्होंने कहा, 'मैं मैच खत्म करने में सफल रहा। हालांकि मेरी कोहनी में थोड़ी समस्या हो रही थी लेकिन यह जल्द ठीक हो जाएगी।' इस जीत के साथ जोकोविक लगातार पांच टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रहे। वह दो जीत दर्ज करने के बाद अपने करियर का 34वां मास्टर्स 1000 की ट्रॉफी उठाएंगे। अगर वह ऐसा कर पाते हैं तो वह इस मामले में राफेल नडाल (35) के बेहद करीब पहुंच जाएंगे।

चोटिल ओसाका ने छोड़ा मैच, केनिन अंतिम-चार में

सिनसिनाटी : विश्व की नंबर एक महिला टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका को यहां सिनसिनाटी मास्टर्स में महिला सिंगल्स का क्वार्टर फाइनल मैच दायें पैर के घुटने की चोट के कारण बीच में ही छोड़ना पड़ा। जापानी खिलाड़ी ओसाका जब अमेरिका की सोफिया केनिन के खिलाफ 4-6, 6-1, 0-2 से पीछे चल रही थी तब उन्होंने मैच को बीच में छोड़ने का फैसला कर लिया। ओसाका के बीच में मैच छोड़ने से उनकी नंबर एक की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई है। अगर ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी फाइनल में पहुंच जाती हैं तो वह फिर से नंबर एक खिलाड़ी बन जाएंगी। ओसाका ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि मेरे दायें घुटने में क्या दिक्कत चल रही है। मैं जल्दी ठीक होना चाहती हूं क्योंकि अमेरिकी ओपन ज्यादा दूर नहीं है।' ओसाका से पहले अमेरिकी दिग्गज खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने भी कमर की चोट के कारण टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया था। सेमीफाइनल में केनिन का सामना अमेरिकी खिलाड़ी मेडिसन कीज से होगा जिन्होंने हमवतन वीनस विलियम्स को सीधे सेटों में शिकस्त दी।

भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को दी शिकस्त

टोक्यो, प्रेट्र : भारतीय महिला हॉकी टीम ने शनिवार को मेजबान जापान पर 2-1 की जीत से ओलंपिक परीक्षण प्रतियोगिता में अपना अभियान शुरू किया।

भारत ने पेनाल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ गुरजीत कौर की मदद से नौवें मिनट में बढ़त बना ली थी लेकिन मेजबान टीम ने 16वें मिनट में अकी मितसुहासी के मैदानी गोल से 1-1 से बराबरी हासिल की। हालांकि गुरजीत ने फिर 35वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर से गोल कर भारत को 2-1 से आगे कर दिया जो निर्णायक रहा। भारतीय टीम ने आक्रामक शुरुआत की और पहले 10 मिनट में ही उसे कुछ मौके मिले। दोनों टीमें ओलंपिक खेलों के दिशानिर्देशों के अनुसार 16 खिलाड़ियों के साथ खेल रही थीं। दोनों ने समय समय पर पूरे मैच के दौरान खिलाड़ियों को अंदर बाहर किया। जापान को स्थानापन्न खिलाड़ी का फायदा हुआ और 29 साल की मितसुहासी ने टीम को बराबरी दिलाई।

मप्र के बोल्ट को तैयार करेगा खेल मंत्रालय

शिवपुरी, नई दुनिया

हौसला

- शिवपुरी के रामेश्वर की 100 मी की दूरी 11 सेकंड में पूरी करने की वीडियो हुई थी वायरल
- पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ट्वीट किया वीडियो, किरण रिजिजू ने भेजा भोपाल साई सेंटर

रामेश्वर गुर्जर का वीडियो हुआ है वायरल। एएनआइ

मध्य प्रदेश के शिवपुरी के 19 वर्षीय धावक रामेश्वर गुर्जर का नंगे पाव 100 मीटर की दूरी 11 सेंकड में पूरी करने का वीडियो सोशल मीडिया वायरल हुआ, तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू तक इस युवा एथलीट से प्रभावित हो गए। शिवराज सिंह चौहान ने रामेश्वर का वीडियो ट्विटर पर अपलोड किया और खेल मंत्री किरण रिजिजू से उसकी मदद करने को कहा। किरण ने भी तुरंत संज्ञान लेते हुए शिवराज से रामेश्वर को उनसे मिलाने की बात कही।

बोल्ट से तेज दौड़ने की हिम्मत : विश्व के सबसे तेज धावक जमैका के उसेन बोल्ट के नाम 100 मीटर की दौड़ 9.58 सेकेंड में पूरी करने का रिकॉर्ड है जबकि रामेश्वर बिना किसी सुविधा के नंगे पैर 11 सेकंड में यह दूरी पार कर लेते हैं। ऐसे में जानकारों का मानना है कि अगर इस युवा खिलाड़ी को सभी सुविधाएं देकर तैयार किया जाए तो यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश को ना सिर्फ कई पदक दिला सकते हैं बल्कि कई रिकॉर्ड भी बना सकते हैं।

मप्र के खेल मंत्री का बुलावा : इस वीडियो को देखकर केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने जहां ट्वीट कर कहा है कि इस धावक को मेरे पास ले आएं तो वहीं मध्य प्रदेश के खेलमंत्री जीतू पटवारी ने रामेश्वर को भोपाल बुला लिया है। जहां खेल मंत्री पटवारी ने भी उसका हौसला बढ़ाया।

फौज में जाने की थी चाहत : शिवपुरी की नरवर जैसी छोटी तहसील में रहकर रामेश्वर की पहली हसरत सेना में भर्ती होनी थी इसलिए उसने दौड़ लगाना शुरू कर दी। रामेश्वर कभी मिट्टी में तो कभी पत्थर भरे ट्रैक पर अभ्यास करते रहे। प्रदेश और देश में वीडियो के जरिये अपनी पहचान बनाने वाले रामेश्वर ने कहा कि वह देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। यदि उन्हें मौका मिला तो वह निराश नहीं करेंगे।

दूध बेचते हैं रामेश्वर : रामेश्वर तीन भाइयों और दो बहनों के साथ रहते हैं। उनके भाई और पिता खेती करते हैं, जबकि रामेश्वर दूध बेचकर परिवार चलाने में हाथ बंटाते हैं। अलसुबह दौड़ लगाना उनकी आदत में शुमार हो गया है। पिता को तो अपने बेटे की इस प्रतिभा का इल्म तक नहीं है। उन्होंने कहा कि हम तो बेहद गरीब लोग हैं। घर की छत भी नहीं डलवा पाए। बेटा दौड़ता तो है पर ये तो आप लोगों से ही पता चला कि इतना अच्छा दौड़ता है।

विविध

पत्नी को विदेश जाने से रोकने के लिए फैलाई थी बम की अफवाह

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- आइजीआइ एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 पर बम होने की दी झूठी सूचना
- बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला है आरोपित नसरुद्दीन

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आठ अगस्त को पत्नी को विदेश जाने से रोकने के लिए बम की झूठी कॉल करने वाले शख्स को दिल्ली के बवाना इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान नसरुद्दीन के रूप में हुई है। आरोपित ने एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 पर बम होने की झूठी सूचना कॉल कर दी थी, जिसके बाद एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया था और दुबई और सऊदी अरब जाने वाली उड़ानों के साथ ही एयरपोर्ट की गहन तलाशी ली गई। इसकी वजह से घंटों तक अफरातफरी मची रही।

स्पेशल सेल के पुलिस उपायुक्त संजीव कुमार यादव ने बताया कि आठ अगस्त की रात आइजीआइ एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में एक कॉल आई थी। फोन करने वाले ने बताया था कि वह चेन्नई से बोल रहा है। जबीना नाम की महिला दुबई या सऊदी अरब जाने वाली उड़ान में सवार होने की जुगत में है। उसके पास बम है और विस्फोट से विमान को उड़ा देगी। बम की कॉल मिलते ही दिल्ली पुलिस व सीआइएसएफ सहित तमाम एजेंसियां जांच में जुट गई थीं।

तकनीकी सर्विलांस से पुलिस को पता चला कि फोन करने वाला नसरुद्दीन बवाना औद्योगिक क्षेत्र इलाके में मौजूद है। पुलिस ने 15 अगस्त को उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से वह मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है जिससे उसने वाट्सएप कॉल किया था।

पुलिस के मुताबिक आरोपित बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला है। वह चेन्नई में सिलाई का काम करता है, जबकि उसके परिजन दिल्ली के बवाना में रहते हैं। चेन्नई में काम करने के दौरान ही उसने 2017 में जबीना से शादी की थी। जबीना बेहतर जीवन जीना चाहती थी। इस वजह से काम की तलाश में विदेश जाने की योजना बनाई थी। पत्नी को विदेश जाने से रोकने के लिए उसने आइजीआइ एयरपोर्ट पर झूठी बम की कॉल कर दी थी।

बारिश में लोको पायलट एक हाथ में छाता लेकर चलाते हैं ट्रेन

शक्ति सिंह, रांची

- रांची रेल मंडल के अधिकतर इंजनों में बारिश के वक्त टपकता है पानी
- एकाग्रता भंग होने और शॉट सर्किट होने का रहता है खतरा

एक हाथ में छाता और दूसरे हाथ से ट्रेन चलाता लोको पायलट, बस इसी से समझ सकते हैं कि ऐसे इंजन को चलाना कितना सुरक्षित और खतरे से भरा होता है। थोड़ी-सी चूक से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यह हाल रांची रेल मंडल के कई इंजनों की है, जिसमें बारिश के समय पानी टपकता रहता है। शनिवार को इस तरह का नजारा एक ट्रेन में देखने को मिला जिसमें लोको पायलट छाता लगाकर बैठा है। इसका मुख्य कारण इंजन के छत की स्थिति जर्जर होना। इस ओर रेलवे के इलेक्ट्रिकल विभाग की नजरें नहीं जाती है। जानकारी होने के बाद भी ऐसे इंजनों को ट्रेन में लगा कर दौड़ा दिया जाता है।

शिकायत के बाद भी नहीं हुई सुनवाई: इस परेशानी को लेकर लोको पायलट कई बार वरीय अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती है। यही नहीं ट्रेन में बारिश का पानी गिरने से कई माइक्रोप्रोसेसर शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं और बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। यही नहीं लोको शेड से निकलने के दौरान

बारिश में इंजन में टपकते पानी के बीच छाता लेकर ट्रेन चलाते लोको पायलट। जागरण

ऐसे इंजनों की ठीक से जांच नहीं होती है। इस कारण बारिश के वक्त खस्ताहाल इंजनों की पोल खुलने लगती है।

लोको पायलट भी नहीं करते जांच: इंजन को चार्ज में लेने के दौरान लोको पायलट भी इसकी जांच नहीं करते हैं और चार्ज ले लेते हैं। उनके इन्कार करने से इंजन को बदलने का विकल्प होता है।

बांधवगढ़ में एक बाघ शावक की मौत, एक माह के अंदर पांच मृत

नईदुनिया, उमरिया

- पांच दिन पहले इन्क्लोजर में रखा था, साढ़े चार माह का था शावक

मध्य प्रदेश स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ शावक की मौत हो गई है। यह मौत 16 अगस्त की रात हुई थी। मृत बाघ शावक की आयु पार्क प्रबंधन ने लगभग साढ़े चार महीने बताई है। शनिवार सुबह बाघ शावक का पोस्टमार्टम करने के बाद उसका दाह संस्कार कर दिया गया। यह शावक पिछले पांच दिनों से बहेरहा के इंक्लोजर में था और अस्वस्थ था। मालूम हो, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिलने के एक महीने के अंदर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में यह चौथे और उमरिया जिले में पांचवें बाघ की मौत है।

बांधवगढ़ के फील्ड डायरेक्टर विंसेंट रहीम ने बताया कि 11 अगस्त को गश्त के दौरान गश्ती दल को यह बाघ शावक धमोखर रेंज में बीमार अवस्था में दिखा था। देखने से ही महसूस हो रहा था कि उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। इसके बाद बाघ शावक को बचाने की अनुमति ली गई और उसे बहेरहा के बाड़े में रखने के बाद उपचार शुरू किया गया। पार्क प्रबंधन ने बताया कि लगभग साढ़े चार महीने पहले बाघिन टी-35 ने तीन शावकों को जन्म दिया था। इसमें से एक शावक बेहद कमजोर था और कुनबे में सबसे छोटा था। बाघिन ने जब इसे बाहर निकाला, तभी से यह उसके साथ नहीं चल पा रहा था। बाघिन अपने उन बच्चों को त्याग देती है जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं।

कब-कैसे हुई मौतें

28 जुलाई की रात बाघ टी-33 ने बाघिन टी-62 के शावकों पर हमला कर दिया था। इसमें बाघिन और उसके एक शावक की जान चली गई।

01 अगस्त को शहडोल के पास रेगुलर फॉरेस्ट में वयस्क बाघ ने बाघ शावक को मार दिया था।

08 अगस्त को बीमारी के कारण बाघिन की मौत हो गई।

16 अगस्त को अब एक और बाघ शावक की मौत हो गई।

ट्रेन के पुराने कोच में रेस्तरां, लजीज व्यंजन के साथ होगा सफर

रमेश यादव, प्रयागराज : इलाहाबाद जंक्शन पर यात्रियों के लिए जल्द ही खास तरह का रेस्टोरेंट ट्रेन के कोच में खोला जाएगा। इसमें चाइनीज और कांटिनेंटल फूड समेत सभी प्रकार के स्वादिष्ट व लजीज व्यंजन उपलब्ध होंगे। खास यह कि कोच को इस तरह सजाया जाएगा कि रेस्टोरेंट में बैठने पर ट्रेन में सफर करने जैसा अहसास होगा। बहरहाल, रेलवे प्रशासन इस रेस्टोरेंट को सिविल लाइंस साइड में खोलने की तैयारी कर रहा है।

यात्रियों को आकर्षित करने के लिए रेलवे का आधुनिक सुविधाओं पर विशेष जोर है। इलाहाबाद जंक्शन पर देश-विदेश के यात्री आवागमन करते हैं। ऐसे में स्टेशन परिसर में खाने-पीने की उम्दा चीजें उन्हें उपलब्ध कराने की तैयारी है। पुराने कोच में बनने वाला यह रेस्टोरेंट आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। इसके लिए कॉमर्शियल डिपार्टमेंट से दो पुराने कोच की मांग की गई है। कोच का इंटीरियर विशेष होगा। खिड़कियों पर विशेष प्रकार की लाइट लगाई जाएगी। इलाहाबाद मंडल के जनसंपर्क अधिकारी सुनील कुमार गुप्ता ने कहा कि भोपाल और चेन्नई में ट्रेन के कोच में रेस्टोरेंट संचालित हैं। उसी थीम पर तैयारी की जा रही है।

स्वतंत्रता दिवस पर दौड़ा सबसे पुराना भाप इंजन

नई दिल्ली, प्रेट्र : रेलवे ने 73वें स्वतंत्रता दिवस को यादगार बनाने के लिए दुनिया के सबसे पुराने भाप के इंजन को चेन्नई के एग्मोर से कोडंबक्कम तक सफलतापूर्वक दौड़ाया।

बता दें कि फेयरी क्वीन जैसा दिखने वाला यह इंजन (द एक्सप्रेस ईआइआर-21) 164 साल पुराना है। 15 अगस्त के दिन रेलवे के अधिकारियों को लेकर एक कोच के साथ यह इंजन चेन्नई के एग्मोर से दोपहर को चला। इसे देखने के लिए एग्मोर और कोडंबक्कम रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। अपनी धरोहरों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से रेलवे इस तरह के आयोजन करता रहता है। दरअसल, यह इंजन 1855 में इंग्लैंड से भारत भेजा गया था। 1909 में सेवा से हटने के बाद यह इंजन जमालपुर कार्यशाला और हावड़ा स्टेशन पर 101 वर्षों तक खड़ा रहा। इस दौरान धूप और बारिश की मार से जहां इसके कई हिस्सों में जंग लग गई वहीं कुछ हिस्से गायब हो गए तो कुछ हिस्से टूट गए।

मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में वर्षा में कमी आएगी। हिमाचल प्रदेश में मध्यम वर्षा जारी रहेगी तथा भूस्खलन की संभावना है। पूर्वी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। राजस्थान के पश्चिमी भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क तथा पूर्वी भागों में हल्की वर्षा होगी।

भारत के मुख्य शहरों का तापमानः

शहर		शहर	
मुम्बई	30/25/व	अहमदाबाद	33/25/व
कोलकाता	33/25/आंबा	बड़ौदा	31/25/व
चेन्नई	31/23/व	नागपुर	30/24/व
हैदराबाद	30/23/व	इन्दौर	27/23/व
बंगलूरू	27/19/व	राँची	33/25/व
त्रिवेन्द्रम	32/25/आंबा	पटना	35/27/व
गुवाहाटी	29/26/व	जमशेदपुर	34/25/आंबा
गंगटोक	21/12/व	पुणे	25/22/व

साप्ताहिक राशिफल

रविवार 18 अगस्त, 2019 से शनिवार 24 अगस्त, 2019 तक — पं. बी. बी. शास्त्री 'देवेश'

मेष (चू,चे,चो,ला,ली,लू,ले,लो,आ)
व्यापार, नौकरी, उद्योग कार्य में प्रयास से सफलता, धनागम में प्रयास, पूंजी निवेश में सावधानी, मानसिक चिंता, दिनचर्या प्रभावित, वाहन-आभूषण योग, अध्ययन में रुचि, चयन में प्रयास, मित्रों से सावधान, शत्रु पक्ष प्रभावी, दांपत्य में अनबन, राज्य पक्ष से सावधान। शुभ अंक 2

वृष (इ,ऊ,ए,ओ,पा,वी,वू,वे,वो)
अर्थ साधन में सफलता, नई शैली से कार्य करें, सामाजिक कार्य का योग, विदेश कार्य में अवरोध, पारिवारिक सहयोग, संतान से सहयोग, विषय चयन में सफलता, ईर्ष्या से बचें, दांपत्य में सुख, राजनीतिक अपयश, आय में वृद्धि। शुभ अंक 4

मिथुन (का,की,कू,घ,ड,छ,के,को,हा)
व्यापार, नौकरी, उद्योग कार्य में सफलता, अर्थ साधन में सफलता, निर्णय सलाह से करें, भावुकता से बचें, चिंता का समाधान, चयन में सफलता, खान-पान का ध्यान रखें, त्वचा विकार का योग, दांपत्य में सुख, जीवन स्तर में सुधार होगा, पद-स्थान परिवर्तन। शुभ अंक 6

कर्क (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डू,डे,डो)
अर्थ साधन में सुधार, सलाह से निर्णय करें, महिला का सहयोग, विदेश से समाचार, भवन निर्माण का योग, संतान से सहयोग, अध्ययन में रुचि, शत्रुपक्ष से सावधान, वाद-विवाद का योग, वाहन में सावधानी, जीवन साथी का मिलन, यंत्र स्थापन योग, राज्य पक्ष से लाभ। शुभ अंक 2

सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे)
अर्थ साधन में सुधार, बदलाव से बचे, धन निवेश के लिए योजना, विदेश कार्य में प्रगति, प्रयास की दिशा में परिवर्तन करें, वाणी पर नियंत्रण, प्रणय में सुख, जीवन साथी का मिलन, वाहन में सावधानी, स्थान परिवर्तन प्रभावी, बेकार कार्य में प्रगति, व्यय अधिक। शुभ अंक 3

कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,उ,पे,पो)
व्यापार, नौकरी, उद्योग कार्य में प्रगति, अर्थ साधन अच्छा, विशेष व्यक्ति से मिलन, ऊर्जा से पूर्ण, कूटनीति का सहयोग करें, विदेश कार्य में सुधार, पारिवारिक सुख, भौतिक साधनों की पूर्ति, अध्ययन में अवरोध, मित्रों का सहयोग, अधिकारी से सहयोग, व्यय अधिक। शुभ अंक 4

तुला (रा,री,रू,रे,रो,ता,ती,तू,ते)
धनागम में अधिक प्रयास, निर्णय सोच विचार कर करें, धन के आवागमन में सावधानी, अति विश्वास से बचें, निर्माण में देरी, अध्ययन में एकाग्रता, कुसंग से बचें, जीवन साथी का मिलन, राज्य पक्ष से सावधान, राजनीति में सफलता, भ्रमण के अवसर, व्यय अधिक। शुभ अंक 3

वृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू)
व्यापार, नौकरी, कार्य में सहयोग से सफलता, अर्थ साधन में सुधार, प्रतिस्पर्धा योग, साझेदारी में अनबन, मतभेदों को भूलने का प्रयास करें, भूमि कार्य में देरी, संतान की प्रगति, चयन में सफलता, प्रणय में सुख, रक्षा साधन कार्य में प्रगति, राजनीति में सफलता। शुभ अंक 5

धनु (ये,यो,भा,भी,भू,धा,फा,ढा,भे)
व्यापार, नौकरी, उद्योग कार्य में सफलता, धनागम अच्छा, निर्णय से पूर्व विचार करें, विदेश से समाचार, निजी कार्य से संतुष्ट, स्वास्थ्य सुधार, संतान के लिए योजना, शिक्षा में व्यवधान, चयन में देरी, विपरीत परिस्थिति में भी सुधार, जीवन साथी का मिलन। शुभ अंक 3

मकर (भो,जा,ज,खी,खू,खे,खो,गा,गी)
धनागम में प्रयास, पूंजी निवेश में सावधानी, विदेश कार्य का योग, नए साधनों तथा विचारों का उपयोग करें, आत्मविश्वास की वृद्धि, साधनों की पूर्ति, संतान से सहयोग, चयन में देरी, शत्रु पक्ष प्रभावी, प्रणय में सुख, यात्रा से बचें, स्थान पद परिवर्तन, व्यय अधिक। शुभ अंक 4

कुंभ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सा,दा)
अर्थ साधन में सफलता, धन के आवागमन में सावधानी, पारिवारिक सहयोग, भावना एवं कल्पना से बचें, प्रयास से सकारात्मक बदलाव होंगे, चयन में सफलता, अध्ययन में रुचि, मित्रों से लाभ, वाद-विवाद से बचें, जीवन साथी का मिलन, व्यय अधिक। शुभ अंक 5

मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची)
धनागम में प्रयास, कार्य शैली में सुधार करें, साझेदारी में सावधानी, महिला से सहयोग, चिंता का समाधान, अध्ययन में रुचि, चयन में सफलता, कार्य में नए साधनों का प्रयोग करें, वाणी पर नियंत्रण करें, जीवन साथी का मिलन, धर्म में रुचि, व्यय अधिक। शुभ अंक 6

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 18 अगस्त 2019
आजकल
16
www.jagran.com

हवा से भी हल्की हीलियम गैस की खोज हुई

1868 में आज ही फ्रेंच खगोलशास्त्री पियरे जॉनसन ने हवा से भी हल्की हीलियम गैस की खोज सूर्यग्रहण के दौरान की थी। इस गैस का इस्तेमाल हीलियम के गुब्बारों के अलावा चिकित्सा क्षेत्र में भी किया जाता है।

सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ

1945 में आज ही महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना में उनका निधन हुआ या नहीं, इसको लेकर आज भी विवाद है। कई लोगों का मानना है कि इस हादसे में उनकी मौत हुई ही नहीं थी और इस घटना के बाद वह रूस में रहे थे।

जिनकी वजह से गुलजार है हिंदी सिनेमा...

मशहूर गीतकार, शायर, लेखक और निर्देशक गुलजार का जन्म 1934 में आज ही (पंजाब, पाकिस्तान) में हुआ। इनका वास्तविक नाम संपूरण सिंह कालरा है। 1963 में आई फिल्म बंदिनी से बतौर गीतकार करियर की शुरुआत की। दिल छू लेने वाले शब्दों के इस्तेमाल से जज्बातों को सामने रखना ही इनकी ताकत है। उन्होंने कोशिश, परिचय, मौसम, आंधी जैसी फिल्में बनाई। उनकी रचनाएं मुख्यत: हिंदी, उर्दू और पंजाबी में हैं। इन्हें पद्मभूषण, साहित्य अकादमी, दादासाहेब फाल्के अवार्ड के अलावा नेशनल फिल्म अवॉर्ड, 20 फिल्मफेयर अवॉर्ड और एक ग्रैमी अवॉर्ड से नवाजा जा चुका है।

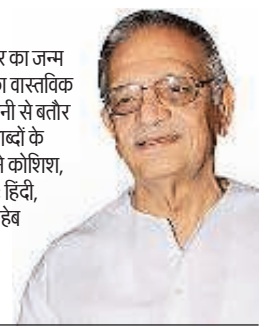

इधर-उधर की

जापान के मंदिर में रोबोट बना पुजारी

टोक्यो,एजेंसी : आमतौर पर मंदिरों में पुरुष ही पुजारी होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने किसी रोबोट को पुजारी का काम करते देखा है? जी हां, जापान में एक 400 पुराने बौद्ध मंदिर में रोबोट को पुजारी नियुक्त किया गया है। इस रोबोट का नाम एंड्रॉयड कैनन है, जिसे क्योटो के कोदाइजी मंदिर में रखा गया है। यह रोबोट मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है और वहां आने वाले श्रद्धालुओं को दया और करुणा के बारे में सीख देता है। वहीं, मंदिर के अन्य पुजारी इस काम में रोबोट की सहायता करते हैं। यह पुजारी रोबोट करीब छह फीट लंबा है, जिसके हाथ, चेहरे और कंधे को बिल्कुल इंसानी त्वचा से मिलते-जुलते सिलिकॉन से बनाया गया है। इस रोबोट को बनाने में करीब 10 लाख रुपये खर्च हुए हैं।

शोध अनुसंधान

कैंसर के इलाज को ज्यादा प्रभावी बनाने का तरीका ईजाद

ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड के शोधकर्ताओं ने ऐसी तकनीक विकसित की है, जिसकी मदद से कैंसर के प्रकाश आधारित इलाज को ज्यादा कारगर और किफायती बनाना संभव होगा। कैंसर के इलाज की प्रकाश आधारित या फोटोडायनामिक थेरेपी में कैंसर को नष्ट करने वाली दवाएं तभी काम करती हैं, जब उन्हें प्रकाश के संपर्क में लाया जाता है। हालांकि, ऐसी कुछ दवाएं प्रकाश की अनुपस्थिति में हानिकारक भी हो सकती हैं और इलाज के निष्प्रभावी होने का कारण बन जाती हैं। अब वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म कार्बन डॉट के जरिये दवा को सीधे कैंसर की गांठ तक पहुंचाने का तरीका ईजाद किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कार्बन डॉट के साथ भेजे जाने वाली दवा प्रकाश की अनुपस्थिति में भी चार गुना कम हानिकारक पाई गई। कार्बन डॉट में एक विशेष चमक होती है, जिसकी सहायता से शरीर में इसकी गतिविधि पर नजर रखना भी संभव होता है। -प्रेट्र

छड़ी के साथ वॉकिंग करना स्तन कैंसर में लाभकारी

नॉर्डिक वॉकिंग यानी छड़ी लेकर वॉकिंग करने का बड़ा फायदा सामने आया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि नॉर्डिक वॉकिंग करना स्तन कैंसर से पीड़ित महिलाओं की सेहत के लिए फायदेमंद है। नॉर्डिक वॉकिंग के दौरान दोनों हाथों में छड़ी लेकर चला जाता है। शरीर और हाथों को सीधा रखते हुए सही तारतम्य में चलना होता है। स्पेन की यूनिवर्सिटी ऑफ विगो के शोधकर्ता जॉर्ज टोरेस ने कहा, 'व्यायाम ना करने वालों को व्यायाम के लिए तैयार कर पाना मुश्किल होता है। ऐसे में नॉर्डिक वॉकिंग जैसे आसान व्यायाम लोगों को जल्दी पसंद आते हैं।' यह लोगों को महंगा भी नहीं पड़ता है और एक साथ कई लोग इसे कर भी सकते हैं। नौ अलग-अलग अध्ययनों में वैज्ञानिकों ने पाया कि नॉर्डिक वॉकिंग करने से स्तन कैंसर से जुड़े कई लक्षणों में लाभ होता है। मरीज के शरीर की क्षमता बढ़ती है और दर्द व सूजन की समस्या भी कम होती है। -रायटर

क्यों आती है हिचकी, वैज्ञानिकों ने खोजे कारण

न्यूयॉर्क टाइम्स से

- किसी के याद करने पर हिचकी आने की धारणा महज एक भ्रांति
- पाचन व श्वास नली में गड़बड़ी से आती है हिचकी

वाशिंगटन : अक्सर खाना खाते या जोर से हंसने के दौरान हमें हिचकी आ ही जाती है। हिचकी आना बहुत आम बात है। इसको लेकर कई तरह की बातें सुनने को मिलती है। कुछ कहते हैं कि किसी के याद करने पर हिचकी आती है तो कुछ मानते हैं कि किसी का कुछ चुराकर खाने से हिचकी आती है। क्या वाकई में यही कारण हैं या ये सिर्फ लोगों के बीच फैली भ्रांति है? वैज्ञानिकों की माने तो यह सिर्फ भ्रांति ही है। हिचकी का संबंध किसी के याद करने से नहीं, बल्कि सांस से जुड़ा है।

अमेरिकन अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन के डॉ. जॉन कुलेन ने कहा, ' हिचकी सबको आती है लेकिन फिर भी इसकी बारे में लोगों को स्पष्ट जानकारी नहीं है। दरअसल, जिन चीजों को खतरा नहीं माना जाता है, उनपर ज्यादा अध्ययन भी नहीं होता है।'

आखिर क्यों आती है हिचकी ? : पेट व फेफड़े के बीच स्थित डायाफ्राम और पसलियों की मांसपेशी में संकुचन हिचकी आने की प्रमुख वजह है। डायाफ्राम के सिकुड़न से फेफड़ा तेजी से हवा खींचने लगता है, इसी के चलते व्यक्ति को हिचकी आती है। इसके अलावा हिचकी आने का एक कारण पेट से भी जुड़ा है। खाना खाने या गैस के चलते पेट बहुत ज्यादा भरा हो तो उससे भी हिचकी आती है। वैज्ञानिकों की माने तो पाचन या श्वास नली में अत्यधिक हलचल व गड़बड़ी से व्यक्ति को हिचकी आ सकती है। गर्म या तीखा खाना खाने, जल्दी-जल्दी खाने से भी हिचकी आती है। बहुत जोर से हंसने के चलते भी डायाफ्राम में संकुचन हो जाता है, जिससे हिचकी आ सकती है।

हिचकी रोकने में कारगर हैं घरेलू नुस्खे

पेट के डॉक्टर स्कॉट गबार्ड कहते हैं कि हिचकी का कारण पता हो तो उसका इलाज भी आसान हो जाता। इसके अलावा घरेलू नुस्खे जैसे चीनी या पानी आदि से भी हिचकी रोकी जा सकती है। अगर हिचकी कई घंटों तक नहीं रुके तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

एक मिनट में चार से 60 बार तक आ सकती है हिचकी : आमतौर पर बच्चों को हिचकी ज्यादा आती है। उम्र बढ़ने के साथ हिचकी का आना कम जरूर होता है, लेकिन बंद नहीं होता है। जिस तरह लोगों के छींकने का तरीका अलग होता है, उसी प्रकार सबको हिचकी भी अलग-अलग तरीके से आती है। एक मिनट में व्यक्ति को चार से 60 बार तक हिचकी आ सकती है। आयोवा के रहने वाले चार्ल्स ऑसबोर्न को लगातार 68 वर्ष तक हिचकी आई थी। इसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है।

बीमारी का भी हो सकता है संकेत : सामान्यत : हिचकी कुछ मिनट या घंटे में ही खत्म हो जाती है। हालांकि, हिचकी यदि कई दिन या हफ्ते तक जारी रहे तो यह गंभीर समस्या हो सकती है। अमेरिका में हर साल हिचकी से होने वाली परेशानी के कारण चार हजार लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं। तनाव, बेचैनी आदि के कारण भी हिचकी आ सकती है। इसके अलावा निमोनिया, मस्तिष्क व पेट के ट्यूमर, पार्किंसन, डायबिटीज और किडनी की बीमारियों के कारण भी हिचकी आ सकती है।

मां के गर्भ से शुरू हो जाती है हिचकी : व्यक्ति को मां के गर्भ से हिचकी आना शुरू हो जाता है। डॉ. कुलेन ने कहा, 'कई बार अल्ट्रासाउंड के दौरान 17 या 18 हफ्ते के भ्रूण को हिचकी आते देखा जा सकता है। आमतौर में भ्रूण में फेफड़े के विकसित होने की वजह से हिचकी आना शुरू हो जाती है।

कोशिका से छोटी वस्तु की 3डी इमेज दिखाएगा नया इंडोस्कोप

तकनीक ▶ संभव होंगे नए प्रकार के शोध और चिकित्सकीय प्रयोग

बिना लेंस वाला यह इंडोस्कोप एक सुई के आकार जितना पतला है

प्रतीकात्मक

बर्लिन, प्रेट्र : वैज्ञानिकों ने एक नया इंडोस्कोप तैयार किया है, जिसके माध्यम से शरीर में कोशिका से भी छोटी वस्तु की 3डी इमेज देखी जा सकती है। शोधकर्ताओं ने बताया कि यह नया इंडोस्कोप बहुत छोटा और लेंस रहित है। बिना किसी लेंस, विद्युत या यांत्रिकी कंपोनेंट वाले इस इंडोस्कोप की नोंक 200 माइक्रॉन की है। जो मनुष्य के बालों के चौड़ाई के बराबर है।

शोधकर्ताओं ने बताया कि जीवित ऊतकों के भीतर की तस्वीरें सामने लाने वाले इस नये और बेहद पतले इंडोस्कोप से विभिन्न प्रकार के शोध और चिकित्सकीय प्रयोग किए जा सकते हैं। जर्मनी में ड्रेसडेन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के जुएरगेन डब्ल्यू कजारस्के ने कहा, 'लेंस रहित फाइबर इंडोस्कोप एक सुई के आकार का है, जो बेहद ही संकरे मार्ग से जाकर अंदर की तस्वीरें उच्च क्वालिटी की दिखाता है।' शोधकर्ताओं के अनुसार नया इंडोस्कोप ऑप्टोजेनेटिक्स के लिए विशेष रूप से बेहद उपयोगी हो सकता है। ऑप्टोजेनेटिक्स एक जैविक तकनीक है, जिसमें जीवों के न्यूरांस में कोशिकाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रकाश का उपयोग किया जाता है। यह इंडोस्कोप चिकित्सा प्रक्रियाओं के दौरान कोशिकाओं और ऊतकों की निगरानी करने और परीक्षण करने के काम भी आ सकता है। पारंपरिक इंडोस्कोप शरीर के अंदर की तस्वीरें लेने के लिए कैमरा और प्रकाश का उपयोग करते हैं। हाल ही के वर्षों में शोधकर्ताओं ने शरीर के अंदर की तस्वीरें लेने के वैकल्पिक तरीके विकसित किए हैं। जिससे भारी कैमरों और अन्य भारी घटकों की उपयोगिता समाप्त हो गई है। हालांकि, इसके बाद भी नई तकनीक में काफी सारी खामियां रही हैं। जैसे कि तापमान का उतार-चढ़ाव न सहन कर पाना, इंडोस्कोप के फाइबर का मुड़ जाना आदि हैं।

इस तरह बनाया नया इंडोस्कोप : नया इंडोस्कोप बनाने के लिए शोधकर्ताओं ने कोहरेंट फाइबर बंडल की नोक पर एक पतली कांच की प्लेट लगाई जो सिर्फ 150 माइक्रान मोटी थी। यह एक प्रकार का आप्टिकल फाइबर है, जिसका उपयोग इंडोस्कोपी के कार्यों में किया जाता है। कोहरेंड फाइबर बंडल सिर्फ 350 माइक्रॉन चौड़ा होता है और इसमें 10,000 कोर होती हैं। जब फाइबर की केंद्र की कोर चमकती है तो यह एक बीम का उत्सर्जन करती है। कांच की वजह से यह परावर्तित होती है। जिसकी वजह से यह एक वर्चुअल गाइड के रूप में काम करने लगती है। इसे ऑप्टिकल ट्रांसफर फंक्शन के रूप में जाना जाता है। इसके बाद यह शरीर के छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट का 3डी इमेज बनाता है।

गूगल ने प्ले स्टोर से 85 एप्स हटाए

गूगल का लोगो। फाइल

सैनफ्रांसिस्को, आइएएनएस : गूगल ने सुरक्षा कारणों के चलते अपने प्ले स्टोर से 85 एप्स को हटा दिया है। बहुराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कंपनी ट्रेंड माइक्रो के शोधकर्ताओं ने इन एप्स के अंदर एक वायरस एडवेयर को छुपा हुआ पाया था, जिसके बाद गूगल ने यह कदम उठाया। मोबाइल थ्रेट रिस्पांस इंजीनियर इकोल्यूलर जू ने बताया कि गूगल प्ले स्टोर पर उन्हें एडवेयर मिले। जिसके बाद प्रभावित एप्स को हटा दिया गया।

उन्होंने कहा, 'यह एडवेयर विज्ञापन प्रदर्शित करते हैं, इन्हें बंद करना मुश्किल है।' कंपनी के अनुसार, प्रभावित अधिकांश एप्स में फोटोग्राफी और गेमिंग एप्स शामिल थे जिन्हें आठ लाख से अधिक बार डाउनलोड किया गया था। सुपर सेल्फी, कॉस कैमरा, पॉप कैमरा और वन स्ट्रोक लाइन पजल उन 85 एप्स में सबसे लोकप्रिय थे जिन्हें ट्रेंड माइक्रो ने एडवेयर से संक्रमित होने के रूप में खोजा था। शुक्रवार को ही गूगल के स्वामित्व वाली जीमेल की सेवाएं कुछ समय के लिए बाधित रहीं थीं। हालांकि, कंपनी की ओर से जल्द ही समस्या सुलझा ली गई थी।

अब पसीने से सेहत की निगरानी करेगा सेंसर

- डिहाइड्रेशन और थकान जैसी स्थिति में तुरंत सूचित करेगा यह सेंसर

स्पेक्ट्रम

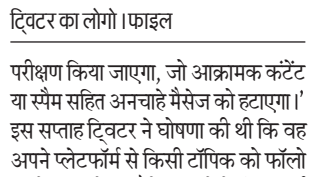

अध्ययन में भारतीय मूल के शोधकर्ता भी हैं शामिल। प्रतीकात्मक

न्यूयॉर्क, आइएएनएस : शोधकर्ताओं ने एक एसा सेंसर विकसित किया है जो पसीने का इस्तेमाल करके आपकी सेहत की निगरानी करेगा। यह तुरंत ही डिहाइड्रेशन और थकान जैसी स्थिति में आपको सूचित करेगा।

शोधकर्ताओं ने सेंसर के माध्यम से पसीने की जांच भी की। उन्होंने पसीने की दर, इलेक्ट्रोलाइट, मेटाबोलाइट आदि के स्तर की जांच की। शोधकर्ताओं की टीम में एक भारतीय शोधकर्ता भी शामिल हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली जवे ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य केवल सेंसर विकसित करना ही नहीं था, बल्कि यह पता लगाना था कि पसीना हमारे शरीर के बारे में क्या-क्या जानकारी दे सकता है। उन्होंने बताया कि ऐसे सेंसर की आवश्यकता है जो विश्वसनीय हों और बड़े पैमाने पर बनाए जा सकें। हम सेंसर को शरीर के विभिन्न स्थानों पर लगा सकें और उन्हें परख सकें। शोधकर्ताओं ने बताया कि नये सेंसर का उत्पादन बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। प्लास्टिक की सीट पर इस तरह से सेंसर बनाए जा सकते हैं जैसे कि कोई पेपर छापा जाता है। इस कम लागत वाले सेंसर में एक माइक्रोस्कोपिक या माइक्रोफ्ल्यूडिक ट्यूब होती है। जो त्वचा से पसीने को इकट्ठा करती है।

इस तरह सेंसर करता है काम : शोधकर्ताओं ने सेंसर को परखने के लिए इसे लोगों के शरीर में विभिन्न जगहों पर लगा दिया। सेंसर के माध्यम से पसीना निकलने की दर, उसमें सोडियम और पोटेशियम का स्तर का पता लगाया गया। इन पैमानों को परखने के बाद ही सेंसर स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी देता है। शोधकर्ताओं ने बताया कि इस सेंसर के माध्यम से व्यायाम करने वालों को पता चल जाएगा कि उनके शरीर में कब पानी की कमी हो रही है।

ब्लड टेस्ट की जगह ले सकता है यह सेंसर : भारतीय मूल की शोधकर्ता मल्लिका बरिया ने आशा जताई है कि भविष्य में यह सेंसर डायबिटीज की जांच और उसकी लगातार निगरानी के लिए ब्लड टेस्ट की जगह ले सकता है। हालांकि, अभी यह पता चला है कि पसीने और शरीर के शुगर लेवल के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है। शोधकर्ताओं ने सेंसर के माध्यम से डायबिटीज के रोगियों के पसीने में शुगर लेवल का पता लगाया और पाया कि पसीने के शुगर लेवल से रक्त के शुगर लेवल का पता नहीं चल सकता है।

इनबॉक्स से अनचाहे मैसेज हटाएगा ट्विटर

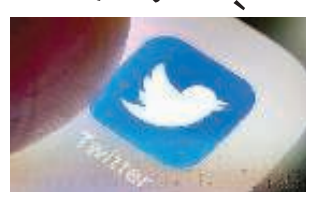

ट्विटर का लोगो। फाइल

सैनफ्रांसिस्को, आइएएनएस : माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर एक नए फीचर का परीक्षण कर रहा है, जिससे यूजर के डायरेक्ट मैसेज (डीएम) इनबॉक्स से स्पैम और एब्यूजिव मैसेज खुद ही फिल्टर हो जाएंगे। ट्विटर की ओर से कहा गया कि अनचाहे मैसेजेस अधिकतर अच्छे नहीं होते हैं। ऐसे में हम आपके डीएम रिक्वेस्ट में एक ऐसे फिल्टर का परीक्षण कर रहे हैं, जो ऐसे मैसेज को आपकी नजर और आपके दिमाग से दूर रखेगा।

वर्तमान में, यूजर्स अपने ट्विटर अकाउंट में किसी से भी संदेश प्राप्त करने के लिए अपने डीएम इनबॉक्स को खोलने अनुमति दे सकते है। टेकक्रंच की रिपोर्ट के अनुसार, 'इस नए प्रयोग में एक फिल्टर का परीक्षण किया जाएगा, जो आक्रामक कंटेंट या स्पैम सहित अनचाहे मैसेज को हटाएगा।' इस सप्ताह ट्विटर ने घोषणा की थी कि वह अपने प्लेटफॉर्म से किसी टॉपिक को फॉलो करने व डायरेक्ट मैसेज करने के लिए सर्च टूल सहित कई सारे बदलाव करने वाला है। ट्विटर ने पिछले महीने अपने डेस्कटॉप इंटरफेस डिजाइन में भी बदलाव किया था।

इनाम के लिए ग्रीस के खंभों पर चढ़ते हैं युवा

ग्रीस लगे हुए खंभों पर चढ़कर इनाम हासिल करने की प्रतियोगिता इंडोनेशिया की सबसे चर्चित और लोकप्रिय इवेंट है। इंडोनेशिया की आजादी के पर्व पर देशभर में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसमें खंभों पर ग्रीस लगा दी जाती है और शीर्ष पर इनाम के रूप में सामान रख दिया जाता है। राजधानी जकार्ता में इनाम की वस्तुएं प्राप्त करने के लिए युवा खंभों पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ ही युवा शीर्ष तक पहुंचने में सफल होते हैं। एपी

स्ट्रीट रन का आयोजन

फिलीपींस के पसे शहर में सेसम स्ट्रीट रन के दौरान फोम के साथ खेलते बच्चे। यह सेसम स्ट्रीट और काउंटिंग के 50 वर्ष का जश्न मनाने के लिए पांच किलोमीटर लंबी दौड़ होती है। इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस मौके पर अन्य कई प्रकार के फन गेम के साथ इवेंट भी आयोजित किए जाते हैं। शनिवार को यहां दुनिया की पहली सेसम स्ट्रीट रन शुरू की गई। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह दौड़ थाइलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया में आयोजित की जाएगी। एजेंसी

स्क्रीन शॉट

दो बड़े फिल्म निर्माताओं की राह पर अक्षय कुमार

अक्षय कुमार इन दिनों जिस फिल्म पर हाथ रख रहे हैं, वह फिल्म उन्हें सफलता की ओर ले जा रही है। बतौर एक्टर और निर्माता उनकी पिछली फिल्में 'एयरलिफ्ट', 'रुस्तम', 'टॉयलेट : एक प्रेमकथा', 'पैडमैन' और अब 'मिशन मंगल' लगातार बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हो रही हैं। अक्षय भी इस बात से सहमत और खुश हैं कि अब उनकी फिल्में कोई नुकसान नहीं झेल रही हैं। बतौर निर्माता किसी फिल्म पर काम शुरू करने से पहले वह फिल्म के स्क्रीनप्ले पर खास ध्यान देते हैं। इसके साथ ही वह इंडस्ट्री के दो दिग्गज निर्माताओं यश जौहर और यश चोपड़ा से भी प्रेरित हैं। अक्षय का मानना है कि दोनों ही दिग्गजों की कही हुई बात 'बजट फिट, फिल्म हिट' उन्हें निर्माण के क्षेत्र में काम करते रहने के लिए प्रेरित करती है। अक्षय के मुताबिक, उनकी सिखाई यह बात उन्हें अपनी प्रोडक्शन कंपनी को आगे बढ़ाने में काम आती है। साथ ही ऐसी फिल्में बनाने की ओर प्रेरित करती हैं, जिन्हें बनाने का कोई अर्थ होता है। अक्षय कुमार बिना किसी ब्रेक के अपनी अगली फिल्म 'लक्ष्मी बॉम्ब' की शूटिंग में व्यस्त हो गए हैं। जल्द ही वह 'हाउसफुल 4' फिल्म के निर्माता-निर्देशक के साथ भी बैठेंगे।

'कुछ कुछ होता है' की रीमेक में होंगे रणवीर, आलिया और जाह्नवी?

करण जौहर अपनी सुपरहिट फिल्म 'कुछ कुछ होता है' की रीमेक बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। इसमें वह रणवीर सिंह, आलिया भट्ट और जाह्नवी कपूर को मुख्य भूमिकाओं में लेना चाहते हैं। करण ने कहा, 'मेरी इच्छा है कि राहुल के रोल में रणवीर दिखें। उनके पास शाह रुख जैसी अभिनय क्षमता है। आलिया भट्ट अंजलि का किरदार करें, उनके पास साहस है और जाह्नवी कपूर टीना का किरदार निभाएं, क्योंकि उनके पास संतुलन है।' करण ने यह बात इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में समापन दिवस पर कही। गौरतलब है कि 1998 में रिलीज हुई फिल्म 'कुछ कुछ होता है' में तीन दोस्तों राहुल, टीना और अंजलि की कहानी थी। करण ने बताया, 'जब मैं शाह रुख से मिलने गया था तो मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं थी, पर एक सीन मेरे दिमाग में था। मैंने उनसे कहा कि यदि आपको यह सीन पसंद आए तो मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा, जो कि पूरा झूठ था। तब्बू, उर्मिला और ऐश्वर्या ने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया था और ऐश्वर्या एकमात्र अभिनेत्री थीं, जिन्होंने मुझे वापस कॉल किया था। फिल्म के लिए रानी के किरदार के लिए अभिनेत्री चुनने में कई महीने लग गए, फिर आदित्य चोपड़ा के प्रस्ताव पर रानी मुखर्जी को चुना गया।'

फिल्म के न चलने का प्रभाव नहीं पड़ता राजीव खंडेलवाल पर

'आमिर' जैसी फिल्म कर चुके अभिनेता राजीव खंडेलवाल की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'प्रणाम' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। राजीव इससे उदास नहीं हैं। उनका कहना है कि फिल्म की सफलता और असफलता का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हैं। फिल्म लोगों को पसंद आए न आए बस, उनका काम दर्शकों को पसंद आना चाहिए। उन्हें केवल अपने काम से मतलब है। फिल्म की असफलता का कारण वह खुद को नहीं, बल्कि फिल्म के कम प्रमोशन को मानते हैं। उनका कहना है कि फिल्म का प्रमोशन कम किया गया था, साथ ही फिल्म को बहुत ही कम थियेटर में रिलीज किया गया। फिल्म के निर्माता जितना इस फिल्म से उम्मीदें लगाकर बैठे थे, फिल्म की कमाई उतनी नहीं हुई। राजीव कहते हैं कि अभिनेता होने के नाते वह जितना कर सकते थे, उन्होंने किया, लेकिन एडिटिंग और प्रमोशन जैसी चीजों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। इस पर निर्णय लेना फिल्म के निर्माता का काम होता है। फिलहाल राजीव 'कोल्ड लस्सी और चिकन मसाला' नामक वेबसीरीज में शेफ के किरदार में नजर आने वाले हैं। इस वेबसीरीज में उनके साथ अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी भी होंगी। दिव्यांका इस शो से डिजिटल डेब्यू करेंगी।

जो मुझे फिल्मों के लायक नहीं समझते थे, वे रिटायर हो चुके हैं : जॉन अब्राहम

स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज हुई फिल्म 'बाटला हाउस' के साथ अभिनेता जॉन अब्राहम ने फिर से अपना सिक्का जमा लिया है। फिल्म लोग पसंद कर रहे हैं। इससे उत्साहित जॉन ने कहा, 'जब मैंने बॉलीवुड में प्रवेश किया था तो मेरी यह कहकर आलोचना की गई कि मैं इस इंडस्ट्री के लायक नहीं हूं। उस बात को अब 17 वर्ष से अधिक हो गया है। जो लोग यह बात मुझसे कहते थे, वे अब शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं। आधे तो रिटायर हो चुके हैं तो कुछ की नौकरी चल गई है। पर, मैं आज भी फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हूं।' गौरतलब है कि जॉन ने 2013 में फिल्म 'जिस्म' से बॉलीवुड में प्रवेश किया था। इसके बाद वह 'पाप', 'धूम', 'गरम मसाला', 'बाबुल', 'दोस्ताना', 'न्यूयॉर्क', 'हाउसफुल 2', 'मद्रास कैफे', 'ढिशूम' और 'परमाणु : द स्टोरी ऑफ पोखरण', 'रोमियो अकबर वॉल्टर' और 'बाटला हाउस' जैसी फिल्मों में नजर आए।

रहस्यमय ब्रह्मांड

4.5 अरब साल पहले हुई टक्कर से ठोस ग्रह बदल गया था गैस और धूल में, इसकी भरपाई आने वाले वाले अरबों वर्षों में भी नहीं होगी

...तो इस वजह से घूम रहा है बृहस्पति

न्यूयॉर्क, आइएएनएस : शोधकर्ताओं का कहना है कि बृहस्पति और एक स्थिर ग्रह में 4.5 अरब साल पहले हुई टक्कर की वजह से बृहस्पति की कोर का घनत्व कम हो गया और इसका विस्तार अनुमान से ज्यादा फैल गया। इस टक्कर के कारण ही बृहस्पति ग्रह घूम रहा है।

नासा के जूनो स्पेसक्राफ्ट से प्राप्त डाटा का विश्लेषण करने वाले शोधकर्ताओं ने बताया कि भले ही यह घटना 4.5 अरब वर्ष पहले हुई हो, लेकिन अब भी बृहस्पति की कोर का घनत्व बढ़ने और उसमें भारी सामग्री जमने के लिए अरबों वर्ष लगेंगे। राइस यूनिवर्सिटी और चीन की सन-येत-सेन यूनिवर्सिटी के खगोलविदों ने बताया कि जूनो द्वारा एकत्र किए गए हैरान करने वाले गुरुत्वीय डाटा से इस टक्कर के के बारे में जाना जा सकता है।

राइस यूनिवर्सिटी के खगोलविद और इस अध्ययन के सह लेखक एंड्रिया इसला ने कहा, ' यह हैरान करने वाला है, इससे पता चलता है कि कुछ बड़ा हुआ होगा जिससे बृहस्पति के कोर में हलचल मच गई होगी और इसका इतना विशाल प्रभाव सामने आया।' नेचर जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में बताया गया कि सिद्धांतों के हवाले से यह कहा जाता है कि शुरुआत में बृहस्पति का कोर ठोस था। यह एक ठोस चट्टानी और बर्फीला ग्रह था। फिर इसने सूरज के जन्म के समय निकली गैस और धूल को अपने वातावरण में समेट लिया।

इस अध्ययन के प्रमुख शांग-फि लीयू ने सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि जूनो के डाटा को बृहस्पति पर पड़ने वाले एक विशाल प्रभाव से समझा जा सकता है। जिसकी वजह से ठोस ग्रह धूल और गैस में बदल गया। शोधकर्ताओं ने अपने हजारों कंप्यूटर सिमुलेशन के माध्यम से यह समझा कि कैसे एक टक्कर ने बृहस्पति के कोर पर प्रभाव डाला। उन्होंने पाया कि जिस स्थिर ग्रह से बृहस्पति की टक्कर हुई वह गोली की तरह से बृहस्पति से टकराया होगा। इस टक्कर ने बृहस्पति को बिखेर दिया और इसकी कोर का घनत्व बेहद ही कम हो गया।

शुरुआत में बृहस्पति एक ठोस बर्फीला ग्रह था। प्रतीकात्मक

क्या है जूनो स्पेसक्राफ्ट

जूनो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मिशन है। यह स्पेसक्राफ्ट पांच अगस्त 2011 को लांच किया गया था। जूनो मिशन को बृहस्पति के विकास और उत्पति के बारे में बेहतर ढंग से समझाने के लिए डिजाइन किया गया था। इस स्पेसक्राफ्ट का उद्देश्य ग्रह की बाहरी और आंतरिक संरचना की जांच, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्रों के बारे में पता लगाना था।